राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का अठारहवां दिवस संख्या: 10

शनिवार,
20 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम राम। राम राम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष जी, आज बहुत सुंदर लग रहे हो।

श्री अध्यक्ष: बहुत लग रहा हूं? आपके देखने की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आज हमारे बड़े भाई की निगाहें आपकी तरफ ज्यादा हैं। आकर्षक ज्यादा ही लग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आज ध्यानाकर्षण इसीलिए पहले है ना। पहला ध्यानाकर्षण श्री केसाराम चौधरी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोजावर राजस्व गांव (मारवाड़ जंक्शन) की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से भूखंड आवंटन

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। राजस्व मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मारवाड़ जंक्शन के, केसाराम जी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से राजस्व गांव जोजावर की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से भूखंड सृजन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही है।

अध्यक्ष महोदय, बंदोबस्त रिकार्ड के अनुसार खसरा संख्या 4987/2717 दक्षिण की तरफ

है तथा खसरा नंबर 2717 उत्तर की तरफ स्थित है। जो कि वर्तमान नक्शा रिकार्ड डीआईएलआरएमपी में परस्पर परिवर्तन है एवं खसरा संख्या 2717 विभाजन होकर 28 भूखंडों के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्दर सेक्रिकेशन हुआ, वन टू वन मैपिंग करते हुए शत-प्रतिशत तरमीम कर राजस्व गांव जोजावर की नक्शा शीट दिनांक 26.02.2020 को अंतिम रूप से प्रकाशित की गई थी। जिसके अनुसार उक्त खसरों में समस्त तरमीमें अंकित हैं। परंतु मूल खसरा 2717 तथा उसके विभाजित खसरे दक्षिण भाग में स्थित हैं। खसरा संख्या 4987/2717 सरकारी भूमि उत्तर भाग में स्थित है, जो कि बंदोबस्त रिकार्ड के अनुसार परस्पर विपरीत दिशा में है।

उक्त प्रकरण में राजस्व गांव जोजावर के मूल खसरा संख्या 2717 जो कि खातेदारी भूमि है तथा संख्या 4987/2717 जो कि सरकारी भूमि है, की तरमीम राजस्व रिकार्ड में परिवर्तित हुई है। जिसके सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर तरमीम दुरुस्ती की कार्यवाही की जा रही है।

नक्शे में हुई इस विपरीत तरमीम की जांच के लिए जिला कलेक्टर, पाली को 19.07.2024 को पत्र भेजा गया है तथा जिम्मेदार अधिकारी, कार्मिकों की रिपोर्ट 15 दिवस में उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि तदनुसार उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपके जवाब में आपने स्वीकार किया है कि गोकुल पुत्र राजा को मूल खसरा 2717 में 1.3911 हेक्टेयर भूमि अलॉट हुई तथा उसमें शेष रही सरकारी भूमि रकबा 0.5818 खसरा नंबर 2717/4987 बना जो किश्तवार नक्शे में क्रमश: उत्तर और दक्षिण में दर्शाया गया है। आपने यह भी बताया कि खसरा नंबर 2717 को भू माफियाओं ने खरीदकर तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन को 100 रुपये के स्टाम्प पर नक्शा बनाकर 2717 के 11 खसरों में परिवर्तित करते हुए बंदरबांट करने के लिए पेश किया। जिसका विभाजन आदेश क्रमांक 374 दिनांक 15.07.2015 के द्वारा नामांतरण संख्या 3513 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार 11 खसरों के रूप में स्टेट हाई वे नंबर 62 के ऊपर दर्ज की है। जो बंदोबस्त के अनुसार तरमीम हुए।

आपने डीआईएलआरएमपी के प्रोजेक्ट के अनुसार उलटा-पुलटा होना बताया है। यह जवाब आपने गलत दिया है। डिजीटल नक्शे तो दिनांक 26.02.2026 को बने थे। जबकि इन भू माफियाओं ने 2020 के पूर्व ही इस सरकारी खसरा नंबर 2717/4987 रकबा 0.5818 में तत्कालीन पटवारी एवं तत्कालीन सरपंच द्वारा नक्शे बनाकर हस्ताक्षर सहित उक्त खसरे को 28 भागों में बांटकर रजिस्ट्रियां भी करा चुके थे। उसमें 2717/6 एक प्रभावशाली व्यक्ति के नाम, उन पर कभी 91 की कार्यवाही भी नहीं की गयी।

इसके साथ भू माफियाओं खुद के खाता धारी के खसरा नंबर 2717 रकबा 1.3911 में भी

पेट्रोल पंप आदि बनाकर अकृषि कार्य कर रहे थे। आज भी मौके पर दोनों ही खसरे खाली नहीं हैं। यह सब जानते हुए भू माफियाओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में मिलीभगत करके अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह 295 नहीं है। आप तो बोलें। हां, वैसे बोलें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आंकड़े तो बताने पड़ेंगे ना।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलो ना।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से भू माफियाओं को सरकारी खसरे से बेदखल कर उन सरकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने गलत सूचना दी है, उनको सस्पैंड करके जो खसरों पर अतिक्रमण किये हुए बैठे हैं, उनको उन खसरों से हटाया जाये। यह मेरी मांग है।

मैं निवेदन करता हूं कि इसके अलावा भी जोजावर में गैर मुमकिन नालों में आबादी कन्वर्ट करने का, मंदिरों की जमीनें बचने का, ओरण में कब्जे करने का, पूरे जोजावर में अतिक्रमण कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं मांग करता हूं कि पूरे जोजावर की जांच करवायी जाये, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि स्पष्ट बात है, प्रथम दृष्टया नक्शों में हेराफेरी हुई है। इधर का उधर और उधर का इधर करने का प्रयास हुआ है।

मैं आपको सदन के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें गलती हुई है, इसकी जांच होगी। मैंने विभाग की तरफ से 19.07.2024 को इस सम्बन्ध में कलेक्टर, पाली को लेटर लिख दिया है। जांच होने पर जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। आपने जो बताया है कि इस भूखंड को 28 भागों में विभक्त करके लोगों के नाम पर दर्ज किया है, वह भी आने वाले समय में पूरी कार्यवाही करके, वापस ठीक करके, दुरुस्त करके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

श्री अध्यक्ष: श्री रतन देवासी। मांग तो कर सकते हो।

पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में संचालित आधार केन्द्रों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाया जाना

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बाद में मिल लेना।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): बोल दिया।

श्री अध्यक्ष: कर दिया ध्यानाकर्षण।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): जी हां।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये हैं। यह हम सबके लिये उपयोगी और जरूरी भी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान की सीमा जालौर, बाड़मेर से लगती है तथा सांचोर व जालौर से नहीं लगती है। जिला बाड़मेर व जालौर में आधार कार्ड केन्द्रों से फर्जी आधार कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया एवं ना ही फर्जी आधार कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रकरण दर्ज हुआ। इस सम्बन्ध में सतत निगरानी जारी है।

दैनिक भास्कर समाचार-पत्र ने दिनांक 21.06.2024 को पाली से प्रकाशित प्रकाशन में फर्जी दस्तावेज बायोमैट्रिक का उपयोग कर फर्जी आधार कार्ड बनाये जाने की खबर प्रकाशित होने पर प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संज्ञान में आया।

Spp/Rtm/20.07.2024/11:10/1b

उपरोक्त खबर पर सूचना प्रौद्योगिकी एचं संचार विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली से उल्लिखित आधार कार्ड के सम्बन्ध में जांच करवायी गयी। जिसमें उक्त आधार कार्ड का नामांकन रजिस्टर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधीन कार्यरत ऑपरेटर कन्हैया लाल की आई.डी. से होना पाया गया। प्रकरण के संलिप्त ई-मित्र आधार संचालकों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी संख्या 63 दिनांक 21.06.2000 पुलिस थाना सरवाना जिला सांचौर में दर्ज करवायी जाकर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी गयी। जिला सांचौर में आधार कार्ड बनाने वाले ई-मित्र संचालकों के विरुद्ध दो प्रकरण दर्ज किये गये। मुकदमा संख्या 209/2023 अन्तर्गत धारा 420 आई पी सी एवं धारा 66 (सी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पुलिस थाना चितलवाना जिला सांचौर में दर्ज किया जाकर आरोपी मनोहरलाल पुत्र गोगाराम निवासी सेडिया जिला सांचौर को दिनांक 21.06.2024 को अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। वांछित अभियुक्तगण विकास पुत्र सदराम विश्नोई निवासी राजीव नगर, महेश कुमार पुत्र मोहन लाल जाति विश्नोई

निवासी सांगवाड़ा, सुनील पुत्र हनुमानराम जाति विश्नोई निवासी चितलवाना की गिरफ्तारी शेष है एवं अनुसंधान जारी है। मुकदमा संख्या 63 अन्तर्गत धारा 420, 465, 478 एवं 120 आई पी सी. पुलिस थाना सरवाना जिला सांचौर में दर्ज किया जाकर प्रकरण में नामजद आरोपी तोगाराम, गणपतसिंह व कन्हैयालाल अपनी जगह से व संभावित स्थानों से फरार है। ..(व्यवधान).. क्या हुआ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किया। आपने इनको जवाब भिजवा दिया। जवाब तो आ गया। यह प्रश्न पूछें और आप उत्तर दें तो इसकी सार्थकता होगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनको कहा नहीं कि मैंने मान लिया। यह कह देते तो मैं तो पढ़ता ही नहीं। यह कह देते। यह शुरू हो गया तो पूरा पढ़ने दो। ये पहले ही कह देते। ..(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष: एक बार विषय आ जाये, पूरा कर लेने दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जिनकी तलाश हेतु उनकी सकूनत एवं दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास व अनुसंधान जारी है। उक्त दोनों एफ आई आर में दर्ज आधार कार्ड जारी होने से देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में उपरोक्त उल्लिखित घटना के विस्तृत अनुसंधान से ही स्थिति स्पष्ट होगी। अनुसंधान जारी है। सांचौर जिले में ई-मित्र संचालकों एवं आधार केन्द्रों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। मुकदमा संख्या 63/2024 पुलिस थाना सरवाना जिला सांचौर के सम्बन्ध में इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा उक्त प्रकरण का अनुसंधान सी.बी.आई. को स्थानांतरित किये जाने का अनुरोध किये जाने पर गृह विभाग के पत्र दिनांक 09 जुलाई, 2024 द्वारा सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को उक्त प्रकरण का अनुसंधान सी.बी.आई. को स्थानांतरित किये जाने हेतु आवश्यक सूचनाएं मय अधिसूचना सहित उपरोक्त अनुरोध पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा तकनीकी स्तर पर की गयी जांच उपरांत 14 आधार आपरेटर्स को कारण बताओ नोटिस (शो-काज नोटिस) जारी किया जाकर इन ऑपरेटर्स को निष्क्रिय कर इनकी मशीन डिएक्टिवेटेड कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशों की अनुपालना में रजिस्ट्रार, सूचना प्रौद्यागिकी एवं संचार विभाग द्वारा इन आधार ऑपरेटर्स एवं इनकी मशीनों को डि-रजिस्टर कर बंद कर दिया गया है एवं प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला प्रशासन स्तर पर रजिस्ट्रार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं अन्य रजिस्ट्रार द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान के आधार केन्द्रों की सघन जांच का अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त प्रकरण में लिप्त पाये जाने वाले आधार ऑपरेटर्स पर कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी

कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कल भी लगा हुआ था और इसकी गंभीरता और इसके महत्व को देखते हुये आपने इसको आज पुन: वापस किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उसमें लगभग सारी बातें आयी है। हमारे कई माननीय सदस्य जो आस-पास के क्षेत्र के जिलों के हैं, उनको भी सुनना था। पर चूंकि सदन के सभी माननीय सदस्य यहां बिराजे हुये हैं और यह इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है कि आपने इसकी पुन: अनुमति दी है तो यह माननीय सदस्यों के ध्यान में भी आना चाहिये, क्योंकि राजस्थान के और भी जिले इसकी चपेट में आयेंगे। यह हमारे, आपके, यह सदन के सदस्य, प्रदेश के जो हमारे जितने भी निवासी हैं, उन सबके लिये खतरा और चुनौती बन गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें दो-चार चीजें आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। पहला तो जो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन किया दैनिक भास्कर के संवाददाता ने, आप देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन चीजें आपके प्रकाश में लाना चाहता हूं। आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहता हूं कि आधार कार्ड बनाने के लिये हम लोग तो ई-मित्र पर जाकर जितने डाकुमेंट्स चाहिये, उतने देते हैं, मांगते हैं और सच्चे डाकुमेंट्स को उनको बताना पड़ता है और फिर जाकर आधार कार्ड बनता है। यहां क्या स्थिति हुई है? यहां स्थिति यह हो रही है कि जो आधार कार्ड सांचौर जिले में बन रहा है, उसका एड्रेस बारां का लिखा रहा है। उसको स्केन करना है, उसके फेस को स्केन करना है, उसका फोटो लेना है, उसकी फोटो की जगह उसकी आंखों को स्केन करने के लिये आई स्केनर को उल्टा पकड़ लेता है और उल्टा पकड़ने के बाद उसका स्केन करता है और फिर उसका फोटो और उसकी आइज आ जाती है उसके अन्दर। उसको हाथों के निशान लेने पड़ते हैं अंगुलियों की और हाथों की उसकी जगह वह पैरों के उल्टे निशान ले रहा है और पैरों के निशान को हाथों के बता रहा है। जब वह स्केन कर जाता है और उसके ऊपर उसका नाम आता है तो वह नाम बताता है। उदाहरण के तौर पर भगवती देवी, उसके पूछा भगवती देवी कैसे आ रहा है? यह अपने आप ठीक हो जायेगा थोड़ी देर के अन्दर। आयु 18 कैसे बता रही है, मेरी आयु तो 40 वर्ष आनी चाहिये तो वह कहता है कि जब अपलोड हो जायेगा और सब कुछ हो जायेगा तो आपकी आयु भी सही आ जायेगी। आप देखिये कमाल, यह सब करने के बाद में उसका आधार कार्ड अपडेट हो गया। पूरी व्यवस्थाओं से हो गया और उसको वह आधार कार्ड मिल गया। अब यह बताइये,माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे और आपके खुद के जो फोटो है, वह फोटो कहीं मिस-यूज नहीं हो रहे होंगे? उन फोटो को कोई उपयोग में नहीं ले रहा होगा इसी प्रकार से आधार कार्ड की तर्ज पर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी सबसे शर्मनाक बात मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं 200-200 रुपये में स्कूल के बच्चों के फिंगर प्रिंट्स लिये जा रहे हैं।

लिस्टेड है और उसने बताया कि किन-किन बच्चों का कैसे हमने लिया है। अब स्कूल के बच्चे, जिनको 200 रुपये का प्रलोभन देकर आप कह रहे हो कि आपके फिंगर प्रिंट्स मुझे लेने हैं और वह बच्चे फिंगर प्रिंट्स दे रहे हैं और फिर वह आधार कार्ड और किसी के नाम से अपलोड हो रहा है। आप बताइये कि उन बच्चों का क्या होगा? (समय समाप्ति सूचक घंटी)

अन्त में, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो महत्वपूर्ण बात है, वह मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इसमें मुझे सिर्फ दो बातें ही कहनी हैं, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं। इसमें आपका अगर सोफ्टवेयर का यह पूरा मामला अपडेट नहीं होगा तो यह बहुत बड़ी चुनौती इस प्रदेश के लिये बने जायेगी। एक इसमें आपने दिया कि बाड़मेर की बॉर्डर तो लगती है मगर सांचौर और जालौर की भी लगती है, पर सांचौर में तो एक खेत ही आड़े आता है। डूंगरी जहां यह कार्यवाही हो रखी है, वह तो वहां से 20-25 किलोमीटर ही दूरी पर है। एक खेत ही आड़े आ रहा है तो अब वहां का व्यक्ति बार्डर के उस पार का, उन्होंने यहां आकर कितने फर्जी आधार कार्ड बनाये हैं या नहीं बनाये होंगे, उसकी अभी तक कोई जांच ही नहीं, कोई पता ही नहीं है। मेरी पहली मांग तो यह है कि उस पूरे एरिया में और राजस्थान के अन्य भागों में सक्षम टीम बनाकर और समस्त जगह सर्च ऑपरेशन किया जाये कि इस प्रकार के फर्जी आधार कार्ड नहीं बने ताकि हमारे प्रदेश और हम लोगों के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वह भविष्य में हम लोगों के लिये खतरा नहीं बनें।

नंबर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक केस जो आपने बताया वह सी.बी.आई. ने खुद ने सुओमोटो अपने पास भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर मंगाया है। ठीक है, वह दे दिया मगर जो बाकी के केसेज हैं, जो बाकी के मुकदमे हैं, बाकी के ई-मित्र संचालकों को आपने बंद किया है, जिन पर शक था उन लोगों पर और उसके अलावा भी सर्च ऑपरेशन में राजस्थान स्तर की टीम बनाकर उसका सर्च करा दें ताकि आपके सामने और भी उसकी सत्यता आ जायेगी। मैं पुख्ता नहीं बता रहा हूं मगर मेरे पास जो सूचना आयी है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आंखों को उल्टा स्केन करके किया है, उसी तरीके से वह पशु और जानवरों का भी उपयोग करते हैं आइज को कैच करके लगाने के अन्दर। इंटेलीजेंस का इसको दिया जाये और ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः महत्वपूर्ण विषय है।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम लोगों के लिये चुनौती है। भले ही सदन के बाहर उठायें या सदन के अन्दर, अब यह क्या होता है कि इस प्रकार के लोग, जो इस तरह का नेटवर्क चलाते हैं, इस प्रकार के लोग, जो इसको फर्जी बिलिंग करने के लिये इन आधार कार्डों को यूज करते हैं तो वह हम लोगों के लिये भी चुनौती बन रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ऐसे इश्यूज उठने के बाद में सोशल मीडिया पर उन लोगों पर भी राजस्थान पुलिस को और सक्षम विभागों को नजर रखनी चाहिये कि कौन व्यक्ति क्या कमेंट्स कर रहा है, उससे पता चल जायेगा कि किसके तार किसके साथ जुड़े हुये

हैं और यह चीजें भी आपके संज्ञान में आ जायेगी। यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं।

MLS/RTM/20.07.2024/11:20/1c

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, बिलकुल सत्य है। पुलिस थाना चितलवाना में जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें मशीन भी पकड़ी थी, लेकिन उस समय की सरकार की जो व्यवस्था थी, उन्होंने अपनी सिफारिश लगाकर उस मशीन को गायब करवा दिया। ईमानदारी की बात यह है। हमारी सरकार बनने के बाद वापस मैंने उस व्यवस्था को लिया। ये आधार कार्ड लेकर मुम्बई में, बंगलोर में, मद्रास में, बड़े-बड़े शहरों में ले जाकर खाते खुलाते हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। विषय गम्भीर है। माननीय मंत्री जी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर, अगर भास्कर स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता तो सरकार तो सोती रहती। सरकार क्यों सोती रही, सरकार क्यों लापरवाही रही?

श्री अध्यक्ष: यह आपके जिले काम मामला नहीं है। बैठिये। विषय आ गया है। इनका अंकित नहीं हो। बिना अनुमति के नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): तत्कालीन सरकार उन्हें प्रश्रय दे रही थी, मदद कर रही थी, सहयोग कर रही थी। आपकी सरकार सहयोग कर रही थी।

श्री अध्यक्ष: बैठिये माननीय सदस्य। यह विषय बहुत गम्भीर है। इस विषय पर हम सब बातें भूलकर बात करें। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अतः इन आधार कार्डों की गहन जांच होनी चाहिये। सरकार इसे गम्भीरता से ले रही है, लेकिन और गति इसमें पकड़े ताकि शीघ्रातिशीघ्र इसकी जांच होकर के इस तरह के जो फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं, ऐसे संचालकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि जनता को लाभ मिले, सुरक्षा भी हो सके और ऐसे एलीमेंट्स पर अंकुश लगाया जा सके।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को बहुत गम्भीरता से लिया है। यह विषय गम्भीरता से लेने योग्य भी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषय को सीरियसली लिया है। मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा है कि अगर भास्कर स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता तो क्या सरकार सोती रहती। यह विषय बहुत सही है। जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया और जिस कालखण्ड में यह फर्जीवाड़ा निकला है, उसके बारे में माननीय सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने बता दिया है। विधान सभा चुनाव के सब पुराने वाले आधार हैं, इसलिए मैं इसमें जाता ही नहीं, ...(व्यवधान)... मैं इस पर राजनीति नहीं करता। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। मैंने आपसे बहुत कहा है, यह आपको हो क्या गया है? ...(व्यवधान)... माननीय हरिमोहन जी, यह हर बात पर खड़े होना, आप जैसे पुराने व्यक्ति को शोभा नहीं देता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह सब किस कालखण्ड का है, इसमें नहीं जाता हूं। यह हम सबके लिए गम्भीर है, चाहे हमारे कालखण्ड का हो या आपके कालखण्ड का हो। आप जिस तरह से अननैसेसरिली बात करते हैं कि सरकार सोती रहती, सरकार सोती नहीं रहती, सरकार ने पकड़ा है, जेल में डाला है, मुकदमे दर्ज कराये हैं, सीबीआई में भेजा है और 14 मशीनों को डी-एक्टिवेट किया है। पूरे बाड़मेर, सांचोर, जालोर में पुलिस और जिला कलक्टर सक्रिय हैं। जैसी माननीय अध्यक्ष महोदय की भावना है, आज मैं आप सबके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में अभियान चलाया जायेगा, सर्च ऑपरेशन चलाया जायेगा, सभी मशीनों की साल भर की रिपोर्टिंग की जांच की जायेगी।

ऐसे-ऐसे कारनामे, ई-मित्र का ऑपरेशन कहीं हो रहा है, आधार कार्ड कहीं बन रहा है। ई-मित्र का रजिस्ट्रेशन कहीं का है, काम कहीं कर रहा है। काम करने के लिए नामजद कोई और है और काम कोई और कर रहा है। मशीन किसी की है, काम कोई और कर रहा है। जैसा कि रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, सात-सात साल, चौदह-चौदह साल, तेरह-तेरह साल तक के बच्चों को भी बनाया जा रहा है। उल्टे हाथ-पैरों के निशान लिये जा रहे हैं। आई का रेटिना उल्टा-सीधा लिया जा रहा है। ये सारे तथ्य सही हैं, लेकिन हम सबको इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिये कि ऐसा भविष्य में नहीं हो। चाहे आपके कालखण्ड में हुआ, चाहे हमारे कालखण्ड में हुआ, हुआ वह गलत है, लेकिन मैं आज सदन के माध्यम से और माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरे राजस्थान में, चाहे वे ई-मित्र धारक हों, आधार कार्ड बनाने वाले हों, सबकी पूरी जांच करेंगे। इसमें जो भी दोषी होगा, उसे सख्त से सख्त सज़ा देंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। धनयवाद।

श्री अध्यक्षः पूरे राजस्थान में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पूरे राजस्थान में जितने भी ई-मित्र धारक हैं। एक निवेदन और कर दूं, ई-मित्र धारकों के बाहर बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। कई शिकायतें मिलती हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा, वे बाहर बोर्ड लगाएं। किस-किस आइटम की कितनी फीस है, कितने दिन में बनाना है ताकि आम पब्लिक को पता रह सके कि इनको यह फलां-फलां अधिकार है और इतनी फीस निर्धारित है और यह चीज निःशुल्क है। यह भी हम पूरी व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हो गया अब। सबको बोलना आवश्यक नहीं है। यह भरतपुर का विषय नहीं है। ...(व्यवधान)... नहीं, हो गया। जब अनुमति मिलेगी, तब आप बोलना। बैठिये।

वार्षिक प्रतिवेदन। डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

हरिदेश जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

1. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का अधिनियम, 2019 की धारा-43 के अन्तर्गत हरिदेश जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24,

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2023-24)

2. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24,

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2023-24)

3. महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

याचिका

बड़ी बांकली कालबेलिया बस्ती (आहोर) में पुरानी क्षतिग्रस्त टंकी के स्थान पर नयी टंकी का निर्माण

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र आहोर के बड़ी बांकली कालबेलिया बस्ती में पुरानी क्षतिग्रस्त टंकी की जगह नयी टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल

बिलाड़ा में सहायक खान अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में सहायक खान अभियन्ता कार्यालय की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक मिनट में, एक वाक्य में। डा. ऋतु बनावत।

सूचना

बयाना में टूटे बिजली के तारों से करंट लगने पर मौतें

डा. ऋतु बनावत (बयाना): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के थ्रू

यह बात कहना चाहती हूं कि कल रात बयाना उप-खण्ड के गांव मन्नापुरा में 24 वर्षीय रामेश्वर, जो एक किसान है, उसकी मृत्यु बिजली के तार टूटने के कारण हो गयी। साथ ही, 20 भेड़ों की भी मौत हो गयी। एक साल पहले भी बयाना उप-खण्ड के गांव पीपरी में दो व्यक्तियों की मौत बिजली का करंट लगने से हो गयी थी। यह बहुत गम्भीर विषय है। आये दिन बिजली के तार टूटने से बयाना विधान सभा क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किये जाएं।

श्री अध्यक्षः हो गयी इन्फॉर्मेशन। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। डॉ. प्रेम चन्द बैरवा

अनुदान की मांग

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा की प्रस्तुति

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,41,32,53,000/- (सत्ताईस अरब इकतालीस करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 22 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्षः तीनों डिमांड्स पर रख दें एक साथ।

मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा की प्रस्तुति

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,71,16,33,000/- (चार अरब इकहत्तर करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

मांग संख्या 62 - परिवहन की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 62 - परिवहन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,24,39,00,000/- (सोलह अरब चौबीस करोड़ उनतालीस लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 62 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री अध्यक्षः श्री अतुल भंसाली।

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा व मांग संख्या 62 - परिवहन पर विचार

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के बजट प्रतिवेदन के अन्दर अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए प्रथम स्पीकर के तौर पर चुना गया है।

mkd/rtm/20.07.2024/11:30/1d

मैं आप सब की आज्ञा से विष्णु पुराण के प्रथम स्कन्ध के 19वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है कि:-

तत् कर्म यत् न बन्धाय,
सा विद्या या विमुक्तये।
आयासाय अपरं कर्म,
विद्या अन्याशिल्पनैपुणम्॥

कर्म वही है, जो बन्धनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाये। सनातन धर्म और भारतीय संकल्पना के मंगल बोध का स्मरण करते हुए मैं मां भारती के चरणों में कोटि-कोटि वन्दन करते हुए और प्रदेश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मन्दिर के इस गौरवशाली सदन के प्रत्येक साथी का अभिवादन करते हुए, सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ स्वतंत्रता के अमृतकाल 2047 के विजन को ध्यान में रखकर युवाओं को केन्द्र में रखकर बनाये गये सर्व समावेशी विकासोन्मुख बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदया का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्त करे। हमारी सनातन भारतीय संस्कृति में विद्या वही है, जो मुक्त करे। देह में स्थित करे। पेट की चिन्ता से मुक्त कर, चिर चिन्तन दिव्य चेतना से युक्त करे। मुक्ति किससे? मुक्ति बस्ते के बोझ से, मुक्ति शिक्षा के आर्थिक बोझ से, मुक्ति अंगेजी सोच से और अंग्रेजी भाषा के मैकाले तंत्र से। मुक्ति कोचिंग सेन्टर के चक्रव्यूह से, मुक्ति प्रतिस्पर्धा के तनाव से, मुक्ति आजीविका की चिन्ता से और मुक्ति कैसे हो? सरकारी स्तर पर शिक्षा नि:शुल्क उपलब्ध करवाकर, विद्ववान कुशल, अनुभवी शिक्षकों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को नि:शुल्क ऑनलाइन उपलब्ध करवाकर, स्कूली शिक्षा पूर्ण होते ही भविष्य के लिए स्वयं की रुचि क्षमता अनुसार उच्च शिक्षा का मार्ग तय कर, प्री-कॉलेज काउंसलिंग के माध्यम से, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को भी मातृभाषा में उपलब्ध करवाकर, आधुनिक तकनीक के उपयोग की सिद्धहस्तता प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान कर, प्रतियोगी युग के अनुरूप आधुनिकतम तकनीकी विषयों की

प्रशिक्षा अभ्यास की उपलब्धता करवाकर और जब ये सभी चैनल पूर्ण कर ले तो इन्हें रोजगार देने वाली कम्पनियों के साथ मिलकर पढ़े हुए विषयों का आजीविका उपयोगी व्यवहारिक उपयोग का कार्य क्षेत्र प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर। सबसे बड़ी बात इस पूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विद्यार्थी को भारतीय गौरव से जुड़ाव बढ़ाकर, उसे अनुभव कराना कि वह मालिक बनेगा, नौकर नहीं, वह सक्षम बनेगा, आश्रित नहीं, अनाश्रित नहीं, वह दूसरों को सहारा देने योग्य सबल और स्वतंत्र बनेगा, यही हमारी भारतीय परम्परा से जुडने का फल है। नई शिक्षा नीति, 2020 में इसका पूरा उल्लेख किया गया है।

आपको लग रहा होगा कि मैं उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा अनुदान की मांगों पर बोलते हुए समय विषयांतर कर रहा हूं, कहीं भटक गया हूं, पर ऐसा नहीं है। ये सारे विषय हमारी नई शिक्षा नीति, 2020 की मूल संकल्पना है। ये विषय हमारे इस बजट के अन्दर है। हमारा बजट नई शिक्षा नीति के आधार पर हमारे प्रदेश के युवाओं को भारतीय परम्परा युक्त आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाला है। आइये, इस बजट के अंशो में से आप इस एसेंस को निकालें। आज हमारा सदन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, ये ऐसे विषय हैं, जो सीधे-सीधे प्रदेश के युवाओं के भविष्य निर्धारित करते हैं। युवाओं का जैसा भविष्य होगा, वैसा ही हमारे प्रदेश का भविष्य होगा। इसी कारण हमारा सम्पूर्ण बजट युवाओं के सुनहरे भविष्य को केन्द्रित करने वाला है।

मैं इस बजट के मुख्य बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, शिक्षा के बजट में 7 हजार 64 करोड़ की वृद्धि की गई है। युवाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए बजट में युवा नीति है। चार लाख सरकारी नौकरियों का सुदृढ़ संकल्प है। 300 करोड़ की लागत से प्रदेश के तकनीकी संस्थानों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आरआईटी आरम्भ करने का नवाचार अद्भुत है। दो वर्षों में 20 नये आईटीआई और 10 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए बजटीय प्रावधान है। एक दर्जन नये महाविद्यालय, आठ कन्या महाविद्यालय, तीन नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प है। इसमें 25 महाविद्यालयों में नये विषय और पीजी स्तर के क्रमोन्नयन का उल्लेख है। 125 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय भवनों के नवीनीकरण और रख-रखाव के कार्यों को इसमें सम्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 हजार करोड़ से भी अधिक की लागत से प्रदेश के आरआईटी में आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं आधुनिकीकरण किया गया है। सबसे बड़ी बात प्रत्येक आरआईटी के लिए, जो बजट में चार प्रस्तावित हैं, उनमें 100 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही दिन से बजट के माध्यम से किया गया है। सबसे बढ़कर उच्च शिक्षा नीति के इन तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम में उपलब्ध होंगे, ताकि सुदूर गांव की ढाणी की प्रतिभाएं अंग्रेजी के डर से इन कॉलेज और महाविद्यालय में एडमिशन लेने से डरे नहीं और वंचित भी नहीं रहे। सामान्य स्नातक स्तर पर ड्रॉप आउट रोकने के लिए और बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए काली बाई स्कूटी योजना चल रही है। हमारी सरकार ने अब तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में

भी बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए 500 स्कूटी की योजना इस बजट के माध्यम से इस वर्ष चालू की है।

कॉरपोरेट सर्टिफिकेशन योजना से अब हमारे बच्चे अध्ययन के साथ-साथ कमाने के लिए भी प्रामाणिक रूप से तैयार हो जायेंगे। अब हमारे सभी शिक्षा केन्द्र, नई शिक्षा नीति के रंग में नजर आयेंगे। इन सभी योजनाओं से निकले युवाओं को अवसर की कमी नहीं रहे, इसीलिए उच्च शिक्षा शिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं को मिलेगा सहारा, यूथ डिपार्टमेंट का। केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रहें, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें, इस भाव से तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ स्टेट स्किल डवलपमेंट की भी पॉलिसी बनाई गई है।

स्किल डवलपमेंट और अपग्रेडेशन से दस लाख रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की ठोस योजना है। आधुनिक डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्ययन अभ्यास के अवसरों के लिए स्पष्ट संकल्पना है। इन अवसरों से तैयार होने वाले युवाओं को अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम द्वारा आधुनिक सफल कम्पनियों के प्रबन्धकों से मिलने, स्वयं का स्टार्ट-अप आरम्भ करने के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया गया है।

अटल इनोवेशन स्टूडियो के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग से लेकर कॉमिक डिजाइनिंग तक तैयार करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है। ये जितनी भी तकनीकी, स्किल डवलपमेंट की रोजगारोन्मुखी योजनाएं हैं, भले ही वह किसी भी डिपार्टमेंट की हो, उन सबका समावेश तकनीकी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में और सभी महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना प्रस्तावित इस बजट में किया गया है। इन सारी योजनाओं की महता के सम्बन्ध में, हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारी सरकार को विरासत में क्या मिला।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार की उच्च और तकनीकी शिक्षा रीति-नीति, 24 फरवरी, 2022 को कांग्रेस की सरकार एक बिल लाई थी। राजस्थान गुरुकुल यूनिवर्सिटी बिल, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बिल, कैसी यूनिवर्सिटी जो धरातल पर नहीं थी। हमारे नेता श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सदन में खड़े होकर कहा था, उन्होंने स्वयं उस स्थान पर जाकर देखा है, वहां का वीडियो बनाया था। कांग्रेस की सरकार को शर्मनाक अवस्था झेलनी पड़ी और उस बिल को वापस लेना पडा।

दूसरा, यही थी वह कांग्रेस की सरकार जिसमें भ्रष्टाचार, आरपीएससी जो इनके भ्रष्टाचार का प्रिय अड्डा बन चुका था। कांग्रेस के हर कार्यकाल में आरपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पर होता है। यह हमने पीछे रिकॉर्ड में देखा है। पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की हरेक परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, हर परीक्षा नकल माफियाओं के हत्थे चढ़ी। युवा ठगा-सा गया, नौकरी के नाम पर परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक के कारण बार-बार परीक्षाएं कैंसिल होने लगी।

मैं बताता हूं, प्रदेश में नकली घोषणाओं की झड़ी लगा दी। नये महाविद्यालय, नये

तकनीकी संस्थान, इनकी घोषणाओं के अधिकांश संस्थान संसाधनों के अभाव में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षक भी पूरे नहीं हैं, भवन भी जुगाड़ में चल रहे हैं। जहां भवन बनाये गये हैं, वे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये हैं।

हमारे जोधपुर में इन्होंने नकली स्वीकृति से वन भूमि में कॉलेज का ढांचा खड़ा कर दिया। अब वन विभाग उसे तोड़ने पर आमदा है। करोड़ों रुपये लग गये कन्या महाविद्यालय, लाल सागर, जोधपुर के नाम पर और कांग्रेस के शासनकाल में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती घोटाला कांड तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे सूर्य नगरी के लोगों को, जब उसका बार-बार उल्लेख आता था तो शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ता था। कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा के लिए एक नया पॉलिटेक्निक कॉलेज, मंडोर में दिया।

आदरणीय सभापति महोदय, पांच साल से वह पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, पर वह उस जगह मंडोर में नहीं चल रहा है। पुराना ही पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो जोधपुर शहर में स्थित है, उसी में उसका संचालन हो रहा है।

अतः हमें जो विरासत में मिला, एक दिशाहीन, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जिसे सुधारकर पूर्णतया सकारात्मक प्रभावी रूप से लाने का संकल्प हमारी भाजपा सरकार का है।

Bhs/Rtm/20.7.24/11.40/1e

और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा साथ में, हमारे आदरणीय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉ. प्रेमचन्द जी बैरवा साहब का कि उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म और नीचे के हर तबके और स्टूडेंट्स के अन्दर जो एक भावना थी उस संकल्पना के साथ इस बजट में उसको उतारा और ऐसे घोटालों, भ्रष्टाचार और नकल माफियाओं के मकड़जाल में रंगी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के हमरंग नेताओं को विश्वास ही नहीं होता है कि सरकार अपने बजट के वादों को भी पूरा कर सकती है पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह मोदी जी और भजन लाल जी की भाजपा की डबल इंजन सरकार है जो राजस्थान को विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ा कर विकसित बना कर ही रहेगी।

सभापति महोदय, हम शिलान्यास भी करते हैं उसी कार्यकाल में लोकार्पण भी करते हैं। हमारी सरकार विजन वाली सरकार है। विजन, प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का, विजन, युवाओं को कुशल प्रशिक्षित प्रतिस्पर्धी बना कर नौकरी प्रदाता बनाने का और हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम यह करके दिखायेंगे और इसको पूरा करने का दमखम हमारे उप मुख्य मंत्री तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा जी में है। उनके नेतृत्व में यह विभाग पूरी कर्मठता से इस बजट में किये हुए वादों को पूरा करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान कुछ ऐसे विषयों

की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो यदि अपने जवाब में सम्मिलित करें तो इससे इतने सुन्दर बजट में और सुगंध बढ़ जायेगी। आपने गुरुकुल शब्द की महत्ता को जान कर पदनाम परिवर्तित किया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूं पर ऐसे भावपूर्ण शब्द की पुनर्प्रतिष्ठा के समय मेरी एक वेदना उभर कर आती है। कई बार हमें ऐसे समाचार मिलते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अपनी पेन्शन भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि वे शिक्षक जिनसे हम सभी पक्ष और विपक्ष के साथी कभी न कभी पढ़े हैं वे हमारे आचार्य हैं गुरु हैं वे यदि वृद्धावस्था पेन्शन पाने के लिए सड़कों पर बैठे, आन्दोलन करे तो हम सभी लोगों के लिए एक लज्जा का विषय है। अतः मैं पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों की सहमति, सम्मति और सहयोग से यह मांग प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पेन्शन भुगतान की जिम्मेदारी सरकार स्वयं उठाये और ऐसी व्यवस्था करे कि कभी भी हमारे आचार्यों को पेन्शन के लिए आन्दोलन नहीं करना पड़े।

सभापति महोदय, जब मैं आचार्यों के लिए इतनी संवेदनशील बात हृदय की गहराई से और वेदना अनुभव करते हुए कह रहा हूं तो एक विचित्र स्थिति इसके विपरीत भी बन रही है। आप सभी सहमत होंगे कि हमारे समय में हम जब कॉलेज जाते थे, कक्षाएं नियमित होती थी। हम कक्षा में अध्ययन-अध्यापन के भरोसे ही आज तक यहां पहुंचे हैं, परन्तु क्या आप सभी को यह नहीं लगता कि आज कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी केवल एक एग्जाम टाइम अटेंडेंस वाले संस्थान बन गये हैं। कक्षाएं प्रायः खाली रहती हैं, परीक्षाओं में स्थानीय स्तर पर अंकों का खेल सिफारिश और संकाय बचा रहे के आधार पर चलता है। ऐसे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, प्रबन्धकों, सरकार के उच्च स्तर की नीति निर्माताओं की ओर सभी विद्यार्थियों को मिल कर सोचना होगा कि हम विश्वविद्यालयों की कक्षाओं की उपयोगिता को कब वापस लौटायेंगे। नहीं तो याद रखिये, यह कोचिंग वालों का चक्रव्यूह पहले तो विद्यार्थियों को खा रहा है, फिर इन कॉलेज विश्वविद्यालय के पदों को खा जायेगा, फिर इन संस्थाओं को खा जायेगा।

सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है, इस बारे में मेरा सुझाव है। आप प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक यू-ट्यूब चैनल बनवाइये। इस प्रकार कक्षावार सैक्शन बनवाइये और यह अनिवार्यता कीजिये कि प्रत्येक शिक्षक को उसकी प्रत्येक दिन की प्रत्येक कक्षा को यू-ट्यूब पर उस दिनांक के नाम से डालना ही है। कोई विशेष खर्चा इसमें नहीं आयेगा और चूंकि कोरोना में हमको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबको ट्रेंड भी कर दिया शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी तो अगर इस तकनीकी माध्यम से इस चीज को अगर हम क्रियान्वित करते हैं तो स्कूलों और महाविद्यालयों और तकनीकी महाविद्यालयों में जो अटेंडेंस का इश्यू है जो एजुकेशन और क्लास नहीं लगने का विषय है उसमें हम काफी रूप से काबू कर पायेंगे।

दूसरा, शिक्षक के पास अपना मोबाइल और वाई-फाई और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह सबके पास उपलब्ध हैं यह बहुत आसानी से हो सकने वाला काम है और इससे निःशुल्क कोचिंग मिलेगी उससे कोचिंग सेन्टर की जो अभी एक वायरस सबमें फेल गया है उसको दूर

करने का मौका मिलेगा।

माननीय मंत्री महोदय, बातें बहुत है कहने की, अवसर भी है पर सबको यहां कहना है। अपने वक्तव्य को पूर्णता देते हुए मेरा यही कहना है कि माननीय प्रधान मंत्री जी नरेन्द्र भाई मोदी ने जो शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को मैकाले की शिक्षा नीति से मुक्त करवा कर भारतीय संस्कारों से युक्त पूर्णतया सुवैज्ञानिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाने की जो शिक्षा नीति लागू की है उस शिक्षा नीति पर आधारित यह बजट है जिसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और युवा मामलों के विभाग समन्वय करके एक सर्वविभागीय समन्वय वाला यह बजट है जिससे पूरे बजट में एक ही टोन निकलती है, 'हम बनायेंगे समर्थ, सफल, सुलझा युवा और युवा बनायेंगे विकसित और श्रेष्ठ राजस्थान।'

सभापति महोदय, इसके साथ ही, मैं मेरे जोधपुर के कुछ विषय हैं उनके लिए बात करना चाहूंगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में संस्कृत व्याकरण विषय में कौमुदी प्रक्रिया के साथ में डॉ. पुष्पा दीक्षित की पाणिनीया पौष्पी प्रक्रिया के अध्ययन का विकल्प भी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय महाविद्यालय, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में भवन विस्तार हेतु विशेष बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय महाविद्यालय, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में व्यवसाय प्रशासन, वनस्पति विज्ञान में पीजी और स्नातक पर संस्कृत संगीत विषय आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा करें।

सभापति महोदय, प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में भी नवीन शिक्षा नीति लागू करने और भारत ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ आईकेएस माध्यम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय कन्या महाविद्यालय, गेवा, जोधपुर में समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिन्दी में पीजी और स्नातक स्तर पर संस्कृत व विज्ञान विषय आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। एमबीएम विश्वविद्यालय की तर्ज पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं केएन कॉलेज महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद का गठन करें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं एमबीएम विश्वविद्यालय को आर्थिक सक्षमता हेतु नवीन पाठ्यक्रम व उपलब्ध संसांधनों के समुचित उपयोग सहित नवाचारों की समयबद्ध कार्ययोजना बना कर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा करें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं एमबीएम विश्वविद्यालय में नियुक्त संविदाकर्मी एवं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति की जांच वांछित योग्यता के दस्तावेजों की जांच, कार्यप्रभार एवं उपस्थिति का भौतिक सत्यापन के साथ प्रदत्त दायित्वों के निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा करें।

सभापति महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं एमबीएम विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कार्मिकों की नियमित पेन्शन हेतु सरकार द्वारा बजट प्रावधान किये जाने पर चर्चा करें और पोलिटेक्निक कॉलेज, जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और माइनिंग विद्या के कोर्सेज

आरम्भ करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें और अन्त में, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में एयरोनोटिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग विषयों पर और साइबर क्राइम प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषयों के समावेश की आवश्यकता पर चर्चा करें।

सभापति महोदय, राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज, जोधपुर में समेकित खेल कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम की स्थापना हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। राजकीय पोलिटेक्निक कॉलेज, जोधपुर में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खनन, हैंडीक्राफ्ट, पैट्रोलियम सम्बन्धी नवीन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, यह गम्भीर विषय है यह गम्भीर इसलिये है कि आज हम सब रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं और जो पढ़ाई हमने की उस पढ़ाई का महत्व किताबों तक ही रह गया और जिस हिसाब से देश में और विदेश में और पूरे विश्व के अन्दर क्योंकि पूरा विश्व आज की तारीख में एक पूरा बाजार है और हम अलग-अलग देशों को अलग-अलग सीमाओं में नहीं बांध सकते क्योंकि तकनीकी ज्ञान इतनी तेजी से बढ़ रहा है, रिसर्च इतनी तेजी से बढ़ रही है, प्रोद्योगिकी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर हम इन चीजों का समावेश हमारे स्कूली, तकनीकी और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नहीं कर पाये तो वह समय नहीं है, हम पिछड़ जायेंगे।

सभापति महोदय, मैंने भी जोधपुर विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की और बाद में मैंने सीए की और अभी मेरे बच्चों की एजुकेशन की वजह से मेरे को विदेश में भी इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला। मैंने एक ही चीज वहां देखी। वहां और हमारी शिक्षा में कोई चैंज नहीं है। वहां पर पढ़ाने वाले अधिकांशतः प्रोफेसर जो हैं टेक्निकल एजुकेशन में वो हिन्दुस्तानी हैं पर सिर्फ एक बात का हमारे में और उनमें फर्क है कि वो जो प्रेक्टिकल ट्रेनिंग पर रिसर्च के ऊपर और आगे रिसर्च करके और उन विषयों पर जितना खर्च करते हैं, नयी प्रोद्योगिकी और नये ज्ञान के ऊपर वो हम में अभी तक नहीं है क्योंकि हमारा जो बुनियादी ढांचा है आज शिक्षकों को जो वेतन देना है, आज हमको क्या करना है हम उसी में अभी तक जूझ रहे हैं। हम उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं कि हम नवाचार के माध्यमों को अपना कर इन कॉलेजों का अपग्रेडेशन करें तो मैं पूरे सदन के सभी सदस्यों को भी यह कहूंगा कि इस बारे में अपने-अपने क्षेत्रों में और जितना भी आपके पास करने योग्य योजना हो वह हम सबके बीच में बांटें, जिससे कि राजस्थान का और भारत का उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जाये कि लोगों को बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और यहां से पढ़े हुए हर छात्र को, हर युवा को नौकरी आसानी से मिल सके। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय भारत। जय राजस्थान।

श्री सभापतिः धन्यवाद। कुमारी रीटा चौधरी जी।

Kas/rtm/20.07.2024/11.50/1f

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद सभापति महोदय, एक पुरानी कहावत है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 22 हायर एजुकेशन, जो कि एक संजीदा विषय है, गंभीर विषय है, इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी भी पीएच.डी. डिग्री धारक हैं, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात है।

सभापति महोदय, अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी। चूंकि यह गंभीर विषय है, संजीदा विषय है, मुझे लगा कि कुछ फलदायी बात वह करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे सामने आयेंगे, जिस पर यह सदन विचार करेगा और वह बात आगे बढ़ेगी। लेकिन पुरानी सरकार को कोसने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। सभापति महोदय, अगर हम भूतकाल में ही जीते रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा, हमारा भविष्य कैसे संवरेगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? बात यह नहीं है कि पिछली सरकार ने क्या किया, उससे पिछली सरकार ने क्या किया और अब वाली सरकार क्या करने जा रही है। मुद्दा यह है कि हम किस तरीके से अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि राजस्थान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो देश में और विश्व में अपनी एक अहमियत रखती हो, अपनी एक पहचान रखती हो, यह सोचने का विषय है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में कुछ बिन्दुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगी। 2018 में बीजेपी की सरकार के टाइम में 222 राजकीय कॉलेज खुले और 2018-23 में कांग्रेस की सरकार में 69 नियमित कॉलेज हम लोगों ने खोले और 303 राजसेस के माध्यम से महाविद्यालय खोले। उसके पीछे कारण यह था जिस तरीके से देश में आबादी बढ़ रही है, एजुकेशन का दायरा बढ़ रहा है तो हमें लगता है कि संसाधन भी हम लोगों को मुहैया कराने चाहिये, उपलब्ध कराने चाहिये। लेकिन हम लोगों की जद्दोजहद इस बात पर टिकी हुई है कि जिन कॉलेजों को पिछली सरकार ने खोला, उन कॉलेजों के बारे में अभी तक वर्तमान सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है और यह करना चाह रही है कि उन कॉलेजों को आगे चलाया जाये या नहीं चलाया जाये, उनको बंद कर दिया जाये, उसके रिव्यू के आदेश इस सरकार ने दे दिये हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगी कि राजस्थान में 12वीं पास कर चुके दस लाख से अधिक ऐसे युवा हैं जो स्नातक की डिग्री या अन्य डिग्रियों के लिये कॉलेज में जाते हैं। हमारी सरकारी कॉलेज नाम मात्र की हैं। हर कोई युवा सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाता है और उसको प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है और स्थिति यह हो जाती है कि अपनी शिक्षा पूरी करने के लिये उनकी जेब से पूरा पैसा निकल जाता है। सभापति महोदय, हम लोग हमारे युवाओं का भविष्य निजी कॉलजों पर छोड़ देते हैं और वहां उनसे मोटी फीस ली जाती है। यह त्रासदी है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हम हमारे युवाओं को अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे संसाधान नहीं दे पा

रहे हैं, इस बात पर हमें इस सदन में चर्चा करनी चाहिये। सभापति महोदय, यह कोई बहस का विषय नहीं है कि किसने ज्यादा कॉलेज खोले, किसने कम खोले। हम जब कोई प्लानिंग करते हैं, चाहे मकान बनाने की प्लानिंग हो, घर को सजाने की प्लानिंग हो, हम लोग भविष्य को लेकर प्लानिंग करते हैं तो पहले संसाधन उपलब्ध नहीं होते, पहले प्लानिंग की जाती है। आप लोग भी अपना घोषणा पत्र लेकर आये और उसमें आपने घोषणाएं की हैं कि हम पांच साल में यह-यह करेंगे, एक विजन लेकर चलते हैं। जब कोई चीज धरातल पर आती है, तभी उसका डवलपमेंट होता है, उसमें संसाधन उपलब्ध होते हैं, इस तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, पिछली सरकार में खोली गई 303 कॉलेज और उससे पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी, उसमें 222 कॉलेज खोली गईं। इन सभी कॉलेजों को मिलकार हमारा यह ध्यान होना चाहिये कि उनमें हम बेहतरीन संसाधन उपलब्ध करा सकें। शिक्षा में गुणवत्ता हम ला सकें और शिक्षा के बजट का दायरा हम लोग और बढ़ा सकें।

सभापति महोदय, वर्तमान बीजेपी की सरकार ने 8 जून, 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी कर राजसेस में जो 303 महाविद्यालय खोले गये थे, उनकी समीक्षा के लिये एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी थी और 8 जुलाई को उस कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिये थी। सभापति महोदय, जिन बच्चों ने उन कॉलेजों में एडमिशन ले लिया, जो उससे पासआउट होंगे, उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय है और चूंकि अभी एडमिशन चालू हैं, तो उनमें एक संशय का वातावरण बना हुआ है कि इन कॉलेजों में हमको एडमिशन लेना चाहिये या नहीं लेना चाहिये। मैं आपके मार्फत उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहती हूं कि जब आप रिप्लाई दें तो बताएं कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है और इन कॉलेजों की क्या स्थिति रहेगी? स्थिति यह है कि आज यहां आयुक्तालय के अधिकारी बैठे हैं, उनको मजबूरन एडमिशन के टाइम को बार-बार बढ़ाना पड़ रहा है और वह इसलिए बढ़ाना पड रहा है कि बच्चे संशय के कारण एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने राजसेस महाविद्यालयों में स्थाई स्टाफ की भर्ती के लिये और शिक्षण कार्यालय सही चले, उसके लिये 'विद्या संबल योजना' पर बल दिया था और उसके माध्यम से गैस्ट फैकल्टी कॉलेजों में लगी थी। मुझे खुशी है कि इस सरकार ने उस योजना को जारी रखा है और सभी कॉलेजों में 'विद्या संबल योजना' के तहत फैकल्टी लगी है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि हमने शिक्षण व्यवस्था कर दी है, वहां टीचर्स लगा दिये हैं, लेकिन अशैक्षणिक स्टाफ की तरह इस योजना के माध्यम से आप ध्यान दें, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ शिक्षक पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें और भी स्टाफ चाहिये, जैसे फोर्थ क्लास, सफाई कर्मचारी, क्लर्क, इस तरीके के स्टाफ की भी वहां जरूरत पड़ती है। इस योजना के माध्यम से अशैक्षणिक स्टाफ की स्वीकृति भी आप लेकर आएं। इससे एक तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरा, कॉलेज की व्यवस्था और अच्छी और सुदृढ़ होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगी कि 2018 में पिछली सरकार ने पीपीपी मोड पर बहुत सारे कॉलेज खोले थे और भामाशाहों से एम.ओ.यू. किया था कि आप लोग कॉलेज की बिल्डिंग बनाएं। इसके लिये आपने उनको फ्री जमीन अलॉट कर दी, ताकि बच्चे उच्च शिक्षा में आगे दाखिला ले सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय मलसीसर को पिछले 6 साल से उस कॉलेज के सिर्फ 7 कमरे अस्थाई रूप से पढ़ाने के लिये दिये गये हैं। न वह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हुई है और उसकी गुणवत्ता पर भी मुझे संशय है। आप इसको दिखवाएं और उस एम.ओ.यू. में आपने क्या रखा था, क्योंकि 6 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है। कॉलेज तैयार नहीं हुई, ऊपर की बिल्डिंग अधूरी है, खिड़कियां लगी नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है और 6 साल से वह कॉलेज चल रही है। उसमें फर्स्ट ईयर, सैकण्ड ईयर, थर्ड ईयर होती है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 7 कमरे खोल रखे हैं और वह भी अस्थाई तौर पर दे रखे हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा उस क्षेत्र का है, क्योंकि वहां से जब झुंझुनूं आते हैं तो राजकीय महाविद्यालय वहां से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस कॉलेज की बिल्डिंग की जांच हो और उसको तुरंत प्रभाव से चालू करवाया जाये ताकि एक ही कक्षा में जो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, फिर उनको शिफ्टों में लाया जाता है, इसलिए वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत बात करना चाहूंगी कि हम निजी विश्वविद्यालय के यहां विधेयक लेकर आते हैं। अभी भंसाली जी ने एक विश्वविद्यालय की बात करी कि कांग्रेस की सरकार में वह बिल आया था और उसको वापस लेना पड़ा।

msk/rtm/20.07.2024/1200/1g

हम लोगों ने बिल वापस ले लिया, लेकिन 2003 और 2008 के बीच में मेरे विधान सभा क्षेत्र में अन्दर जेजेटी यूनिवर्सिटी का आप विधेयक लेकर आये। उस यूनिवर्सिटी की स्थिति यह है कि वहां पर फर्जी डिग्रियां बहुत ज्यादा तादाद में बांटी जा रही हैं, जैसे कि न्यूज पेपर वाला सुबह-सुबह अख़बार डालता है, वैसे फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही हैं। पिछले टाइम कांग्रेस की सरकार थी। मैंने शिकायतें कीं और उस समय उस बात को गंभीरता से लेते हुए पांच ऐसे निजी विश्वविद्यालय थे, जिनके ऊपर रोक लगाने की बात चली और उनको ब्लैकलिस्ट किया गया।

सभापति महोदय, 20.10.2020 को एक सर्कुलर, पब्लिक नोटिस जारी हुआ था, उसके अन्दर वे पांच विश्वविद्यालय थे। ओपीजीएस विश्वविद्यालय, चूरू, जिसको आप लोगों ने थोड़े दिन पहले बन्द किया है। विद्या संबल योजना के अन्दर जिन शिक्षकों के पास इस ओपीजीएस की डिग्री है, उनको भी आप लोगों ने निराधार बताया है और उसको उस योजना के अन्दर शामिल नहीं करते हुए, उसमें नहीं दिया। उन विद्यार्थियों की गलती नहीं है, उन युवाओं की नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जो ओपीजीएस है, वह ब्लैक लिस्टेड हो

चुकी है। दूसरे नम्बर पर जेजेटी यूनिवर्सिटी चुड़ैला, झुन्झुनू; तीसरा सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ा, झुन्झुनू; चौथा श्रीधर विश्वविद्यालय बिगोदना, झुन्झुनू; पांचवां सनराइज विश्वविद्यालय, बगर राजपूत, अलवर। ये पांच ऐसे विश्वविद्यालय थे, जो यूजीसी के नॉर्म्स में नहीं थे और इनको ब्लैक लिस्ट किया।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे युवाओं को पता नहीं है। अभी इन कॉलेज के अन्दर एडमिशन ले रहे हैं। जेजेटी ने तो कमाल कर दिया। उसी यूनिवर्सिटी के अन्दर उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, ब्लड बैंक चालू कर दिया। वह ब्लड नकली पकड़ा गया। वह यूपी के अन्दर बेचते हुए पकड़ा गया। उसकी हालत बहुत खराब है और उन्होंने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जगह-जगह छोटे खेल मैदान बना दिये, कहीं पर सब्जी उगा दी और पूरे गांव पर वे कब्जा करने पर लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जिसके अन्दर एक सिंगल विंडो बनायी जाये, जिसके माध्यम से हम प्रचार-प्रचार कर सकें कि युवाओं को कौनसे विश्वविद्यालय में, कौनसे कॉलेज के अन्दर एडमिशन लेना चाहिए, ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके और उनको आगे नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर मैं समझती हूं कि हमारे मंत्री महोदय भी इस मामले में बड़े गंभीर हैं। बजट में मैंने देखा कि उन्होंने कुछ नवाचार किये हैं, हमारे मुख्य मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, और वित्त मंत्री जी ने। लगता है कि कुछ नवाचार आने वाले दिनों में हमें उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में देखने को मिलेंगे। सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ मुद्दे लेकर आयी हूं, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी मिली थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर राजकीय महाविद्यालय, बिसाऊ; राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलसीसर; इसके अन्दर विज्ञान संकाय, क्योंकि पिछले दो-तीन साल से यह कॉलेज संचालित है। अलसीसर कन्या महाविद्यालय में लड़कियों की अच्छी संख्या है। इसमें विज्ञान संज्ञाय आप खोलें। मेरे स्वयं के गांव के अन्दर कन्या महाविद्यालय, हेतमसर खोला था। इस कॉलेज को पांच साल होने जा रहे हैं। उसके अन्दर पीजी नहीं है तो आप दो विषय में नहीं तो कम से कम एक विषय के अन्दर पीजी वहां पर खोलें। मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी इस सदन के बहुत सम्मानित सदस्य रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा में उनकी रुचि थी और उनकी इच्छा थी कि झुन्झुनू के अन्दर भी, मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी वनस्थली की तर्ज पर लड़कियों की कॉलेज हो। यहां पर बच्चियों को उच्च शिक्षा मिले, ताकि वे आगे बढ़ सकें और दो परिवारों को मजबूत कर सकें। मंत्री महोदय, मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि पिछले पांच वर्षों में जो राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, उनके अन्दर भी आप बजट दें, ताकि वहां पर जो शिक्षा व्यवस्था है, संसाधन हैं, वे अच्छे से उपलब्ध हो सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे

समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री जसवन्त सिंह यादव।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी उधर से वक्ता बोल रही थीं कि इतने कॉलेज खुल गये, इतना यह हुआ। इसको सदन माने या न माने, पिछली सरकार ने, यह मैं बीजेपी से एमएलए हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। पर आप लोगों ने जो सरकार चलायी, वह सरकार बचाने के लिए चलायी है। आप लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया कि कहां जरूरत है, कहां जरूरत नहीं है। किस क्षेत्र के अन्दर क्या काम होना चाहिए? आपकी बहादुरी की तो कोई दाद ही नहीं। पिछली सरकार में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री गहलोत जी ने जिले तक खोल दिये, चाहे वे जिले वाइबल थे या नहीं थे। उनकी जरूरत थी या नहीं थी, पर अपने निर्दलीय एवं अपने एमएलए खुश रहें, कहीं दूसरे खेमे में न भाग जायें। इस आधार पर आप लोगों ने जो कॉलेजों की बन्दरबांट की। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बीच में मत बोलें।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे यहां खुले हैं, वही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां खुले हैं। लेकिन खुलने के बाद न उसमें प्रिंसीपल है, न लेक्चरर है, न प्रोफेसर है। उन कॉलेजों का क्या करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बैठे-बैठे नहीं बोलें। टोका-टोकी का सिस्टम दोनों से तरफ से नहीं हो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अभी तो टाइम आया है। अभी तो हमारा समय शुरू हुआ है। आप सच्चाई तो सुनें। आपके भी बच्चे हैं, आपके क्षेत्र में भी बच्चे हैं। एमएलए का उद्देश्य यह होता है कि मेरे क्षेत्र में काम की घोषणा हो जाये, इससे मुझे वोट मिल जायेंगे। जिन्होंने जिले खुलवाइये, वे तो ज्यादातर धराशायी हो गये, एकाध ही जीत पाया है। एक जीता है, खैरिया जीते हैं। मेरे यहां खुले हैं, उनमें देखें कि स्ट्रेंथ क्या है? एडमिशन बच्चे कहां से लें, जब प्रोफेसर ही नहीं है, लेक्चरर ही नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं इस मामले में तो यह कहूंगा कि कम से कम मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे सकता हूं कि आज आप पढ़िये। भजन लाल जी ने, भजन लाल जी की सरकार ने ध्यान तो दिया कि स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, आईटी सेक्शन अच्छा होना चाहिए, इसके अन्दर अपग्रेडेशन होना चाहिए। ये सब चीजें देखकर लगता है कि आदमी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है, खाली संख्या बल से नहीं होता है।

हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। मैं ज्यादा तो क्या बोलूंगा, पर निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार के समय में जो खेल हुआ, उसको आप बन्द कर दें, जैसा कि अभी माननीय बुडानिया जी कह रहे थे। तुरन्त बन्द करें, जितने लोग थे, जिनकी भर्ती हुई, जो प्रोफेसर लगे, जो लेक्चरर लगे, उनको उस एमएलए को ओबलाइज करने के लिए डेपूटेशन पर भेज दिया। एक ही लाइन में, इसमें तो कोई बजट खर्च नहीं हो रहा। अब तो आगे ट्रांसफर का समय भी आने वाला है। आप एक लाइन में डेपूटेशन को खत्म को कर

सकते हैं, जिससे कुछ तो सुधार हो। मेरे यहां से आपने सारे डेपूटेशन पर भेज रखे हैं। सीट भरी हुई नजर आती है, वहां पर कोई नहीं है। आप संख्या की गिनती कर रहे हैं। मेरे यहां पांच साल पहले, जो हमारी सरकार थी, उसमें जो सब्जेक्ट था, वह एक ही सब्जेक्ट पीजी के अन्दर है, जबकि उसके अन्दर तीन-चार हजार बच्चों की स्ट्रेंथ है। दो-चार ही बढ़ा देते। धर्म चन्द गांधी महाविद्यालय नाम है। उसके अन्दर केवल एक पीजी क्लास है। एक पीजी सब्जेक्ट है। जहां इतनी स्ट्रेंथ हों तो उनके अन्दर कम से कम दो-चार सब्जेक्ट ही खोल दो। सच्चाई तो यह है कि संख्या गिन लो, पर पिछली सरकार ने एजुकेशन का भट्टा बैठा दिया। अब भजन लाल सरकार से उम्मीद है कि इसके अन्दर सुधार करे। माननीय मंत्री जी, आपसे उम्मीद करता हूं, आप उप मुख्य मंत्री भी हैं, आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है। जवान भी हैं, मेहनत करिये और पिछले ढर्रे को ठीक करिये। काम करने का मौका है, मन भी है।

mdp/rtm/20.07.2024/12:10/1h

माननीय मुख्य मंत्री जी को बार-बार धन्यवाद देता हूं, भजन लाल जी की सोच को कि जो टेक्निकल एजुकेशन के अन्दर काम किया है, जो टेक्निकल एजुकेशन पर अपनी इच्छा जताई है, सच्चाई यह है कि आज के युग में अगर बेरोजगारी खतम करनी है तो टेक्निकल एजुकेशन पर ही ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि जो थ्री डी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फायबर टू होम, आज चाइना तो इसी बेस पर कमा रहा है। किसी होटल में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, हाई क्लास बिल्डिंग में चले जाइए, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, सब जगह अगर सबसे ज्यादा कहीं डिमांड हो रही है तो इस थ्री डी प्रिंटिंग की। यह सबजेक्ट तो आपको हर आईटीआई के अन्दर लागू कर देना चाहिए। इससे बच्चों को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

आपसे निवेदन है, पिछली सरकार का एक किस्सा बताता हूं कि कितनी सीरियस थी बच्चों की नौकरी के लिए। मेरे कार्यकाल में पिछली बार बहुत बढ़िया हमने आईटीआई खोली। कम्प्लीट हो गयी। पांच साल उसको चलने नहीं दिया, जबकि हमने उसको जापानी जोन से जुड़वाया था। हमने उस कार्यकाल के अन्दर बनाया था जापान-इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। उसका अता-पता ही नहीं है, कहां चला गया। पिछली सरकार का पैसा भी खर्च हो गया। इसके अन्दर 30 हजार बच्चों को जापानी कंपनियों के अन्दर ट्रेनिंग करने का मौका मिलता। आज इस पांच साल के आपके कार्यकाल के अन्दर, पिछली सरकार के कार्यकाल के अन्दर ऐसा भट्ठा बैठा दिया बच्चों के प्रति, केवल एमएलएज पर ध्यान दिया। जापानी कंपनियों से जाकर मैंने बातचीत की कि हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। वे कहते हैं कि साहब, आप ऐसा तो डवलपमेंट कीजिए कि वे हमारे लायक तो बन जाए। आपसे मेरा निवेदन है कि आजकल जो सबजेक्ट वॉयबल हैं, जो पुराने जमाने के चल रहे हैं, वही मशीनें,

वही सब चीजें, इनको बदलिए और इनको बदलकर जहां जिस एरिये में, मेरे एरिये के अन्दर फैक्ट्रियां बहुत हैं, उसी हिसाब से जिस एरिये में जिस तरीके की फैक्ट्रियां हैं, भीलवाड़ा में कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं, उधर अलग सबजेक्ट की जरूरत है। मेरे यहां पर जापानी और कोरिया कंपनियां हैं, उनको अलग सबजेक्ट की जरूरत है। आपसे निवेदन है कि एक बार आप सर्वे कराइए कि किस एरिये में किस सबजेक्ट की जरूरत है, किस सबजेक्ट से लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सकता है।

अब बात ट्रांसपोर्ट की। मैं सच कह रहा हूं आपका ट्रांसपोर्ट तो माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में, एमएलएज के यहां गिरवी रखा हुआ था। गहलोत जी के समय में। धन्यवाद देता हूं माननीय भजन लाल जी को, इस सरकार को कि इन्होंने नयी बसें खरीदने का रखा है कि दो साल के अन्दर 500 बसें, 800 बसें मॉडल के ऊपर लेंगे, इलेक्ट्रिकल बसें, ग्रामीण बस सेवा, पांच साल में एक भी गांव ऐसा नहीं है, एक भी पंचायत ऐसी नहीं है, हमारे यहां तो और कहीं चलती हो तो मुझे पता नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो वसुन्धरा जी की सरकार के अन्दर गांव के अन्दर बसें जाती थी, वह पूरी लोक परिवहन बसें, ग्रामीण बसें, पांच साल में कतई बंद कर दीं। शहर के आदमी को तो दुनियाभर के साधन मिल सकते हैं। गांव का आदमी कैसे जाए? उसके पास तो कोई और साधन होता नहीं है। गरीब आदमी बस का ही सहारा ले सकता है। लोक परिवहन बस दोबारा चालू करने की योजना बनायी, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि हमारे ढर्रे को हम बदलना नहीं चाहते। ढर्रे को हम बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हर गांव के अन्दर जीपें हैं। जानबूझकर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। जीपें जितनी भी हैं, वहां सवारियां ढ़ोती हैं, गांव में, शादी के अन्दर और ओवरलोड चलती हैं। अगर हम इनको ही, नौजवानों को वहां पर यह कह दें कि हम साल का ये टैक्स लेंगे, आप अपनी जीप को यूज कर सकते हैं। कितने लोगों को तो रोजगार मिल जाए, कितने आवागमन के साधन हो जाए, परंतु करने की क्षमता चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, उनके कार्यकाल से पहले रेल का भट्ठा बैठा हुआ था, रेल बहुत बड़े घाटे में जा रही थी। उन्होंने इसको उबारने के लिए कि सवारी के लिए तो रेल अच्छी बने और रेल को घाटे से उबारा जाए तो उन्होंने गुड्स ट्रेन पर ध्यान दिया।

इसी तरह से मैं जानता हूं इसके अन्दर परेशानी है, अगर ट्रांसपोर्ट विभाग थोड़ा-सा सुधर जाए या मंत्री जी, थोड़ा-सा सुधारने की कोशिश कीजिए। जितना रेवेन्यू आपका लोस हो रहा है, अगर वह विभाग को मिल जाए तो सारा घाटा पूरा हो जाए। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में, यह मैं होशो-हवास में बात कर रहा हूं, रोजाना रात को हजार से डेढ़ हजार ट्रक अवैध निकलते हैं, जो ओवरलोडेड होते हैं, बजरी के होते हैं, पत्थरों के होते हैं और आपके विभाग की मिलीभगत से निकलते हैं। पिछली सरकार में तो एमएलएज ने तो ठेका ले रखा था कि मेरे एक हजार ट्रक निकलेंगे। मजबूर थी सरकार, हम तो मजबूर नहीं है। आप जाकर आज ही जांच करा लीजिए। शाम को 6 बजे ट्रक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आने-जाने

के साधन बंद हो जाते हैं। आज प्रति ट्रक सरकार का कितना रेवेन्यू लोस हो रहा है? कितना सड़कों का लोस हो रहा है? ओवरलोड ट्रक निकलता है, उनसे दस-दस हजार आपका विभाग लेता है। आपके विभाग के अधिकारी पूरी रात इसी काम में लगे रहते हैं। दिन भर तो उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। इसको बंद कीजिए। अगर विभाग के पास ये पैसा आएगा तो विभाग का घाटा दूर होगा। हमको काम करने का मौका मिलेगा। आपके अधिकारी चाहे आपको कुछ भी बताए, सीधा उनकी मिलीभगत से काम हो रहा है। पूरी रात वसूली चलती है। इसी तरह हमारे बार्डर पर जो खेल हो रहा है, वैसे ही राजस्थान के और बार्डर पर भी यह खेल हो रहा होगा। आपसे निवेदन है कि आप काबिल हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि यात्रियों को सुविधा मिले। मेरे यहां पर बड़े-बड़े गांव हैं, जो पंचायतें ग्रामीण सेवा से जुड़ी हुई थी, बसें आती थी, अब उनके पास सारी बंद हो गयी। आप उन गांवों को जुड़वाएं। आपसे उम्मीद है, आप काबिल मंत्री हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी का भी यह उद्देश्य है कि किसी भी तरह आम आदमी को सुविधा मिले, (समय समाप्ति सूचक घंटी) नौजवान को रोजगार मिले। हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि आपकी सोच पूरी हो। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः दो मिनट और बोल सकते हैं आप। मैंने तो दो मिनट के लिए बजाया है।

सूचना

अहुआ गांव (मारवाड़ जंक्शन) में बिजली गिरने से मृत्यु

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पाइंट ऑफ इंफोरमेशेन। माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ विधान सभा में अहुआ गांव में खेत पर काम करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से सुमन पुत्री हरिराम की खेत पर ही मौत हो गयी। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार उसके परिवार की सहायता करे।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री श्रवण कुमार।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा एवं मांग संख्या 62 - परिवहन पर विचार

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 22, 24 और 62 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। सबसे पहले शिक्षा की बात है।

श्री सभापतिः शिक्षा पर बोलिए आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा था कि जीवन का प्रकाश शिक्षा से आता है, नहीं तो आदमी अंधेरे में रहता है। ये प्रकाश कौन लायेगा? ये आपकी सरकार लेकर आयेगी। पहले राजस्थान में 250 कॉलेज थी और 304 कुछ कॉलेज कांग्रेस सरकार ने खोली। कॉलेज तो खूब हो गयी। जहां मांगी, वहीं मिल गयी।

Ans/rtm 12.20 1j 20.07.2024

लेकिन भूमि की कमी की वजह से, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, सूरजगढ़ में कॉलेज नहीं बन पा रही है। एक छोटी सी स्कूल में 450 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप भूमि की व्यवस्था भी करे। पूर्ववर्ती सरकार ने सारे कॉलेजों के पैसे हाथों-हाथ दे दिए, जिनके पास भूमि थी वहां बन भी गई, लेकिन जहां नगरपालिकाओं के पास भूमि नहीं थी वहां नहीं बन पा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आप दस बीघा जमीन की व्यवस्था करके सूरजगढ़ में बिल्डिंग बनावाए। मैं समझता हूं कि महिला कॉलेज में भी गुजरात के बाद दूसरा नम्बर राजस्थान में ही है।

अशोक जी ने शिक्षा के मार्ग का इतना अच्छा खोज लिया कि अँग्रेज़ी मीडियम स्कूल भी खोली, कॉलेज भी खोली, लेकिन पढ़ाने वाले प्रिंसिपल कम हैं, मास्टर भी कम हैं। दुखद बात तो यह है कि सारे वीसी यूपी के लेकर आ गए। वे सारे घोटाले कर रहे हैं। गुजरात का तो कोई डायरेक्टर आ जाएगा और यूपी का वीसी आ जाएगा, तो राजस्थान में वीसी है ही नहीं क्या। आज तक के इतिहास में जो भी वीसी बना वह राजस्थान का ही बना है। अब यूपी के बनने लग गए। यूपी के ज्यादा साहूकार हैं क्या? यह समझे कि राजस्थान में सब लोग सही-सही हैं, गलत कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यूपी के वीसी लगा रखे हैं। बहुत बड़ा घोटाला है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): श्रवण जी, इनका इलाज क्या है?

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): One solution is there, on the advice of the Government, वाइस चासंलर नियुक्त हो जाएं।

श्री सभापति: श्रवण जी, आपसे इलाज पूछ रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लाए भी कहां से, गवर्नर यूपी का है। आप कौन हो लाने वाले, वह लेकर आएगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके समय में हुए थे।

श्री सभापति: आपके समय के हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे टाइम गवर्नर था ना, गवर्नर तो हम बदल नहीं सकते तो गवर्नर ही करेगा, तो हमें क्यों ओलमा देते हो। सीएम साहब की मेहरबानी होनी चाहिए यह तो। गवर्नर क्या करेगा, सीएम साहब करेंगे वह होगा। गवर्नर का तो नाम ही क्यों ले रहे हो। मैं यह कह रहा था कि आपको वीसी राजस्थान के रखने चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ भी करे तो पकड़ में आ सके। इनको जिस दिन हटाओगे उस दिन यूपी चले जाएंगे, आपके हाथ कहां आएंगे। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपकी सरकार होटल में बंद थी, उस समय वह कुलपति नियुक्त हुए थे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारी सरकार के समय के हैं तो हटा दो। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने कोई गड़बड़ की, उसका मेंडेट आपको दिया, आप ठीक करो। इसलिए

दिया है क्या कि आप चर्चाएं करते रहेंगे। ट्रेन में बैठने वाला कहेगा आप पहले, आप पहले, तो ट्रेन निकल जाएगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी सलाह मान लेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरी सलाह मान लेते तो अच्छे दिन आ जाते लेकिन मानते ही तो नहीं हो, यही तो रोना है। आप तो जब भी खड़े होते हो, तो यह कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया। हमने सारी गड़बड़ की, आप अच्छी कर दो ना। यह बात ही क्यों करते हो। जब ही तो सरकार बदलती रहती है। ज्योति बसु ने बंगाल में 33 साल तक राज किया था। वह यह नहीं कहता था कि कौन क्या है। वह कहता था कि मैं जो करूंगा वह अच्छा करूंगा, सोचकर करूंगा। उसने 33 साल बाद स्वयं ने इस्तीफा दिया कि अब मैं मुख्य मंत्री नहीं रहना चाहता। मैं यह भी कहता हूं कि राज आने के बाद और घर में बीवी आने के बाद जानी नहीं चाहिए। जाती क्यों है, कारण है। जिसकी बीवी भाग जाए..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपका अनुभव सही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सही है ना। जिसकी बीवी भाग जाए, यह समझो कि वह खुद कमजोर है। जिसका राज आए और चला जाए, वह खुद कमजोर है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपका यह अनुभव परफेक्ट है। आपका अनुभव सही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं उस विधान सभा में भी था, इसमें भी हूं। एक बार आप, एक बार हम, यह नहीं होना चाहिए। राज करके दिखाओ, 15-20 साल लोगों को लगे कि राज कौन कर रहा है, राज कैसे चल रहा है। लेफ्ट हैंड की गाड़िया पहले थी, अब राइट हैंड की आ गई, बात तो वही हुई ना। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आत्मा की आवाज आ गई।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरी आवाज तो यह है कि आप काम करिए। राजस्थान की जनता को लगना चाहिए कि राज बदला है। अभी तो 6 महीने में आपने कुछ भी नहीं किया है। एक लोटा पानी का नहीं पिलाया। एक नई गाड़ी नहीं लेकर आए। कोई नई कॉलेज नहीं खोली। नगरपालिका एक दो खोल दी हो मालूम नहीं है। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया है। जिसकी स्टार्टिंग ही गड़बड़ होती है, उसका एण्ड भी बुरा होता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब आप यह कहोगे कि आप क्यों कह रहे हो। आपका एक्सपीरियंस भी मेरे से कम है, ज्यादा नहीं है। मेरा 44 साल का एक्सपीरियंस है। अफ़सरों की बात करते हैं। अफसर आपकी नहीं मानते हैं, वह मनमर्जी करते हैं। आपकी बात सुन लेंगे और सर-सर कह देंगे, करेंगे नहीं। अफसरों को ट्रेनिंग में यही पढ़ाया जाता है सर को तोड़ना नहीं और फली फोड़ना नहीं। चाहे कांग्रेस वाले हो, इनको भी सर-सर कहकर राज़ी कर देते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आर्डर में जान होनी चाहिए। आर्डर आपने दिया है या तो नो का हो या यस का हो, पर आर्डर खाली नहीं जाना चाहिए। आर्डर देते हैं, मंत्री लोग क्या

कहते हैं, साहब देख लेना। क्या देख लेना It will get done. काम चाहता हूं यह रिप्लाई दीजिए। यह कहने की जब तक इच्छा नहीं होगी, तब तक काम नहीं होंगे। इच्छा तो सबकी है पर इच्छाशक्ति नहीं है। जब तक मानव की इच्छाशक्ति नहीं होती है तब तक वह प्रोगेसिव नहीं हो सकता। आप अपना ढर्रा बदलिए। मैं डेली देखता हूं, सर देख लेना। सर वह है क्या, सर तो आप हो अगर मानो तो। लोकतंत्र में सर कौन है, जो चुनकर आता है वह सर है। हमारा प्रशसनिक अधिकारी है वह भी सर है, लेकिन वह ऑफिस में सर है,आपके सामने सर नहीं है, आप लोग सर कहकर बात करते हो। क्या चलाओंगे राज, नहीं चलेगा। मैं अब भी कह रहा हूं कि अगर राज करना है तो बगैर टोरे के राज नहीं होगा। जिसके पास टोरा होगा उसका राज भी पक्का चलेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): श्रवण जी, अबकी आपकी सलाह मानेगे, टरके से राज करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मानोगे तो दुबारा भी आपका नम्बर पड़ जाएगा नहीं तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अफसर का तो, रात 12 बजे राज बदला और ढर्रा बदला, सबको जानते हैं। हमारे कई एमएलए बोलते थे साहब मेरा एसडीएम लगा दो, मेरा तहसीलदार लगा दो, क्यों बावला हो रहा है, कुछ नहीं है। ये अपना काम निकालते हैं, डंडो पाड्यो खेत के बाहर। ये डंडा पाड़ते हैं और खेत के बाहर चले जाते हैं, इनको मतलब नहीं है कि किसने बोया था, कौन काटेगा।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अफसरों पर चर्चा चल रही है, अपन तो शिक्षा पर आओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शिक्षा पर आ रहे है। तकनीकी शिक्षा देखिए। हमारी सरकार ने ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप इनको तो रोको ही मत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): संसदीय मंत्री जी ने जब कह दिया तो, सभापति महोदय, आप पीड़ा क्यों पा रहे हो।...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्रवण जी, आप कुछ भी बोल सकते हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सदन में अध्यक्ष के बाद संसदीय मंत्री होता है। हां भर ही ली हमारी, कोई दिक्कत थोड़े ही है।

हमारे पिलानी में तकनीकी कॉलेज खो दी। पिलानी तो इन्द्रदेवी के नाम की नगरी है। वहां भी खोल दी। अब खोल तो दी, लेकिन कौन आए, बंद पड़ी है, कोई बिल्डिंग ही नहीं बनी। ऐसी कई चीजें कांग्रेस सरकार में भी हुई जिनका उपयोग ही नहीं था, बिना उपयोग के। जब आदमी भूखा ही नहीं है और अधिक खाना खा लेगा तो एसीडिटी ही होगी, और क्या होगा?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सही बात है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गलत किया यह भी नहीं कहना चाहता। जहां भी जरूरत है वहां खोलने से फायदा मिलेगा, उससे सरकार की नीति और निर्देश भी अच्छे रहेंगे।

मैं तीन-चार दिन पहले वित्त मंत्री जी को कह रहा था कि मेरे सूरजगढ़ में 1936 में नगरपालिका बनी थी। संसदीय मंत्री जी, आज तक उसकी सीवरेज लाइन नहीं पड़ी। मैंने कांग्रेस सरकार में भी कह दिया, धारीवाल साहब को भी। कागज ले लिया, पता नहीं कौनसे खड्डे में डाल दिया, देखा ही नहीं।

श्री सभापतिः आपने धारीवाल साहब से बोला था या नहीं बोला था?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): धारीवाल साहब अब तो ठंडे हो रहे हैं, उस समय तो देखा ही नहीं करते थे। अब तो ठंडे हुए। क्योंकि जब आदमी ठंडा होता है तो सबको मालूम हो जाता है कि ठंडा हो गया। मैं तो मंत्री बना नहीं। मैं तो प्रधान, सरपंच सब रह लिया, एमएलए भी कई बार रह लिया। मंत्री जब बनता है, उसके सैकेण्ड दिन रात को कौनसा देवी-देवता आता है, इनको पागल बना देता है।

VPS-RTM-20.07.2024-12.30-1k

ये देखते ही नहीं है और पांच साल में लाल-चट हो जाते हैं और लाल होकर बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं कि जब जनता ने तुमको मौका दे ही दिया और तुमको मौका मिल ही गया और जन्म तुम ने ले ही लिया इस काम के लिए और जलेबी की तरह घूम ही गये तो रस में डूब कर मजा लो तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता का काम करके लोगों में बताओ कि मैं क्या हूं। जो जनता का काम करेगा, उसका आज नहीं तो कल प्रतिफल मिलेगा। कोई कहता है कि मैंने काम किया, मेरे को प्रतिफल नहीं मिला। मैं यह कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कर्मों को कोई खा जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सत्यता को कोई धुला देगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि सोने के ऊपर काई डाल देगा। जो सोना होगा, वह सोना ही होगा और जो पीतल होगा वह पीतल ही होगा। जो आदमी काम करेगा वह इस सदन में धड़ल्ले से बोलेगा और गांव में जाकर भी गली में बोलेगा।

अभी हमारे मंत्रीजी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट में, मंत्रीजी, इतना बड़ा घोटाला है कि अगर आप आँख खोल कर देखोगे तो दोनों आंखों पर दो चश्मे लगाने पड़ेंगे। आप यह देखिये कि आप अब रोडवेज की बातें करते हो तो रोडवेज को धूमिल करने वाली तो बी.जे.पी. की सरकार ही है। आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट गाड़ियों को परमिट दे दिये। कहां पर जरूरत थी? जब हमारे पास रोडवेज अवेलेबल है, हम रोडवेज के इतने बड़े लवाजमे को चला रहे हैं, जगह-जगह हमने डिपो खोल रखे हैं और उसके बाद भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कर दिया न? आगे-आगे बस जा रही है प्राइवेट और पीछे-पीछे आ रही है रोडवेज तो रोडवेज में कौन बैठेगा? प्राइवेट वाला ए.सी. बस लेकर चल रहा है। क्यों संसदीय कार्य मंत्रीजी, गलत तो नहीं कह रहा हूं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सही कह रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अब आप यह बताइये कि आपने परमिट दे दिये। किसने

दिये? सरकार ने दिये हैं। यह हमने तो दिये नहीं है और वह प्राइवेट बसें, आज हालत यह कर दी कि रोडवेज के कर्मचारी बगैर तनख्वाह के छह-छह महीने तक भी बैठे रहते हैं और हड़ताल करते हैं और सरकार के लिए सिरदर्द बन जाते हैं और उसके बाद कोई मुख्य मंत्रीजी की मेहरबानी होती है तो वे दूसरे फंड से पैसा उठाकर रोडवेज को फंड देते हैं और वे कर्मचारी तनख्वाह उठाते हैं। ऐसा नहीं है, रोडवेज बहुत बड़ा बेनिफिट का एक कारखाना है परंतु यूज करने वाला चाहिए। उसको ढंग से चलाने वाला कोई नहीं है। उसको अगर सही ढंग से चलाया जाये तो रोडवेज आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, इतने यात्री उठते हैं कि वह कभी भी फेल नहीं हो सकती। अब बस टूट जाती है, टायर फट जाता है, उसके बाद में भी ड्राइवर उसको चलाता रहता है। तेल का एवरेज निकालने का नाम नहीं है। दस चीजें गाड़ी के अन्दर होती है जो मूलभूत आवश्यकता है उनको सही नहीं करते हैं इसलिए रोडवेज फेल होती है। ब्रेक फेल हो गये, आदमी मर गया, उसका क्लेम आ गया। ब्रेक फेल होते ही गाड़ी क्यों नहीं खड़ी की? खड़ी हो जानी चाहिए साइड में, यात्रियों को दूसरी गाड़ी में बैठाये, कैसे भी करे लेकिन पता नहीं ड्राइवर की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। कई आदमी बेघर हो जाते हैं। किसी का एक बच्चा भी मर गया तो कितने लोगों को नुकसान हुआ है। उसके बाद ड्राइवर दारू, शराब पीकर गाड़ी चलाता है। जो गाड़ी शराब पीकर ड्राइवर चलाता है, उस ड्राइवर को इमीडिएट टर्मिनेट कर देना चाहिए। कितनी प्रोपर्टी लेकर वह चल रहा है, कितने लोगों का जीवन लेकर वह चल रहा है और वह शराब पीकर अपने जीवन की लीला तो खतम कर ही चुका साथ ही जनता की लीला खतम करने चला है।

श्री सभापतिः दो मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेहरबानी करके पांच मिनट दे दो।

श्री सभापतिः दो मिनट।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या दो मिनट? आपको बोलने वाले ही नहीं मिलेंगे।

श्री सभापतिः आप बोलो तो सही।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कह रहा हूं कि जब वह इतनी बड़ी लीला खतम कर रहा है, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, इससे बड़ा और क्या होगा और वे ड्राइवर यह कहते हैं कि आज-आज इसको माफ कर दो। चार्ज शीट दे दो तो किस बात की चार्ज शीट? इमीडिएट उसको टर्मिनेट करिये। एक्शन दुनिया की सबसे बड़ी कुंजी है और जिसका एक्शन कमजोर है, वह दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति है। एक आदमी कंडक्टर, वह पांच सौ रुपये की चोरी में पकड़ा गया, कोई बात नहीं पर एक पूरी गाड़ी को ही बिना टिकट लेकर जा रहा है और फिर भी कहते हैं कि बारह महीने में वह फिर आ जायेगा तो वह फिर क्यों आ जायेगा? किसने कहा था? तनख्वाह से काम नहीं चलता है क्या? बिना टिकट ही लेकर जा रहा है, पांच हजार रुपये कमा लिये, डिक्की में माल लेकर चल रहा है, सरकार का टैक्स खा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आदमी नौकर है तो नौकर की हैसियत होनी चाहिए। राजनीति करने वाले की राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए अगर वह भी अपनी हैसियत से ज्यादा करता है तो

वह फैल हो जाता है इसलिए रोडवेज की आप सबसे बड़ी कुंजी लेकर आये हो कि आप पांच सौ बसें नई खरीदोगे। नई बसें खरीदोगे तो उसमें आपको नियम भी नये बनाने पड़ेंगे। ड्राइवर भी आपको चतुर लेने पड़ेंगे, कंडक्टर भी आपको अच्छे लेने पड़ेंगे। आपको टी.आई. वगैरह जो पहले होते थे, उनको भी लगाने पड़ेंगे। आजकल तो आप लोगों के पास टी.आई. ही नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर सहित सारी पोस्ट्स आपने खतम कर दी और कोई आपके पास में टी.आई. नहीं है, ए.टी.आई. नहीं है। वह क्यों नहीं है? चैकिंग तो होनी ही चाहिए। जब तक इस हिन्दुस्तान में चैकिंग नहीं होगी तब तक हिन्दुस्तान का आदमी काम नहीं करेगा।

एक नई बात रोडवेज में कहूंगा कि यह सब सिस्टम तो आपने कर ही दिया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, उसी दिन रोडवेज फेल हो गयी थी। आप डी.टी.ओ. ऑफिस को देखिये। डी.टी.ओ. ऑफिस का भी आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आपका फिटनेस कौन करेगा? प्राइवेट आदमी करेगा और प्राइवेट आदमी को पांच हजार रुपये दे देंगे तो वह गाड़ी को देखेगा ही नहीं, प्राइवेट आदमी उसकी फिटनेस कर देगा। आज से पन्द्रह दिन पहले एक केस पकड़ा गया कि गाड़ी थी गुजरात में और फिटनेस हो गयी झुन्झुनूं में। जब वहां पर एक्सीडेंट हो गया तो तब उसने कहा कि गाड़ी तो उस दिन झुन्झुनूं में थी तो वे बोले साहब, गुजरात में एक्सीडेंट हुआ है। माननीय सभापति महोदय, देखिये कि यह कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विडंबना है? गाड़ी की फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है अगर जिसकी फिटनेस ही सही नहीं है तो वह गाड़ी क्या चलेगी और उसकी फिटनेस हो रही है कागजों में और वह दूसरी जगह पर चल रही है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके डी.टी.ओ. ऑफिस में परमिट बनाने वाले प्राइवेट ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री केसाराम चौधरी। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट। सारा सिस्टम आपका प्राइवेट हो गया। उसके बाद में नई बात और सुनिये आपकी कि आपके डी.टी.ओ. ऑफिस में आपका इंस्पेक्टर अगर कोई बोर्डर पर लगा हुआ है गुजरात में तो उसका ट्रांसफर हो सकता है? हरियाणा बोर्डर पर हो तो जायेगा लेकिन वह जायेगा नहीं, घूमता हुआ वहीं बोर्डर पर ही रहेगा तो वह क्यों रहेगा बोर्डर पर? बारह महीने के बाद में बोर्डर से उसको हटाइये और दूसरा इंस्पेक्टर वहां पर लगाइये। उसने वहां पर अपनी जड़ जमा रखी है। वे चोरी करते हैं, दारू और भू-माफियाओं से, दारू माफियाओं से मिले हुए होते हैं और गुजरात में दारू भेजते हैं तो इस तरह की कमियों को अगर आप दूर नहीं करेंगे, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, अपन कोई ऐसे तो जन्में नहीं थे कि मुख्य मंत्री बनेंगे या कुछ बनेंगे पर जब आ ही गये, बन ही गये और अपने मन में कर ली, ठान ली तो आप सुधार करें। बहुत सारे लोग आये हैं, मैंने देखा कि वे चोरी में पकड़े गये और वे जेल में पड़े हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये। श्री केसाराम चौधरी। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप तो ठान लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन जो आपने किया है। मोदीजी का शौक है प्राइवेटाइजेशन तो। मोदीजी ने रेल को प्राइवेट कर दिया, यहां भी रोडवेज को प्राइवेट करोगे क्या?

श्री सभापति: बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आप मन में ठान लीजिए और करिये, आपका नतीजा अच्छा होगा और आपका नाम होगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो आदमी काम नहीं करता है, उसकी कोई पूछ नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मंत्रीजी, कोटा में सात कॉलेज है पर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिये। आप विराजिये।

सूचना

जमवारामगढ़ में अज्ञात बीमारी से बकरियों की मौत एवं मुआवजा

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गरीब किसानों की सौ से ज्यादा बकरियां मर गयी हैं किसी बीमारी से तो मैं विभाग से यह मांग करता हूं कि उनका जल्दी से जल्दी इलाज करें और उनको मुआवजा दिलाया जाये।

श्री सभापति: बैठिये।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा एवं
मांग संख्या 62 - परिवहन पर विचार

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, युवा की आज जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हालात हो रही है उसको देखते हुए अगर युवाओं में नैतिकता, चरित्रवान शिक्षा की अगर हमने शुरूआत नहीं की तो आने वाला समय किस तरह का होगा, उसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए।

युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी ने भी यह कहा था कि बहादुर, राष्ट्रवादी, साहसी आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एक मात्र नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है। विवेकानंद जी ने उस जमाने में युवा के लिए ऐसी कल्पना की थी और आज हम कॉलेजों की शिक्षा में बी.ए. करके बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। आज कॉलेजों में हम जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, आज कोई भी महाविद्यालय में देखा जाये तो पूरी तरह से कहीं पर क्लासेज नहीं लगती हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): तो कहीं पर पढ़ाने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आने वाले समय में किस तरह के युवा को इस राष्ट्र को सुपुर्द करना चाह रहे हैं?

मैं यह निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में अपने को शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना पड़ेगा। यह मैकाले पद्धति की शिक्षा हमारे को, इस राष्ट्र को कहां पर ले जायेगी, उसमें सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। आज कोई भी व्यक्ति कॉलेजों में चले जाये, हम यहां जयपुर में बैठे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में जाकर देखा जाये तो कितने बच्चे क्लासों में बैठ रहे हैं और कितने पीरियड लग रहे हैं, उसकी तो हम चिंता ही नहीं कर रहे है। हमारे कॉलेज खोल दो, हमारे वह काम कर दो मगर आज इन कॉलेजों की हालात क्या है, उस सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। अगर हमने इस सिस्टम को नहीं सुधारा तो आने वाले समय में कॉलेजों से बेरोजगार निकालकर, हम बी.ए. करके भी बेरोजगार निकालेंगे, ऐसी शिक्षा राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है।

SSY/RTM/20.07.2024/12:40/1I

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज जिस तरह से कॉलेजों में, हमारे समय में, भारतीय जनता पार्टी के राज में मारवाड़ जंक्शन में कॉलेज खोला था। मगर उस कॉलेज की आज भी हालत देख लें, 5 साल में आप उस कॉलेज का भवन नहीं बना सके। आज की तारीख में जो भवन बनाना है, उसमें भी कई कमियां हैं। उसको पूरा करने के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मारवाड़ जंक्शन के कॉलेज में गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है उसको बनाना चाहिए। इसके साथ ही एनसीसी, स्काउट गाइड्स के लिए भी स्थाई कार्यालय होना चाहिए। महाविद्यालयों में राजनीति विज्ञान, भूगोल विषय होते हैं। मैं राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन में बीएससी और बीकॉम विषय खोलने की मांग करता हूं। मेरे क्षेत्र में कहीं भी सरकारी महाविद्यालय नहीं होने के कारण से मारवाड़ जंक्शन पर ही पूरा दबाव रहता है। बच्चों को विषय नहीं मिलने के कारण बाहर जाना पड़ता है। ऐसा मेरा निवेदन है।

आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा राजस्थान के 14 विश्वविद्यालय जिनमें 7 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। जिसका कारण यूजीसी के अनुसार बताया गया छात्रों की शिकायत का निवारण 2023 के अनुसार अभी तक विश्वविद्यालय में लोकायुक्त नहीं नियुक्त किये गये हैं। इसके कारण से 14 विश्वविद्यालय बंद होने के कगार पर हैं। यूजीसी ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। मैं निवेदन करता हूं कि उन विश्वविद्यालयों को, इन्होंने तो वह काम किया नहीं, हमारी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह तुरंत प्रभाव से अगर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गयी है,तो करें। ताकि इन विश्वविद्यालयों को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोका जा सके।

मैं आज सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारी सरकार ने युवाओं को जो सोच पैदा हुई है,

उसमें हम केवल किताबी ज्ञान से इस युवा वर्ग का कल्याण नहीं कर सकते। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी सरकार युवाओ के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमारी सरकार ने 70 हजार भर्तियों की घोषणा की है। जिससे जो युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए हम 70 हजार नौकरियां देंगे। इस 6 माह में 20 हजार युवाओं को नियुक्ति दे चुके हैं। इसलिए हमारी सरकार की मंशा साफ है कि राज में आते ही युवाओं के लिए चिंता करना शुरू किया। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री ने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख से अधिक भर्तियां किया जाना प्रस्तावित किया है। मैं इसके लिए सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि आपने आते ही युवाओं के लिए चिंता की है।

देश के प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं कि युवा भारत है। युवा भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में जो हमने संकल्प लिया है, उसका सपना पूरा करने के लिए जब तक युवाओं को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक यह भारत जिस तरह से पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। यह हमारी सरकार का लक्ष्य है।

हमारी सरकार ने युवाओं की समस्याओं के लिए युवा नीति, 2024 लाने की जो घोषणा की है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। युवाओं को 5 वर्ष में उत्तरोतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए सरकार 3 सूत्री कार्यक्रम अपडेट कर रही है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्किल अपग्रेडेशन के साथ 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं।

युवाओं को राज्य के विकास में सम्मिलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही अप्रेंटेशिप, इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किया जाना प्रस्तावित है। जिससे विद्यार्थी को तकनीकी शिक्षा लेकर के अपने जीवन को अपने बलबूते पर खड़ा करने की शिक्षा दी जाये, जिससे निश्चित रूप से युवा वर्ग में आने वाले समय में क्रांति आयेगी। चयनित युवाओं को देश, विदेश विजिट के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि हमारे विद्यार्थियों को विश्व के किसी भी देश में वहां की शिक्षा के बारे में जानकारी करने का भी मौका मिलेगा। यह हमारी सरकार की मंशा है। सरकार निश्चित रूप से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि आने वाले समय में स्किल पॉलिसी लाकर रोजगार योग्य करने के लिए 2 वर्षो में 1 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग करवायी जायेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब तक बच्चे के हाथ में हुनर नहीं देंगे, ऐसी शिक्षा लाकर के नहीं देंगे, तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। वह अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। केवल किताबी ज्ञान से हम बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको, पक्ष और विपक्ष को मिलकर इस शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान

देना होगा ताकि आने वाले समय में बेरोजगारों की फौज पैदा ना हो। पढ़ा-लिखा व्यक्ति बेरोजगार हो रहा है। यह हमारे लिए सोच और चिंतन का विषय है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। अगर उनको मजदूरी करने का कहेंगे तो वह नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कॉलेज शिक्षा में, उनको तकनीकी शिक्षा में प्रवीण किया जाये।

मैं मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मारवाड़ जंक्शन में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की जो घोषणा की है, मैं उनका सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मारवाड़ जंक्शन जैसे क्षेत्र में कोई भी टेक्निकल विद्यालय नहीं था और आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलकर के हमारे क्षेत्र में किया।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है। बसों का तो बोला ही नहीं है।

श्री सभापतिः आपका 10 मिनट का समय पूर्ण हुआ। श्री पितराम सिंह काला।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं।

श्री सभापतिः आप डिमांड दे देना।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, जिस देश में मंदिरों की छतें सोने से मंढी हों और विद्यालय, महाविद्यालयों की छतों से पानी टपकता हो, वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज यह हालात हमारे शिक्षा विभाग के अन्दर चरितार्थ हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मास्टर हजारी लाल जी शर्मा, जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने डिग्री कॉलेज के लिए बिल्डिंग दी थी। जो लगभग 24 करोड़ की थी। वह 35 साल पहले बनी थी। सर्वप्रथम तो उस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। वहां रिपेयरिंग की जरूरत है। आज तक वहां किसी भी प्रकार से एक रुपया बजट में नहीं दिया।

इसी प्रकार से महाविद्यालय में एक भी सहायक कर्मचारी नहीं है। मात्र 4 व्याख्याता हैं। बाकी विद्या संबल के सहारे, वह भी अभी वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां जो रिक्त पद हैं, शैक्षणिक हैं, गैर शैक्षणिक हैं, उन पदों को भरा जाये।

महाविद्यालय के अन्दर दैनिक खर्चा होता है। जैसे बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, उसके तहत कंन्टिजेंसी का कुछ बजट प्रति वर्ष दिया जाये। उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वहां बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर नहीं है। वहां फर्नीचर का भी बजट दिया जाये। महाविद्यालय में कला संकाय है। विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलने की भी मैं आपसे निवेदन करता हूं।

Spp/Rtm/20.07.2024/12:50/1m

इसी के साथ, चिड़ावा बहुत बड़ा कस्बा है, उसके आस-पास 60-70 ग्राम हैं। वहां से बच्चे अध्ययन करने के लिये आते हैं तो उस महाविद्यालय को भी क्रमोन्नत करने की भी आपसे मांग करता हूं।

इसी के साथ, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, कि पिलानी विधान सभा जिससे मैं आता हूं, वह विश्वविख्यात शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां बिट्स जैसे संस्थान हैं, यह विश्वविख्यात है। बिड़ला विद्यापीठ है वह पूरे भारत के अन्दर प्रसिद्ध है, बिड़ला पब्लिक स्कूल जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। वहां पिलानी में पंचायत समिति मुख्यालय है, तहसील है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अत: मैं यह जो शहर हैं वहां दो नगरपालिकाएं हैं। राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी एक शहर के अन्दर दो नगरपालिकाएं हैं। यहां 80 के लगभग विद्यालय संचालित हैं। इनमें लगभग 40 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। निकटवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिये आते हैं और यहां हरियाणा की सीमा से लगता हुआ एरिया है। यहां के जो छात्र हैं, वह गरीब, मजदूर, किसान और आम आदमी के बच्चे अध्ययन करने के लिये आते हैं तो मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं यहां पिलानी के अन्दर एक महाविद्यालय खोला जाये।

इसी के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मंडयाला के अन्दर कन्या महाविद्यालय खोला था, उसके लिये मैं पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां कन्या महाविद्यालय खोला। उसके लिये जमीन की व्यवस्था की गयी। भवन लगभग बनकर तैयार हो गया है लेकिन उस कन्या महाविद्यालय के अन्दर एक भी सरकारी व्याख्याता नहीं है। वहां पर कम से कम एक तो सरकारी व्याख्याता लगा दिया जायेगा तो कम से कम बिल्डिंग को हैण्डओवर कर दिया जाये। संविदाकर्मी हैं, विद्या सम्बल के कार्मिक हैं, उनको ट्रांसफर नहीं की जा सकती। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आपसे मैं निवेदन करूंगा और जब आप जवाब दें तो कम से कम हमारे यहां एक स्थायी व्याख्याता तो लगा दें जिससे वह भवन उनको हैण्डओवर किया जा सके और उस भवन का उपयोग हो सके।

इसी के साथ, वहां पर विद्या सम्बल और संविदाकर्मियों के भरोसे वह संचालित है। इस महाविद्यालय के आस-पास लगभग 15-20 ग्राम पंचायतें पड़ती है, वहां पढ़ने का कोई दूसरा साधन नहीं है। मैं इसके लिये भी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वहां विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोला जाये और जो व्याख्याता के पद रिक्त हैं, उनको भी शीघ्र भरा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि महाविद्यालय चिड़ावा के अन्दर खोला गया था। आज भी उस कृषि महाविद्यालय की वैसी ही स्थिति है। आज वह मात्र दो कमरों के अन्दर, जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, उसके दो कमरे अलॉट किये हैं, उनके अन्दर संचालित है। वहां पर न तो कोई व्याख्याता लगाया गया

है और न ही अन्य कोई कर्मचारी लगाये गये हैं, न वहां पर शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ की व्यवस्था की गयी है। वहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस महाविद्यालय के अन्दर स्टॉफ लगाया जाये, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ लगाया जाये। जमीन की व्यवस्था की जाये और बजट अलॉट करके उसकी बिल्डिंग बनाने के लिये बजट दिया जाये जिससे वहां पर वह भवन बन सके और यहां आने वाले आसपास के जो विद्यार्थी हैं, उनको लाभ हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र के अन्दर जो पिलानी विधान सभा क्षेत्र है, अभी श्रवण कुमार जी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वहां से वह चार बार विधायक रह चुके हैं, अब उनका क्षेत्र सूरजगढ़ है और अब मैं पिलानी से विधायक हूं। वहां पोलिटैक्निक कॉलेज खोला गया था और वह 2021-22 से संचालित हैं। वहां सारे संकाय संचालित थे। वहां पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और बढ़िया संचालन हो रहा था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह महाविद्यालय पिलानी का होते हुए पिलानी के अन्दर संचालित नहीं हो रहा था। झुन्झुनूं जिला उसके हैडक्र्वाटर पर संचालित हो रहा था। वहां तक भी हमें संतुष्टि थी, लेकिन उस महाविद्यालय को 24 जून, 2024 को निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के द्वारा आदेश निकाला गया, उसके द्वारा बंद कर दिया गया। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जब कोई कॉलेज और महाविद्यालय खोला जाता है, चाहे वह डिग्री कॉलेज हो, चाहे पी.जी. कॉलेज हो, वह सरकार के आदेश से खुलता है। आपने इसका कब आदेश दे दिया कि निदेशक महोदय कालेज खोल सकता है और बंद कर सकता है तो मुझे तो इस आदेश पर भी शंका है। राज्य सरकार को यह काम करना चाहिये, अधिकारियों से यह काम नहीं करवाना चाहिये और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तकनीकी महाविद्यालय को पुनः संचालित किया जाये। वहां जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, जो तीन साल से अध्ययन कर रहे हैं, वे बच्चे कहां जायेंगे? उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तकनीकी महाविद्यालय को वापस संचालित किया जाये और यहां के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको लाभान्वित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट हैं, वह शिक्षा विभाग का है। माननीय मंत्रीजी, आप यहां बैठे हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं, वह भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उस शिक्षा विभाग की मांग का यहां जिक्र नहीं किया गया। सबसे बड़ा जो विभाग है, उस विभाग की भी सदन के अन्दर चर्चा होनी चाहिये थी। आज उस विभाग के यह हालात कर दिये गये हैं कि जो हमने नामांकन एक लाख के लगभग पहुंचाया था, वह नामांकन आज वापस 70 हजार के करीब आ गया। वह क्यों आया, इसके कारणों पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति थी, उसके अन्दर यह प्रावधान किया गया था कि हम पहले एल के जी खोलेंगे, यू के जी खोलेंगे और नर्सरी खोलेंगे, उसके बाद में छह साल का बच्चा हो जायेगा उसको

सरकारी विद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था करेंगे। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उस नई शिक्षा का अध्ययन नहीं किया। जो आंगनबाड़ी चल रही हैं, उसके अन्दर ट्रेंड टीचर नहीं हैं तो वे बच्चे आंगनबाड़ी के अन्दर नहीं जाते। राजकीय विद्यालयों के अन्दर नहीं जा रहे हैं। वह निजी विद्यालयों की ओर रूख कर रहे हैं तो जो निजी विद्यालय हैं, उनके अंदर नामांकन बढ़ रहा है और राजकीय विद्यालयों के अन्दर नामांकन घट रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक नई शिक्षा नीति की पूर्ण तरह से क्रियान्विति नहीं होती तब तक इसकी जो प्रवेश की आयु है, उसको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया जाये जिससे हमारे जो हमारे बच्चे हैं, उनका एडमिशन हो सके और जो सबसे बड़ा रोजगार देने का साधन है शिक्षा का, वह सही हो सके। यदि इसी प्रकार से चलता रहा, माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि 5 साल के अन्दर आपकी स्कूलें बंद करने के कगार पर स्थिति आ जायेगी। जो सबसे बड़ा रोजगार देने का जो साधन है, वह बंद हो जायेगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह व्यवस्था नहीं हो, प्रवेश की जो आयु है, वह 5 वर्ष की जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, यह बार-बार कहते हैं कि महात्मा गांधी विद्यालय खोलकर यह कर दिया। जब बहस चल रही थी उस समय मैं यह सुन रहा था कि कुछ लोग आपके सत्ता पक्ष के भी यह कह रहे थे कि हमारे यहां भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जायें। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, जब अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोले गये थे, मैं चूरू संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित था और हमारे पास सिफारिशें आती थीं कि हमारे विद्यालयों के अन्दर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाये। प्रथम चरण में हमने जिला हैडक्वार्टर पर इंग्लिश मीडियम खोले, उनका प्रशिक्षण दिया और टीचर्स का इंटरव्यू लिया और उसके अन्दर उनको पदस्थापित किया। जब वह स्कीम सफल हुई उसके बाद हमने ब्लॉक स्तर पर स्कूलें खोलीं और ब्लॉक स्तर पर भी वही सिस्टम हमने लागू किया। वहां इंटरव्यू लिये गये और जो सक्षम टीचर थे, उनका सलेक्शन किया गया और ब्लॉक लेवल पर महात्मा गांधी विद्यालय संचालित किये गये।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर खोले गये और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, वही एक ऐसे स्कूल थे जहां आई ए एस के बच्चे पढ़ते थे, नेताओं के बच्चे पढ़ते थे। जहां एडमिशन के लिये वेटिंग चलती थी। एक सेक्शन में 30 बच्चों का नामांकन था, वह 60-70 बच्चों की वेटिंग लिस्ट थी। हमको अतिरिक्त संकाय खोलने पड़े थे। ऐसी स्कीम को आप बंद मत कीजिये, उसकी समीक्षा कीजिये। इसका अलग कैडर बनाइये और उस कैडर के अन्दर इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो टीचर इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़े हुए हैं, उनका आप इंटरव्यू लीजिये और इंटरव्यू के माध्यम से उनका ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः बिराजिये। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

MLS/RTM/20.07.2024/14:00/2c

(समयः 14.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः राम-राम सा। श्री हरिसिंह रावत।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा

व मांग संख्या 62 - परिवहन पर विचार

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा व मांग संख्या 62 - परिवहन पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारा जो यह बजट पेश हुआ है, वह एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का बजट है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी का एक सपना है कि सम्पूर्ण भारत के साथ-साथ हमारा राजस्थान भी एक विकसित प्रदेश बने, उसी अनुरूप यह बजट पेश किया गया।

आज मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह जो बजट है, वह एक साहसिक बजट है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार ने इस बजट वर्ष 2024-25 में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध की परम्परा को पुनः स्थापित करने का काम किया है। उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान की गयी है, जो कि पूर्व काल में शिष्य के साथ सम्बन्ध को चरितार्थ करती थी।

सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा युवाओं में स्किल, टैक्निक को बढ़ाने के लिए i-start के अन्तर्गत "Learn, Earn And Progress (LEAP) programme" प्रारम्भ किया, जो एक स्वागत योग्य कदम है। युवाओं को गुणवत्ता, कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्ष के मध्य 20 नवीन आईटीआई केन्द्र व 10 पॉलिटैक्निक महाविद्यालय बनाने का प्रावधान करना एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने किसी के साथ कोई भेद-भाव नहीं रखा। विपक्ष के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो हमने घोषणाएं की हैं, उन्हें क्रियान्वित भी करेंगे।

हमारे विपक्ष के साथियों को तो लगता है, यह तो असत्य का पुलिन्दा है। असत्य का

पुलिन्दा तो तब होता, जब हम लास्ट के समय ये घोषणाएं करते, तब तो आप यह महसूस करते कि यह वास्तव में एक असत्य का पुलिन्दा है। जब हमने प्रथम बजट में ही ये घोषणाएं की हैं तो आप खुद ही देख लेंगे कि साल भर में क्या प्रोग्रेस होने वाली है। वैसे हमारे मुख्य मंत्री जी ने मंत्री मण्डल की मीटिंग भी ले ली है और हर मंत्री को जिला प्रभारी के माध्यम से भेजा जा रहा है और तत्काल कैसे उन्हें गति मिले, उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं परिवहन की बात करना चाहता हूं। हमने एक एजेंडा बनाया, ''One nation, one election'', उसी प्रकार ''One nation, one tax'' हमारे केन्द्रीय मंत्री गडकरी जी ने एक सपना संजोया कि पूरे भारत में एक ही पैटर्न पर टैक्स लिया जाये। उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया और उसी प्रोग्राम के माध्यम से परिवहन मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं परिवहन को एक सस्ते एवं सुगम साधन के रूप में उपलब्ध कराने की नीति से एआईटीपी परमिट को तुरन्त प्रभाव से लागू करते हुए 700 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह से घटाकर 200 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह कर दिया, परन्तु राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी हठधर्मिता के कारण केन्द्र की योजना को लागू नहीं किया। सभापति महोदय, इस कारण से आज हमारे जो प्राइवेट बस ओनर्स हैं, वे समस्याओं से जूझ रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में स्लीपर बसों के लिए अलग टैक्स स्लैब बनाये गये हैं। राज्य में परमिट लेकर चलने वाली बसों के लिए, जो बसें केन्द्र सरकार द्वारा जारी एआईटीपी परमिट से संचालित हो रही हैं, उनके लिए। उत्तर प्रदेश में स्लीपर बस का टैक्स है 9 हजार रुपये प्रतिमाह। बिहार में वह टैक्स है 7 हजार रुपये प्रतिमाह। मध्य प्रदेश में वह टैक्स है 7200 रुपये। इसी प्रकार नागालैंड और अरुणाचल में प्रतिमाह 1 हजार रुपये। अफसोस है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार की हठधर्मिता के कारण हमारे टैक्स स्लैब में कोई कमी नहीं की गयी। अभी जो हमारी राजस्थान सरकार टैक्स ले रही है, 39,915 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से ले रही है।

यह वाहन स्वामियों के लिए बहुत गलत है। इसी वजह से आज हमारे राजस्थान के बस ओनर्स मार्केट के कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी करीब 3100 बसें, सब परमिट लेकर चल रही हैं, वापस इस स्लैब में अमैंडमेंट करके एमपी पैटर्न या अन्य पैटर्न पर किया जाये। चलिये, मानते हैं पूर्व में तो हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन अभी तो हमारी सरकार है। हमारी सरकार ये स्टैप्स ले, इसी पैटर्न पर करे। चाहे 8 हजार की जगह 10 हजार कर लीजिये। मैं समझता हूं, 3100 बसें जो आउट ऑफ स्टेट गयी हैं, वे वापस यहां आ जाएंगी। इसके अलावा, बजट घोषणा के इन्तजार की वजह से हमारे बस ओनर्स की 250 बसें अभी तैयार खड़ी हैं, वे यही इन्तजार कर रही हैं कि हमारे भी अगर यही टैक्स स्लैब लागू हो तो हम राजस्थान में करेंगे, अन्यथा ये 250 बसें अन्य स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आरटीओ, डीटीओ, ये पूर्व के ही हैं, ये जो नियम-कानून बना रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के अभी भी बैठे हुए हैं, उनकी हठधर्मिता है कि हम लोग यह करने नहीं देंगे। सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी 30-35 गाड़ियां पकड़ रखी हैं और उनके लिए क्या कह रहे हैं कि ये गाड़ियां सही पास नहीं हुई हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, गाड़ियों को पास करने वाले कौन हैं, वे आपके ही अधिकारी-कर्मचारी हैं। बस ओनर्स तो मैं समझता हूं कम पढ़े-लिखे हैं, उन्हें इतना पता भी नहीं होता है, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं,जो आपके आरटीओ, डीटीओ हैं, अगर उन्होंने गलत तरीके से पास की हैं तो सबसे पहले सज़ा उन्हें मिलनी चाहिये।

उन्हीं की वजह से यह हुआ है। अगर तकनीकी खराबी थी तो जब गाड़ियां पास होने आयी थीं तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया? उन्हें तो कमाई मिल रही थी। कमाई की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। आज उल्टा-सीधा करके करीब 30-35 गाड़ियां खड़ी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर थोड़ा गौर करें। साथ ही, वापस टैक्स स्लैब में अमैंडमेंट करें ताकि जो हमारी 3100 बसें बाहर की परमिट लेकर चल रही हैं, वे तत्काल वापस यहां रजिस्टर हो जाएं ताकि हमारी सरकार को रेवेन्यू लोस न हो। आज इसकी वजह से बहुत रेवेन्यू लोस हो रहा है।

मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा हूं, केन्द्र सरकार ने 2021 में एआईटीपी परमिट जारी किया था, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन मिले, जनता को सस्ता व सुगम साधन मिले। इसके लिए उन्होंने परमिट पर 90 हजार रुपये त्रैमासिक लगाया था और 3 लाख रुपये वार्षिक निर्धारण सुनिश्चित किया था। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। आज अगर उन पर 10 हजार तक का टैक्स निर्धारित कर देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। इससे राज्य सरकार को कम से कम 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की आयु सीमा भी 8 वर्ष से 12 वर्ष कर दी जाये। 8 वर्ष पश्चात् वाहन स्वामी वाहन को अन्य राज्य से पंजीकृत कराता है। इससे करीब प्रति बस 7 लाख 70 हजार वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि अगर इसी स्लैब से हमारे राजस्थान में चालू कर दिया जाये तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो जायेगी। जो पूर्ववर्ती सरकार ने सामान्य परिवहन के लिए बसों की व्यवस्था की, 6 हजार रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया। इसकी जगह अगर यही टैक्स वसूल करें तो सरकार को कम्पाउंडिंग फी के रूप में रसीद काटकर बसों को चलाने की परमिशन देंगे तो इससे करीबन 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

mkd/rtm/20.07.2024/14:10/2d

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

राजस्थान राज्य पथ परिवहन में कुल 2500 बसें हैं और इसके अगेंस्ट में 3100 बसें राज्य में पंजीकृत हैं। केन्द्र सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो नीति है, उसे प्रभावी करने पर एक हजार बसें प्रतिवर्ष बन रही हैं, जिससे जीएसटी के रूप में राज्य सरकार को करीबन एक सौ पचास करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो रही है।

परिवहन घाटे का उपक्रम है। आज राजस्थान रोडवेज की बात करूं, यह हमारे लिए एक सफेद हाथी के रूप में है। हमारे राज्य को इससे नुकसान हो रहा है। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला हैं। लास्ट टाइम, हमारे श्रवण जी बोल रहे थे कि रोडवेज तो घाटे का सौदा है।

आज राजस्थान रोडवेज को चलाने के लिए हमारी सरकार टैक्स में रियायत देती है, जीएसटी में रियायत देती है, पेट्रोल डीजल में रियायत देती है, उसके बाद भी हमारी बसें घाटे में क्यों चलती हैं? प्राइवेट बसें तो घाटे में नहीं चल रही हैं, क्योंकि इसका कोई धणी-धोरी नहीं है, इसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है।

आज डीटीओ रोड पर खड़े होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है? उनकी ड्यूटी यह होती है कि कोई एक्सीडेंट हो तो तत्काल वहां पर फर्स्ट ऐड मुहैया कराई जाये, ट्रैफिक जाम है तो उसको व्यवस्थित किया जाये। वे यह काम नहीं करते हैं। रात को दो बजे, तीन बजे तक, आज कोई भी अधिकारी, कर्मचारी मैं समझता हूं कि अपना घर रात को छोड़कर कोई जाता नहीं हैं, लेकिन वहां रातों रात वसूली होती है, रातभर वसूली करने के लिए खड़े होते हैं, वह काम जरूर करेंगे, लेकिन किसी जनता का भला या यातायात का भला करने के लिए ये लोग नहीं हैं।

श्री सभापतिः सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री हरिसिंह रावत भीमः सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गौर फरमाया जाये। मेरी कॉलेज सम्बन्धी मांग है। हमारे भीम में राजकीय महाविद्यालय संचालित है, जिसमें व्याख्याताओ की कमी है, भीम देवगढ़ में व्याख्याताओं की कमी पूरी की जाये। दूसरा, मेरे पूर्व काल में पृथ्वी राज चौहान..।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को आप दे दें। यह ठीक रहेगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): राजकीय महाविद्यालय में सवा तीन करोड़ में नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने पास किये थे, वह भवन कम्प्लीट है, अगर वहां हॉस्टल कर दिया जाये तो गरीब बच्चे, जिनके मां-बाप सक्षम नहीं हैं, वे बच्चे भी पढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।

साथ ही साथ, हमारे यहां राजकीय महिला महाविद्यालय है, वह भीम शहर से करीबन 5 किलोमीटर दूर हैं। उस भवन को वापस हमारे राजकीय महाविद्यालय में शिफ्ट कर दें। मैं समझता हूं कि बच्चों का पांच किलोमीटर जंगल में आना-जाना अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए, एक ही प्रिमाइसेज में यह हो जायेगा तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री सुभाष गर्ग साहब।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का समय दिया। मैं सबसे पहले हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की बात करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, "Appointment of the Vice-Chancellor" पर मैं चर्चा करना चाहूंगा।

इस सम्बन्ध में, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि हमने भी कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाये। आपसे अनुरोध है कि सबसे ज्यादा कुलपतियों की नियुक्तियों के मामले आये हैं। आपने पहले भी अखबारों के माध्यम से देखा होगा, इस तरह के बार-बार केसेज आते हैं।

एक संशोधन जो एक्ट में कर दिया गया था। पहले यह था कि, on the advice of the State Government, कुलपतियों की नियुक्ति होती थी, बीच में एक साउथ के गवर्नर महोदय आये और कुछ ऐसा संशोधन हो गया, उसकी जगह, in consultation with the Government, हो गया। जिसकी वजह से सरकार का कोई शह ही नहीं है, अपोइंटमेंट में।

जहां तक जानकारी है, पहले पत्रावली भी आती थी, लेकिन अब तो पत्रावली भी नहीं आती है और "Appointment of the Vice-Chancellor", कर दिये जाते हैं। जिसकी वजह से राजस्थान के जो शिक्षाविद् हैं, किसी भी मायने में कम नहीं हैं। राजस्थान के लोगों ने बाहर जाकर कुलपतियों के रूप नाम रोशन किया है। मेरी गुजारिश है, ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको मौका मिला है, जनता ने मौका दिया है। आपकी केन्द्र में सरकार है, आप यहां हैं, गवर्नर आपके हैं, मिलकर के इस एक्ट में परिवर्तन करिये। राज्य में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और जितने भी कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है, उनके साथ न्याय होगा, शिक्षाविदों के साथ न्याय होगा।

दूसरी बात, मैं ऑटोनॉमी की कहना चाहूंगा। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी कि पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए, बिलकुल सही है, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी था कि उनकी जो ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

आज हालत यह हो रही है कि अधिकांश एमएलए, जो सिंडिकेट में नियुक्त किये जाते हैं, बॉम में नियुक्त किये जाते हैं, वे कुलपतियों के खिलाफ लिख रहे हैं कि उनके द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कारण, सरकार की सीमाएं हैं। चांसलर कुलाधिपति होते हैं, उनके ऊपर सारा डायरेक्शंस होता है, सरकार रिक्मंड करके भेज देती है।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान हो या पिछले 15-20 साल से जिसकी भी सरकारें रही हैं, कुलपतियों के खिलाफ जांच सिद्ध होने के बावजूद भी क्यों प्रोटेक्शन मिलता है? यह मुझे समझ में नहीं आता है, किस लेवल पर प्रोटेक्शन मिलता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि सरकार का नहीं

तो कम से कम चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट जस्टिस की अध्यक्षता में ऐसा कोई एक जांच आयोग बनायें कि इन विश्वविद्यालयों की जो कार्यप्रणाली है, इसको चैक किया जाये और उनमें सुधार के प्रयास किये जायें।

मैं उदाहरण दे सकता हूं। भरतपुर चले जाइये, अलवर चले जाइये, बीकानेर, उदयपुर ऐसा पहले भी अखबारों में छपा है, तो यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, ना ही मेरी आलोचना सरकार या पूर्ववर्ती सरकार के लिए है। मैं एक शिक्षाविद् रहा हूं, मैं शिक्षक रहा हूं। इस माने एक पीड़ा है कि कुलपति विश्वविद्यालयों में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। यूपी से शिक्षक बुलाये जाते हैं, यूपी के शिक्षकों से कॉपी चैक कराई जाती है और सॉफ्टवेयर के नाम पर करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और बेइमानी की जा रही है। यह **शेम** की बात दोनों पक्षों के लिए है।

इसमें मेरा कतई यह नहीं है, क्योंकि सदन में हम सभी सदस्य हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है कि इन विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली सुधरे। वहां बच्चा पढ़ने के लिए आता है, एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें।

अभी मैंने देखा भरतपुर के विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक अख़बार में विज्ञापन दिया और परफोर्मिंग आर्ट के नाम पर, अमिताभ बच्चन जी का भी नाम दिया और भी कई नाम दिये। इनसे पूछिये कि आप उनको बुला सकते हो क्या, केवल अखबारों में वाहवाही लूटने के लिए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पर स्पेशल ध्यान दे। चाहे कोई भी कुलपति हो, चाहे कुलपतियों का जो भी कार्यकाल हो, इसकी कृपया जांच करायें और एक्शन लें और दूसरा वह संशोधन करें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, बिलकुल, अर्जुन सर, मैं भी सहमत हूं। मान लीजिये, हम तो फेल हो गये, हम तो नहीं सुधार कर पाये, लेकिन जनता ने मौका दिया है। हम यहां विद्यार्थियों के हितों के लिए हैं, जनता के हितों के लिए हैं, पब्लिक फंड है, पब्लिक इंवेस्टमेंट है, पैसा है।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि 7 विश्वविद्यालयों की बात हुई है, जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया। फर्जी डिग्री की बात कही गई है। सरकार कानून लेकर आई पेपर लीक पर, सब पर तो क्यों नहीं उनके निरसन का बिल लाया जाये और उन विश्वविद्यालयों को खत्म किया जाये। माननीय मंत्री महोदय, यह मील का पत्थर साबित होगा। यह इनिशिएटिव लीजिये। इन फर्जी विश्वविद्यालयों को बन्द करने की कार्यवाही कीजिये।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हम एकेडमिक की बात करते हैं। आप विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पूछिये कि कितने कुलपति निकलते हैं और विश्वविद्यालय के कॉलेजों का दौरा करते हैं। विश्वविद्यालयों की ड्यूटी केवल विश्वविद्यालय कैम्पस को डवलप करने की नहीं है, विश्वविद्यालय कुलपति की ड्यूटी, जो एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं, उनके लिए भी जिम्मेदार हैं।

वे प्रत्येक वर्ष सौ रुपया, दो सौ रुपया विद्यार्थी से डवलप फंड के नाम से वसूल करते हैं। वह पैसा वापस एफिलिएटेड कॉलेजों को नहीं दिया जाता है। आप हिसाब मंगवा लें। विश्वविद्यालयों ने एफिलिएटेड कॉलेजों को विकसित करने के लिए कितना पैसा वापस इन

कॉलेजों को दिया।

मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि चाहे सरकार हमारी थी, चाहे आपकी सरकार है, कॉलेजेज खुलेंगे, आप भी खोलेंगे, हमने भी खोले। डवलपमेंट होने में टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट होने में टाइम लगता है, भवन बनने में टाइम लगता है, फैकल्टी नियुक्त करने में टाइम लगता है। अगर विश्वविद्यालय वह जिम्मेदारी ले ले तो मैं समझता हूं, बहुत कुछ फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर से बच सकता है।

दूसरी बात कहना चाहूंगा, एकेडमिक कोर्सेज में कोई अपडेशन नहीं हो रहा है। तकनीकी शिक्षा में हमने कोशिश की थी, प्लेसमेंट की कोशिश की थी, इंडस्ट्री एकेडमिक सैल भी स्थापित किये गये थे, लेकिन अभी वे काफी कम हैं।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप रिव्यू करें, तकनीकी शिक्षा का भी, उच्च शिक्षा का भी और कुलपतियों की भूमिका को भी रेखांकित कर दिया तो ये राजस्थान के विश्वविद्यालय बचा लिये जायेंगे।

मैं कहना चाहूंगा, प्लेसमेंट एम्प्लॉयबिलिटी की, जो सबसे बड़ी कमी है। ये विश्वविद्यालय बिलकुल व्हाइट एलिफेंट हो गये हैं। मैं जब मंत्री था, तब भी मैंने सुझाव दिया था कि हम ये विश्वविद्यालय खोल तो रहे हैं, क्या वास्तव में इतने विश्वविद्यालय की जरूरत है क्या? ये विश्वविद्यालय क्या काम कर रहे हैं? केवल एडमिशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और परीक्षा कराते हैं।

चौथा काम, रिसर्च का नहीं हो रहा है। एकेडमिक प्रोग्राम्स को अपेडट नहीं किया जा रहा है। फैकल्टी डवलमेंट प्रोग्राम, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों की एक स्कीम लागू की गई थी, वह बिलकुल धरातल में चली गई है। जहां नये टीचर्स आते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी।

Bhs/Rtm/20.7.24/14.20/2e

दस साल या बीस साल जिनको पढ़ाई का अनुभव हो जाता था उनको भी इन एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों में बुलाया जाता था, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे वो बन्द कर दिये गये तो अपडेशन क्या होगा? बात करते हैं हम यह नॉलेज युग है यह नॉलेज टाइम है। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है पूरा सिस्टम आईटी बेस्ड है और हमारे टीचर्स का कोई अपडेशन नहीं किया जाता तो ट्रेनिंग पार्ट पर भी आप ध्यान दें। यह भी मेरी गुजारिश है।

चौथी बात कहना चाहूंगा कि एक यह जो घोटाला हो रहा है विश्वविद्यालयों में एफिलिएशन के नाम पर और सीटों को कम करने के नाम पर या शर्तों को पूरा न करने के नाम पर वसूली की जाती है, आप इसकी जांच करवा लें। क्यों नहीं एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दे दें। मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेज के लोग भी आते हैं किस तरह से विश्वविद्यालय कुलपतियों के द्वारा अगर आप जांच करवाएंगे तो आपको मालूम पड़ जायेगा, तो इस चीज को आप खत्म करें। मुझे उम्मीद है आपसे। आप खुद डॉक्टरेट हैं, पीएचडी की हुई है आपसे उम्मीद है कि आप

करेंगे इसको, इनिशियेट लेंगे।

सभापति महोदय, एक बात कहना चाहूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। यह बहुत इम्पोर्टेंट विषय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और मैं कहना चाहूंगा अगर मौका मिले, अध्यक्ष जी से मैंने अनुरोध किया है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पूरे सदन में चर्चा करें। क्या राजस्थान या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट फिट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए? हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी तो नहीं, चाहे आपका पक्ष हो चाहे हमारा पक्ष हो, बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार काम करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिक्विजिशंस क्या हैं, आवश्यकताएं क्या हैं वो तो पढ़ लीजिये। उसमें फ्री एग्जिट है, फ्री एन्ट्री है। स्टूडेंट कोई भी आयेगा कोई भी विषय ले सकता है। कॉमर्स का विद्यार्थी कैमेस्ट्री भी ले सकता है, साइंस का विद्यार्थी कॉमर्स भी पढ़ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर सिस्टम है। क्या हमारे कॉलेजेज जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के लिए उपयुक्त हैं क्या? टीचर्स तो हैं नहीं अपने पास और वो तीन या चार टीचर्स होते हैं वो ही एडमिशन का काम करते हैं वो ही एग्जामिनेशन का काम करते हैं वो ही सब काम करते हैं तो बताइये सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे निकालेंगे? यह कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर का ऑटोनोमस इंस्टिट्यूशंस के लिए, रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज के लिए। यह एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में सक्सेस हो ही नहीं सकता। अदरवाइज क्या होगा हर वक्त बस एग्जामिनेशन होगा, एडमिशन होगा, प्रमोशन होगा। इस पर रिकंसीडर करिये आप। यह सक्सेस नहीं हो सकता। मेरे से बहुत सारे टीचर्स आर्गेनाइजेशंस अभी मिले क्योंकि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, दूरदराज के कॉलेज हैं उनमें एक टीचर है वो कैसे करेगा, कैसे सेमेस्टर सिस्टम को लागू करेगा? आप इस पर विचार करिये अभी इसको फेजेज में लागू करिये और केवल आप चाहते हैं तो कॉलेजेज को ऑटोनोमस इंस्टिट्यूशंस बना दीजिये वो अपना ही एग्जाम करायें, अपने पेपर सैट करें।

सभापति महोदय, आज हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, पोलिटेक्निक कॉलेजेज खोलें। हमने भी खोले लेकिन स्टडी की, मैं तो बिलकुल विरोध में था एक भी पोलिटेक्निक कॉलेज नहीं खोला जाये और मेरी कोशिश रही फिर भी हमारे दस-पांच कॉलेजेज खोले गये। कारण क्या है, उसकी जगह आईटीआई खोलिये आप। स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग है आईटीआई है और मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि इस आईटीआई को आप तकनीकी शिक्षा में लीजिये। हम नहीं ले पाये। यह जो यूथ अफेयर्स में दे दिया है न, आईटीआई और तकनीकी शिक्षा एक ही विभाग में होनी चाहिये जिससे कि सही मायने में एक इंटीग्रेटेड डवलपमेंट हो सके और जो यह आप राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी की बात कर रहे हैं, स्टेट इंस्टिट्यूट की बात कर रहे हैं यह कंसेप्ट हमारा ही था। हमने सबसे पहले जयपुर में शुरू किया, जो यहां एक नया कॉलेज खुला है सौ करोड़ की लागत से वह शायद आपने देख भी लिया होगा, बिल्डिंग चल रही होगी।

सभापति महोदय, यह कंसेप्ट था आईटीआई से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो

इंस्टिट्यूशन पढ़ाई कराये, रिसर्च कराये, यह नहीं कि पुराने कॉलेजों को इसके रूप में प्रवृत्त करें। दिया है, अच्छा है कोई बात नहीं। रिसोर्सेज हमारे पास भी कम हैं, आपके पास भी कम हैं चाहे बात हम कितनी भी कर लें तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसमें आईटीआई की क्लासेज भी हों। एक मॉडल मैंने केरल से तिरुची या मेरे को ध्यान नहीं है वहां से मंगवाया था, एक लोंगोवाला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी है वहां से मंगवाया था।

श्री सभापतिः प्लीज सहयोग करें।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, बस मैं ज्यादा नहीं सिर्फ दो मिनट। तो उसकी स्टडी करवा लें, अच्छा रहेगा। समय बहुत कम है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन दो चीज कहना चाहूंगा। भरतपुर के सम्बन्ध में जरूर मैं आपके सामने मांग रखूंगा कि भरतपुर मेरा गांव है पीपला और वहां मेरे पिता ने एक भूमि दान देकर के गर्ल्स कॉलेज का भवन बनवाया तो मेरी गुजारिश है कि उसमें अतिरिक्त विषय खोल दिये जायें और बता दूं आपको, कई लोग कह रहे थे, वहां ढाई सौ लड़कियां हैं तीसरा साल है ढाई सौ बच्चियां हैं और न केवल राजस्थान की बल्कि यूपी की बच्चियां भी वहां पढ़ने आती हैं और वह भवन बन गया आपने टीचर्स भी लगा रखे हैं, प्रिंसिपल लगा रखा है। एक तो यह कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, दूसरा, भरतपुर एक ऐसा सम्भाग है जहां विश्वविद्यालय नहीं है। सारे सम्भागीय मुख्यालयों पर किसी पर तीन हैं, किसी पर दो हैं, किसी पर एक है लेकिन भरतपुर मुख्यालय पर एक भी नहीं है तो मेरी गुजारिश है ज्यादा नहीं तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की है वह और एमएसजे कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत कर दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज उच्च शिक्षा पर जो वार्ता है यह बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है जो भी इसको पीयेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, पर आज दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में शिक्षा पिछले आठ माह से थोड़ी ठहर सी गयी है। शिक्षा का जो स्तर कम हुआ है उसका मुख्य कारण है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजों के कारण हमारे प्रदेश के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट विश्वविद्यालयों में जो स्थिति है वह पूरे प्रदेश के सामने है।

माननीय सभापति महोदय, पक्ष के सभी माननीय विधायक विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किये इसलिये स्थिति खराब हुई और हम कहते हैं कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है इसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किये वो तो प्रदेश की जनता जानती है और आज पूरे प्रदेश में किसी भी

डिपार्टमेंट में हो, जैसे काम पिछले पांच साल में हुए वो कभी सत्तर साल में नहीं हुए। आज शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, सभापति महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अपनी बात रखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप प्राइवेट कॉलेजों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे और जो मनमानी फीस वसूली जा रही है उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आज गरीब किसान, मजदूरों के बच्चे हैं, वो इतनी महंगी फीस जमा नहीं करा सकते तो इसके कारण वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। आज गांवों में गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जब कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है और यहां दो-तीन लाख रुपये जब फीस मांगी जाती है तो वापस घर को चला जाता है या फिर दूसरे स्टेटों में वह मालूम करता है कहां कम फीस है हम वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करें, तो मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जाये और प्राइवेट कॉलेजों पर अंकुश लगाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से एक कमेटी का गठन किया जाये और उस कमेटी में सभी दलों के विधायकों को रखा जाये और प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं इनका निरीक्षण किया जाये कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। एक-एक, दो-दो अध्यापक लगा रखे हैं उनमें, दो-दो,ढाई-ढाई लाख रुपये वेतन ले रहे हैं, उनमें सीट हैं नहीं और इस तरह की जो उनकी व्यवस्था है उसका पता ही नहीं लग पा रहा है राजस्थान की जनता को पता नहीं लग पा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और उसके कारण हमारे प्रदेश के बच्चों को नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, जब हम प्रदेश को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा की बड़ी भूमिका रहती है। शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो लोग वही अंधविश्वासों में फंसते रहेंगे और प्रदेश का भट्ठा बैठता रहेगा।

इसी तरह से मैं इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करूंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला हैडक्वार्टर पर, हर ब्लॉक स्तर पर होने चाहिये। जितने ज्यादा ब्लॉक स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, तो उससे बेरोजगारी खत्म होगी। आईटीआई खोलेंगे हम तो उससे रोजगार मिलेगा और जो बच्चे उनमें पढ़ कर आयेंगे और वह तकनीकी शिक्षा लेंगे तो उससे वो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो सरकारी सेवाओं में ही जायें। सरकारी सेवा नहीं मिलेगी तो वह और कोई धन्धा खोलेगा, बिजनस खोलेगा, कोई फैक्टरी खोलेगा, कोई और दुकान खोलेगा तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप आईटीआई पर ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद आईटीआई की बात हुई। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे परिवहन की सुविधा, परिवहन की हालत यह हो रही है कि पिछले दो-तीन साल से बसों का बिलकुल अभाव है और जो पुरानी बसें हैं वो रास्ते में खड़ी रहती हैं, सवारियों को उतार देती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोगों को

वापस प्राइवेट बसों में या और साधनों से जाना पड़ता है।

Kas/rtm/20.07.2024/14.30/2f

इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ग्रामीण बसें जो हमने बंद की हैं, उससे भी जनता को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीण बसों के हालात यह हैं कि पहले नादोती से टोडाभीम, टोडाभीम से गंगापंर, महावीर जी, मेहंदीपुर बालाजी, केलादेवी के लिये उनको एक आसान परिवहन का साधन मिलता था, उनके बंद होने से जनता को भारी नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि टोडाभीम से गंगापुर जिला हैडक्वार्टर है, वहां जाने का सीधा कोई साधन नहीं है, इस पर आपको रोडवेज की सीधी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ ही टोडभीम से महुवा सीधा जाने की बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी भी आप व्यवस्था करेंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है। टोडाभीम में आज तक बस स्टेंड नहीं बनाया गया है और उसके लिये जमीन भी अलॉट नहीं की गई है। अगर वहां जमीन अलॉट हो जाये तो वहां एक बस स्टैंड का निर्माण हो सकेगा, इससे यात्रियों को सुविधा होगी।

सभापति महोदय, हमारे समय में यूजी कॉलेजों में 'विद्या संबल योजना' के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। हमारी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा हर ब्लॉक स्तर पर महाविद्यालय, कॉलेज खोलने का प्रावधान रखा गया था। वहां कॉलेज व्याख्याता नहीं हैं। कहीं सिर्फ एक है, कहीं दो हैं, कहीं तीन हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इन व्याख्याताओं को जल्दी से जल्दी लगाया जायेगा तो आने वाले समय में उनको फायदा मिल सकेगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूं कि टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में हमारे कॉलेजों में कई व्याख्याताओं के पद खाली हैं, वहां भी व्याख्याता लगाने की व्यवस्था करें। वहां हमें जो जमीन का अलॉटमेंट हुआ है, वहां रास्ते में विवाद चल रहा है, उसको भी ठीक कराने का काम करें। प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों की स्थिति मैंने आपको अवगत करा दी। हमारे नादोती में आईटीआई कॉलेज पहले से चल रहा है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उसकी बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। उस बिल्डिंग को पुनः बनवाया जाये। नादोती के अलावा नांगल शेरपुर हमारी एक बड़ी जगह है। नांगल शेरपुर में आप आईआईटी कॉलेज खोलें, वहां टोडाभीम, नादोती, श्री महावीर जी, बालाजी, चारों तरफ के बच्चे उसमें आ सकते हैं, वहां चारों तरह रोड है। हमारे गुढ़ा चन्द्र जी में तहसील हैडक्वार्टर है, बालघाट में तहसील हैडक्वार्टर है, इन तहसील हैडक्वार्टरों पर अगर आप आईटीआई खोलेंगे तो इससे बच्चों को भारी फायदा मिलेगा। आपने मुझे इस मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रामस्वरूप जी लाम्बा। (अनुपस्थित), श्री विरेन्द्र सिंह जी। (अनुपस्थित)। श्रीमती शोभा जी चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी श्री भजन

लाल जी शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाने वाले सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखते हुए प्रदेश के युवाओं के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उल्लेखनीय व्यवस्थाएं की हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की घटनाओं से आहत युवाओं के लिए हमारी भाजपा सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने एवं रोजगार देने के उद्देश्य से 5 वर्षों में 4 लाख नई भर्तियां करने की घोषणा की है। इन युवाओं के लिए ना सिर्फ सरकारी नौकरीयों की घोषणा की गयी है, बल्कि इनकी कौशल क्षमताओं को विकसित करने हेतु नई योजना लाई गई है। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति-2024 लाये जाने की घोषणा की गयी है। इन युवाओं के सुरक्षित भविष्य हेतु हमारी वर्तमान भाजपा सरकार ने गहराई से चिंतन एवं मनन किया है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में पांच राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी, श्री आई माता कन्या महाविद्यालय सोजत सिटी, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय गुडा कलां एवं राजकीय महाविद्यालय देवली कलां संचालित है।

सभापति महोदय, इन महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति और मांग के बारे में मैं अवगत कराना चाहूंगी। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के रायपुर में वर्ष 2018 में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था। महाविद्यालय स्वीकृत होने से पूर्व उपखंड क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ब्यावर अथवा सोजत महाविद्यालय जाना पड़ता था, मगर अब रायपुर उपखंड मुख्यालय पर महाविद्यालय संचालित होने के कारण छात्र-छात्राओं को काफी राहत मिल रही है। इस महाविद्यालय में वर्तमान में 350 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। यह महाविद्यालय नेशनल हाईवे 162 पर स्थित श्री करणी माता प्राथमिक विद्यालय के भवन में संचालित है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल एवं अंग्रेजी विषयों का अध्ययन करवाया जा रहा है। इनमें से सिर्फ हिंदी एवं भूगोल विषय के ही व्याख्याता पदस्थापित हैं, बाकी पांच विषयों के व्याख्याता सहित प्रिसिंपल का पद विगत लंबे समय से रिक्त चल रहा है। स्वीकृत विषयों के व्याख्याता पद रिक्त होने के कारण विद्यार्थियों को अन्यत्र प्रवेश लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है और महाविद्यालय में नामांकन लगातार घट रहा है। विगत कार्यकाल में मेरी अनुशंसा पर डीएमएफटी मद से इस महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी। मेरे द्वारा इस भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया, तो पाया कि पांच वर्षों में पिछली कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता की वजह से बिल्डिंग अभी तक पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाई है। भवन परिसर में वृक्षारोपण किया जाकर भवन पूर्ण रूप से जल्दी ही तैयार हो जाये तो नवीन भवन में महाविद्यालय को स्थानान्तरित किया जा सके, ताकि वर्तमान में नेशनल हाईवे पर संचालित महाविद्यालय में विद्यार्थियों के आने जाने पर होने वाली दुर्घटनाओं

से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, रायपुर महाविद्यालय को स्वीकृत हुए 6 वर्ष हो गये हैं, लेकिन अभी भी यहां के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु अन्यत्र महाविद्यालयों में जाना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि रायपुर महाविद्यालय को हिन्दी एवं भूगोल विषय के साथ स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जाए। सभापति महोदय, रायपुर महाविद्यालय भवन कपूर्डी में स्थित खेल मैदान की जमीन पर किया जा रहा है। करोड़ों रुपये की 38 बीघा यह जमीन रायपुर ठिकाना श्री की ओर से विद्यार्थियों के लिए सिर्फ खेल मैदान उपयोग करने की शर्त पर निःशुल्क दान में दी गयी थी। महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए कस्बे के नजदीक एवं पर्याप्त जगह इसी कपूर्डी खेल मैदान में उपयुक्त होने के कारण रायपुर ठिकाना श्री की ओर से इस महाविद्यालय का नाम उनके पूर्वज सम्मानीय "श्री सज्जन सिंह जी राजकीय महाविद्यालय रायपुर" के नाम से नामकरण किये जाने की शर्त पर खेल मैदान भूमि पर महाविद्यालय निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी। सभापति अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ऐसे भूमि दानदाता के नाम से इस महाविद्यालय का नामांकरण किया जाए, ताकि सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन मिल सके।

सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत की देवली कलां में राजकीय महाविद्यालय एवं गुडा कलां में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किये। इस कांग्रेस सरकार ने जाते-जाते दो महाविद्यालय स्वीकृत तो कर दिये, मगर इनमें स्वीकृत 7 पदों पर ना तो कोई व्याख्याता नियुक्त किये ना ही प्राचार्य और ना ही संसाधन एवं आधारभूत संरचना की कोई व्यवस्था की। इन दोनों ही महाविद्यालयों में 'विद्या संबल योजना' से व्याख्याताओं की व्यवस्था की जा कर छात्र-छात्राओं को पढाया जा रहा है। गुडा कलां कन्या महाविद्यालय में इस वर्ष सिर्फ 72 आवेदन ही आये हैं। मेरा यह सुझाव है कि मगरा क्षेत्र में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में सह-शैक्षणिक व्यवस्था लागू कर दी जाए तो वहां के स्थानीय छात्रों को अन्य महाविद्यालयों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा व इससे महाविद्यालय में नामांकन भी बढेगा। विगत कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किये गये देवली कलां राजकीय महाविद्यालय में राजनीतिक द्वेषता की भावना रखते हुए प्रबंध समिति का गठन कर दिया। इस प्रबंध समिति को भंग कर पुनः नियमानुसार गठन उच्च शिक्षा विभाग से करवाया जाना भी सुनिश्चित कराया जाए। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से इस लोक कल्याणकारी भाजपा सरकार से, मंत्री जी से मांग है कि कांग्रेस सरकार की खामियों को सुधारते हुए उक्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों सहित सभी 7 रिक्त पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति करवायी जाए एवं महाविद्यालयों के लिए आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं की विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था करवायें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में राजकीय महाविद्यालय संचालित है। यह महाविद्यालय वर्ष 2006-07 में स्वीकृत हुआ था। इसमें वर्तमान में लगभग 1650 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस महाविद्यालय में 15 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं।

msk/rtm/20.07.2024/1440/2g

इनमें से 3 व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे है। प्राचार्य का पद भी रिक्त है। मेरी सरकार से मांग है कि प्राचार्य एवं रिक्त व्याख्याताओं के पद शीघ्र ही भरे जाएं, ताकि विधार्थियों को संबंधित विषय के अध्ययन हेतु कोई परेशानी न हो। साथ ही, इस महाविद्यालय के 3 व्याख्याता अन्यत्र स्थान पर प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अविलंब ही निरस्त करवायी जाए, ताकि इस महाविद्यालय में अध्यापन सुचारु हो सके। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस राजकीय महाविद्यालय हेतु स्नातकोत्तर में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय भी स्वीकृत किये जाएं। महोदय जी, यह भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत शहर के खेल मैदान की भूमि पर बनाया गया है और विद्यालय को इतनी ही भूमि दानदाताओं द्वारा विद्यालय खेल मैदान हेतु उपलब्ध करवा दी गयी, लेकिन जमीन महाविद्यालय के नाम से आज तक दर्ज नहीं हो पाने के कारण यूजीसी एवं अन्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान का लाभ इस महाविद्यालय को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि महाविद्यालय द्वारा मौका काबिज लगभग 5 हेक्टेयर भूमि इस महाविद्यालय के नाम दर्ज किये जाने हेतु अविलंब ही विभाग को आदेशित करवायें, ताकि महाविद्यालय को मिलने वाली अनुदान राशि निर्बाध रूप से मिलती रहे और महाविद्यालय एवं छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके।

सभापति महोदय, श्री आई माता कन्या महाविद्यालय में 600 छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन व्याख्याताओं के सभी 21 पद रिक्त हैं। राजशेष से नियुक्त व्याख्याताओं के द्वारा अध्यापन करवाया जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि कन्या महाविद्यालय में शौचालय एवं चार दीवारी निर्माण कार्य एवं रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ परम्परा के लिए मेरी ओर से कुछ सुझाव हैं। सभापति महोदय, युवा पीढ़ी देश का भविष्य होता है। महाविद्यालयों में पढ़ने वाला छात्र बचपन से निकल कर युवावस्था की ओर बढ़ रहा होता है और जमाने की हकीकत से दूर, अलग ही जोश में रहता है। पढ़ाई करते हुए मौज-मस्ती करने के बहाने कई छात्र अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं और माता-पिता की गाढ़ी कमाई बर्बाद करने के साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय भी गंवा बैठते हैं। इसका मुख्य कारण होता है महाविद्यालय में पनपने वाली नशे की प्रवृत्ति। कुछ समाजकंटक अवैध कारोबार से पैसा कमाने के लिए महाविद्यालय के छात्रों को ही नशे के आदी बनाकर उनका जीवन खराब कर देते हैं। शौक के रूप में शुरू किया गया नशा आगे जाकर उसकी मजबूरी बन जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक महाविद्यालय में जागरूकता शिविर लगाये जाए। नॉरकोटिक्स विभाग द्वारा भी छात्रों को सचेत किया जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को नशे की अवांछित गतिविधियों से दूर रहने की समझाइश के

साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें।

महोदय जी, महाविद्यालयों में शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाए, ताकि युवा मन में उद्दण्डता के स्थान पर भारतीय गुरुकुल परंपरा के साथ समाज एवं देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव कायम हो सके। महापुरुषों की जीवनी सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रखी जाए, सद्चरित्रों को गहराई से जीवन में उतारने के लिए भी सार्थक प्रयास किये जाएं। कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र अपने भविष्य के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं कर पाते है, सही मार्ग दिखाने के लिए काउंसलिंग सेन्टर की स्थापना भी महाविद्यालयों में की जाए।

सभापति महोदय, वर्तमान समय डिजिटल का है, इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाले प्रत्येक युवा को इससे जोड़ा जाए, इसके लिए प्रत्येक महाविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जाए। इन डिजिटल लाइब्रेरी में जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो, ज्ञानवर्धक अन्य पुस्तकों का भी समावेश हो।

मेरा यह भी सुझाव है कि महाविद्यालय में प्रत्येक अध्ययनरत छात्र को खेल से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क में सकारात्मक सोच का विकास होता है। इसलिए खेल के लिए प्रशिक्षित कोच भी नियुक्त किये जाएं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापतिः सहयोग करें।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): मैं आपके माध्यम से युवा पीढ़ी को दो लाइन कहना चाहूंती। एक मिनट साहब।

ऊंचे ख़्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है,

यूं नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन-रात जलना पड़ता है।

मैं एक बार परिवहन विभाग में यह कहना चाहूंगी कि बगडी नगर से जोधपुर एवं करमावास पट्टा से जोधपुर रोडवेज बस संचालित होती थी, विगत सरकार के कार्यकाल में उसे बन्द कर दिया गया। अतः सभी ग्रामीणजनों के लिए सुरक्षित एवं सुगम यात्रा हेतु बसों को पुनः प्रारम्भ करवाया जाए।

श्री सभापतिः श्री यूनुस खान जी।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): एक सेकण्ड, रायपुर बस स्टेण्ड पर जो आवागमन के लिए बसें आती थीं। वहां पर बसों को अन्दर नहीं ले जाकर, यात्रियों को बाहर ही हाई-वे पर छोड़ दिया जाता है, जिससे उनको असुविधा होती है। पुनः गांव के अन्दर की तरफ बस आने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगी कि उनका रूट निर्धारित कर आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप विभागीय कार्यवाही करें। पुनः धन्यवाद।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक माननीय सदस्यः यूनुस जी, एक मिनट। माननीय सभापति जी, विधान सभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 269 में पार्ट का 14 का उल्लंघन हो रहा है। बहुत सारे

माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा, 62-परिवहन, 24-तकनीकी शिक्षा पर आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनका और मुख्य मंत्री जी एवं वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्य मंत्री हैं, उन तीनों का मैं धन्यवाद करुंगा, इन्होंने राजस्थान लोक परिवहन सेवा को पुनर्जीवित किया है, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद। यह राजस्थान की जनता के हित में बहुत ही सुन्दर कदम उठाया है। उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करुंगा। दूसरा, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को भी, मैंने देखा कि हीरापुरा में मुख्य मंत्री जी का दौरा हुआ। मुझे लगा कि राजस्थान में ट्रांसपोर्ट में अब कोई न कोई क्रान्ति आने वाली है। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय विराज रहे हैं। इनसे मैं यहीं से आग्रह करुंगा कि हमने 2015 में राजस्थान लोक परिवहन सेवा शुरू की थी। पिछले पांच साल में, हो सकता है कि तत्कालीन मंत्री महोदय को कोई संशय रहा है, या तो वे राजस्थान के विषय को समझ नहीं पाये या इस रोडवेज का अध्ययन नहीं कर पाये, इसलिए उनको थोड़ी तकलीफ थी कि यह लोक परिवहन सेवा बन्द होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे हाथ में दो आंकड़े हैं। एक तरफ तो राजस्थान में आज की तारीख में सड़कों की लंबाई 3 लाख 9 हजार 497 वर्ग किलोमीटर है। मेरे पास दूसरा आंकड़ा है, रोडवेज जो चलती है, जब इनके पास 3157 रोडवेज बसें थीं तब ये 4729 किलोमीटर चलती थीं। मैंने आंकड़े देखे हैं, अभी इनके पास 2600 ही बसें बची हैं, इसका मतलब है कि ये लगभग 3500 किलोमीटर रोज चलती हैं। एक तरफ तीन लाख और एक तरफ 4 हजार किलोमीटर बसें चलती हैं। ये गेप को कौन पूरा करेगा? 1998 से लेकर 2023 तक इस रोडवेज की औसत बसों की संख्या 4 हजार रही है। हाइएस्ट 5700 रही है और अभी 2600 है।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज का ही दूसरा है। जब मैं 2003 में पहली बार मिनिस्टर था, तब डीजल के भाव 22 रुपये 74 पैसे थे, आज 90 रुपये प्रति लीटर भाव है। यानी डीजल बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज बढ़ गये। रोडवेज की बसें कम हो गयीं। 7th पे कमीशन लग गया। रोडवेज के जो खर्चे हैं, वे तो बढ़ते चले गये, लेकिन आय घटती चली गयी, क्योंकि बसों की संख्या घटती चलती गयी। इसलिए मैं सारे माननीय सदस्यों से आग्रह करुंगा, इधर बैठे हैं उनसे भी और उधर बैठे हैं उनसे भी। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जायेंगे। अभी मैं उनके परमिट भी देख रहा था कि इन्होंने जो परमिट दिये हैं। रोडवेज को 6696 परमिट दे रखें हैं, रोडवेज के पास बसें मात्र 2600 हैं। प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने 22 हजार 703 परमिट दे रखे हैं। आप देखिये, जब माननीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं और मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो हमने 22 हजार सड़कें इस राजस्थान में बनायीं। सड़कों की संख्या बढ़ रही है, परमिट की संख्या घट रही है। लोक परिवहन सेवा का जो कंसेप्ट था कि 476 मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो अधिकृत किये हुए थे, उनमें आपकी रोडवेज

बहुत कम मार्गों पर चल रही थी। अगर अपन उन आंकड़ों से आगे बढ़ें। जब मैं मिनिस्टर बना था तो नेशनल हाई-वे 7 हजार किलोमीटर था। अभी मैं नेशनल हाई-वे के आंकड़े देख रहा हूं। एनएच और जुड़ गया, 10789 किलोमीटर है।

mdp/rtm/20.07.2024/14:50/2h

अब आज दो एक्सप्रेस वे बन गये। दिल्ली से मुम्बई, इधर जामनगर से जालंधर तक। अब ये नेशनल हाईवे हैं, एक भी सिंगल परमिट नहीं है। जब तक आप इस परमिट के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, राजस्थान की जनता को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। माननीय मंत्री महोदय, ये लोक परिवहर सेवा क्या है? इसमें आप परमिट दे रहे हैं उसको। वह आपको रोडवेज के आधे किराये से सेवा दे रहा है। एसी की गाड़िया भी ले जा रहा है। इसके अलावा रोज के उस जमाने में 1 हजार रुपये आपको टैक्स भी दे रहा है। यानी 30 हजार, 35 हजार रुपये महीने का टैक्स भी दे रहा है। आपसे कुछ नहीं ले रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोडवेज बंद करो। आपकी जितनी मर्जी हो, सरकार की जितनी मर्जी हो, उतना रोडवेज को सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप कितनी-सी गाड़ियां दे रहे हैं? 500, तो 500 गाड़ियां तो कंडम हो जायेंगी, क्योंकि 8 साल की लाइफ हो गयी, दस लाख किलोमीटर गाड़ियां चल गयीं। जितनी आप दे रहे हैं, उतनी कंडम हो जायेगी। बसों की संख्या आपके पास वही रहनी है। इसलिए मेरा आपका स्वागत करने का मकसद यही था कि ये परियोजना जो उस समय, मैं किसी व्यक्ति की आज तक आलोचना नहीं करता, मैं उनके स्टेटमेंट पढ़ता था तत्कालीन मंत्री जी के, वह कहते थे कि इस लोक परिवहन सेवा को मैं बंद करूंगा। माननीय आप बंद करेंगे तो इस जनता को सुविधा कहां से देंगे?

आपने देखा नहीं कि उस समय परमिटों की संख्या, 22,703 परमिट तो प्राइवेट सेक्टर में चल ही रहे हैं। आपने ग्रामीण बस सेवा की बात की। ग्रामीण बस सेवा से पार नहीं पड़ने वाली। जयपुर के आसपास जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, उनमें आप लगायेंगे, फिर उनको वीजीएफ देंगे, वॉयबिलिटी गैप फंड उनको देंगे तो सरकार पर भार आयेगा। उससे बढ़िया है कि नये सिरे से सर्वे कराइए और सर्वे करवाकर इस राजस्थान लोक परिवहन सेवा को जिंदा कीजिए।

माननीय सभापति, जो हम दूसरा बिल लाये थे उस समय, राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण। यह 2000 में इसलिए लाये थे कि आज एयरपोर्ट्स हैं, उनका एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया बना हुआ है। उस पर आपके इंडिगो का भी चलेगा, उस पर एयर इंडिया का भी चलेगा, इंडियन एयरलाइंस का भी चलेगा और उस पर विस्तारा का भी चलेगा। सभी का चलेगा। जो चलायेगा, वह किराया देगा। अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि राजस्थान रोडवेज के पास में 111 बस हैं। मैंने कल भी कहा था कि 11,214 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी तो आपको बस टर्मिनल्स देने हैं। माननीय नगर निकाय मंत्री बैठे हैं। इनके भी 312 के करीब नगर निकाय हैं, वहां भी आपको टर्मिनल्स देने हैं। जब तक आप प्राइवेट को रोडवेज को एक बस अड्डे से नहीं चलाएंगे तब तक राजस्थान की जनता को आप बस

टर्मिनल की फेसिलिटी नहीं दे पाएंगे।

आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्टेट कैरिज ओर कांटेक्ट कैरिज की बसें चलती हैं, सिन्धी कैम्प के सामने देख लीजिए या इस शहर के आसपास देख लीजिए, हमारी बहिनें जब उन बसों में बैठती है तो न तो टॉयलेट की सुविधा है, न पीने के पानी की सुविधा है। इसलिए बस टर्मिनल्स पर आप ध्यान दीजिए। इसमें और बजट बढ़ाइए। आप रेवेन्यू कलेक्ट चाहे जितना कीजिए, लेकिन इस पर भी पैसा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत से लेकर, नगर निकाय से लेकर जयपुर तक आप बस टर्मिनल्स बनाइएं। उनको फेसिलिटेट करिए। अब जयपुर की जो समस्या है सिन्धी कैम्प से चलने वाली नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने, उस समय हमने एक जमीन दी थी, जेडीए का भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने लगभग 54 हजार मीटर जमीन दी थी, जिधर आपकी विधान सभा है, वहां हीरापुरा में स्थित है। उसमें 6 करोड़ रुपये लगाकर जो प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट था, चाहे वह जोधपुर डिविजन है, पाली डिविजन है, अजमेर डिविजन है, उदयपुर डिविजन है, जितने जिले थे, उनकी बसें वहां लगनी थी। विधाधर नगर में सीकर चूरू, झुंझुनूं, गंगानगर, बीकानेर की लगनी थी। सांगानेर में कोटा, झालावाड़, बारां इनकी लगनी थी। कल जेडीए ने एक मीटिंग की है, मैं अख़बार में पढ़ रहा था, वह लैंड है आपकी ट्रांसपोर्ट नगर में, इस शहर का इतना विस्तार हो गया कि अब सिन्धी कैम्प को केन्द्र बिंदु मत मानिए, अब आप जो जिले जिधर हैं उनको उधर बस की सुविधा दीजिए। उनको सिटी में कनेक्टिविटी दीजिए, तब आपका ये बस प्राधिकरण वाला सक्सेस होगा, आपके पास रेवेन्यू आयेगा। जिसको बस लगानी है, जैसे हवाई जहाज लगता है विस्तारा का, तो उसको किराया देता है और उसी से वह चलता है। यात्री के किराये में जुड़ा हुआ है।

मेरा निवेदन है कि पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ गये, आप इन बसों को चला नहीं पाएंगे। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करके राजस्थान लोक परिवहन सेवा को जो जिंदा किया है, उसमें आप परमिट्स ईमानदारी से दीजिए। जहां आवश्यकता है, माननीय सब जन-प्रतिनिधियों से पूछ लीजिए और आप चिट्ठी लिखिए इनको कि आपको कहां-कहां बसों की आवश्यकता है। इनके कहने से नये रूट्स खोलिए और उन पर परमिट दीजिए। वह आपको पैसा देंगे। वह आपको परमिट का पैसा भी देंगे और जहां बस टर्मिनल पर खड़ा करेंगे, उसका भी पैसा देंगे।

मैं आपका बजट देख रहा था। बजट में तो आपको जीरो कर दिया इन्होंने। बिलकुल जीरो कर दिया। इस सेक्टर में अबकी बार ये आते-आते नीचे चले गये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि आपके ट्रांसपोर्ट में एक ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक बने। अभी जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक है, वह आपके खाली 39 बने हैं, जबकि आपके 58 डीटीओ ऑफिस हैं। 58 के 58 में बन जाने चाहिए। इस पर आप फोकस कीजिए, दबाव में मत आइए। इसमें दो तरीके के लोग दबाव डालेंगे। एक तो दलाल और एक आपके डिपार्टमेंट के डीटीओ और इंस्पेक्टर दबाव डालेंगे, क्योंकि उनकी ऊपर की कमाई रुकती है। इसलिए बिना किसी की

परवाह के इसको आप स्ट्रेंथन कीजिए। आपके पूरे डीटीओ ऑफिस में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक बनाइए।

एक हमने एचएसआरपी, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को चालू किया था। इसकी लड़ाई मैं 2004 में लड़ने लगा था। 2018 में हमें सफलता मिली। जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 है, उसके सेक्शन 50 में हमने माननीय गडकरी जी से परिवर्तन करवा कर इसको लागू करवाया था। इसमें बहुत ज्यादा खास चीज नहीं है। हमने कहा कि मेन्यूफेक्चरर जो है वह प्लेट लगाकर देगा। भाई, ढ़ाई करोड़ की गाड़ी बना कर दे रहा है, वह डेढ़ सौ रुपये की प्लेट नहीं लगायेगा, प्लेट लगाकर देगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका, जो उस गाड़ी को बेचता है, वह उसको कम्पोज करके हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाकर देगा। लेकिन क्या हो रहा है? सियाम को काम दे दिया। क्यो दे दिया? वह तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आपके अभी नोटिस में नहीं आया।

मैं अभी डीडवाना में था। मैंने पूछा ये प्लेट कितने में लगा रहे हैं? आप आश्चर्य करेंगे सीकर से प्लेट बनकर आती है और एक प्लेट के जिसके 150 रुपये आपने कर रखे हैं, उसके 1700 रुपये ले रहे हैं। इसका मतलब राजस्थान में कितने लोग लुट रहे हैं, इसकी कल्पना कीजिए। इस एचएसआरपी पर इतनी बड़ी लड़ाई राजस्थान में लड़ी। राजस्थान लीडर था इनोवेशन का। हमने पहली बार जो गाड़ियां बेचते हैं डीलर, डीलर को रजिस्ट्रेशन का पावर दिया। राजस्थान पहला राज्य था जिसमें स्मार्ड कार्ड लाए। राजस्थान पहला राज्य था जिसने एचएसआरपी को मोडिफाॅइ करके लगाया। राजस्थान पहला राज्य था जिसने लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन किया। आज तो जो फेसिलिटी आप देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि चाहे हमारा स्मार्ट कार्ड हो, चाहे हमारा लाइसेंस सिस्टम हो, चाहे बस टर्मिनल हो, चाहे एचएसआरपी हो या फिट सेन्टर हो, राजस्थान पहला राज्य था जिसने पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए राजस्थान के सारे पेट्रोल पम्प को अधिकृत किया, जिससे लोगों को जगह-जगह नहीं जाना पड़े। पेट्रोल पम्प वालों ने बंद कर दिया, जबकि उनके लिए ये मेंडेटरी है।

आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी वेन खड़ी है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो राजस्थान लीडर था और आप तो लीडर हैं ही, उप मुख्य मंत्री हैं, भले आदमी है तो मुझे उम्मीद है कि इन एक-एक विषय को समझकर इसको लागू करने का काम आप करेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो लोगों के कंफ्यूजन है रोडवेज का (समय सूचक घंटी) बस मैं तो कन्क्लूड कर देता हूं। मैं तो सरकार को राय दे रहा हूं। मेरी तो कोई मांग है नहीं। दो मिनट दे दीजिए।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, बहुत सीरियस होकर आपकी सारी राय नोट कर रहे हैं।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): मैं आपकी अनुमति, चीफ व्हिप और मंत्री महोदय की अनुमति से ही बोल रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा दो ही मिनट दे दीजिए। एक सबसे बड़ा जो इश्यू है वह है एक्सीडेंट डैथ। आप देखिए कि लास्ट इयर 2023 में 11,762 लोग मर गये। धीरे-धीरे ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको भी आप साथ-साथ

फोकस कीजिए क्योंकि जब माननीय वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं और गडकरी जी के निर्देश पर राजस्थान में धीरे-धीरे जागरूकता लाकर डैथ में कमी की थी। इस पर भी आप फोकस कीजिए। जो आपका बस टर्मिनल बन रहा है, शायद 15 अगस्त पर सरकार इसका उद्घाटन करेगी। आप उद्घाटन बेशक कीजिए, लेकिन जिस परपज से इसको लिया गया था, ये राजस्थान का वह बस टर्मिनल बने जो हमारे पूरे राजस्थान में नहीं है।

सभापति महोदय, दो मिनट मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। डीडवाना विकास परिषद समिति एक कॉलेज चलाती है पीपीपी मॉडल पर। माननीय वसुन्धरा जी ने 12 हजार मीटर जमीन इसमें दी। हमने 23 करोड़ रुपया लगा कर कॉलेज बनायी और आज 2000 बेटियों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि माननीय गहलोत साहब के समय में स्थानीय एमएलए और खुद माननीय गहलोत साहब हमारे पीछे पड़े इस संस्था के और उस पर 62 लाख की तो पेनल्टी ठोकी, जो निःशुल्क शिक्षा दे रही है और इस कॉलेज को अधिग्रहण करने का, माननीय मंत्री महोदय, इसकी बिल्डिंग को देखिए।

श्री सभापतिः प्लीज, सहयोग कीजिए। श्रीमती इन्द्रा जी।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): इन्द्रा जी, दो ही मिनट। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कॉलेज को भी आप बचाने का काम कीजिए।

Ans/rtm 15.00 2j 20.07.2024

दूसरा, मैं कहूंगा कि 10 करोड़ रुपये से हमने डीडवाना में रोडवेज का बस स्टैण्ड बनाकर दिया। जमीन दी, 10 करोड़ खर्च किए। उसको भी राजनीतिक द्वेष के कारण शिफ्ट नहीं होने दिया। मेरा आग्रह है कि डीडवाना का बस स्टैण्ड है उसको..

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सहयोग करे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): उच्च शिक्षा मंत्री होने के कारण आप कॉलेज पर फोकस करिए।

श्री सभापतिः श्रीमती इन्द्रा।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, इसमें यह है कि राजनीतिक प्रताड़ना हुई..

श्री सभापतिः प्लीज, आप इनसे मिल लेना।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय, आपने समय दिया, आज थोड़ा ज्यादा दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24 तकनीकी शिक्षा और मांग संख्या 62 परिवहन पर बात रखने का मौका दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी, सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि जिस तरीके से पांच सालों के अन्दर

हमने देखा, उससे पहले की सरकार हमने नहीं देखी। पिछले पांच सालों में हमने जो देखा चाहे उच्च शिक्षा का मामला हो, चाहे तकनीकी शिक्षा का मामला हो, राजस्थान सरकार ने ऐसे-ऐसे काम किए जो युवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। चाहे अनुप्रति कोचिंग योजना हो, जिसमें बच्चों को 30 हजार रुपये फ्री कोचिंग के लिए दिए गए। 500 बच्चों को विदेश भेजने की बात हो, चाहे नीट में 20 हजार रुपये स्कॉलरशिप मिलने की बात हो। रोजगार के लिए 100 मेगा जॉब फेयर लगाकर, रोजगार के मौक़े दिए गए। 21 मेगा जॉब में 70 हजार युवाओं का चयन किया गया, उसी प्रकार कॉलेज खोले गए।

आप कॉलेज खोलने की बात करते हैं। कॉलेज तो खोल दिए लेकिन उसमे व्यवस्थाएं नहीं की गई। शिक्षक नहीं लगाए गए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जब किसी मकान की नींव रखी जाती है, पहले नींव रखी जाती है फिर मकान तैयार होता है, फिर उसका प्लास्टर होता है, फिर उसकी साज सज्जा होती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूँ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बौंली में जनरल कॉलेज दिया। आईटीआई कॉलेज बौली के अन्दर दिया। महिला कॉलेज मित्रपुरा में दिया। आंधी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां महिला कॉलेज दिया। यह वहां के क्षेत्र के लोगों की मांग थी उस समय। वहां बिल्डिंग्स बन गई है। सारे सुचारु रूप से चल भी रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी है वह आप पूरी कर देना। बाकी तो कहां कमी है, कॉलेज किसको बुरे लग रहे हैं। आज एक किलोमीटर कोई पैदल नहीं चल सकता। पहले एक टाइम था जब बच्चे 10-10 किलोमीटर चलकर भी पढ़ाई करते थे। आज आवश्यकता है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है।

सदन में हमारे सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि आनन-फानन में इतने कॉलेज खोल दिए। उन लोगों से जाकर पूछिए, उनके पेरेंटस से जाकर पूछिए कि वे कितने खुश होते हैं। आज मेरे एरिया से कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने कहा कि साहब अब कॉलेज बंद करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई बंद नहीं करेगा, बिल्डिंग तैयार हो गई है। इस तरह की भ्रांति राजस्थान में लोगों को सुनाई देती है। सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं। दुबारा उसका सर्वे कराने की बात करते हैं। बंद करने की बात करते हैं, इससे स्टूडेंट चिंतित होते हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी विराजमान है, उच्च शिक्षा मंत्री जी का चार्ज इनके पास है। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस तरह की बातें नहीं आए, ताकि बच्चे गुमराह नहीं हो और बच्चे अपनी पढ़ाई करे।

माननीय सभापति महोदय, देश और प्रदेश में संविधान निर्माताओं द्वारा आरक्षण व्यवस्था लागू कर, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का रास्ता दिया। इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की गई, जिसमें कई वर्गों को आरक्षण का लाभ मिला। आरक्षण सही तरीके से मिलता रहे। लेकिन आज दिनांक तक बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें रोस्टर रजिस्टर संधारण नहीं हो पाया। यहां सत्ता पक्ष के सदस्य बैठे हैं, उन लोगों को भी याद दिलाना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी और मैं विधायक थी, उस समय भी मैंने रोस्टर का मुद्दा उठाया। एससी, एसटी के बालकों का मुद्दा उठाया और हर

समय उनके लिए तैयार रही। हमारी सरकार के सामने भी कुछ कहना पडा तो मैंने कहा। ऐसा नहीं किया कि हमारी सरकार है तो हमें कुछ मुद्दों पर दबना चाहिए।

भर्तियां किस आधार पर निकाली जा रही है, इसका कोई पता नहीं है। मनमर्जी से भर्तियां निकाली जा रही है। उनका परिणाम है कि प्रदेश में सबसे बड़े विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 30 विभाग, जिनमें मात्र 5 विभाग में ही विभागाध्यक्ष आरक्षित वर्ग के हैं। क्या यह हमारी भागीदारी है, हिस्सेदारी है? एससी, एसटी के वर्गों के लिए यह सही है?

मान्यवर, हाल ही में यूजीसी ने फिर से 31 जुलाई तक रोस्टर रजिस्टर बनाकर ऑन लाइन, मैं सरकार से मांग करती हूं कि 31 जुलाई तक कर दे। तय सीमा में बनाने के लिए आदेश जारी करे, जिससे सभी आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ हो सके। 2021 में रोस्टर के अभाव के कारण आरक्षित वर्ग के कम पद निकाले गए, जिससे आम छात्रों को नुकसान हुआ, यह आप सबको पता है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 में उच्च शिक्षा में पीएचडी कर रहे हज़ारों छात्रों को जिनको कोई फैलोशिप नहीं मिल रही, उनके लिए रिसर्च फैलोशिप स्कीम फॉर पीएचडी स्टूडेंड चालू की थी, जिसके लिए आवेदन मांग लिए फिर आचार संहिता लग गई, जिस कारण बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। शिक्षा विरोधी सरकार ने आज तक किसी भी विद्यार्थी को फैलोशिप नहीं दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर अनुरोध करना चाहूंगी कि शीघ्र ही फैलोशिप जारी कर हज़ारों ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र-छात्राओं को राहत प्रदान करने का कार्य करे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 310 महाविद्यालय खोले। जिनमें शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्या सम्बल योजना चलाई गई जिसमें नियुक्ति एक वर्ष के लिए एपीआई स्कोलर के आधार पर शुरू की गई। जिसमें 1500 के लगभग नीट, जेआरएफ, पीएचडी, डिग्री धारी बेरोजगारों को रोजगार मिला। इन योग्यधारी युवाओं से सरकार हर महीने 6 आवेदन मांग रही है, जो कि गलत है। प्रदेश में नई नीति लागू होने के कारण सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है,जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। अब दुबारा नियुक्ति की प्रक्रिया से समय खराब होता है, इसलिए इसे बंद कर साल में एक बार आवेदन किया जाए। साथ ही मैं मांग करती हूं कि इन कॉलेजो में पढ़ाने वाले अतिथि सहायक आचार्य को अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाए, जो उनके भविष्य में काम आ सके।

मान्यवर, वर्तमान सरकार विचार कर रही है कि पिछली सरकार द्वारा खोले गए विद्यालयों को बंद कर दिया जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा। जो मेरी पार्टी का विरोध करते हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि अगर उनकी बंद करने की मंशा है तो बंद कर दिया जाए। अगर नहीं करने की मंशा है तो इस तरह की बातें नहीं फैलाई जाए। दूर-दराज गांव व ढ़ाणी में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की हमारी सरकार की मंशा थी। आज स्थिति यह है कि गरीब किसान के बच्चे, उन कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको इससे काफी

लाभ मिल रहा है।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाए जा रहे हैं। पहले हमने स्कीम लागू की थी, ताकि युवा संविधान को जाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, लेकिन भाजपा की मंशा संविधान विरोधी है, आप सबको पता है। आप देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय व जोधपुर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क में संविधान को ही बदलकर अपनी मनमर्जी से क्या लिख दिया, जिससे उद्घाटन माननीय राज्यपाल और शिक्षा मंत्री जी कर आए उसके लिए।

VPS-RTM-20.07.2024-15.10-2k

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): उसमें गलत लिख दिया। हां, गलत लिख दिया।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): हां, गलत लिख दिया। मैं धन्यवाद देती हूं देश की जनता को। उसमें आपने गलत लिख दिया। मैं धन्यवाद देती हूं देश की जनता को जिन्होंने 400 पार के नारे को मिट्टी में मिला दिया।

श्री सभापति: मैडम, आप अपनी बात को समाप्त करें, सहयोग करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अगर आप संविधान पार्क को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो तो संविधान को बदल दो, आपकी सरकार है राज्य में और वहां पर। अब आप लोग तो कह रहे हैं कि 400 पार कराओ लेकिन सर, जनता तो मान ही नहीं रही है न आपकी बात को। वह क्यों मानेगी?

माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद के क्षेत्र की थोड़ी सी मांग निवेदन करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में परिवहन की बात करूं तो परिवहन के क्षेत्र में हमारे यहां पर काफी सारी बसें जो बौंली से जयपुर आती थीं, पीपलवाड़ा से जयपुर आती थीं और जो अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां से जयपुर आती थी। मित्रपुरा एरिया से भी आती थीं, लेकिन वे सारी की सारी बसें आज की तारीख में बंद हैं। बामनवास से कोई भी परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है आज की तारीख के अन्दर, तो मैं यह अनुरोध करना चाहूंगी कि इस पर विचार किया जाये और जो बसें बंद कर दी गयी हैं उनको वापस से चालू करवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, वैसे मुझे समय ज्यादा चाहिए था पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कुलदीप।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 एवं 62 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जो एक विशेष बिंदु राजस्थान का है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। अभी मैंने सभी सदस्यों को सुना है उच्च शिक्षा के ऊपर और विशेषकर एक बिंदु निकल कर आया, यह राजसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अशोक गहलोतजी की सरकार में 2022 में लगभग 330 कॉलेज खोले गये और जिसमें 278 कॉलेज

तो अभी किराये के मकानों में चल रहे हैं। चाहे वह सरकारी स्कूल है, चाहे अन्य कोई प्राइवेट भवन है, उनमें अब तक संचालित होते आ रहे हैं और यह राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने हमारे प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक किसान का बेटा हूं, गांव और ढाणी से निकल कर आता हूं। हमेशा हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं लेकिन जितने भी हमारे सदन के सदस्य हैं, मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं कि जहां पर शिक्षा की बात चलती है, जहां पर परिवहन की बात चले या अन्य कोई विषय निकल कर आते हैं तो मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि जो सत्यता है, उस पर हमें बात कहने की आवश्यकता है। मेरे यहां पर राजसेस के महाविद्यालय खोले गये। एक पावटा में खोला जिसमें 200 सीट स्वीकृत थे। अबकी बार मेरे यहां आवेदन 668 छात्रों ने किया है और मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत विडंबना है कि आजादी के बाद भी आज 77 साल निकल गये लेकिन आज भी हमें शिक्षा की बात करनी पड़ती है, हमें प्राध्यापक लगाने की बात करनी पड़ती है, हमें प्राचार्य लगाने की बात करनी पड़ती है। हमें पीने का पानी मांगना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पावटा राजसेस का जो हमारा महाविद्यालय कांग्रेस की सरकार ने खोला उसमें मात्र एक प्राचार्य का पद भरा हुआ है बाकी एक भी अन्य पद पर किसी व्यक्ति को नहीं लगाया गया है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अभी हमारे कई कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमारी सरकार ने यह किया, हमारी सरकार ने राजसेस के कॉलेज खोले तो मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता, आपको प्रणाम भी करना चाहता हूं आपकी सरकार को भी कि आपने ऐसे कॉलेज खोलकर हमारे प्रदेश के जो नौजवान थे, उनके साथ आपने ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक मात्र प्राचार्य कैसे कॉलेज को चला सकता है? माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से यह आग्रह करूंगा कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए। तत्काल प्रभाव से वहां पर हमारे प्राध्यापक भी लगे, अन्य स्टाफ भी लगे।

दूसरा विषय में इसी सदन में रखना चाहता हूं कि बाबा भगवानदास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा का, वहां पर भू-गर्भ शास्त्र, जियोलॉजिकल विषय राजसेस सोसायटी के अंतर्गत संचालित कॉलेज है और मैंने यह पूरा रिकार्ड मंगवाया और मैंने देखा है तो मुझे इस बात के लिए अफसोस हो रहा है कि आखिर में पहले की सरकार कर क्या रही थी? मैं पहले की सरकार पर इसलिए सारा भार डालना चाह रहा था क्योंकि हमारी सरकार ने अब तक सात महीने में आने के बाद एक भी किसी कर्मचारी को, अधिकारी को वहां से हटाया नहीं है। जो कांग्रेस के शासन के समय में प्राध्यापक थे, वे ही अभी काम कर रहे हैं, जो प्राचार्य थे वे भी अभी काम कर रहे हैं और अन्य जो सहयोगी स्टाफ था, वह भी अभी काम कर रहा है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर 67 पद स्वीकृत थे यहां चिमनपुरा की कॉलेज में, जिसमें से 31 पद रिक्त चल रहे हैं और मुझे यह बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि 31 में से भी आप यह देखिये कि लगभग 24 लोगों को जयपुर डेपुटेशन पर

लगा रखा है। यह मेरी समझ से परे है कि आखिर में हमारे छात्रों के भविष्य का होगा क्या? इसलिए मैं माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से यह कहना चाहता हूं कि इसमें तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए और जितनी भी प्रतिनियुक्तियां की गयी हैं जयपुर में उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त भी किया जाना उचित होगा। माननीय सभापति महोदय, इस महाविद्यालय में 1600 छात्र अध्ययनरत हैं।

अगला महाविद्यालय जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कला वर्ग का, जैसा कि पावटा का जिक्र अभी किया और साथ ही मेरे विराटनगर में महाविद्यालय कांग्रेस के शासन में, गहलोतजी की सरकार ने खोला था, विज्ञान संकाय इसमें है, एम.ए. भूगोल विषय राजसेस के अंतर्गत संचालित है तो आखिर में इन कॉलेजों को खोलने का उद्देश्य इनका था क्या? स्टाफ इनके पास नहीं है, भवन इनके पास नहीं है और मुझे यह कहते हुए बड़ी तकलीफ भी इसलिए हो रही है कि जिस इलाके से हम लोग आते हैं, जनता ने हमें यह दायित्व दिया है और हम पर ढाई लाख जनता ने भरोसा करके राजस्थान की विधान सभा में भेजने का काम किया है तो आखिर में हम करेंगे क्या?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यह दोनों कॉलेज जो राजसेस के कॉलेज कांग्रेस के शासन में खुले, उनके शिलान्यास भी हो गये, उनके उद्घाटन भी हो गये पर आज तक इनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो ऐसे हालात कांग्रेस की सरकार ने किये और फिर यह कहा जाता है कि भाजपा के सारे के सारे सदस्य हम पर आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने यह नहीं किया, भाई, किया तो आप लोगों ने, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो शुरूआत है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि जो सच्चाई है, उसके साथ हमेशा जाना चाहिए। यह प्रदेश की जनता आपको और हम सबको देख रही है। चुनाव आना-जाना तो एक सिस्टम का हिस्सा है, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं लेकिन सदन में आखिर में हम बातचीत करते भी क्या है? एक दूसरे का विरोध करना लेकिन आप कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाकर लाते, आपके नॉर्म्स के आधार पर हमारे कोई कॉलेज खोले होते।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर ऐसे-ऐसे कॉलेज की हालात है, एक जगह पर 11 पद थे उनमें से 6 रिक्त चल रहे हैं और कुछ को डेपुटेशन पर जयपुर लगा रखा है इसलिए यह मेरा गम्भीर आरोप कांग्रेस सरकार पर है, जो पहले की पांच साल की सरकार थी उस पर है और मैं प्रदेश के माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में हमारे यह जो तीनों महाविद्यालय हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति जयपुर में या अन्य किसी स्थान पर की गयी है, वह तत्काल प्रभाव से निरस्त होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बाबा भगवानदास राजकीय महाविद्यालय, आप यह देखिये कि यह कितना पुराना महाविद्यालय है, 1982 का है, एक कृषि संकाय इसमें संचालित हुई थी और 2016 में कला संकाय का अलग कॉलेज खोला

गया था। इतना बड़ा जहां पर त्रिवेणी धाम का हमारा मन्दिर है, जहां संत शिरोमणि नारायणदासजी महाराज की जन्म-स्थली है, ऐसी हमारी यह पौराणिक नगरी है, ऐसी हमारी पूज्य स्थली है, इतना पुराना वहां महाविद्यालय है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि 4500 छात्र वहां पर अध्ययनरत हैं और दोनों कॉलेज जो हमारे बने हुए हैं, बाबा नारायणदास कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग नौ करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया है लेकिन आज तक वह भवन धूल चाट रहा है तो मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि डिप्टी सी.एम. साहब इस पर भी कार्यवाही करें।

साथ ही, जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय, पावटा का स्नातक स्तर का जो हमारा यह कॉलेज पूर्ण रूप से जो राजसेस में चला गया था इसको वापस पुन: महाविद्यालय के रूप में, जो तीनों हमारे राजसेस के महाविद्यालय है, इनको इसमें जोड़ा जाना उचित होगा।

मैं मांग संख्या 24 पर हमारे डिप्टी सी.एम. साहब से यह आग्रह करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में एक भी तकनीकी शिक्षा का संस्थान हमारे यहां पर नहीं है क्योंकि पहले हम जयपुर जिले में आते थे और अब हमारा जिला कोटपूतली-बहरोड़ जिला हुआ है। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में होना चाहिए। मैंने यह पहले भी कहा था कि विराटनगर की धरती, यह ऐसा स्थान है जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया है।

SSY/RTM/20.07.2024/15:20/2I

जहां सम्राट अशोक ने 300 दिन रहकर आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का काम किया था। मैं माननीय डिप्टी सीएम से आग्रह करता हूं कि यह कॉलेज ऐसे स्थान पर खोला जाये। हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत जो हमारी लोक सभा है, उसमें भी विराटनगर का उल्लेख किया गया है।

साथ में जो एक महत्वपूर्ण स्कीम पूरे देश में चल रही है। हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा स्किल डवलपमेंट के बारे में मैं बात रखना चाहता हूं। स्किल डवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। जो हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है, उसका सबसे बड़ा कारण है, अगर हम कौशल विकास की बढ़ोतरी करेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो अच्छा होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में एक मात्र विश्वविद्यालय जयपुर में है। अगर कौशल विकास के हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जिला स्तर पर संचालित होंगे तो मैं समझता हूं कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है क्योंकि आपने इसी राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है। आपने डॉक्टरेट यहां से की। आपका शिक्षा से बड़ा लगाव है। मैंने आपको बहुत बरसों से देखा है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह जो 2-3 विषय हमारे थे, इसमें प्रदेश की समस्या भी है। इसको मैं आपके सामने रखना चाहता

हूं।

साथ ही, परिवहन की बात चल रही थी। यूनुस खान जी ने एक बहुत अच्छा विषय रखा है। राजस्थान रोडवेज की हालत क्या है? कांग्रेस के 5 साल के शासन में डिपो की जो बर्बादी हुई है, राजस्थान रोडवेज की जो बर्बादी हुई है, उसको हमें भी ठीक करने में बहुत बरस लग जायेंगे।

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री कुलदीप (विराटनगर): सभापति महोदय, 2 मिनट का विषय है। मैं सुदूर ढाणी से निकलकर आता हूं। मेरा दायित्व बनता है कि मैं मेरे क्षेत्र की जो बड़ी समस्याएं हैं, बहुत लंबी-चौड़ी थी, लेकिन डिप्टी सीएम साहब आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि विधान सभा विराटनगर एक ऐसा इलाका है जो 4 भागों में बंटा हुआ है। दिल्ली में हमारे यहां से बहुत लोगों का आना-जाना होता है। जयपुर में बहुत लोगों का आना-जाना होता है। अजमेर, नागौर में हमारे यहां की बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। रोडवेज तो हमारे यहां चल रही हैं, लेकिन मैं सभी बसों के राउंड बढ़ाने के लिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं। इनके राउंडों को बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: प्लीज माननीय सदस्य, मंत्री महोदय से बात कर लेना। श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री कुलदीप (विराटनगर): इसी अपेक्षा के साथ कि माननीय डॉ. प्रेम जी बैरवा मेरी सभी मांगों पर गौर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22, 24, 62 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज की मांग बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और परिवहन पर मैं बात रखूंगा। वर्तमान बजट की तुलना में हमने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में अद्भुत कार्य किये। वह इस बजट में कहीं पर भी कोई कार्य या घोषणा नजर नहीं आई। हमारी सरकार ने कोचिंग, विदेश में नि:शुल्क शिक्षा, स्कॉलरशिप, मेगा जॉब फेयर, डिजीटल लाइब्रेरी युवा विकास कल्याण कोष 500 करोड़ रुपये से बनाना, हर जिले के अन्दर एक आईटीआई नर्सिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज खोले गये थे। नये कॉलेजों की इमारतें बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपये का बजट भी दे दिया गया था। यह हमारी पूर्ववर्ती सरकार में अशोक जी गहलोत ने महत्वपूर्ण फैसले किये थे।

हमारी सरकार में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, 2018 तक प्रदेश में 250 राजकीय महाविद्यालय थे, 223 सामान्य शिक्षा व 15 विधि शिक्षा के थे। जिसमें 203 सह शिक्षा और 47 कन्या महाविद्यालय थे। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 309 नवीन राजकीय महाविद्यालय मात्र 5 सालों के अन्दर खोले गये। जिसमें 132 कन्या एवं 4 म्युजिक शिक्षा के महाविद्यालय हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार राजकीय महाविद्यालयों में 1309 योग्य सह आचार्य को प्रमोशन के पद पर पदोन्नत किया गया था।

हमारी सरकार में छात्राओं के लिए काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत 21,458 स्कूटियां वितरित की गई थी। देवनारायण स्कूटी योजना में 3,937 स्कूटियां वितरित की गयी, ताकि बच्चियां अपने घर पर स्कूटी पर जा सकें। असहाय और गरीब बच्चियां, अन्य जो भी हैं। युवाओं के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किये। अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से 30 हजार बच्चियों को फ्री कोचिंग दी गई थी और 500 बच्चियों को विदेश में नि:शुल्क शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने भेजने का निर्णय लिया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल संपत्ति की शर्त को हटाया गया। इससे राजस्थान में केन्द्र सरकार की तुलना में 3 गुना से अधिक ईडब्ल्यूएस के प्रमाण-पत्र जारी हुए। ईडब्ल्यूएस के परीक्षार्थियों को आयु सीमा में छूट दी गई।

हमारी सरकार में एक महत्वपूर्ण फैसला पेपर लीक पर उम्र कैद की सज़ा का कानून बनाया गया। पेपर लीक जांच के लिए एसटीएफ बनाई गई। नई कॉलेजों की इमारतें बनाने के लिए करीब 1800 करोड़ रुपये का बजट दिया गया। जिसमें 250 कॉलेजों की इमारतों का काम चल रहा है। 50 कॉलेजें संपूर्ण हो गयी हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण फैसले पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने शिक्षा के प्लेटफार्म पर लिये थे, जितनी कॉलेजें प्रदेश में खोली, इतिहास में इतनी कॉलेजें, विश्वविद्यालय या सब्जेक्ट नहीं खोले गये। जो प्राइवेट कॉलेज वाले मनमानी फीस ले रहे हैं, इन पर आप जरूर अंकुश लगायें।

माननीय सभापति महोदय, मकराना में महाविद्यालय को लेकर कुछ हमारी मांगें हैं। मकराना में 4 साल पूर्व ही कॉलेज की घोषणा हो गई थी। वह चल भी रहा है। अभी वह महाविद्यालय हमारे यहां हायर सैकण्डरी स्कूल, मकराना के अन्दर चल रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभापति महोदय, 115 में से सत्ता पक्ष के 10 आदमी भी नहीं हैं। इससे गंभीरता का पता लगता है। हम चले जायेंगे तो कोरम भी नहीं रहेगा। यह हालात हैं आपकी सरकार के ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बोलिये। सब सदस्य यही हैं। सब आ जायेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप बुलाओ सभी को, खाली उप मुख्य मंत्री बैठे हैं। जिनकी मांग हैं वह हैं ही नहीं।

श्री सभापतिः आपका सदस्य बोल रहा है। आप सीनियर सदस्य हैं।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मेरा टाइम देख लो, यह बीच में बोल लिये।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मकराना में 4 साल पहले कॉलेज खुला था। वहां अभी कॉलेज की भूमि नहीं है। ढाणी के अन्दर कॉलेज की भूमि के लिए एसडीओ ने वहां पर स्वीकृति दी। लेकिन वहां पर कोर्ट का स्टे आने की वजह से भवन नहीं बन रहा है। अभी हमारे वहां हायर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर कॉलेज चल रहा है। एक तो आप वहां पर अधिकारियों, कलेक्टर को बोलकर कोर्ट में पैरवी करायें क्योंकि कोर्ट की जब-जब पेशियां होती हैं, तब वहां कोई सरकारी वकील खड़ा नहीं होता है। आज तक उसका

निस्तारण नहीं हुआ। वहां नया भवन बनाया जाये।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जितने भी रिक्त पद पड़े हैं, वे सारे के सारे रिक्त पद कॉलेज के अन्दर भरे जायें। अभी केवल आर्ट्स का विषय संचालित हो रहा है। हमारे वहां बच्चों की मांग है कि विज्ञान, कॉमर्स, सामाजिक शास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट भी खोलें ताकि मकराना में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

आईटीआई, तकनीकी शिक्षा में मैं यह बोलना चाहता हूं कि बजट भाषण 2010-11 के अन्दर मकराना में आईटीआई कॉलेज की घोषणा हुई थी। जमीन के अभाव में आज तक वह बनी नहीं है। आप कलेक्टर, एसडीएम को बोलकर जहां भी जमीन मिले वहां पर आईटीआई कॉलेज खुलवाने की घोषणा करें।

दूसरी बात, मैं आपको कहना चाहता हूं परिवहन के बारे में, यह राज्य सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है, जो एक-दूसरे व्यक्ति को, एक-दूसरे गांव, शहर में जाने के लिए होता है। 3 साधन होते हैं। एक तो होता है हवाई, जो केन्द्र सरकार के अधीन आता है। दूसरा रेलवे होता है, वह भी केन्द्र सरकार के अधीन होता है।

Spp/Rtm/20.07.2024/15:30/2m

तीसरा रोडवेज बसें, जो आम आदमी, गरीब आदमी के काम आती है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक अपने खुद का।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): खुद का, वह सक्षम लोग तो करते ही हैं।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, अपनी बात रखिये। समय हो रहा है।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अभी रूकिये, मैं डिस्टर्ब हो गया।

श्री सभापतिः आपको डिस्टर्ब नहीं होना है।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): मेरे यहां माडर्न मकराना बस स्टेण्ड की घोषणा हो रखी है। उस माडर्न बस स्टैण्ड को जमीन उपलब्ध करायी जाये माडर्न बस स्टेण्ड बनाया जाये। मकराना में एक बुकिंग खिड़की है, वह बंद हो गयी है। कोई भी यात्री टिकट लेने जाता है तो वहां पर टिकट नहीं मिलता है, बस में बैठने के बाद में उसको टिकट मिलता है। वह खिड़की पुनः चालू करवायी जाये। बोरावड़ बस स्टेण्ड पर कोर्ट का मामला चल रहा है, उसमें भी आपके द्वारा पैरवी करवायी जाये। मकराना में पूर्व में 30-35 बसें चलती थीं, आज उनमें से मात्र 4-5 बसें चल रही हैं। उसके अलावा अलग अलग गांवों के अन्दर ग्राम पंचायत मकराना से संचालित होने वाली बसें गच्छीपुरा से गेडा, बेसरोली, बोरावड़, मकराना, अजमेर और रानीगांव से कल्याणपुरा, मनाणा, कालवा, बोरावड़, मकराना और गेलासर से भरनेत, मकराना और विशेष तौर से मकराना, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली वोल्वो बस भी आप वहां से संचालित करें ताकि वहां पर व्यापारी को अर्जेंट ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है तो मकराना से दिल्ली वोल्वो बस का संचालन करायें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि परिवहन की मांग में बताना चाहता हूं कि मकराना में उप परिवहन कार्यालय वहां संचालित है लेकिन जमीन अलॉटमेंट कराकर वहां पर स्थायी कार्यालय भी बनाया जाये। जिला डीडवाना, कुमामन में अभी DTO ऑफिस चल रहा है, इसे RTO में कन्वर्ट कराया जाये, क्योंकि RTO आफिस अजमेर में चल रहा है। हमारे कुचामन-डीडवाना जिले में विदेश जाने के लिये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। आई डी पी ट्रक ट्रेलर के लिये नेशनल परमिट बसों के लिये स्टेट कैरिज तथा ऑल इंडिया ट्यूरिस्ट परमिट, मोटर ड्राइविंग स्कूल से सम्बन्धित कार्य, ट्रांसपोर्ट कम्पनी, बस स्टेंड, नोटिफिकेशन से संबंधित कार्यों के लिये अजमेर जाना पड़ता है और DTO कार्यालय डीडवाना-कुचामन तथा ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः प्लीज माननीय सदस्य, सहयोग करें। श्री राजेन्द्र जी।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): तथा मकराना, कुचामन, नावां आता है और आप RTO आफिस कार्यालय खोलेंगे तो वहां भार नहीं रहेगा और मकराना नगर परिषद ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 62 एवं 22 पर आज मुझे बोलने का अवसर आपने दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में चार महाविद्यालय वर्तमान में हैं। इनमें तीन महाविद्यालय पूरी तरह से बन्द हैं। वहां पर दो महाविद्यालयों के लिये तो अभी जमीन भी अलॉट नहीं हुई है। राजनीतिक कारणों से शहरी क्षेत्र से तीन-तीन किलोमीटर उनके लिये जमीन आंवटन का काम किया। जनता का जबरदस्त विरोध था। 2015 में आदरणीय वसुन्धरा जी जब मुख्य मंत्रीजी थीं, तब डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय महवा में खोला गया। सिर्फ एक महाविद्यालय है जो पूरी तरह से संचालित हैं। बाकी तीन महाविद्यालय हैं जो प्राइवेट के एक-एक, दो-दो कमरों में संचालित हैं। वहां पर व्याख्याता बिलकुल भी नहीं हैं और सब जगह पोस्ट वेकेंट ही पड़ी हैं। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इन सभी महाविद्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किया जाये, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणाएं बहुत कीं। लेकिन घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया। निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो, घोषणा करे लेकिन समय पर उनकी पूर्ति होना बहुत जरूरी है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मुख्यालय पर एक महाविद्यालय है, उसको यू.जी. से पी.जी. करने का आपसे अनुरोध है, क्योंकि महवा एक बहुत बड़ा कस्बा है, उपखण्ड है। एक बालाहेड़ी कस्बा है, जो पीतल के बर्तन बनाने के लिये बहुत प्रसिद्ध है। मंत्रीजी को भी ध्यान है और एन.एच. के पास में स्थित है। मेरा निवेदन है कि एक महाविद्यालय वहां पर खोला जाये। इसके साथ ही बांदीकुई के जो माननीय सदस्य

बैठे हैं, उनका और मेरा बराबर का क्षेत्र है बेजूपाड़ा। इसमें आधी ग्राम पंचायत इनकी आती है और आधी मेरी आती है। हम दोनों विधायकों का आपसे आग्रह है कि बेजूपाड़ा में भी एक महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही जो अम्बेडकर महाविद्यालय मेरे महवा में है, वह अभी तक इतने वर्ष हो चुके, वहां पर कमरों की बहुत जबरदस्त कमी है। कॉलेज की चारदीवारी भी वहां पर नहीं है, क्योंकि जन सहयोग से उसकी बिल्डिंग का काम किया था। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इन बातों पर गौर फरमायें।

इसके साथ ही हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा और परिवहन को लेकर बहुत गंभीरता से इस बजट में बहुत सारी चीजें हमको दी हैं। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। परिवहन विभाग भी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आदान-प्रदान करने का। मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर आदि जिले एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर-आगरा के मध्य में महवा बसा हुआ है एवं आस्था के प्रसिद्ध धाम-जिनमें मेंहदीपुर बालाजी, कैलादेवी, गोवर्धनजी, भर्तृहरि, नारायणी माता, पाण्डुपोल आदि समीप होने के कारण हजारों भक्तों का आवागमन होता है। रोजगार हेतु बहुत बड़ी संख्या में जयपुर, अजमेर, आगरा, धौलपुर, दिल्ली, हरिद्वार, मथुरा, सोरोजी, गुड़गांव, भिवाड़ी आदि व्यवसायी लोग कारोबार के लिये यहां से निकलते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि राजस्थान रोडवेज का डिपो वहां पर होना बहुत जरूरी है। अभी महवा में मेरा बस स्टैंड है, अगर मंत्रीजी उसको डिपो घोषित कर दें तो निश्चित रूप से वहां के सभी आवागमन भक्तगणों को, आम जनता को बहुत फायदा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जनता की भावना को देखते हुए जो भी मैंने सदन में आज यहां पर मांग रखी है, उनको डिप्टी सी.एम. साहब आपके मार्फत पूरी करेंगे और निश्चित रूप से आज जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन में दोनों विषयों को लेकर हुई है, हमारी सरकार बहुत गंभीरता के साथ इन सब कामों को पूरा करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह दीन, हीन, गरीब सबको साथ लेकर काम करने में विश्वास करती है। पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं तो कीं, लेकिन घोषणाएं ही रहीं, अभी जमीन पर उनको नहीं उतारा गया। मैं पुनः मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगा कि महवा विधान सभा का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये जो भी मैंने मांग की हैं, उनको आप जल्द से जल्द पूरा करें। पुनः सभापतिजी का और मंत्रीजी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ. ऋतु बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। उच्च शिक्षा, जिस तरह से नींव का पत्थर प्रारम्भिक शिक्षा होती है उसी प्रकार घर की इमारत हमारी उच्च शिक्षा होती है और जब उस घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है जब मकान तैयार है, बिल्डिंग तैयार है लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं है।

आप समझ रहे होंगे कि रहने वाले से मतलब यह है कि पढ़ने वाले तो हैं पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम देख रहे हैं कि मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में चार कॉलेजेज हैं। दो कन्या महाविद्यालय हैं और दो राजकीय महाविद्यालय हैं। दोनों की स्थिति जब मैं देखती हूं तो जो देवनारायण कन्या महाविद्यालय है उसमें एक प्राध्यापक है। रूपबास में भी जो कालेज पिछली सरकार में खुला है, वहां पर भी केवल एक प्राध्यापक है। स्थिति सोचने वाली बनती है कि कॉलेज खुलते हैं, स्टॉफ होता नहीं है। हमारा राजकीय महाविद्यालय बयाना को क्रमोन्नत कर दिया गया। साइंस विषय खोल दिया गया पर वहां पर न तो लैब है, न लैब टैक्निशियन है, न पढ़ाने वाला है। तीनों सब्जैक्ट्स में से एक भी सब्जैक्ट का प्राध्यापक, फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बॉयोलॉजी तीनों का कोई भी प्राध्यापक वहां पर नहीं है। यह बहुत गंभीर विषय है। उच्च शिक्षा नौजवानों को एक दिशा देती है आगे बढ़ने के लिये। 2007 में, क्योंकि मैं भी छात्र राजनीति से आयी हूं, 2007 में जब बी जे पी की गवर्नमेंट थी, तो यू.जी. और पी.जी. महाविद्यालय थे, उनमें स्किल डवलपमेंट के लिये अलग अलग कम्पनियों के कैम्प करवाये जाते थे, प्लेसमेंट तक होते थे, लेकिन इन विगत वर्षों में ये चीजें खतम हो गयीं।

MLS/RTM/20.07.2024/15:40/2n

ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेेएशन करने के बाद नौजवान सोचता है, अब क्या करूं, सरकारी नौकरी की तैयारी करूं या किसी प्राइवेट फर्म में जाऊं या प्राइवेट नौकरी करूं। एक दिशाहीन भविष्य हमारे देश का हो रहा है। जैसा कि स्किल डवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें इस बजट में कहीं गईं, मैं यह कहना चाहूंगी, हमारे डिप्टी सीएम साहब यहां बैठे हैं, वे भी एक संघर्ष वाले जीवन से यहां पहुंचे हैं, उन्हें मालूम होगा कि जो वंचित वर्ग है, उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करके महाविद्यालय तक पहुंचते हैं। जब वे वहां तक पहुंचते हैं और उन्हें उस एजुकेशन से रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते तो वह शिक्षा बर्बाद हो जाती है। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि स्किल डवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, स्किल डवलपमेंट की बात कह रहे हैं, वह साधारण जो एजुकेशन होती है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उन कॉलेजों में भी स्पेशल प्रोग्राम बनाये जाने चाहिये।

साथ ही, मेरे यहां पर कॉलेजों में, जो बयाना में देवनारायण गर्ल्स कॉलेज है, वहां लम्बे समय से मांग की जा रही है कि एक स्थायी सैक्शन बनाया जाये। सीट्स तो बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन स्थायी सैक्शन नहीं बनाया जाता। मेरी मांग है कि वहां पर स्थायी सैक्शन बनाया जाये। जो चारों महाविद्यालय हैं, उनमें किसी में भी छात्रसंघ कार्यालय नहीं है, कैंटीन नहीं है। हम ''खेलेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया'', ''फिट इंडिया'' की बात करते हैं, कहीं पर भी एक खेल मैदान नहीं है। जमीन है, लेकिन खेल मैदान कहीं पर भी नहीं हैं। युवा, जो खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

(समय:)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा कहना है कि रूपवास और बयाना, दोनों उप-खण्डों पर, दोनों महाविद्यालयों में से किसी का चयन करके वहां इंडोर, आउटडोर स्टेडियम या मिनी स्टेडियम, कुछ दिया जाये, जिससे युवाओं को खेलों की तरफ जाने का भी, अपनी प्रतिभा और कौशल बढ़ाने का भी मौका मिल पाये।

राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा में भी हर ब्लॉक पर 20-20 आईटीआई खोलने की बात कही थी। उसमें रूपवास उप-खण्ड का भी नाम है। मैं निवेदन करूंगी कि आप रूपवास उप-खण्ड में आईटीआई खोलें। हमारे वहां पर खनन का भी क्षेत्र है और आईटीआई के माध्यम से रोजगार के साधन भी डवलप होंगे। साथ ही, यह भी कहूंगी कि बयाना में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय होना चाहिये।

भरतपुर जिले में पशुओं की संख्या भी अच्छी खासी है। भरतपुर जिले की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में साढ़े तीन लाख के आस-पास पशुधन है, लेकिन वहां पर वैटरनरी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सरकार सोचे, यह मेरी सरकार से डिमांड है। अगर ऐसा होता है तो पशु-पालकों को भी सुविधा मिलेगी और इस ओर लोगों का ध्यान भी जायेगा। इस क्षेत्र में सम्भावनाएं हैं, जिनसे हम रोजगार भी सृजित कर सकते हैं।

साथ ही, मैं कहूंगी कि भरतपुर में किसी प्रकार के औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं हमें दिख नहीं रही हैं। मैं यही कहूंगी कि वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ भी हम ध्यान दें। अभी जब से सदन चला है, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा बहुत सी वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष: श्री मुकेश भाकर।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): बस एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: समय का ध्यान रखें।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): परिवहन की बात कर दूं बस।

श्री अध्यक्ष: जो कहना चाह रहे हैं, टेबल कर दें।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): एनसीआर में दस वर्ष पुरानी बसें नहीं चलतीं। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे यहां दस वर्ष से ज्यादा पुरानी बसें हैं, उन्हें अलग जगह शिफ्ट करके नयी बसें वहां दी जाएं ताकि वहां रूट प्रॉपर हो सके। साथ में, यही कहूंगी कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने रूपवास में मुझे बस स्टैंड दिया और बयाना में अभी किराये के भवन में चल रहा है तो मैं अपनी नैक्स्ट मांग यही रखूंगी कि मेरे यहां पर बस स्टैंड दिया जाये और साथ ही स्टाफ भी दिया जाये ताकि सब चीजें प्रॉपर हो सकें।

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 और 62 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में हम पक्ष-विपक्ष के सारे सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा में राजस्थान में क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय,

पिछले पांच साल हमने उच्च शिक्षा का बजट देखा, आज छठा साल है जब भारतीय जनता पार्टी उस बजट को लेकर आयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 साल आजादी को हो चुके हैं और हर साल एक बजट आता है, जिसमें उच्च शिक्षा को लेकर वर्णन होता है, उसमें उत्सुकता की बातें होती हैं।

जो भी सत्तापक्ष में बैठा होता है, चाहे हम हों या भारतीय जनता पार्टी हो, वह अपनी पीठ थपथपाता है कि हमने उच्च शिक्षा को लेकर ये घोषणाएं कीं, हमने कॉलेज खोल दिये, हमने विश्वविद्यालय खोल दिये, भविष्य में बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, उसे लेकर काम कर दिया। मैं समझता हूं कि यह सदन, जिसका काम कानून बनाने का है, लॉ मेकर्स हम सब लोग हैं, जिन्हें चुनकर जनता ने यहां भेजा है। आज 75 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है। यह बजट आया, अगला बजट आयेगा, पांच बजट आप लाएंगे, पीछे हम लाये, लेकिन आज भी जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनके हालात हम सबके लिए सोचने लायक हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 21 सरकरी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें यूजीसी से एनएएसी की ए प्लस प्लस, ए प्लस तो छोड़िये, ए ग्रेड का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। आज यह हम सब लोगों के लिए एक चिन्ता का विषय है कि हर बार हम बजट लाएंगे, घोषणाएं करेंगे, लेकिन एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो ए ग्रेड में भी आ रहा है। 31 विश्वविद्यालयों में से एनएएसी की जो मान्यता की प्रक्रिया है, उसमें हिस्सा तक ये विश्वविद्यालय नहीं ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने विश्वविद्यालय हैं, उनके अधिकांश कुलपति उत्तर प्रदेश के यहां जमे हुए हैं। वे यह तय तक नहीं कर पा रहे कि हमें इस प्रक्रिया में भाग लेना है या नहीं। यह हम सबके लिए एक सोचने की बात है कि हम लोग इस शिक्षा की ग्रेड सुधारने के लिए क्या कर पाएं।

इसे लेकर चिन्ता होगी और इसमें अगर पांच साल में हम एक भी विश्वविद्यालय को एक अच्छी ग्रेड में ला पाये तो हम समझेंगे कि कुछ काम उच्च शिक्षा के लिए हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बजट में आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ग्रैजुएशन कॉलेज, पीजी कॉलेजों की हम घोषणाएं करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति यह है कि एक भी पॉलिटेक्निक और आईटीआई किया हुआ बच्चा जब एजुकेशन लेकर बाहर निकलता है तो कितने लोग उनमें से रोजगार पा रहे हैं? घर बैठे उन्हें हम डिग्रियां दे रहे हैं। इस बात पर हम सबको सदन में चिन्ता करनी चाहिये। हमें यह सोचना पड़ेगा कि केवल हम डिग्री दे रहे हैं या गुणवत्ता की पढ़ाई हम दे पा रहे हैं।

आईटीआई में बच्चा क्या सीख रहा है, पॉलिटेक्निक में बच्चा क्या सीख रहा है? क्या बीए, बीएससी और पीजी करने के बाद वह कोई रोजगार पा रहा है? आज पूरे देश में बेरोजगारी का आलम हम सब लोगों के सामने है। पिछली कांग्रेस सरकार ने 333 कॉलेज पूरे राजस्थान में खोले। जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य खड़े हुए, उन सबने बड़ी चिन्ता जतायी कि एक में भी भवन नहीं है, एक में भी मास्टर नहीं है, एक भी कॉलेज सुचारू रूप

से चालू नहीं है। यह हमने नहीं किया, आपको मौका जनता ने दिया है। इन पर केवल आलोचना, टीका-टिप्पणी को परे करके, इनके हालात आप सुधारें। इनमें टीचर्स, मानव संसाधनों, बिल्डिंग की सुविधाएं दें ताकि बच्चे पढ़ पाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय कब कर रहा है, जोधपुर कब कर रहा है, उदयपुर कब कर रहा है। कम से कम राजभवन से एक ऐसा आदेश जाये कि सारी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं एक समय पर हो पाएं, क्योंकि जब कोई भी वेकेंसी निकलती है, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र है, वह ग्रेजुएट हो गया, लेकिन रिजल्ट जोधपुर का नहीं आया। कम से कम यह व्यवस्था की जाये कि आने वाले समय में राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं एक समय पर हों ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें अपने बच्चे भाग ले पाएं।

mkd/rtm/20.07.2024/15:50/2o

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले समय में देखा कि कितनी फर्जी यूनिवर्सिटीज खुलीं, कितनी फर्जी डिग्रियां लेकर लोग नौकरी लग गये और जो बच्चे असली हकदार थे, वे पिट गये।

आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन यूनिवर्सिटीज को बन्द किया जाये और जो फर्जी डिग्रियां लेकर नौकरियां लग रहे हैं, जो इस शिक्षा की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, उन पर उच्च शिक्षा मंत्री जी कार्यवाही करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पिछली सरकार राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना लेकर आई थी। उसमें जो एकेडमिक रूप से टापर्स थे, उन बच्चों को हम लोग विदेश भेजेंगे, हमने यह व्यवस्था की थी। उसमें हमने 200 बच्चों को स्कॉलरशिप का वादा किया। आपने उसे 500 किया, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने नाम भी राजीव गांधी जी से विवेकानन्द कर दिया।

शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पहले जो 200 बच्चे गये थे, उनमें से 100 बच्चे अधिकारियों के थे। आईएएस और अधिकारियों के 100 बच्चे वह शिक्षा पा रहे हैं और जिन टॉपर्स के लिए हम यह योजना लाये थे, वे लोग कहीं न कहीं उससे पिछड़ रहे हैं। जिनको विदेश भेज भी दिया, उन बच्चों की भी स्कॉलरशिप समय पर नहीं जा रही है। मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप नाम भले ही बदल दें, इस स्कॉलरशिप योजना में सुधार करें और जो अधिकारी दोषी हैं, उन पर सरकार कार्यवाही करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की बात हैं। हम सभी जितने भी लोग छात्र राजनीति से आकर यहां बैठे हैं, वे अगर छात्रसंघ चुनाव की बात नहीं करेंगे तो वे अपनी जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आज छात्रसंघ चुनाव बन्द हैं। भाजपा यह कहती है कि हमारी सरकार ने बन्द किये तो हमने भुगता, हम आकर विपक्ष में बैठ गये। आप लोग

सत्ता में हैं और उप मुख्य मंत्री जी आपके पास उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट है। आप कुछ ताकत दिखाओ। हम तो आपको ही मुख्य मंत्री मान लेंगे। राजस्थान का जो युवा है, वह कह रहा है कि हम तो प्रेम चन्द जी को मुख्य मंत्री मान लेंगे। आप अपनी ताकत को परखो और आप ये चुनाव चालू करवाओ। हम तो यह मानेंगे कि सरकार में किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ प्रेमचन्द जी बैरवा, उप मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने ये चुनाव शुरू करवा दिये, क्योंकि आप भी विश्वविद्यालय से ही निकले हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे लाडनूं की तरफ से दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले राज में हमने वहां महिला कॉलेज की स्थापना की और बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन अभी भी भूमाफिया उस जमीन पर नजर डाले हुए हैं। रेवेन्यू बोर्ड में बार-बार स्टे के लिए फाइलें जा रही हैं। आपसे निवेदन करूंगा, चार करोड़ रुपये की बिल्डिंग तैयार है। उसमें किसी भी तरह की कानूनी रूकावट नहीं आये। इसके लिए आप लोग सरकार की ओर से अपना पक्ष मजबूती से रखे।

हमने पिछले राज में लाडनूं के लिए बस स्टैंड स्वीकृत कराया। बस स्टैंड का पैसा जारी हो चुका है, लेकिन राज बदलने के बाद, उस बस स्टैंड का काम चालू नहीं हुआ है।

आपसे निवेदन करता हूं कि उसका टेंडर करवाकर जल्दी से जल्दी से शुरू करवाये। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द्र। श्री देवी सिंह शेखावात।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज परिवहन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के आवागमन परिवहन सम्बन्धी, जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ केन्द्रित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से राजस्थान रोडवेज की बसें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। जो बसें चल रही हैं, उनकी फिटनेस सही नहीं है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुझे कई बार यह लगता है कि इन बसों की फिटनेस में, सरकारी निगम होने की वजह से शिथिलता दी जाती है, नहीं तो कई बसें ऐसी कंडीशन में लगती हैं कि वे सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। बसों की कंडीशन खराब होने के कारण कई एक्सीडेंट भी सामने आते हैं। हम देखते हैं कि कइयों में ब्रेक टाइम पर नहीं लगता है, टायर कमजोर होते हैं और क्लच ब्रेक जैसी बसों की बहुत गम्भीर समस्याएं हैं। जो बसें चलती हैं, वे साफ-सुथरी भी नहीं रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड हैं, एक बानसूर है और दूसरा नारायणपुर है। बानसूर में आज से दस साल पहले, जब पहले भाजपा सरकार थी, तब अलवर, सीकर की बहुत बसें चलती थीं और उनमें पर्याप्त भार होता था, लेकिन वे बसें पिछले

पांच सालों में दिखाई नहीं दीं। आजकल जो कोटपूतली, अलवर की बसें चलती हैं, उनमें भी भारी कटौती देखने को मिल रही है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारा जो कोटपूतली से अलवर का, हमारे बच्चे या तो कोटपूतली पढ़ते हैं या अलवर पढ़ते हैं और बानसूर हमारे बीच का सेंटर है तो वहां के लिए पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध कराई जायें।

इसके साथ ही मेरे क्षेत्र से जयपुर आने वालों की संख्या प्रतिदिन काफी रहती है। जयपुर से नारायणपुर के लिए जो बसें जाती हैं, वे सवा चार बजे चांदी की टकसाल से चलकर लगभग सात बजे नारायणपुर पहुंचती हैं, लेकिन ऑफिस का टाइम आम तौर पर 6 बजे तक का होता है और बाजार भी 6-7 बजे तक रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति गांव से चलकर आता है तो उसको इतना टाइम लग जाता है, वापस जाते वक्त उसको नारायणपुर के लिए सुविधा कम मिलती है। जो बसें अलवर जाती हैं, वे वाया थानागाजी होकर जाती हैं और व्यक्ति को घाटा बांदरोल में उतरकर वहां से किसी प्राइवेट व्हीकल को मैनेज करना पड़ता है। नारायणपुर के आस-पास की हमारी लगभग 20-25 पंचायतें जयपुर से कट जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शाम को 5 बजे के बाद 6 से 8 बजे तक जयपुर से अलवर जाने वाली कम से कम तीन बसों को वाया नारायणपुर निकाला जाये, ताकि नारायणपुर और उस क्षेत्र के आसपास के तकरीबन दो दर्जन गावों के लोगों को परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े।

इसके साथ ही, हमारे यहां नारायणपुर से कोटपूतली वाया कराणा होकर रास्ता है। इस पर भी बसों की काफी कमी है। दूसरी, नारायणपुर से वाया नीमूचाणा होकर कोटपूतली की बसें हमें और चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे कराणा से जो रास्ता निकलता है और वह नयाबास, बासदयाल, रसनाली, नवलपुरा, खेड़ा, श्यामपुरा जाता है। उस रूट पर बसें चलाई जायें।

(समय: बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

वे बसें नारायणपुर से बानसूर के लिए चलती हैं और वाया कराणा, बासदयाल होकर बानसूर तक चलें। आपसे पहले भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर ट्रांसपोर्ट में आ रही परेशानी के बारे में आपको बताया। हमारे क्षेत्र का बड़ा कस्बा रामपुर है। पहले कोटपुतली से रामपुर भी काफी बसें चलती थीं। उनकी संख्या में भारी कमी आई हैं। वे बसें लेट ऑवर्स में नहीं चलती हैं। साथ ही, हमारे हरसोडा भी एक बड़ा कस्बा है तो वहां भी लेट आने-जाने वाले लोग के लिए सुविधा नहीं है। इसलिए कोटकासिम से बानसूर तक की बसें लेट ऑवर्स में चालू हों, ताकि वहां के लोगों को परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं मिले।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी, इस सदन के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र, वर्तमान में जिला कोटपूतली है, इसमें तकरीबन सारे ओवर लोड व्हीकल चलते हैं।

Bhs/Rtm/20.7.24/16.00/2p

प्रतिदिन 1600 ट्रक किसी न किसी जगह वाया कोटपूतली होकर निकलते हैं जिनमें साठ टन से लेकर सौ टन तक माल होता है जो कानूनी रूप से भी सही नहीं हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, बड़े खतरनाक तरीके से चलते हैं, रोडें टूटती हैं और कहीं न कहीं आर.टी.ओ., डी.टी.ओ. उनको परेशान करते हैं तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इनको रेगुलर कर दिया जाये या इनका सख्ती से पालन कराया जाये क्योंकि चलवाते भी हैं तो कहीं न कहीं सरकार की उपेक्षा होती है उसमें और रोकने में उसका टॉर्चर होता है और उसको कोई फायदा नहीं होता। फायदा कंजूमर को होता है और ट्रांसपोर्ट वाले को बड़ी तकलीफ होती है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): दो मिनट, सर।

माननीय, मेरे यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज नारायणपुर और बानसूर में नहीं है उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। साथ ही, हमारे नारायणपुर में जो बच्चियों का कॉलेज बन रहा था उस कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया लेकिन वह जमीन पी.डब्ल्यू.डी. को नहीं दी जा रही है और वहां एक भी सरकारी नियोक्ता नहीं हैं, सारे ही विद्या मित्र से लगे हुए हैं और सब्जैक्ट भी कम हैं वहां इकॉनॉमिक्स का खोला जाना बहुत जरूरी है। हमारे यहां नारायणपुर और बानसूर में बस स्टैण्ड के लिए जगह अलॉट करवा कर वहां बस स्टैण्ड भी बनाया जाना जरूरी है। बानसूर में जो कॉलेज खोला गया वहां केवल एक प्रोफेसर है और दो लैक्चरार हैं, चार जगह खाली है। वहां फैकल्टी हमें बी.एससी. साइंस की और चाहिये। यह आपसे निवेदन है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सारे सब्जैक्ट चाहिये।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, सहयोग करें, प्लीज विराजिये।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सभापतिः श्री अभिमन्यु।

श्री अभिमन्यु (संगरिया): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 22,24 और 62 पर मुझे बोलने का मौका दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि दुनिया में ऐसे कोई देवी-देवता, शक्ति या नेता नहीं है जो तुम्हारी गरीबी व गुलामी को दूर करें, वह तुम्हें ही करनी है शिक्षा के माध्यम से। राज्य में समस्त विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम कुलगुरु कर दिया गया, यह स्वागत योग्य है लेकिन वहां पर कुलगुरु जो बैठे हैं वे यू.पी. और बिहार से दूसरे राज्यों से आकर बैठे हैं। निवेदन है कि वहां वो शिक्षाविद बैठें, जो राजस्थान के हों, राजस्थान में पढ़े हुए हों, ताकि उच्च शिक्षा को ऊँचाई पर हम ले जा सकें। उच्च शिक्षा नौजवान के भविष्य का सवाल होता है राजस्थान के अन्दर प्राइवेट संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, बी.पी.एड., बी.एड., बी.एस.टी.सी. के नाम पर खुलेआम लूट मचाने का काम राज्य के अन्दर करते हैं।

सभापति महोदय, आम गरीब, मध्यम परिवार के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो अनेक प्रकार के एडिश्नल चार्ज उन पर लगा कर उनसे फीस

वसूली के नाम पर बीस हजार, तीस हजार, पचास हजार रुपये वसूले जाते हैं। मंत्री साहब से निवेदन है कि इस पर एक ऐसी पॉलिसी बनायें कि प्राइवेट और सरकारी के अन्दर जो फीस का अनुपात है कहीं न कहीं उसके अन्दर ज्यादा बड़ा फासला नहीं हो कि एक दो हजार है और एक एक लाख रुपये है, ताकि आम गरीब परिवार और मध्यम परिवार के बच्चों को उनके सुरक्षित भविष्य के लिए उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया में सन 1980 से कन्या महाविद्यालय संचालित है उसका नाम है मीरा कन्या महाविद्यालय। एक मजाक का विषय यह महाविद्यालय बना हुआ है इसमें खेल मैदान भी है और समाज कल्याण के द्वारा सौ कमरों का हॉस्टल भी है। आठ बीघा कृषि भूमि भी इसके नाम है। इस महाविद्यालय का सरकारीकरण दिनांक 31.8.2013 को हुआ। इसी क्रम में 2.10.2013 को राजकीय प्राचार्य की नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन भाजपा की सरकार द्वारा 26.9.2014 को इसको डिनोटिफाइड कर दिया गया। जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा रिट पिटीशन में डिनोटिफाई के आदेश को रद्द कर दिया गया व महाविद्यालय को राजकीय बताया गया।

सभापति महोदय, बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार 10.7.2020 को राज्य सरकार द्वारा पुन: महाविद्यालय को राजकीय कर दिया गया। 3.3.2021 को इसका नाम राजकीय किया गया। बजट 2023-24 में बिन्दु संख्या 24 में मीरा कन्या महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय की घोषणा कर दी गई, लेकिन 21.9.2023 को बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 24 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तन किये जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वहां कार्यरत कार्मिकों को राजसेस नियम, 2023 के अनुरूप लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की। इस महाविद्यालय का संचालन नॉडल अधिकारी के द्वारा प्रभारी अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। अत: आपसे निवेदन है कि महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य, प्रोफेसर नियुक्त किया जाये तथा वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को जिनको कई माह से वेतन नहीं मिला है उन 126 कर्मचारियों के परिवार के पालन-पोषण के लिए उन कर्मचारियों को वेतन दिया जाये और महाविद्यालय के सरकारीकरण की शेष प्रक्रिया को सम्पन्न किया जाये। मंत्री साहब, आप इसकी जल्द से जल्द सरकारी प्रक्रिया पूरी करवायें।

सभापति महोदय, संगरिया विधान सभा क्षेत्र में दो आई.टी.आई दीनगढ़ व सूरवाला में है। यहां पर स्थायी अनुदेशक नहीं है। इनका सारा कार्य गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से किया जाता है। हर वर्ष गेस्ट फैकल्टी को एक-दो माह हटा कर पुन: रख लिया जाता है। अत: आपसे निवेदन है कि इस व्यवस्था को समाप्त करके इनको पुन: संविदा में रख कर स्थायी किया जाये ताकि अनुदेशक 2024 में भी इनको अनुभव के आधार पर बोनस दिया जाये। मंत्री साहब, यह आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, संगरिया विधान सभा क्षेत्र के गांव साबवाना में संस्कृत महाविद्यालय की घोषणा हुई 2013 में। इसके पास जगह भी है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट लेना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इसके पास जगह भी है। आठ बीघा गांव साबवाना में। चार बीघा पर न्यायालय द्वारा फैसला चल रहा है, तीन बीघा भूमि खाली पड़ी है। कलेक्टर साहब को बार-बार अवगत करवा दिया गया है फिर भी इस महाविद्यालय को चालू करवाने की एनओसी नहीं दी जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि इस महाविद्यालय को चालू करवाने का काम करें।

सभापति महोदय, परिवहन के लिए पूरे संगरिया, टीबी के अन्दर संगरिया विधान सभा क्षेत्र में एक भी रोडवेज बस नहीं है। हम सरकार चलाते हैं रोडवेज के द्वारा, महिलाओं को बोनस मिलता है। वहां आने-जाने के लिए ग्राम के अन्दर, शहर के लिए सुविधाएं होती हैं लेकिन एक भी रोडवेज की व्यवस्था संगरिया विधान सभा क्षेत्र में नहीं होना कहीं न कहीं यह सरकार के प्रति एक सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि जो बसें दी हैं उनमें से दो-चार बसें आप संगरिया और टीबी से भी जोड़ने का काम करें और सर, आप खुद छात्र संघ के माध्यम से आये हैं। हम सब लोग छात्र संघ से यहां पर पहुंचे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर, छात्र नेताओं पर हम उसकी निन्दा करते हैं। आपको चुनाव करवाने को लेकर इस पर जल्द से जल्द आपको फैसला लेना चाहिये, ताकि छात्रों पर मुकदमे नहीं लगें जो छात्र, इसके लिए लगातार छात्र नेता अपने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और अपने जिलों में संघर्ष कर रहे हैं, अतः राजनीति की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ है तो हम सब आप लोगों से निवेदन करते हैं कि सरकार आपकी आ गई है और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आपको हम सब लोग निवेदन करते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22,24 और 62 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार।

सभापति महोदय, देश का भविष्य बनाने के लिए राष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता एवं भारत के अवतारी पुरुष माननीय श्री नरेन्द्र मोदी एवं राजस्थान का भविष्य बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा, उप मुख्य मंत्री माननीय दिया कुमारी जी, उप मुख्य मंत्री माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना।

सभापति महोदय, वर्तमान में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। यह डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर प्रदेश में निवास करने वाली जनता के हितों को ध्यान में रख कर उनकी भलाई के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता के अनुसार काम ले रहे हैं ...

Kas/rtm/20.07.2024/16.10/2q

और प्रदेश को अग्रणी राजस्थान बनाकर रहेगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय

मगरा-मेरवाडा व मेवाड़ क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा का सबसे पुराना एवं प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में ब्यावर ही नहीं, कई जिलों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यहां तक कि प्रदेश के मुख्य सचिव रहे श्री निरंजन आर्य जैसे कई अधिकारी इसमें पढ़े हुए हैं। वर्तमान में यहां पर करीब 4000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में सीटें कम होने एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं नहीं होने के कारण गांव व गरीब वर्ग के बच्चे बडी संख्या में हर साल नियमित प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। वह या तो स्वयंपाठी के रूप में अध्ययन करते हैं या ऊंची फीस देकर प्राइवेट महाविद्यालयों में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि अब ब्यावर जिला है, यहां पर सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं, जैसे गणित, अंग्रेजी साहित्य, प्राणी शास्त्र व संगीत शास्त्र की संकाय की जाए तथा प्रथम वर्ष कला वर्ग में 2 नये वर्ग खोले जाएं तथा प्रथम वर्ष विज्ञान (बायो) में नया वर्ग एवं प्रथम वर्ष विज्ञान (गणित) में एक नया वर्ग खोला जाए, जिससे अधिकतम बच्चों को प्रवेश मिले सके। यहां पर वर्तमान में स्टाफ की भी काफी कमी चल रही है, इस कमी को तुरन्त पूरा किया जावे। मेरा उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सबसे पुराने महाविद्यालय में एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाने की आज ही घोषणा करें।

सभापति महोदय, साथ ही निवेदन है कि ब्यावर में कन्या महाविद्यालय भी संचालित है। इस महाविद्यालय में बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए यहां पर पूरा स्टाफ लगाया जावे। मेरा विधान सभा क्षेत्र के बाराखेड़ा में दो-तीन कमरों में ही महाविद्यालय संचालित हो रहा है। यहां पर महाविद्यालय का भवन बनाने के लिये पूर्व में भी टेंडर जारी हो चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार का कार्य चालू नहीं हुआ है। टेंडर करवा कर इस भवन को बनवाया जाये। सभापति महोदय, निवेदन है कि मैं पिछले काफी समय से यहां पर विधि महाविद्यालय खोले जाने की मांग कर रहा हूं। मुझे आपसे पूरी आशा है कि आप ब्यावर में विधि महाविद्यालय की मांग को पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, अब तो ब्यावर जिला बन गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है। पहाड़ी और मगरा क्षेत्र के गरीब बच्चे दूर इलाके में जाकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उप मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ब्यावर में तकनीकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें।

साथ ही निवेदन है कि प्रदेश के प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर एक आईटीआई खोले जाने की कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में टाटगढ़ उप खण्ड जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहां के बच्चों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए ब्यावर आना पड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है कि टाटगढ उप खण्ड में एक आईटीआई खोलने की आज घोषणा करें। साथ ही मेरी मांग है कि शिक्षा विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो, नये कर्मचारियों की भर्ती में मैरिट बनाते हैं, वह प्रत्येक जिलेवाइज बननी चाहिये, ताकि हर वर्ग के बच्चे को, हर समाज को न्याय मिल सके।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): एक मिनट साहब। सभापति महोदय, परिवहन के लिये निवेदन है, ब्यावर जिला चारों तरफ से आने वाली बसों का संगम है। ब्यावर से टाटगढ़ तथा बराखन एवं दूधालेश्वर के लिए रोडवेज बसो का संचालन होता है, जो पिछली सरकार में बंद कर दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि टाटगढ़, बराखन और ब्यावर वाली बसों को नियमित रूप से चलाने के लिये बसों की संख्या बढ़ाई जाये।

आपसे मेरा निवेदन है कि मैंने जो भी मांगें रखी हैं, उसको आप पूरा करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।।

श्री सभापतिः श्री पूसाराम।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे को आपने मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी पिछली सरकार ने 333 कॉलेज खोले। इनमें बहुत से कॉलेजों के भवन बन चुके हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है। आपने भी कन्या महाविद्यालय, आईटीआई खोलने का प्रावधान किया है। मेरे जिले चूरू में कृषि विद्यालय खोला, इसके लिये धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह स्थिति है कि बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फर्जी डिग्रियां बाट रही हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं हमारे उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर तत्परता से कार्यवाही की जानी चाहिये। इसमें बहुत से विद्यार्थियों का शोषण भी होता है और कई विद्यार्थी इससे नौकरी भी लगते हैं और इस वजह से योग्य वंचित रह जाते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में तीन महाविद्यालय हैं। राजकीय जालान महाविद्यालय रतनगढ़ में हिन्दी, अंग्रेजी, पीटीआई और लाइब्रेरियन की पोस्टें खाली हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि विद्या संबल योजना से काम चलने वाला नहीं है। उसमें पारदर्शिता नहीं होती, एक औपचारिकता है। उसमें विद्यार्थियों का विश्वास भी नहीं है। इसलिए नये सिरे से भर्ती होनी चाहिये और व्याख्याता और प्राचार्यों के पदों को भरा जाना चाहिये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में लुइया कॉलेज, महाविद्यालय है, जिसमें हिन्दी, संस्कृत व विज्ञान के तीन पद खाली हैं, एक प्राचार्य बैठा है और उसमें कम से कम 400 लड़कियां हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप खुद स्वयं प्रोफेसर रहे हैं, डाक्टर हैं, निश्चित रूप से इन पदों को भरोगे। चार साल पहले राजलदेसर में कॉलेज खोला गया। बहुत शानदार भवन बन गया। 14 बीघा जमीन की हमने व्यवस्था कर दी, लेकिन वहां एक प्रिंसिपल बैठा है, सातों की सात पोस्ट खाली हैं और अन्य 12 पोस्टों पर भी एक भी कर्मचारी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता से इन्हें भरा जाये।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में छापर बहुत बड़ा कस्बा है, नगरपालिका है। वहां 25-30 किलोमीटर ऐरिये में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं

माननीय मंत्री महोदय, छापर में महाविद्यालय खोला जाये। राजलदेसर तहसील बन गई, वहां आईटीआई संस्था खोली जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र की आपसे यह विशेष मांग है।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कॉलेज में विद्यार्थियों का आना-जाना सिर्फ स्टाफ के अभाव में है। मेरे राजलदेसर कॉलेज में 200 सीटें हैं, वहां 438 आवेदन पत्र आये हुए हैं। वहां कम से कम 100-150 सीटें बढ़ाई जानी चाहिये, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का यह एरिया है, तत्काल यह व्यवस्था की जाये, ताकि छात्रों को परेशानी नहीं उठानी पड़े।

मैं लंबी बात नहीं करते हुए मांग संख्या 62 पर निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज सुरक्षित करने के लिये प्रयास करना चाहिये। आज कम से कम 11 हजार प्रति वर्ष और 15-20 रोज दुर्घटना में मौतें हो रही हैं, इनको कम करने का रास्ता अपनाना चाहिये।

msk/rtm/20.07.2024/1620/3a

जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गयी है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़क सुरक्षा जागरुकता सप्ताह चलता है, उसमें चालानों की औपचारिकता होती है। किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। औपचारिकता करके सड़क सप्ताह समाप्त कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उनमें कई इस प्रकार के वाहन होते हैं, जो इल्लिगल हैं, जिनके पास कागजात नहीं हैं। ऐसे कई लोग जो लगातार ओवरलोड चलते हैं, उनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग अपनी लोकल गाड़ियां लेकर चलते हैं, उनका चालान होता है। इससे असुरक्षा बढ़ती है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। आरटीओ, डीटीओ ऑफिस की स्थिति आप जानते हैं।

इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण बस सेवा शुरू की। कोविड के कारण बन्द हो गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां रोडवेज की व्यवस्था नहीं है। वहां पर रोडवेज की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण बस सेवा भी शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो रोडवेज बसें हैं, वे बहुत-सी जगह रुकती नहीं हैं। जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीकानेर से रोडवेज बसें आती हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, सरदारशहर से आती हैं और पूरे क्षेत्र में से निकलती हैं। भीरमसर एक बड़ा गांव है, चूरू बॉर्डर का गांव है। वहां दो बस स्टेण्ड, एक पुलिस स्टेशन के पास और एक सावदा गांव है। वहां मैंने आपके एमडी को बोल दिया। आपके कमिश्नर को भी मैंने कह दिया। आज तक वहां पर बसें नहीं रुकतीं। जबकि वह आइडेंटिफाई बस स्टेण्ड है। आज माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं। वहां पर जो बस स्टेण्ड है, उस पर आज से बसें रूकनी चाहिए। आप यह अपने प्रशासन को अवगत कराइये। यह बहुत बड़ी मांग है, जो आज नहीं, मेरे पास चुनाव से लेकर अब तक लगातार आती जा रही है।

इसके अलावा आपकी जो लोक परिवहन सेवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत फास्ट है। रोडवेज प्राइवेट गाड़ियों से आगे चलती है, इतनी फास्ट चलती है कि बहुत-सी बार दुर्घटनाएं होती हैं, इन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर यह स्थिति रही तो काम चलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो नई रोडवेज बसों का जो बेड़ा शामिल किया जा रहा है। बहुत-से ऐसे गांव हैं।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य। श्री अमृतलाल जी।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): साहब, मैं एक मिनट में कह दूंगा।

मेरे चूरू से रतनगढ़ वाया दाउदसर शुरू की जाये। चूरू और सरदारशहर की जो बसें रतनगढ़ में रूकती हैं, उन्हें सालासर तक किया जाये। सालासर तक रूट सुनिश्चित किया जाकर फेरे बढ़ाये जाने चाहिए। यह भी मेरी आपसे मांग है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सभी माननीय सदस्यों को 5 मिनट का वक्त दिया गया है। कृपया अपना वक्तव्य 5 मिनट में समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री अमृतलाल जी।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 22-उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24-तकनीकी शिक्षा और मांग संख्या 62-परिवहन। माननीय उप मुख्य मंत्री जी भी हैं, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी है। इस सदन में सभी सदस्यों की आशा और इच्छा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि बजट भाषण में विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी देना पुराने जमाने की परम्परा को जीवित रखने का अच्छा संदेश है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपये की घोषणा से काफी राहत प्रदान की गयी है।

राजकीय महाविद्यालय सराड़ा, सलूम्बर में शिक्षक और कर्मचारियों के कई पद रिक्त हैं। इससे अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन कॉलेज हैं। सराड़ा कॉलेज में स्नातक तक भूगोल व इतिहास के विषय खोले जायें। सलूम्बर नवगठित जिला मुख्यालय है। सलूम्बर में राजकीय तकनीकी महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जाये। साथ ही, आईटीआई झाडोल जो जयसमन्द पंचायत समिति है। जावर माइन्स, जो कि एक बहुत बड़ा खनन क्षेत्र है, हिन्दुस्तान जिंक के नाम से जाना चाहता है। वहां अगर एक आईटीआई मिल जाये। मेरे क्षेत्र में गिवला में एक आईटीआई खोली जाये। सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी व झलारा की आईटीआई में विभिन्न ट्रेड खोली जाये। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि सराड़ा, सलूम्बर, सेमारी के तीनों कॉलेजों की चारदीवारी करायी जाये। सभी महाविद्यालयों में सम्बन्धित विषय की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी नहीं होने से अध्यापन प्रभावित हो रहा है। सेमारी के नवीन महाविद्यालय को राजसेस से निर्मित महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाये। वर्तमान में नियमित शिक्षक शून्य

हैं। महाविद्यालय हेतु फर्नीचर भी नहीं है। छात्रों के अनुपात में विषय विशेषज्ञों की कमी होने से अध्यापन कार्य समय पर नहीं हो रहा है। कक्षा-कक्षों की कमी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से तकनीकी शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। बजट में प्रदेश की 30 आईटीआई में आधारभूत सुविधा, डेढ़ सौ आईटीआई का किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन महाविद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण कराना बहुत जरूरी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय, गिंगला में खोली जाये, ताकि बालिकाएं पढ़ सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन में यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार ने परिवहन के मामले में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने का कहा था। लेकिन नहीं जोड़ पाने की वजह से काफी असुविधा हो रही है। पिछले पांच साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र के सरकारी गाड़ी कोई नहीं जा रही है। जिला परिवहन कार्यालय में रिक्त पदों को भरा जाये। सलूम्बर में सरकारी बसों का संचालन, उदयपुर से सराड़ा, सेमारी, टोकर, सरकारी बसों को संचालित किया जाये। दूसरा रूट, उदयपुर से केवड़ा, अदवास, जावद, मेथूडी, गिंगला, करावली, गामरापाल, इसरवास, सलूम्बर, इटालीखेड़ा, रोठोड़ा, बोरई, देसूमनाथ होते हुए डूंगरपुर बस शुरू की जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान रोडवेज के लिए 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करेंगे। इनको बढ़ाने की जरूरत है। 800 बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है, उसको भी बढ़ाया जाये। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासनिक व संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आप 1650 कर्मियों की भर्ती करने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, मेरा उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि सब जानते हैं कि आपका डीटीओ, आरटीओ नकली बनकर, उस क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर साइड में गाड़ी लगाकर सारे दिन लूटमार करते हैं, उसको रोका जाये। धन्यवाद। जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री मनीष यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 22, 24, 62 पर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की एक ऐसी बात आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा। जिस शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम आजादी के पूर्व से पढ़ते आये हैं। आजादी के बाद तक देखते आये हैं। हमारे देश के बहुत स्वतन्त्रता सेनानी, जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश में गये। महात्मा गांधी हो, भीमराव अंबेडकर हो, उन्होंने जो हालात, परिस्थिति देश में उच्च शिक्षा को लेकर देखी।

mdp/rtm/20.07.2024/16:30/3b

आजादी के साथ में उच्च शिक्षा को लेकर इस प्रकार के अच्छे संस्थान स्थापित करके इस देश में उच्च शिक्षा का एक बड़ा स्तर करते हुए उन्होंने योगदान दिया। इसके साथ में शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, हर वर्ग को उसमें अवसर मिले और संविधान द्वारा आरक्षण की

व्यवस्था भी की गयी। आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा में रोस्टर प्रणाली बनायी गयी। रोस्टर प्रणाली के आधार पर यह तय किया गया कि ओबीसी/एससी/एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों को कैसे आरक्षण दिया जाए। आज हालात ऐसे हैं कि आरक्षण को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में रोस्टर रजिस्टर नहीं बने हुए। अगर कहीं पर रोस्टर रजिस्टर है भी तो सही तरीके से नहीं बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप बताइए भर्तियां किस आधार पर निकाली जा रही हैं? आरक्षित वर्ग के बहुत सारे युवकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, 2023 में 134 के लगभग एससी/एसटी के पद कम है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, 2014 में एससी/एसटी के 153 पद बेकलॉग के हैं, वह कहां पर हैं।

सभापति महोदय, ये जो शिक्षा नीति के साथ में उच्च शिक्षा में हम जिस प्रकार की चर्चा आज सेमेस्टर शिक्षा की हम कर रह हैं कि नई नीति लाकर सेमेस्टर प्रणाली हमने यहां पर लागू कर दी। आज परिस्थिति ऐसी है कि महाविद्यालयों में बच्चों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। बैठने की बात तो दूर, कई महाविद्यालय ऐसे हैं जहां वह सही तरीके से खड़े होकर संसाधनों के अभाव में शिक्षा नहीं ले सकते। दूसरी तरफ आपने सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ कर दी, जिससे फीस को दोगुना करके आपने गरीब युवाओं का नुकसान करने का काम किया है। यह एक तरीके से गलत है।

मैं राजस्थान विश्वविद्यालय सहित जो प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, उनके शिक्षकों के सम्बन्ध में भी चर्चा करना चाहूंगा। आज उनकी पदोन्नति समय पर नहीं हो रही है। उन शिक्षकों को पांच-पांच साल का इंतजार करना पड़ता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 325 शिक्षक ऐसे हैं, जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इससे शिक्षा का स्तर कम हो रहा है, गुणवत्ता कम हो रही है और शिक्षकों का मनोबल भी कम होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं विद्या संबल योजना की बात करना चाहूंगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने लगभग 300 से ज्यादा राजकीय महाविद्यालय खोले और शिक्षण व्यवस्था के लिए विद्या संबल योजना चलाई, जिसमें नियुक्ति एक वर्ष के लिए एपीआई स्कोर के आधार पर शुरू की गयी। इसमें 2000 के लगभग नेट/जीआरएफ/पीएचडी डिग्रीधारी बेरोजगारों को रोजगार मिला, लेकिन उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) सरकार इन योग्यताधारी युवाओं से हर 6 महीने में आवेदन मांग रही है।

सभापति महोदय, दो मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा।

पूरे सत्र के लिए इन युवाओं की नियुक्ति कर दें तो ये युवा अवसाद में नहीं आएंगे। इनको शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जाए। प्रदेश में फर्जी डिग्री का खेल भी बहुत चल रहा है। बहुत सारे ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय बन गये जो फर्जी डिग्री दे रहे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए बिल लाकर इनका निरसन किया जाए ताकि नौजवानों के साथ

अन्याय नहीं हो। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में छात्रसंघ के चुनाव बंद है। मैंने नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण लगाया और इस प्रस्ताव पर सरकार का जवाब आया जिसमें कहा गया कि 2006 से 2010 तक छात्रसंघ के चुनाव स्थगित किये गये। मैं कहना चाहता हूं कि 2006 से नहीं 2005 से 2010 के मध्य छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए। उच्च शिक्षा मंत्रालय से अगर ऐसा गलत जवाब गलत तथ्यों के आधार पर आता है, वह चिंताजनक है। इसमें यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के चुनाव हो रहे हैं। छात्रसंघ के चुनाव आवश्यक हैं। आज मुझे यहां आने का अवसर मिला है तो उस राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद की वजह से मिला। वहां के छात्रों ने मुझे छात्रसंघ का अध्यक्ष बनाया। मैं अनुरोध करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी छात्रसंघ के चुनाव शुरू करवा कर छात्रों के साथ न्याय करें। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारे विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट जैसी संस्थाओं में लाकर वहां पर भी छात्रों का रिप्रजेंटेशन बढ़ाने का काम करें।

मेरे क्षेत्र की कुछ डिमांड्स हैं। हमारे वहां पर बाबा गंगादास महिला महाविद्यालय है। वहां इतिहास सबजेक्ट को पीजी में लिया जाए। अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिक शास्त्र, संस्कृत, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र को पीजी में लिया जाए।

श्री सभापतिः विराजिए। श्री थावर चंद मीना।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): हमारे राड़ावास में कॉलेज बना हुआ है, उसमें विज्ञान संकाय खोला जाए। खेतरोली में सहशिक्षा महाविद्यालय खोला जाए। माननीय सभापति महोदय, परिवहन पर एक मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में जयपुर ग्रामीण का बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा हाईवे है और यहां पर बहुत बड़ी आवश्यकता है, लम्बे समय से हमारे यहां पर बस स्टॉप नहीं है, बस स्टैण्ड नहीं है, वह खोला जाए। हमारे यहां पर शाहपुरा आगार को प्रशासनिक और वितीय स्वीकृति जारी की जाए, जिससे हमारे इस आगार को फायदा हो।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 अन्य बसें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे जयपुर, दौसा, अलवर, चौमूं, सीकर, दिल्ली, बांसवाड़ा, हरिद्वार तक हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वह ठीक से चालू हो। हमारे यहां पर 200 फीट अजमेर बाइपास से जयपुर से लेकर दौलतपुरा, शाहपुरा, पावटा, विराट नगर, कोटपूतली के लिए नया रूट बनाया जाए, जिससे हमारे लोगों को फायदा हो।

श्री सभापतिः विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): हमारे यहां पर कई ऐसे रूट हैं, अभी तक जहां पर सरकारी बस सेवा नहीं है, वहां पर बस सेवा शुरू की जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री थावर चन्द।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का अवसर दिया। हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अन्दर उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, मैं उसका थोड़ा जिक्र करूंगा। हम उस इलाके से आते हैं जहां पर हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में सबके बड़े-बड़े वादे रहते हैं, बड़ी-बड़ी बातें रहती हैं और हमेशा रही हैं। अगर उस इलाके को आगे बढ़ाना ही है तो शिक्षा की सख्त आवश्यकता है। हमारे इलाके के अन्दर मजबूरी यह है कि कॉलेज की महंगी फीस और कॉलेज की सुविधा न होने की वजह से हमारे नौजवान भाई बहिन गुजरात, अहमदाबाद जैसे पास के इलाकों में जाकर मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं। हर साल यही स्थिति पैदा होती है कि महंगी फीस नहीं भर पाने के कारण कभी मां के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, कभी ब्याज से लाना पड़ता है, कभी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है।

हमारे क्षेत्र के अन्दर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आदिवासी को हम लोग उच्च शिक्षा में आगे लाएंगे, यदि आदिवासी को मुख्य धारा में जोडेंगे, शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है। हमारे इलाके का मुकाबला यदि सीकर, झुंझुनूं, जोधपुर से करने जाएंगे तो यहां पर बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलेगी। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे मेरा धरियावद का एक कॉलेज है, जिसके अन्दर 276 बच्चे उसके अन्दर है। हर बार तीन से चार हजार लोगों के आवेदन आते हैं। वह महाविद्यालय अभी थोड़े दिन पहले का ही बना हुआ है। अभी पानी टपकना स्टार्ट हो गया है। उस महाविद्यालय के चारों ओर न कोई बाउंड्री है, न कोई लेब है, न प्रोफेसर है। ऐसी स्थिति में हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वहां उच्च शिक्षा बेहतर हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले कई समय से मांग होती रही है कि वहां पर 80 सीटें एक बैच के अन्दर है, तो बाकी के नौजवान कहां पढ़ने जाएंगे। यह हमारे लिए सोचने की बात है। साथ ही साथ हमारी बड़ी विड़म्बना यह है कि 12वीं तक जैसे-तैसे हमारी बहिन-बेटियां पढ़ाई लिखाई करती हैं। उसके बाद में कॉलेज में सीटें न होने के कारण, उनके घर-परिवार वाले, घर से बाहर नहीं निकलने के कारण सोचते हैं कि उसको कितना दूर, कब तक, कहां तक भेज पाएंगे। हमारे धरियावद की स्थिति ये है कि उदयपुर 120 किलोमीटर है, बांसवाड़ा 100 किलोमीटर से ऊपर है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अन्दर कॉलेज की सीटें कम हैं तो जाएंगे तो कहा जाएंगे? प्राइवेट कॉलेज की बात आती है तो उनके अन्दर महंगी फीस की लूटमार होती है। इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह महंगी फीस नहीं ली जाए।

हम लोग छात्रवृत्ति पर निर्भर होते हैं तो वह भी समय पर उपलब्ध नहीं होती है तो जो गहने गिरवी रखे हैं, वे भी चले जाते हैं। जो जमीनें हमने गिरवी रखी हैं, वह भी चली जाती हैं। ऐसे वक्त में हमें कॉलेज के लिए सोचना पड़ेगा। यह स्थिति सिर्फ धरियावद की नहीं है। यह स्थिति बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में देखेंगे, हर जगह की

स्थिति है। इसको गंभीरता से लेकर सोचना चाहिए। चाहे धरियावद हो, प्रतापगढ़ जिला स्तर पर जो महाविद्यालय है, उसके अन्दर भी यही हाल है। सेक्शन बढ़ाने की बात थी, कभी बढ़ नहीं पाए।

Ans/rtm 16.40 3c 20.07.2024

यही हाल आसपुर व अन्य जगह का भी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक इलाका लसा़डिया है, जहां कॉलेज में स्टाफ की कमी है, दो-दो, तीन-तीन लोगों के भरोसे पूरा कॉलेज चलता है। जलारा एक ऐसा ब्लाक है, जहां आज तक कॉलेज की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाई। जलारा के अन्दर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो महंगी फीस इकट्ठी के लिए बाहर मजदूरी करने जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उन नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। आज आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि वहां की बहन-बेटियों के लिए धरियावाद विधान सभा में एक कॉलेज खोला जाए, साथ ही सीटों में वृद्धि की जाए।

मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहूंगा। वहां की स्कूलें हैं, पिछले साल एक स्कूल में 104 बच्चे पढ़ाई करते थे, बारिश के समय भवन गिर गया। मौक़े पर कलक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, सब दौड़कर गए, फोटो लिए, सब किया लेकिन अभी तक भवन नहीं बना पाया है। उस स्थिति में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। एक ही कमरा है उसके अन्दर। मानपुर का ओडाफला गांव है। मैंने एक विद्यालय का उदाहरण दिया है, ऐसे कई विद्यालय हैं, चाहे वह पहाड़ा का इलाका है, चाहे मुंगाना का इलाका है, इस स्थिति में हम लोगों के लिए शिक्षा की बहुत जरूरत है, हमें क्रमोन्नत विद्यालय व विद्यालय भवन उपलब्ध करवाने चाहिए।

मैं परिवहन की बात करना चाहूंगा। जरूरी मांगें हैं, मैं वही करना चाहूंगा। मेरे धरियावाद ब्लाक से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से नौजवान सुबह-सुबह डयूटी करने जाते हैं, कोई बस नहीं है। पहले चलती थी, अब बंद हो गई। धरियावाद से मंसोर के लिए सुबह व शाम को बसें, आठ बजे तक चालू करने की जरूरत है, ताकि सब समय पर डयूटी पर जा सकें। हमारे लसा़डिया के ब्लाक हैं, सलूम्बर वाया लसा़डिया, लसाडिया से बड़ी सादड़ी तक आम जन का लगा रहता है, लेकिन कोई बस सेवा नहीं है, अतः वहाँ एक बस की आवश्यकता है। हमारे अधिकतर लोग मजदूरी के लिए अहमदाबाद जाते हैं, मुम्बई जाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट वाले मोटी रकम वसूल करते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि धरियावाद से होकर लोहागढ़, बगराना होते आसपुर से हिम्मत नगर और अहमदाबाद की तीन बसें चालू की जाएं, जिससे आने जाने में सुविधा हो सके। जब त्यौहार का दिन होता है तो हमें अतिरिक्त बस सुविधा मिलनी चाहिए।

साथ ही, एक और मांग करना चाहूंगा कि धरियावाद से जोधपुर हाईकोर्ट के लिए, कोई भी मामले होते हैं तो वहां जाना पड़ता है,वहां बस सेवा करनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो उदयपुर में ही हाईकोर्ट खोल दिया जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा

कि आज हम लोग शिक्षा में काफी पिछड़े व कमजोर है। ट्राइबल बेल्ट के लिए शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान भी करना चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ उस बेल्ट में अलग से बजट भी देना चाहिए, ताकि वहां के नौजवान पढ़-लिख सकें। पढ़ लिखकर समाज का निर्माण कर सकें। देश का भविष्य हैं, उन नौजवानों को आगे बढ़ने का एक अवसर मिल सके।

साथ ही, यह भी बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर पढ़ाना चाहिए लेकिन प्रोफेसर यहां जयपुर बैठेगा, कई बार कोचिंग चलाते होंगे, नाम उसक होगा लेकिन उनके नाम पर दूसरे लड़के वहां पढ़ाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था पर आपको अकुंश लगाना पड़ेगा। व्यवस्था करके आगे बढ़ाना पड़ेगा।

मैं जब विद्यालय में बीएड की इन्टरशिप करता था तो पूरे दिन देखता था कि मां-बहनें खाना बनाती थीं तो उनको पूरा दिन लगता था, लेकिन उनको 2400 रुपये ही मिलते थे। ऐसे में परिवार का पेट कैसे पाले, बच्चे कैसे पाले। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं माता-बहनें जो स्कूल में पढ़ाती है, आंगनबाड़ी में जो खाना बनाती हैं, उनके लिए अतिरिक्त मानदेय बढ़ाने की जरूरत है ताकि वह अपना परिवार चला सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, आपको इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे इलाक़े में मुंगाना क्षेत्र है। वहां से बहन-बेटियां कॉलज पढ़ने के लिए आती है तो 50 किलोमीटर तक धरियावाद दूर पड़ता है। ऐसे में एक बस सेवा भी चालू करनी चाहिए साथ ही एक बालिका कॉलेज उस इलाक़े में देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की बात मैंने आपके सामने रखी।

मेरे अन्य साथियों ने भी छात्रसंघ चुनाव की बात की। छात्र राजनीति की पहली नींव ही कॉलेज है जहां से हमारे कई होनहार नौजवान निकले हैं जो आज देश के अन्दर बड़े-बड़े मुकाम पर राजनीति के माध्यम से गए हैं। कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव कराने की अति आवश्यकता है।

मैं आपका पुनः धन्यवाद करुंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बीएड, एसटीसी, बीपीएड की परीक्षा में न्यूनतम पात्रता अंक लागू कर दिया गया है। न्यूनतम पात्रता अंक हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। हम लोग बड़ी मुश्किल से फीस जुटाकर यहां जयपुर कोचिंग करने आते हैं, ऐसी हालत में हमारे लिए पात्रता पर कभी-कभी पहुंच पाना भारी पड़ जाता है, इसलिए कई बीपीएड, नर्सिंग की सीटें खाली रह जाती है।

एक बात और बताना चाहूंगा। सेमेस्टर पद्धति लागू है। इस सेमेस्टर के माध्यम से चाहे वह बीएड हो, नर्सिंग हो, अन्य जगह पर दो-दो, तीन-तीन बार फीस वसूल की जाती है। ऐसे वक्त वहां के नौजवान के लिए बहुत मजबूरी होती है, मजबूरी में कभी-कभी वह फीस नहीं भर पाते हैं, ऐसे में उनको कभी-कभी संस्था से निकाला जाता है या एग्जाम से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए सेमेस्टर प्रणाली खतम कर दिया जाना चाहिए। मैं आपका पुनः धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया।

मैं एक बात और बताना चाहूंगा। हमारे इलाक़े के बहुत सारे नौजवान अहमदाबाद,

गुजरात, मुम्बई काम करने जाते हैं, जब त्यौहार के दिन होते हैं, वापस आते वक्त किराये का साधन करके आते हैं। रतनपुर बॉर्डर पर आरटीओ, डीटीओ द्वारा उनकी गाड़ी को पकड़ा जाता है और भारी भरकम रकम वसूली जाती है। बड़ी मुश्किल से तो किश्तों पर गाड़ी लेकर आते हैं। जब भारी भरकम रकम वसूली जाती है तो उनके लिए गाड़ी छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब भी त्यौहार के दिन हों, हमें रतनपुर बॉर्डर पर छूट दी जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री रामबिलास।

श्री रामबिलास (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 की अनुदान मांग संख्या 22 पर उच्च शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव के तहत बोलने का अवसर दिया।

माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी व माननीय उप मुख्य मंत्री प्रेम चंद जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा उक्त बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कन्या विद्यालय को यूजी से पीजी में क्रमोन्न्त किया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने राजसेस के तहत 3-4 कॉलेज खोली थी। कॉलेज तो खोल दी पर आज उनकी स्थिति यह है कि फैकल्टी के नाम पर उन कॉलेजों में जीरो है। वहां एक भी लेक्चरार, प्रिंसिपल नहीं है। डेपुटेशन पर एक-एक, दो-दो लेक्चरार लगे हुए थे, वह भी वहां से अब हट गए सरकार द्वारा डेपुटेशन खतम करने की वजह से। तीनों-चारों कॉलेज की यह स्थिति है कि वहां स्टाफ जीरो हो गया, खाली विद्या सम्बल के एक-एक, दो-दो लड़के लगे हुए हैं। इसके तहत मैं तो मानता हूं कि ऐसे कॉलेज जहां युवा व बच्चियां पढ़ने जा रही है, उनके पढ़ने के बजाय भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जिस कॉलेज में शिक्षा नहीं मिलेगी, टीचर नहीं है, फैकल्टी नहीं है तो क्या पढ पाएंगे और क्या आगे बढ़ पाएंगे, वह तो एक फॉर्मेलिटी है कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, पर वहां शिक्षा नहीं मिल रही। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि उन कॉलेजों में पिछली सरकार तो केवल घोषणा कर गई और कुछ व्यवस्था नहीं की। मेरा आपसे आग्रह है कि इन कॉलेजों में फैकल्टी की व्यवस्था की जाए और वहां लेक्चरार लगाए जाए।

दूसरा, माननीय सभापति जी, मेरी विधान सभा का एक क्षेत्र आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से पिछ्डा हुआ है। उसमें एक इलाका ऐसा है जहां 20-25 किलोमीटर तक कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। कोथून रोड पर, सुशीलपुरा, दौलतपुरा, ओदायली, सवासा, महाराजपुरा ऐसी ग्राम पंचायतें पड़ती है जहां बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

VPS-RTM-20.07.2024-16.50-3d

बच्चियां कॉलेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण या तो 12वीं तक पढ़कर वे पढ़ाई छोड़ देती हैं या अन्यथा उनको बहुत दूर जाना पड़ता है तो मेरा विशेषकर माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि वहां पर एक कॉलेज खोला जाये ताकि बच्चियों को पढ़ाई की व्यवस्था

हो सके और यह कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने वाला निर्णय होगा। पुनः आपको धन्यवाद देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री ललित यादव।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आज मुझे आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकरजी ने यह कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा भी और देश दुनिया में अपने इलाके का नाम भी रोशन करने का काम भी करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। आदरणीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा को लेकर विशेष प्रबंधन करने का आप काम करेंगे। उच्च शिक्षा के तंत्र में हिन्दुस्तान अपना अव्वल स्थान रखता है। सभी को उच्च शिक्षा का समान अवसर मिल सके, इसके लिए एक नीति के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में आजादी के बाद महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में काफी वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस हमारा देश और प्रदेश कर रहा है, लेकिन मैं कुछ विकसित देशों की चर्चा यहां पर करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ पढ़ा है, न्यूजीलैंड के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में बजट लगभग 14.5 परसेंट का वे लोग रखते हैं। अमेरिका में 6.89 परसेंट का रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5.9 का, फ्रांस में 5.20, जर्मनी में 4.22 का, जापान में 4.8 और हमारे हिन्दुस्तान में इसका बजट हर वित्तीय वर्ष में कम होने का काम हो रहा है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि इस पर भी विशेष ध्यान देने की आज जरूरत है, लेकिन विकसित देशों के अन्दर बहुत सारी संस्थाएं नहीं हैं, कुछ एक संस्थाएं उनकी हैं तो उनमें हजारों लोग पढ़ते हैं एक ही छत के नीचे, हम गांव-गांव, गली-गली में भले ही कितनी ही संस्था खोल ले पर मेरा इस सदन से अनुरोध है कि हम भी कोई उस प्रकार के संस्थान बनायें कि जिससे विश्व स्तर पर उनकी पहचान हो सके और देश दुनिया से आकर वह विद्यार्थी यहां हमारे आकर पढ़ने का काम कर सके। हम भी सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करें। भारत के अन्दर बहुत सारे कॉलेज, संस्थाएं एवं महाविद्यालय चल रहे हैं जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में चल रहे हैं तो मेरा यह अनुरोध आप लोगों से है कि जिन महाविद्यालयों के अन्दर जो गली-गली में हमने खोल रखे हैं, उनमें प्रोपर सुविधाएं मिल सके, बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सके, इस पर ध्यान देने की हमें आज आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अन्दर रोस्टर प्रणाली का संधारण नहीं किया जा रहा है जिससे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए मेरा अनुरोध

आपसे यह है कि उन विश्वविद्यालयों के अन्दर रोस्टर रजिस्टर बनाया जाये ताकि हमारे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग का प्रतिनिधित्व इन विश्वविद्यालयों में हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की एक अख़बार की कटिंग पढ़ रहा था, जिसमें मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के अन्दर सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने का हम लोग काम करेंगे, तो मेरा यह अनुरोध है कि यह बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ न्याय नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक बात की ओर कि यह आप देखिये कि कितनी भेदभाव की हद पार हो गयी कि सितम्बर, 2023 में सामाजिक न्याय के पुरोधा राहुल गांधी महारानी कॉलेज में आये थे जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, स्कूटी वितरण प्रोग्राम में वे गये और स्कूटी वितरण प्रोग्राम के बाद चुनाव हुआ और हमारी सरकार बदल गयी। इस सरकार ने बदले की भावना से प्रोफेसर निमाली सिंह जो प्रिंसिपल वहां पर थीं, उसके ऊपर यह दबाव बनाया और यह कहा कि आप इस्तीफा दे दो। क्यों? क्योंकि आपने राहुल गांधी का वहां पर प्रोग्राम करवाया है। वह कोर्ट में गयीं और कोर्ट में जाने के बाद उसको स्टे मिल गया, उसके बाद विश्वविद्यालय डी.बी. में गया, वहां पर वे भी भी डी.बी. में गईं, वहां पर भी उसको स्टे मिल गया लेकिन आज तक उसके साथ न्याय नहीं हो सका है तो मैं सदन के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि उस प्रिंसिपल के साथ में न्याय हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो छात्र संघ के चुनाव प्रदेश में बंद हो गये, ये हमारे जितने भी साथी यहां पर बैठे हैं, ये सब लोग उस छात्र संघ के चुनाव से यहां आकर बैठे हैं, उस चुनाव की बदौलत हम लोग यहां पर पहुंच पाये हैं तो इसलिए उस चुनाव को भी चालू करवाने का काम किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालयों में जो वी.सी. लगाये गये हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, कौन लगा रहा है? मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने तो नहीं लगाये लेकिन यह कहां से लग रहे हैं, आदरणीय प्रेम चन्दजी जानते हैं इस बात को, तो इनको भी ठीक करने का आप लोग काम करें, जिससे प्रदेश के साथ न्याय हो सके।

माननीय सभापति महोदय, विद्या सम्बल योजना केन्द्र में 1500 जो हमारे साथी लगे हुए थे उनके साथ में न्याय करने का भी काम करें। हर छमाही में हम लोग उनका आवेदन मांग रहे हैं, जिससे पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है तो आप लोग इस पर भी ध्यान देने का काम करें। मेरे क्षेत्र में राजकीय कॉलेज का भवन बनना बाकी है जो पिछले ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट चाहूंगा, मैं मेरी मांग करूंगा।

राजकीय कॉलेज में भवन बनना है जो नहीं बन पाया है तो मेरा अनुरोध सदन से यह है कि आप उस भवन को बनाने का काम करें, जिससे वहां के विद्यार्थी को फायदा हो सके। नीमराना का भवन भी नहीं बन पाया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग के अन्दर जयपुर से लेकर दिल्ली रोड के ऊपर जितने भी हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, वे इस सरकार के बनने के बाद वसूली भाई बन गये हैं, वे वसूली कर रहे हैं, नाम से वसूली कर रहे हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं कि जिन अधिकारी के रिश्तेदार की गाड़ी चल रही है और दूसरे आदमियों को रोकने का काम कर रहे हैं। वे उनकी पर्ची निकाल कर, वे लोग वहां पर चालान काटने का काम कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उनका नाम भी बताऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे मुण्डावर क्षेत्र के अन्दर 170-180 कम्पनियां लगी हुई हैं। मैं मांग करता हूं कि मेरे मुण्डावर में भी कोई तकनीकी महाविद्यालय खुलें, जिससे हमारे वहां के नौजवानों को फायदा हो सके और जो तकनीकी महाविद्यालय खुलेगा, आई.टी.आई. हमारे वहां पर है, उनसे हमारा जो विद्यार्थी पढ़कर बाहर निकल रहा है, उस पर भी हमको चिंता करने की आवश्यकता है कि उससे वास्तव में कितनों को रोजगार मिल रहा है?

श्री सभापतिः आप समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): उसको भी सुनिश्चित करने का आप लोग काम करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः आप शुरू करें। माननीय सदस्य, आप पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 एवं 62 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की बात चल रही है तो आज के समय में पूरे प्रदेश के युवा बड़ी उम्मीद के साथ में इस तरफ देख रहे हैं। मैं खुद छात्र संघ चुनाव के माध्यम से, छात्र राजनीति के माध्यम से उस विश्वविद्यालय से यहां तक पहुंचा हूं। उस विश्वविद्यालय की बात मैं करने आया हूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि समस्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है, क्लासेज प्रोपर कहीं पर भी नहीं लग रही हैं। छात्र राजनीति से कई सारे भाई आ रहे हैं तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो सीटें खाली हैं, इनको जल्दी से जल्दी भरी जायें। साथ ही साथ जोधपुर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा कि एम.पी.ई.टी. एक एग्जाम हुआ था पीएच.डी. का तो उसमें भारी अनियमितताएं हुई थीं उसकी भी एक बार सही तरीके से जांच करवायी जाये।

साथ ही साथ, मैं अपने क्षेत्र की बात भी करूंगा कि सीमांत क्षेत्र से मैं आता हूं। शिव और गडरा में आजादी के 70-75 साल के बाद एक-एक कॉलेज दी गयी पर आप यह मानेंगे

कि उस कॉलेज में स्टाफ के नाम पर सिर्फ एक आदमी को अपाइंट कर रखा है। एक आदमी के भरोसे वह पूरी कॉलेज चल रही है। पिछले दो-तीन दिन पहले भी कई सारे अखबारों में यह खबरें भी छपी हैं तो हमें बड़ा दु:ख होता है। छात्र राजनीति के माध्यम से एवं विश्वविद्यालयों से जो निकल कर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचते हैं उन्हीं के क्षेत्र की अगर यह स्थिति हो तो हम सभी के लिए, विशेषकर मेरे लिए यह पीड़ा की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो खाली पद हैं, कृपा करके इनको जल्दी भरा जाये और साथ ही साथ उस सीमांत क्षेत्र में विज्ञान संकाय खोलने की ज्यादा जरूरत है, आप विज्ञान संकाय खोलें। स्किल के मामले में हमारे उस तरफ के युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस हेतु आप पॉलिटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई. और यह तमाम जितने भी नये संस्थान हो सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र को दें, यह मेरा निवेदन है।

साथ ही साथ, खेलों के मामले में धीरे-धीरे हम पिछड़ते जा रहे हैं। आपसे इंडोर स्टेडियम के लिए मैं डिमांड करूंगा, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि आप शिव में एक इंडोर स्टेडियम कॉलेज को दें, ई-लाइब्रेरी दें।

SSY/RTM/20.07.2024/17:00/3e

शिव बाबा गरीब नाथ जी की धरती है। वहां जो महाविद्यालय खुला है, उसका नाम बाबा गरीब नाथ जी के नाम से हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी वाइस चांसलर्स की बात चल रही थी। वाइस चांसलर एक एकेडमिक पोस्ट है। आप वहां शिक्षाविदों को भेजें, राजनीति करने वालों को कृपया ना भेजें।

मेरा निवेदन रहेगा कि बीएड, बीएसटीसी और तमाम यह जो कॉलेजेज हैं, इनके अन्दर डोनेशन के नाम पर मोटा पैसा वसूला जा रहा है, कृपया कर आप इस पर भी एक बार नजर डालें। साथ ही पेट्रोकैमिकल की जरूरत उस क्षेत्र को है, पेट्रोकैमिकल के लिए आप नई ब्रांचेज उस क्षेत्र को दें।

शिव के लिए मैं एनसीसी की डिमांड भी करुंगा। एगीकल्चर कॉलेज की और वेटरिनरी कॉलेजेज की जरुरत है। आप उस क्षेत्र को देखते हुए एग्रीकल्चर और वेटरिनरी कॉलेज की भी व्यवस्था करावें।

मेरा निवेदन रहेगा, मैं ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि बालिका शिक्षा की हम हर समय बात करते हैं, बालिका शिक्षा को मुफ्त करने का आपको मेरा सुझाव है। आप एक ऐतिहासिक कदम बढ़ायें ताकि हमारी बच्चियां पढ़ सकें। जब कहा जाता है कि केजी से लेकर पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे लेकिन एक जगह भी यह नहीं हो रहा है। आप कृपया करके इस बारे में भी सोचें।

साथ ही, आज का समय एआई का, रोबोटिक्स का, डेटा एनालिस्टिक का है, आज भी हम उसी पुराने रीति-रिवाज से चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में सोचें। जो भी

हमारे पुस्तकालय हैं, प्रयोगशालाएं हैं, आप उनको रिनोवेट कैसे कर सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नये संसाधन कैसे जुटा सकते हैं, इस हेतु भी आप आगे कदम बढ़ायें। इस चीज का मुझे भरोसा है।

आज के समय में समस्याएं ज्यादा हैं। 8 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले यह तमाम लोग जो आज आपसे निवेदन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2027-28 तक, आने वाले 5 साल बाद तक हमारे पास 70 लाख बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो जायेगी, उसके लिए हमें सोचना होगा। नये संसाधनों को तैयार करना होगा।

श्री सभापतिः श्री भैरा राम।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सरकारी आंकड़े और रिपोर्ट कह रही हैं कि 88 लाख आज के समय में बेरोजगार हैं। समस्याएं खूब हैं पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी पूरी मेहनत करके इन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे।

श्री सभापतिः श्री भैरा राम।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा। यह आज नहीं तो कल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव जरूर करायें।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): सभापति महोदय, मांग संख्या 22, मांग संख्या 24, मांग संख्या 62 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं ओसियां विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। ओसियां में एक राजकीय पीजी कॉलेज है, उसमें 2013 से 2018 के टाइम में उस कॉलेज का शैक्षणिक स्टाफ को छोड़ा था तो लगभग पूरी पोस्टें भरी हुई थी। पिछले 2018 से 2023 के बीच में 5 स्टाफ तो डेपुटेशन पर चले गये और पीजी कॉलेज को चलाने के लिए मुश्किल से 5 स्टाफ बचे हैं। विद्यार्थियों की संख्या 1200 से ऊपर है। इसमें मेरा निवेदन है कि आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग की 41 पोस्टें हैं और उसमें से 22 खाली पड़ी हैं, माननीय उप मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस कॉलेज में जल्दी से जल्दी पोस्टों को भरा जाये।

मथानिया में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय है। उसके भी यही हालात हैं। उसकी स्वीकृत पोस्टें 20 हैं, उसमें भी 3 तो डेपुटेशन पर हैं और आज वहां मुश्किल से 3-4 लोग ही काम कर रहे हैं। उसमें भी लगभग 14 पोस्टें खाली हैं।

एक आपका राजकीय कृषि महाविद्यालय है, जो 2022 की बजट घोषणा में खुला था। 29.06.2022 को आपका राजकीय कृषि महाविद्यालय खुला। उसमें आपके स्वीकृत पद तो टोटल 30 हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि उस कृषि महाविद्यालय के अन्दर एक चपरासी भी नहीं है। अगर महाविद्यालय का भवन ही नहीं है तो उसको ताला लगाने की भी जरूरत नहीं है। उधार की बिल्डिंग में यह कृषि महाविद्यालय चल रहा है। मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, आपके स्वीकृत पद 30 हैं तो जल्दी से जल्दी कृषि महाविद्यालय में, क्योंकि हमारा

ओसियां विधान सभा क्षेत्र है, वह कृषि आधारित क्षेत्र है और डबल क्रॉप एरिया है, वहां किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, उसके अन्दर पिछले लगभग डेढ़, 2 साल से एक भी कार्मिक टीचिंग या नॉन टीचिंग उपलब्ध नहीं है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि इसकी व्यवस्था की जाये।

एक मेरा दूसरा विषय है, 1971 के अन्दर वीर गोरखा राम जी हमारे क्षेत्र के शहीद हुए। ओसियां विधान सभा क्षेत्र में जो पीजी कॉलेज है, उसके नामकरण की फाइल 2017 से 2018 तक चलकर पूरी तैयार हो गयी थी, लेकिन उसका नामकरण नहीं हुआ। आपसे मेरा निवेदन है कि शहीद वीर गोरखा राम जी के नाम से इस कॉलेज का नामकरण हो जाये। आपके पास में फाइल पड़ी है। यह मेरी मांग है कि शहीदों के सम्मान में इस कॉलेज का नामकरण हो जाये।

मांग संख्या 62 में मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि 2013-18 में ओसियां विधान सभा क्षेत्र में 3 रोडवेज बसें चलती थी, वह 2018 में बंद हो गई। पूरे ओसियां विधान सभा क्षेत्र में किसानों के बच्चे जोधपुर जाते, कोई बीमार होता तो वह इलाज के लिए भी जाते, और भी शहर का कोई काम होता तो भेड़-भाकरी से लेकर, सामड़ो, एकलखोड़ी, डाबड़ी, खाबड़ा, खेतासर, मांडी होते हुए जोधपुर जाती थी। आपसे मेरा निवेदन है कि इन तीनों बसों को वापस शुरू किया जाये।

एक महत्वपूर्ण सुझाव है माननीय मुख्य मंत्री जी से, कॉलेज शिक्षा के अन्दर एक पाठ्यक्रम यदि सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग सुरक्षा का लागू कर दिया जाये, जो बच्चे कॉलेज शिक्षा में आ जाते हैं तो उनकी उम्र 17 से 18 साल होती है, यह मेरा पूरे सदन के माध्यम से सुझाव है कि जितने सड़क एक्सीडेंट होते हैं, उसके अन्दर कहीं न कहीं जो हमारा नवयुवक है...

श्री सभापतिः विराजिये। श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): उनको शुरू से ही यदि सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग सुरक्षा दें तो यह महत्वपूर्ण सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरी आखिरी बात, एक मिनट।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): ओसियां विधान सभा क्षेत्र में और पूरे जोधपुर जिले में मैंने देखा है कि जो किसानों की ट्रेक्टर ट्राली है, उनके पीछे यदि रिफलेक्टर लगा दिये जायें तो यह एक्सीडेंट कम से कम हो जायें।

माननीय उप मुख्य मंत्री जी, आपने ओसियां विधान सभा में कन्या महाविद्यालय दी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। शिक्षा के द्वारा उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। विद्यां ददाति विनयं, शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, चन्दनं न वने वने। चंदन एक वृक्ष है जो सब जगह नहीं प्राप्त होता है। शिक्षा भी एक ऐसा ही शस्त्र है। जिसके अन्दर अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के ब्लाक मुख्यालय पाचूं में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव भेजा था। वित्त मंत्री महोदय को बजट पूर्व यथा समय लिखित में भिजवा दिया था, परंतु यह खेदजनक है कि परिवर्तित बजट 2024-25 में पाचूं महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा नहीं की गई।

एक तरफ हम उच्च शिक्षा में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का दिखावा कर रहे हैं, वहीं यदि मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के ब्लॉक मुख्यालय पाचूं व आसपास के ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा की बात करूं तो वहां आज भी स्थिति यही है। पाचूं के आसपास, दूरदराज कोई महाविद्यालय नहीं है। यहां के स्थानीय बालक, बालिकाओं को उच्च अध्ययन हेतु काफी दूर जाना पड़ता है। ऐसे में वहां का मजदूर, किसान अपने बच्चों की पढ़ाई 12वीं के बाद छुड़वा देते हैं। खास तौर पर बालिकाएं निकट में महाविद्यालय के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती हैं।

Spp/Rtm/20.07.2024/17:10/3f

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा का पांचू मुख्यालय बीकानेर जिले के अंतिम छोर में स्थित है। पांचू और बिलोद मुख्यालय में लगभग 30 हजार की आबादी है। पांचू वर्तमान में उप तहसील है। पांचू के आसपास लगभग 11 ग्राम पंचायतें और 85 ग्राम राजस्व ढाणियां लगती हैं और इन ग्रामीण इलाकों में एक लाख से अधिक मजदूर व किसान निवास करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा की तहसील जसरासर के राजकीय महाविद्यालय की यदि मैं बात करूं तो यह महाविद्यालय के केवल एक सहायक आचार्य के भरोसे चल रहा है। उप सहायक आचार्य की सेवाएं भी संविदा पर है। महाविद्यालय में कुल 21 कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं, इनमें से करीब 20 रिक्त चल रहे हैं। इस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? महाविद्यालय की शैक्षिक व प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूं कि मजदूर व किसान के बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा व्यवस्था व सुविधाओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार जसरासर महाविद्यालय में रिक्त चल रहे तमाम 20 पदों को भरने का काम करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के पांचू ब्लॉक मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करायें।

विद्या ददाति विनयं विनायकद् याति पत्रातम्|
पत्रत्वत् धनं आप्नोति धनाद धर्मं ततः सुखम्||
धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज न्यांगली (अनुपस्थित) श्री जयकृष्ण पटेल। माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। सीधे अपने क्षेत्र की कोई बात हो तो वह कह दें दो मिनट में।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हम जिस उच्च शिक्षा की बात करते हैं, हम आपके माध्यम से हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्य मंत्री महोदय हैं, उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, वह अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर हमारा जो विश्वविद्यालय है, उससे पूर्व हमारा मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय था और बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर हमारा जो गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय है, वह स्थापित तो कर दिया है, 2014 से लेकर अब तक वहां पर जो कार्मिक हैं, वह संविदा पर लगे हुए हैं तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र का अगर सुधार करना है, उसको विकास की मुख्य धारा के अन्दर अगर लाना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो गुरु गोविन्द विश्वविद्यालय है उसके अन्दर जितने भी रिक्त पद हैं, उनको तत्काल रूप से भरा जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गुरु गोविन्द विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जितने भी महाविद्यालय आते हैं, उन महाविद्यालयों के अन्दर पृथक् से हमारे स्थानीय बच्चे जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उन बच्चों के हिसाब से वहां पर आरक्षण की व्यवस्था हो। वहां पर उनके एडमिशन नहीं होते हैं। वहां पर 16, 12 और EWS सहित पांच प्रतिशत और 36 सामान्य की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर हमारे वहां पर एडमिशन लागू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर जो आरक्षण की व्यवस्था है, अनुसूचित जनजाति के लिये 16 और अनुसूचित जाति के 5 और अनारक्षित के लिये 50 प्रतिशत है, उसके अनुसार ही भर्ती की जाये। हमारे वहां पर अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर जो उच्च शिक्षा और माध्यमिक के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से कई सारे विद्यार्थी उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययन से वंचित हो रहे हैं। छह माह से हमारे यहां जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उसको प्रदान की जाये और हमारे वहां पर सरकारी महाविद्यालय में प्रत्येक महाविद्यालय में पृथक बालक और बालिका छात्रावास खोले जायें।

माननीय सभापति महोदय, गुरु गोविन्द विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में बने छात्रावास की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये। आदिवासी विद्यार्थियों को ...(व्यवधान).. धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपीचन्द मीणा।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा, 24 - तकनीकी शिक्षा एवं 62 - परिवहन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री ने और हमारी सरकार ने शिक्षा के सर्वोच्च संस्था विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरू की पदवी देकर हमारी सभ्यता और संस्कृति को चरितार्थ किया है। कुलपति से कुलगुरू की ओर जाना गुरु-शिष्य परम्पराओं को जीवित करता है। यही से संस्कार परिष्कृत होने प्रारम्भ होते हैं। प्रदेश में आवश्यकतानुसार महाविद्यालय, आई टी आई, पोलिटैक्निक महाविद्यालय खोले गये हैं। यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी और हमारे डिप्टी सी एम बैरवा साहब के नेतृत्व में शानदार बजट प्राप्त हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी उपकृत किया गया है। जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय की सौगात के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय वित्त मंत्री महोदया और हमारे उप मुख्य मंत्री प्रेमचन्द जी बैरवा साहब को भी जहाजपुर की जनता की ओर से इनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। महाविद्यालयों में यू.जी. से पी.जी. में क्रमोन्नत किया गया हमारी सरकार के द्वारा। प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुधार की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 22 के तहत सदन के माध्यम से सरकार से मेरी विनयपूर्वक मांग है कि मेरे क्षेत्र में विकास के कुछ कार्य हों। जहाजपुर महाविद्यालय की चारदीवारी पूर्ण की जावे। जहाजपुर महाविद्यालय में खेलों के लिये आउटडोर-इनडोर स्टेडियम स्वीकृत करके भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ करवाई जाये। कोटड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोला जावे। लम्बे समय से हमारे उस क्षेत्र में जोकि हमारे नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा कोटड़ी ब्लॉक में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। जहाजपुर महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरा जाये। आवासीय छात्रावास भी स्वीकृत किया जाये। जहाजपुर महाविद्यालय में पानी, बिजली की व्यवस्था एवं मूलभूत जो हमारे बच्चों के लिये रिक्त पद हैं, वह रिक्त पद भरे जायें, यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर उपखण्ड क्षेत्र में आई टी आई पोलिटैक्निक कॉलेज खोला जाये। मैं मेरे क्षेत्र की मांग रखता हूं। जहाजपुर उप खण्ड मुख्यालय एवं कोटडी उपखण्ड मुख्यालय पर पृथक्-पृथक् से बस स्टैंड भवन का निर्माण कराया जाये। माननीय सभापति महोदय, वहां पर लम्बे समय से मांग है। कोटड़ी में चारभुजा नाथ का मन्दिर है, हजारों श्रद्धालु यात्री आते हैं तो वहां बहुत अति-आवश्यक है। उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन बस डिपो बनाये जाने की स्वीकृति की मैं मांग करता हूं। भीलवाड़ा जिले की बसों को वापस पुनः चालू की जाये। पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे भीलवाड़ा जिले की 117 में से 47 बसें बन्द कर दी गयी थी द्वेषतापूर्वक, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि हमें 50 नई बसें आवंटित की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर और भीलवाड़ा का मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आर टी ओ कार्यालय में फर्जी रजिस्ट्रेशन किये गये। निजी क्षेत्र को

लाभ पहुंचाने की मंशा से अनेक नीतियां बनायी गयीं, लेकिन फायदा परिवहन माफियाओं को पहुंचाया। इस सबका समाधान हमारी सरकार ने खोज लिया है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार से मेरा विशेष आग्रह है कि विगत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के पांच वर्षों के दौरान विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर और भीलवाड़ा परिवहन और यातायात की दृष्टि से बहुत ही दीन-हीन रहा है। कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया था। उल्टा भाजपा समर्थित विशेषकर हमारे क्षेत्र के गांवों में पहले से जो निगम की बसों का संचालन होता था, उनको बन्द कर दिया गया। बस स्टैंडों का अभाव बना रहा। मैं, माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की मांग आपके माध्यम से रखता हूं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस के कुशासन एवं भ्रष्टाचार के कारण भीलवाड़ा में हर विभाग में घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए। बजरी घोटाला, बस घोटाला और यू आई टी घोटाला, भूमि के घोटाले हुए हैं। भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार की राशि के रूप में पारिवारिक सदस्यों के नाम रजिस्ट्री करायी गयी। जिला लेवल के अधिकारी केवल मूकदर्शक बनकर हारे हुए विधायकों को मुख्य मंत्री का पॉवर दिखाकर सत्ता हासिल की।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे कामों की जांच कराना चाहता हूं। हमारे भीलवाड़ा में जिस तरह से उन्होंने किया, जनता ने सबक सिखाया है। वर्तमान में विधान सभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदीजी की विधान सभ चुनाव के दौरान उन्होंने कोटड़ी में सभा की और उन्होंने अपने उदबोधन में देवतुल्य जनता से आहवान किया कि भीलवाड़ा और राजस्थान प्रदेश में जिस तरह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह इन भ्रष्टाचारियों को, इन माफियाओं को, कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों को, दीपावली में हम जिस तरह से साफ सफाई करते हैं, ऐसे कांग्रेस की सफाई करनी है। देवतुल्य जनता ने प्रधान मंत्रीजी के आशीर्वाद से भीलवाड़ा जिले में सात की सात सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है और लोक सभा में प्रचण्ड बहुमत से हमारे लोकप्रिय सांसद दामोदर जी को साढ़े तीन लाख वोटों से जिताकर मोदी जी की झोली में भेजा। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने धनबल, बाहुबल, भ्रष्टाचार हर तरीका अपनाया लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको नकारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्य मंत्री प्रेमचन्द जी बैरवा के नेतृत्व में हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में शानदार विकास हो रहा है, इसके लिये मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: डॉ. शिखा मील बराला।

MLS/RTM/20.07.2024/17:20/3g

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का मौका दिया। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग हम दुनिया बदलने के लिए

कर सकते हैं। बात शिक्षा की आयेगी तो आरक्षण की भी आयेगी। वर्तमान में राज्य में संविधान द्वारा दिये गये आरक्षण की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। आरयूएचएस में शैक्षणिक पदों की एक भर्ती निकाली गयी, आवेदन मांगे गये और विज्ञापन में लिखा गया कि भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार आरक्षण के नियमों को पूरी तरह फॉलो कर रही है।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, प्रथम दृष्टया आरक्षित वर्गों, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि हम कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट एज 65 साल करने पर विचार कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अभी के जो टैलेंटेड, अपडेटेड और स्किल्ड युवा शिक्षक हैं, इससे उनके अवसर सीमित होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महारानी कॉलेज का एक प्रकरण हमारे सामने बार-बार आ रहा है। उससे सरकार की मंशा जाहिर हो रही है कि शैक्षणिक संस्थानों का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो कालाडेरा हमारे शिक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्ता रखता है। आजादी के समय से इस कॉलेज ने बहुत से प्रशासनिक अधिकारी दिये हैं, बड़े-बड़े राजनेता दिये हैं।

कालाडेरा सहरिया कॉलेज स्कूटी योजना के लिए नोडल सेंटर है, जहां पर प्रतिवर्ष 400 से 500 स्कूटियां वितरित की जाती हैं। दुविधा यह है कि पांच प्रोफेसर, तीन-चार बाबू पूरे साल सिर्फ इसी काम में लगे रहते हैं कि किस तरह स्कूटी वितरित की जाये, कब आरटीओ से आरसी मंगायी जाये, कैसे छात्राओं के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किये जाएं। इसमें हमें कुछ सुधार की आवश्यकता है।

छात्रवृत्ति में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। छात्र-छात्राओं को बार-बार ई-मित्र पर चक्कर काटने पड़ते हैं। इन प्रोसीजर्स को हमें सिम्प्लिफाई करना जरूरी है। कम से कम सौ आदर्श कॉलेज राज्य में होने चाहिये। वहां पर वाचनालय की सुविधा जरूर होनी चाहिये, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि सरकारी कॉलेजों में अटैंडेंस नहीं है और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमारे कॉलजों में लाइब्रेरीज ही अवेलेबल नहीं हैं। अगर प्रिमाइसिस में लाइब्रेरी होगी तो इससे हमारे छात्र-छात्राओं को मौका मिलेगा कि वे अपने शिक्षकों के सुपरविजन में वहां रह सकें। **(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)**

मैं अपने क्षेत्र की मांगों पर बात करूं, मुझे प्लीज दो मिनट दें। हमारे क्षेत्र चोमू को कृषि और पशु-पालन कॉलेज दी जाये, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज दी जाये। कालाडेरा सहरिया कॉलेज में कुछ नये यूजी कोर्सेज- गृह विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस, भूगोल और पीजी कोर्सेज-हिन्दी साहित्य, जूलॉजी, बॉटनी आदि दिये जाएं।

परिवहन की बात करूं तो ब्लू लाइन बसों पर, रोडवेज पर हमें बचपन से भरोसा रहा है, पर चिन्ता का फिलहाल विषय है आरटीओ और डीटीओ ऑफिसेज, जो भ्रष्टाचार का केन्द्र बन

चुके हैं, सरकार इस बात को गम्भीरता से ले।

चोमू शहर को एक बस अड्डा दिया जाये। कुछ मुख्य रूट- गोविन्दगढ़, सीतारामपुरा, आलीसर, हस्तेड़ा, बधाल रूट, सामोद रूट, बांसा जाटाली रूट, इन पर नयी रोडवेज बस सेवाएं दी जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री लक्ष्मण।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): एक जरूरी चीज, हरिद्वार जाने के लिए कम से कम हमें दो रोडवेज बसों की उपलब्धता करायी जाये।

श्री अध्यक्ष: कोई चीज रह गयी है तो टेबल कर दें।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का अवसर दिया।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित तो हो ही नहीं रहा है। दूसरा नाम पुकारते ही अंकित नहीं होता है।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में प्रदेश भर में शिक्षा के लिए दी जाने वाली विभिन्न ऐतिहासिक सौगातों के लिए माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा, उप-मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी और उप-मुख्य मंत्री श्री प्रेम चन्द बैरवा का हार्दिक आभार।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट में पूरा करना है।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोटन बहुत बड़ा कस्बा है, जहां दो-तीन बड़ी फैक्टरियां हैं, औद्योगिक नगरी है। मैं मांग करूंगा, वहां एक कॉलेज खोली जाये, जिससे बच्चों को पढ़ने में फायदा मिले। मेरे क्षेत्र का एक गांव है इंदावड़, बहुत बड़ा गांव है, जहां तीन सीनियर सेकंडरी स्कूलें हैं, 500-600 बालिकाएं हर साल उत्तीर्ण होती हैं। मैं आपके माध्यम से वहां एक एग्री कॉलेज खोलने की मांग करूंगा। मेरे मेड़ता में जो पीजी कॉलेज है, उसमें कला वर्ग हिन्दी इतिहास, समाज शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के संकाय खोले जाने की मैं मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं, मेड़ता में बहुत बड़ा कस्बा है, वहां एक पॉलिटैक्नीक कॉलेज खोजा जाये, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और उनका खर्चा कम हो। रियां में कॉलेज भी खुला है और मेड़ता में भी कॉलेज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भंवर सिंह डांगावास जी ने बहुत संघर्ष करके मेड़ता में कॉलेज खोला। उस समय सरकार के पास पैसे नहीं थे तो चन्दा इकट्ठा करके खोला गया था। मैं राजकीय पीजी महाविद्यालय का नाम भंवर सिंह डांगावास के नाम पर करने की मांग करता हूं।

अभी मेरे मेड़ता में एक कन्या महाविद्यालय बन रहा है, आपसे मांग करूंगा, उसका नाम मां मीरा के नाम से रखा जाये, क्योंकि मीरा बाई के नाम से मेड़ता का नाम विश्व विख्यात है। रियां में आपके कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। रियां एक बहुत बड़ा कस्बा है ग्रामीण

क्षेत्र का, जहां एक कहावत है, ''बां रियां बां डूंगरी बो माता को थान, शेर सिंह महिला नहीं, बडले नहीं भुगान।'' बहुत अजीब कहानी है, ठाकुर शेर सिंह जी थे, जिन्होंने 500 बीघा जमीन राज को बिलकुल फ्री में दी थी। मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करूंगा, उस कॉलेज का नाम शेर सिंह के नाम से रखा जाये। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है।

परिवहन विभाग में आपसे मांग करूंगा, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, मेड़ता बहुत बड़ा कस्बा है, आपकी जमीन पड़ी है तो उसकी चारदीवारी बनाकर उसे डिपो बनाकर डवलप किया जाये ताकि लोगों को और आपके डिपार्टमेंट को फायदा मिले। मैं विभिन्न बसों की मांग करता हूं। मेरे मेड़ता क्षेत्र के अधिकांश गांवों में यानी सिर्फ मेड़ता उप-खण्ड मुख्यालय और नेशनल हाईवे से जुड़े मुख्य मार्गों को जोड़ दें। रियां बड़ी, मेड़ता रोड दो मुख्य कस्बे हैं, जो रेलवे जंक्शन जोड़ता है। अब यह नगरपालिका बन गयी है। वहां बसों का संचालन करें। मैं जनहित में आपसे मांग करूंगा, रियां बड़ी और मेड़ता रोड कस्बे में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर डिपो की रूट बसें अतिशीघ्र संचालित करायी जाएं। **(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)** बोलने को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समय के अभाव के कारण बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका।

श्री अध्यक्षः श्रीमती रमीला खड़ीया। पांच मिनट का है।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा, मांग संख्या - 24 तकनीकी शिक्षा और मांग संख्या - 62 परिवहन के ऊपर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय सज्जनगढ़ 2018-19 के बजट में खोला गया था। वह बिल्डिंग ठेकेदार के मार्फत् आज तक अधूरी पड़ी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि जल्दी से जल्दी उस ठेकेदार की जांच कमेटी को बैठाकर उस बिल्डिंग को पूरी कराएं। हमारे करीब 800-900 बच्चे हैं। इसी तरह से कुशलगढ़ में हमारी सरकार ने कन्या महाविद्यालय दिया। उसकी भी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। उसका रंग-रोगन भी हो चुका है। जल्दी से जल्दी उसमें कन्या महाविद्यालय शुरू करें।

इसी तरह से आज शिक्षा के ऊपर मैं एक गम्भीर बात कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार बच्चे तालाब में डूब गये हैं। वे पढ़ने के लिए स्कूल गये थे। रोहित पुत्र राजू (8 वर्ष), शैलेन्द्र पुत्र राजू (6 वर्ष), शैलेष पुत्र देवसन (8 वर्ष), हेमेन्द्र (12 वर्ष) की कल मृत्यु हो चुकी है। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार इस पर गम्भीर विचार करे।

मैं मेरे घाटा क्षेत्र में कॉलेज खुलवाने की मांग करती हूं। इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृत किया था, उसका काम चालू करवाएं। मैं साथ में यह भी कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डूंगरपुर-इंदौर बस जो चल रही थी, कोरोना काल में वह बस बन्द हो गयी, यात्रियों को आने-जाने में काफी समस्या हो रही है। अतः इस बस को चलाया जाये।

इसी तरह से बांसवाड़ा से कसारवाड़ी होती हुई बस चल रही थी। डूंगरपुर-इंदौर, कुशलगढ़

से दाहोद, बांसवाड़ा से सूरत। ये बसें चल रही थीं। **(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)**

mkd/rtm/20.07.2024/17:30/3h

श्री अध्यक्षः श्री भागचन्द, नहीं हैं। श्री सुरेश गुर्जर, लास्ट। आप पांच मिनट में खत्म करें।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): अनुदान की मांग संख्या 22, 24 और 62 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा विधान सभा क्षेत्र खानपुर बकानी झालावाड़ के आखिरी छोर पर है। जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से सटी हुई है। मैं आपका ध्यान यहां की उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के पिछड़ेपन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां छात्र, छात्राओं को उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार किसी भी दल की हो, बिना किसी भेदभाव के चाहे उच्च शिक्षा हो, परिवहन हो, सड़क हो, पानी हो, सब उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, किन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने इस बजट में, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, चाहे तकनीकी शिक्षा की बात हो, खानपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता को कुछ भी नहीं दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान खानपुर विधान सभा क्षेत्र के बकानी ब्लॉक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां पूरे झालावाड़ जिले में सबसे गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी जीविका का मुख्य साधन मजदूरी और खेती-बाड़ी है, जिससे वे अपने बच्चों को पढ़ाते, लिखाते हैं। लम्बे समय से बकानी में महाविद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है। बकानी ब्लॉक में 28 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें 2500 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं। बकानी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर है। वहां महाविद्यालय के अभाव में छात्र और छात्राओं के पास दो ही विकल्प हैं या तो वे 50 किलोमीटर अप-डाउन करें या पढ़ाई छोड़ दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान ऐसे विद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर आप आसानी से कॉलेज खोल सकते हैं, उस विद्यालय का नाम है, स्वामी रामेश्वरम आश्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुरुकुल, बकानी। यह विद्यालय 25 बीघा जमीन में स्थित है। परिसर महाविद्यालय हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है, जहां अविलम्ब महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है। जिससे राज्य सरकार को भूमि का चयन करने और भवन निर्माण में लगने वाले समय और धन की बचत होगी। इस इलाके के छात्र और छात्राओं को इसी वर्ष महाविद्यालय की सौगात दे सकते हैं। अतः मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसी सत्र में महाविद्यालय बकानी क्षेत्र में खोला जाये।

दूसरी मांग यह है कि राजकीय महाविद्यालय, खानपुर को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जाये। मैं स्नातक पाठ्यक्रम में विज्ञान व कॉमर्स संकाय खोले जाने की भी मांग करता हूं। खानपुर स्नातक कॉलेज को परीक्षा केन्द्र नहीं बना रखा है, जिसके कारण

छात्र और छात्राओं को झालावाड़ जाकर परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए खानपुर महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र खोले जाने की भी मांग करता हूं। साथ ही, महाविद्यालय में रिक्त पद हैं और प्राचार्य का पद भी रिक्त है, इसको जल्दी से जल्दी भरा जाये। मैं इस कॉलेज को नये भवन में शिफ्ट करने की भी मांग करता हूं।

खानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की भी मांग करता हूं। झालावाड़ हैड क्वार्टर पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज व राजकीय कॉलेज, खानपुर में लगभग पीजी कॉलेज में 4500 छात्र और छात्राएं हैं और गर्ल्स कॉलेज में 1500 छात्राएं हैं। खानपुर में 1000 छात्र और छात्राएं हैं। यहां पर यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में कई पद भर गये हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो छात्र वंचित रह गये हैं, उनको आप सीटें बढ़ाकर लाभ दें।

श्री अध्यक्षः हो गया। श्री सुरेश मोदी। तीन-चार मिनट ही हैं। इन्होंने तो दो मिनट के लिए कहा है, मैं तीन मिनट दे रहा हूं।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): साहब, नहीं। आप तो कैंसिल ही कर दो। दूसरे को बुला दें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी, जवाब शुरू करें। अब जो सूची आती है। अब बैठिये, अब हो गया। माननीय मंत्री जी को बुला लिया है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः सदन का समय जवाब होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय जवाब होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा

मांग संख्या 24 - तकनीकी विभाग व

मांग संख्या 62 - परिवहन पर विचार

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, 16वीं विधान सभा के द्वितीय सत्र की अनुदान मांग पर सदन में बोलते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार राज्य में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के साथ विकसित राजस्थान एवं विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूर्ण करने के लिए वर्तमान बजट प्रस्तुत किया गया है।

अब मैं, हमारे सभी सम्मानित विद्वान सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में अपने बहुमूल्य विचार रखकर एवं राज्य हित में अपने सुझाव दिये हैं।

आज मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा व मांग संख्या 62 - परिवहन में कुल 587 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से उच्च शिक्षा के 258, तकनीकी शिक्षा के 79 एवं परिवहन के 250 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्राप्त सभी कटौती प्रस्तावों के उत्तर सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दिये जायेंगे। अनुदान मांगों पर अपनी बात पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा:-

जब तक ध्येय नहीं होगा पूरा,
तब तक पग की गति नहीं रूकेगी,
आज कहे चाहे जो दुनिया,
कल झुके बिना नहीं रहेगी दुनिया।

अर्थात् हमारी सरकार का ध्येय है कि प्रदेश शिक्षा एवं परिवहन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। हम सब इसके लिए अनवरत प्रयास करते रहेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करके रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं मांग संख्या-22 उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनमें से नवीन महाविद्यालय खोलने के लिए 35, नवीन कन्या महाविद्यालयों खोलने के लिए 26, यूजी-पीजी करने के लिए एवं नवीन विषय के लिए 44, आधारभूत एवं खेल सुविधाओं के सम्बन्ध में 43 एवं अन्य 41 हैं।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 34 वर्षों के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक बनाकर भारत को जीवंत ज्ञान, समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहुंच समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के पांच आधारभूत स्तम्भों से निर्मित सतत विकास का एजेंडा है। प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल अनुपात से अधिक है। जहां प्रदेश का 28.6 है, जबकि राष्ट्रीय 28.4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र, बहुविषयक शिक्षा, एकाधिक प्रवेश एवं निकास, सेमेस्टर सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एवं च्वाइस बेस क्रेडिट सिस्टम की व्यवस्था है।

हमारी सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को सभी प्रकार की भौतिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये और उनके शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में सभी बाधाएं दूर की जाये। हमारी सरकार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शोध, कौशल विकास, आधारभूत संरचना को केन्द्र में

रखते हुए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगी। हमारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के साथ-साथ रोजगार के सुनहरे स्वप्न को साकार होते हुए देख सके, इसके लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर विषय ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संख्या पर नहीं अपितु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विश्वास रखती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गुणवत्ता के मामले में हमारी सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। माननीय उप मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, वह पूर्ण रूप से शिक्षा नीति के अनुरूप एवं राजस्थान के उच्च शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

Bhs/Rtm/20.7.24/17.40/3j

पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने युवाओं के लिए कहा था, "all of us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents", को ध्यान में रखते हुए सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए बजट में सभी जिला मुख्यालयों पर कंप्यूटर विषय, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बी.बी.ए. सभी सम्भाग मुख्यालयों पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम.बी.ए., बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बी.सी.ए. चरणबद्ध रूप से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एम.सी.ए. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। इन पाठ्यक्रमों को महाविद्यालयों में इसी सत्र से प्रारम्भ करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

हमारे प्रदेश के विद्यार्थी विदेशी भाषाओं को सीख सकें, इसके लिए जिला स्तर पर फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कीम प्रारम्भ की जायेगी, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, इटालियन एवं रशियन भाषाएं सीख कर विद्यार्थी को कोर्स के सर्टिफिकेट प्रदान किये जायेंगे। हमारे प्रयास हैं कि इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकें। हमारा विद्यार्थी कौशल के आधार पर अपने गांव शहर में ही रोजगार प्राप्त कर सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मेरे प्रतिपक्ष के विद्वान साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सुविधाविहीन 4 विधि महाविद्यालय एवं 39 कृषि महाविद्यालयों के साथ 345 राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये। 2019 में 40, 2020 में 43, 2021 में 37, 2022 में 117 और 2023 में 108 महाविद्यालय खोले गये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय, कोई उम्र का तकाजा तो नहीं है, किसी उम्र में सीख सकते हैं? तो हमारे हरिमोहन जी को फ्रेंच सीखनी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना है कि 115 में से 20 आदमी हैं।

श्री अध्यक्षः यहां 70 में से 12 हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): इधर की छोड़ो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः दोनों की चिन्ता मुझे है। मैं दोनों की चिन्ता करता हूं मेरे लिए समान है। आपने कल कहा था समान तो मेरे लिए दोनों समान हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य, इधर-उधर की छोड़ो बीस की रखो।

श्री अध्यक्षः वो ही तो मैंने कहा कि बराबर है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इसमें से 2019 व 2020 में खोले गए 42 महाविद्यालय नियमित राजकीय महाविद्यालय हैं परन्तु शेष सभी 303 महाविद्यालय राजसेस सोसाइटी के अन्तर्गत खोले गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2029 से पूर्व प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 291 थी। विगत पांच वर्षों में 345 महाविद्यालयों में से 330 महाविद्यालय राजसेस सोसाइटी के अन्तर्गत खोले गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस राजसेस सोसाइटी का गठन 1.7.2022 को किया गया। राजसेस सोसाइटी के अन्तर्गत मानव संसाधन उपलब्ध कराने के नियम विधान सभा आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जारी होने के एक दिवस पूर्व 8 अक्टूबर, 2023 को जारी किए गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने कार्यकाल में इन राजसेस महाविद्यालयों में राजसेस सोसाइटी के माध्यम से एक भी मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करवाया केवल वाहवाही लूटने के लिए महाविद्यालय खोले। इन महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति की चर्चा करें तो इनमें केवल 40 कॉलेज ही अपने भवन में संचालित हैं और 263 कॉलेज अभी अस्थायी भवनों में चल रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए निकटवर्ती महाविद्यालयों के प्राचार्यों को नोडल अधिकारी बना कर कॉलेज चलाने की औपचारिकता पूरी की जा रही थी। विगत सरकार ने केवल संख्याओं के आधार पर राजसेस के अन्तर्गत सुविधाविहीन महाविद्यालय खोल दिए थे, उन राजसेस महाविद्यालयों की समस्याओं को देखते हुए हमारी सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। यह

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समिति इन महाविद्यालयों की वस्तुस्थिति की समीक्षा करके इन कॉलेजों की गुणवत्ता व राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय संचालन के लिए अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार इन महाविद्यालयों के लिए एक सुन्दर और गुणात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भी नये महाविद्यालय खोलने की पक्षधर है। वर्तमान बजट में 14 सहशिक्षा महाविद्यालय, 10 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय को मिला कर कुल 27 नये महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इन महाविद्यालयों को वर्तमान सत्र में ही शुरू करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट में 25 महाविद्यालयों में नये विषय संकाय खोले जाने के लिए 10 यू.जी. महाविद्यालयों को पी.जी. में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय एवं विद्यालय में भवनों के निर्माण, उन्नयन, मरम्मत के लिए 125 करोड़ रुपये तथा स्मार्ट क्लास रूम और आई.सी.टी लैब के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उप मुख्य मंत्री जी, वित्त के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि प्रदेश में पहली बार प्रत्येक जिले में व्यावसायिक पाठ्यक्रम बी.बी.ए., बी.सी.ए., एम.बी.ए., एम.सी.ए. तथा कंप्यूटर विषय प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया गया है। हमारा प्रयास है कि ये सभी पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र से ही प्रारम्भ हो जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2,500 पद रिक्त पड़े हैं, जिनके विरुद्ध 1,936 पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा परीक्षा आयोजित कर ली गई है। आशा है कि आगामी तीन माह में चयनित सहायक आचार्य उपलब्ध हो जायेंगे जिससे अधिकांश पद भर दिए जायेंगे। शिक्षण कार्य शुरू करने के रूप में चलाये जाने वाले नवीन सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों को लगाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी। लगभग सौ से अधिक अतिथि व्याख्याताओं ने महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। आशा है कि शीघ्र ही सभी महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा, जबकि पिछले वर्ष में यह प्रक्रिया अगस्त, सितम्बर में प्रारम्भ होती थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की भर्ती के साथ-साथ राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों के 247 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। आशा है कि इन पदों पर भी आगामी तीन माह में हमें पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संकल्प पत्र में जो शोध विषय कार्य योजना के अनुरूप सभी राजकीय महाविद्यालय पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में वर्तमान सत्र में ही छात्रों के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छात्राएं खेलों में अपने प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम रोशन करती हैं उनके विकास के लिए ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटे में सम्मिलित करते हुए मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त प्रमाण पत्र धारी छात्राओं को राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत बोनस अंक इसी सत्र से दिया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, काली बाई भील मेधावी एवं देव नारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना में राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 12वीं की कक्षा में अध्ययन कर रहे नियमित छात्रों में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है। छात्राओं को स्वीकृत वर्ष में ही स्कूटी मिलने पर उसका उपयोग कॉलेज में अपने अध्ययन के लिए कर सकती है। विगत वर्षों में छात्राओं को स्कूटियां समय पर नहीं देने छात्राओं को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना

करना पड़ा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद सौ दिवसीय कार्ययोजना में 2021-22, 2022 और 2023 की बकाया स्कूटियों में से दस हजार स्कूटियों का वितरण लक्ष्य रखा गया। आपको जान कर खुशी होगी कि सौ दिवसीय कार्ययोजना में 10,152 स्कूटियों का वितरण कर छात्राओं को लाभान्वित किया गया। विगत तीन वर्षों की शेष स्कूटियों का वितरण शीघ्र ही करने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, काली बाई भील मेधावी एवं देव नारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना में सफल क्रियान्वयन एवं छात्राओं को पैट्रोल के खर्चे से मुक्ति दिलाने के लिए अब सरकार द्वारा इस योजना में इलेक्ट्रिक स्कूटियों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। चयन वर्ष में स्कूटियों का वितरण कर दिया जायेगा, जिससे छात्राओं को महाविद्यालय में आने-जाने की सुलभता रहेगी और इलेक्ट्रिक स्कूटी होने से उन पर ईंधन का आर्थिक भार नहीं आयेगा।

Kas/rtm/20.07.2024/17.50/3k

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विगत भाजपा सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पदनाम यूजीसी के अनुसार सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य किये गये थे, परंतु RVRES व्याख्याताओं के पदनामों में अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ था। कॉलेज शिक्षा में कार्यरत RVRES व्याख्याताओं के पदनाम सहायक आचार्य, सह-आचार्य और आचार्य RVRES किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, RVRES व्याख्याताओं के केरियर एडवांसमेंट योजना सी.ए.एस. का लाभ पिछले वर्षों से बकाया चल रहा है। इन व्याख्याताओं को स्क्रिनिंग समिति की बैठक आयोजित करवा कर पात्र RVRES व्याख्याताओं को सी.ए.एस. का लाभ दिया जायेगा।

हमारी सरकार के गठन के पश्चात कॉलेज शिक्षा विभाग में बकाया सभी पदोन्नतियां कर दी गई हैं। वर्ष 2024-25 की सभी पदों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राजकीय महाविद्यालय में आचार्यों की वरिष्ठता सूची का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्राचार्य पद पर पदोन्नति विलंबित हो रही है। माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत शीघ्र ही यह पदोन्नति प्रक्रिया संपन्न करवा दी जायेगी।

राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य एवं सह-आचार्यों को केरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देने के लिये 30 जून, 2024 तक पात्र शिक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही सी.ए.एस. का लाभ दे दिया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थान की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिये नैक द्वारा प्रत्यायन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस प्रत्यायन के बाद केन्द्र सरकार से पीएम उषा योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं के सर्वांगीण विकास के लिये अनुदान प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री उषा योजना के अंतर्गत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को 100 करोड़ रुपये, एम.बी.एम विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,

बांसवाड़ा को 20-20 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 26 राजकीय महाविद्यालयों को 5-5 करोड़ मिलाकर कुल 130 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। बांसवाड़ा, जैसलमेर और करौली जिलों के राजकीय महाविद्यालयों के लिये प्रति जिला अनुसार 10-10 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार पीएम उषा योजना में कुल 320 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। इसी अनुदान के द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नवीन निर्माण, जीर्णोद्धार, उपापन, शोध कार्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष 19 राजकीय महाविद्यालयों ने नैक प्रत्यायन के लिये आवेदन किया था, जिसमें 17 महाविद्यालयों का नैक प्रत्यायन पूर्ण हो चुका है। शेष 2 महाविद्यालयों में शीघ्र ही नैक पीयर टीम का निरीक्षण होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का गठन होने के पश्चात सतत प्रयासों से गत वर्ष से 3 गुणा, अर्थात 54 राजकीय महाविद्यालयों ने नैक प्रत्यायन के लिये आवेदन किया था। इन सभी महाविद्यालयों का नैक प्रत्यायन इसी सत्र में करवाने का प्रयास किया जा रहा है। नैक प्रत्यायन होने के पश्चात इन महाविद्यालयों को सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्ता सुधार के लिये केन्द्रीय संसाधनों से बजट आवंटन हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत भाजपा सरकार द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को 7वां यू.जी.सी. वेतनमान स्वीकृत किया गया था। इस वेतनमान के ऐरियर के 50 प्रतिशत का पुनर्भरण यू.जी.सी. द्वारा किया जाना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 50 प्रतिशत, अर्थात 309 करोड़ रुपये का पुनर्भरण यू.जी.सी. के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त होना था, परंतु विगत कांग्रेस सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण यह राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो सकी। हमारी सरकार का गठन होने के पश्चात इस सम्बन्ध में प्रयास किये गये, परंतु योजना बंद होने के कारण अब यह राशि प्राप्त किया जाना संभव नहीं है।

कॉलेज शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित शिक्षण संस्थान एवं हितधारकों को स्कूल शिक्षा के शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर एक ही पोर्टल पर लाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग के सहयोग से कौशल दर्पण के नाम से एकीकृत उच्च शिक्षा पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें संचार में सभी आवश्यक मोड्यूल को शामिल किया जायेगा। कौशल दर्पण विद्यार्थियों, शैक्षणिक संस्थानों और हितधारकों के लिये पाठ्यक्रमों विद्यार्थी नामांकन, प्रवेश प्रक्रियाओं मानव संसाधन, सरकारी अधिसूचनाओं, परीक्षा परिणाम सम्बन्धी आदि के लिये एक केन्द्रीकृत डेटाबेस संचालित प्रणाली के रूप में काम करेगा। इस प्रणाली को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल, ऑनलाइन भुगतान गेटवे राज.एस.एस.ओ. ई-मित्र, राज धारा, राज ई- सेवाद्वार, जनाधार जैसे विभिन्न पोर्टल के साथ सहजता से कार्य करने के लिये तैयार किया जायेगा।

राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश नीति के अनुसार पूर्व में मूक -बधिर, दृष्टिहीन एवं महिला अभ्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य अभ्यार्थियों को अर्हकारी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात दो अकादमिक सत्रों से अधिक अंतराल होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसका प्रतिकूल प्रभाव ऐसे छात्रों पर हो रहा था जो नीट, आईआईटी, क्लेट जैसी प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के कारण अधिकतम दो सत्रों के अंतराल के नियम में बंध कर प्रवेश से वंचित रह जाते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सबको शिक्षा एवं सदैव शिक्षा के लिये समान अवसर प्रदान हो, इसके लिये सत्र 2024-25 से प्रवेश नीति के इस नियम को विलोपित कर दिया गया है। अब कोई भी विद्यार्थी कभी भी अपने अध्ययन को जारी रख सकता है।

निजी महाविद्यालय अब तक अपने संस्थाओं के संचालन हेतु ऑफलाइन आवेदन करते थे, किन्तु अब इन आवेदनों के लिये ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। सत्र 2024-25 से यह आवेदन राज.एनओसी पोर्टल पर आमंत्रित किये जाकर महाविद्यालयों को एन.ओ.सी. दिया जाना शुरू कर दिया गया है। इससे अनापत्ति जारी करने के कार्य में पारदर्शिता में वृद्धि होगी। समय की दृष्टि से भी सरकार का यह एक सराहनीय प्रयास सिद्ध होगा। महाविद्यालयों में शैक्षणिक और अन्य सभी गतिविधियों का सुचारु संचालन, प्राचार्य, आचार्य और विद्यार्थियों की समस्याओं के निरंतर अवलोकन एवं समस्या के समाधान के लिये विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिमाह महाविद्यालयों में निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित कर समस्याओं के समाधान में महाविद्यालयों का सहयोग करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी समय-समय पर महाविद्यालयों में जाकर आचार्यों एवं विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अभी कुछ घटना घटी तो मंत्री जी की आवाज तेज हो गई है, जोश आ गया है। कोई न कोई बड़ा राज है। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महाविद्यालयों में नवीन सत्र प्रारम्भ के प्रथम दिवस 1 जुलाई से स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में शिक्षण कार्य शुरू करवा दिया गया है, जबकि इनकी विगत परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए थे।

हमारा प्रदेश भामाशाहों के लिये जाना जाता है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी 4 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य भामाशाहों के द्वारा करवाये गये हैं। मां अम्बे के.पी. संघवी राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही का भवन निर्माण श्री किशोरी बाई संघवी द्वारा करवाया गया है। श्रीमती मोहनी देवी चाचान राजकीय महाविद्यालय साहवा व राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख (सादुलपुर) का भवन निर्माण श्री विनोद कुमार अग्रवाल द्वारा करवाया गया है। राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का भूमिमय भवन निर्माण श्री कुमार जय मोदी द्वारा करवाया गया है। मैं राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी

भामाशाहों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

msk/rtm/20.07.2024/1800/3l

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): जालौर, पाली, सिरोही की मैं गारंटी लेता हूं। आप जितने भी संस्थान खोलेंगे, भवन हम बनाकर देंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय, आपका बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक और भी जुड़ गया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप इस चीज का ध्यान रखना, रिकॉर्ड हो रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सोच-समझकर बोला हूं और माइक चालू करके बोला हूं, ऑन रिकॉर्ड बोला हूं कि भामाशाहों से भवन बनवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप संस्थान खोलो।

श्री अध्यक्ष: केवल जालौर के लिए या पूरे राजस्थान के लिए?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): सर, ये तीन के लिए बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, इन्होंने तीन की गारंटी ली है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक जिला और हो गया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष जी, अगर हमें स्वीकृति प्रदान कर दें, भवन बनाकर दे देंगे।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): पूरा मारवाड़ भी आ गया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक जिला और जुड़ गया है, अभी कहें तो पूरे 50 जिले हो सकते हैं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): मैं राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी भामाशाहों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरता, ज्ञान विचार और दृष्टि के बिना फलदायी नहीं हो सकती है। इसलिए इस भूमि का हर नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवीर बनकर उभरे, यही हमारा प्रयास रहेगा और हम इसके लिए निरन्तर कर्मशील रहेंगे।

राजस्थान प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब बनाने के लिए निजी क्षेत्रों का सहयोग आवश्यक है, इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने के लिए नीति बनायी। निजी विश्वविद्यालय को विधान सभा में अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में 54 विश्वविद्यालय संचालित हैं। इन विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए समय-समय पर प्रवेश, अध्यापन, अनुसंधान, प्रबंधन में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए कृत संकल्पित हैं।

हमारी सरकार के गठन के पश्चात निजी विश्वविद्यालय के लिए दिशा-निर्देश, 2024 जारी कर दिये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानुसार कार्यवाही की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन के दौरान ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू की अनेक डिग्रियां फर्जी होने के तथ्य संज्ञान में आने पर एसओजी द्वारा जांच की गयी। एसओजी द्वारा जांच में कूटरचित तरीके से बिना प्रवेश, बिना अध्ययन के डिग्रियां जारी करने के विभिन्न प्रकरण सामने आने पर विभाग द्वारा दिनांक 26.03.2024 को संभागीय आयुक्त, सीकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 21.06.2024 को विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी।

इसके साथ ही, वर्ष 2021-22 से आज तक जारी की गयी उपाधियों की जांच के लिए संभागीय आयुक्त, सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 04.07.2024 को भी एक अन्य समिति का गठन किया गया है, जो इस समयावधि में जारी उपाधियों की वैधानिकता की जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सरकार को समय-समय पर निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करवायी जाती रही है। हमारी सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही), राफेल्स विश्वविद्यालय, नीमराणा (अलवर), निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़, सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेर बड़ी (झुंझुनू) के विरुद्ध शिकायत मिलने पर सम्बन्धित अधिनियम की तत्सम्बन्धित धाराओं के अंतर्गत सम्बन्धित संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन कर जांच करवायी जा रही है। कमेटी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं यूजीसी के नियमानुसार शोध कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से हमारी विगत भाजपा सरकार के समय से नियामक प्राधिकरण विचाराधीन है। हमारी सरकार के गठन के पश्चात इस नियामक प्राधिकरण को बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग संस्थानों में अध्ययरत छात्रों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों की क्रियान्विति की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा कोचिंग संस्थाओं के पंजीयन एवं विनियमन हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 16 जनवरी, 2024 को जारी किये गये तथा राज्य सरकारों को उनके अनुरूप

लीगल फ्रेम वर्क तैयार करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

हमने केन्द्र के दिशा-निर्देशों को अडॉप्ट करते हुए उनकी पालना हेतु सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है। साथ ही, केन्द्र के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 'विचाराधीन राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एवं रेगुलेशन) विधेयक का प्रारूप तैयार कर विधिक्षा हेतु विधि विभाग को भिजवा दिया गया है। विधिक्षा होने के उपरान्त विविध प्रक्रियानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।

गुरु-शिष्य सम्बन्ध की परम्परा को पुन:स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान किये जाने की बजट 2024 में घोषणा की गयी है। इस हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चरणबद्ध रूप से पूर्णतया लागू किया जायेगा। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नयी शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली एवं चॉइस बेस्ड केडिट सिस्टम (CBCS) प्रणाली भी पाठ्यक्रमों में समाविष्ट कर दी गयी है। सभी छात्र-छात्राओं का एबीसी में पंजीकरण हो चुका है। ABC (Academic Bank of Credit) के माध्यम से समस्त विद्यार्थियों का इस वर्ष का परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर पर अपलोड किया जा रहा है। राज्य के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को विगत 10 वर्षों की उपाधियां एवं अंकतालिकाएं डिजी लॉकर पर अपलोड करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, डिजी लॉकर पर अपलोड करने से विद्यार्थियों एवं भर्ती एजेंसियों को एक क्लिक पर डिग्री उपलब्धता एवं सत्यापन की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दहमी कलां, जयपुर का दिनांक 15.03.2024 को एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, दहमी कलां, जयपुर के भवनों का लोकार्पण दिनांक 29.06.2024 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किया जा चुका है।

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 15 विश्वविद्यालयों में मुख्य परीक्षा 2020, 2021, 2022, 2023 की उपाधियों का वितरण नहीं किया गया था, हमारी सरकार के गठन के पश्चात सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित कर 9 विश्वविद्यालयों में मुख्य परीक्षा 2023 तक की उपाधियां, 4 विश्वविद्यालयों में परीक्षा 2022 तक की तथा 2 विश्वविद्यालयों में परीक्षा 2021 तक उपाधियां छात्रों को वितरित की गयीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दीक्षांत समारोह में लगभग 10 लाख 80 हजार उपाधियां एवं 982 मेडल वितरित किये गये हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्य परीक्षा 2024 की सभी उपाधियां एवं मेडल वर्ष 2025 के दीक्षांत समारोह में वितरित किये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार विद्यार्थियों के हित में कार्य करने वाली सरकार है। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ही राज्य के सभी महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों में 25 प्रतिशत वृद्धि कर दी गयी है। अभी पूसाराम जी कह रहे थे, हमने 25 परसेंट वृद्धि सभी महाविद्यालयों में कर दी है। यह सरकार, जो सही होगा, वह

करेगी। जो मांगेंगे, मिलेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से मिलेगा।

mdp/rtm/20.07.2024/18:10/3m

ये मोदी जी के विजन की सरकार है, भजन लाल जी के विजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनमें नवीन महाविद्यालय खोलने के लिए 43, नये विषय और शाखा खोलने के लिए 12, रिक्त पदों को भरने के लिए 5 एवं अन्य 19 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के अमृतकाल में भारत को विश्व गुरु बनाने में राजस्थान के युवा भी अपना योगदान करें, इसके लिए हमारी सरकार ने तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु आईआईटी की तर्ज पर अजमेर, बीकानेर, भरतपुर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों का उन्नयन कर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तन किया जाना बजट में प्रस्तावित कर दिया गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि ये राजस्थान प्रौद्योगिक संस्थान अजमेर, बीकानेर और भरतपुर इसी सत्र में कार्य करना प्रारम्भ कर दे। यह राज्य की तकनीकी शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस हेतु हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक संस्थान को 100-100 करोड़ रुपये राशि का आवंटन किया गया है। ये सभी संस्थाएं प्रदूषण रहित होगी।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक एवं अभियांत्रिकी संस्थानों में बालिकाओं के प्रवेश में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू कर दिया गया है। प्रस्तुत बजट में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा विभाग की तर्ज पर मेरिट के आधार पर 500 इलेक्ट्रिक स्कूटियों का वितरण किया जायेगा। हमारी सरकार प्रत्येक तकनीकी संस्थाओं में बालिकाओं के लिए अलग से पिंक टॉयलेट कानिर्माण करवा रही है। राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 में तकनीकी शिक्षा विभाग में भिवाड़ी, फागी, बांदीकुई, मारवाड़ जंक्शन, गुडामालानी, वल्लभनगर, निवाई सहित 10 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इन सभी नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को 4 शाखाओं के साथ प्रारम्भ किये जाने की योजना है। एआईसीटीई से अनुमति प्राप्त कर शीघ्र ही इन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को प्रारम्भ किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तुत बजट में 7 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक, सिविल, केमिकल, माइनिंग, इजीनियरिंग जैसी नयी ब्रांच खोली जा रही है एवं दो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सीटों में वृद्धि की जा रही है, जिससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। हमारा संकल्प है कि हम छात्रों को वर्तमान तकनीकी और उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार करके राजस्थान के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाएं। अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा में केन्द्र सरकार ने पॉलिटेक्निक अभियांत्रिकी

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा शोध क्षेत्र में बढ़ावा देने केलिए मेराईट योजना लागू की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय को 5 करोड़, अभियांत्रिकी महाविद्यालय को 10 करोड़, तकनीकी विश्वविद्यालय को 18 करोड़ की राशि आवंटित की जाती है। विगत सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया, परंतु हमारी सरकार के आते ही इस महत्वाकांक्षी योजना में राजस्थान को सम्मिलित करने हेतु प्रभावी प्रयास शुरू कर दिये गये हैं। जल्दी ही इस योजना का लाभ राज्य को मिलने की खुशखबरी मिलने वाली है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान को लगभग 300 करोड़ रुपये आवंटित होने की संभावना है।

अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा विभाग की तरह ही तकनीकी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान के एरियर का 50 प्रतिशत अर्थात 23 करोड़ रुपये भारत सरकार से पुनर्भरण प्राप्त किया जाना था, परंतु विगत सरकार द्वारा प्रयास नहीं किए जाने से यह राशि भी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई। विगत भाजपा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में 509 प्रवक्ताओं एवं 38 अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी। परंतु गत सरकार ने 5 साल के अंतराल में तकनीकी शिक्षा में किसी भी अशैक्षणिक तकनीकी पदों पर भर्ती नहीं की। हमारी सरकार द्वारा 2020 तकनीशियनों की भर्ती की अर्थना राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड को भेज दी गयी है। गत सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में 4 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारम्भ किया, जिसमें से एक का भी भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। फलस्वरूप ये सभी महाविद्यालय अपने निकटतम महाविद्यालयों में संचालित किये जा रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बिल्डिंग का काम भी चल रहा है या नहीं चल रहा है?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): बिल्डिंग का काम ही तो नहीं चल रहा। चार ही तो खोले थे आपने। चार ही में तो नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बात तो यही है कि चार खोले ...(व्यवधान)... चारों में ही बंटाधार कर दिया।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा 'विकसित राजस्थान 2047' के अंतर्गत तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को कार्बन फ्री हेतु बृहद स्तर पर वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन तथा सोलर ऊर्जा के उपयोग हेतु कार्य-योजना बनायी गयी है, जिसे इसी सत्र में लागू किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, हमारे विभाग के छात्र व शिक्षक, दोनों ही वर्तमान आवश्यकता के अनुसार तकनीकी योग्यता प्राप्त करें, इसके लिए हमारे विभाग ने केपीआई निर्धारित किए हैं, जिनमें छात्रों की योग्यता बढ़े, उनके व्यक्तित्व का विकास हो तथा शिक्षकों का भी आवश्यकता के अनुरूप उन्नयन हो। इस हेतु चयनित चिह्नित महाविद्यालयों को विभाग द्वारा दिशा-निर्देशित किया गया है तथा प्रत्येक 15 दिवसों में इसकी प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग के गैर-अभियांत्रिक डिप्लोमा शिक्षकों के लम्बे समय से छठे एआईसीटीई वेतनमानों

का लाभ दिये जाने की मांग लंबित थी, जिसको हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी गैर-अभियांत्रिकी डिप्लोमा शिक्षकों को छठे एआईसीटीई वेतनमानों का लाभ प्रदान कर दिया गया है।

अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सेंटर फॉर इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस (सीईजी) जयपुर द्वारा छात्रों के ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम व शिक्षकों के ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं। साथ ही छात्रों के नियोजन हेतु भी कार्य किये जाते हैं। हमारी सरकार ने आते ही सेंटर फॉर इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस, जयपुर को सक्रिय किया ताकि छात्रों का नियोजन किया जा सके। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सीईजी द्वारा फरवरी, 2024 से अब तक कुल 400 से भी अधिक छात्रों का नियोजन किया जा चुका है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सेंटर फॉर इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस, जयपुर द्वारा छात्रों को रोबोटिक्स, थ्री-डी प्रिटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग एवं पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे उच्च गुणवत्ता के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये सभी पाठ्यक्रम रोजगारपरक है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हर बात को ध्यान से सुनते हैं। आज आपका कोई विशेष ध्यान है, आप कुछ पढ़ भी रहे हैं साथ-साथ। माननीय की हायर एजुकेशन में रुचि ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: मैं देख रहा हूं कितने अरब हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, आप तो जोगाराम जी को बीस मिनट देकर एक दिन बुलवा दीजिए। मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं तब भी आप नहीं मान रहे हैं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुश इसलिए है कि अजमेर में कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी ले गये और आयुर्वेदिक भी ले गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने मांग संख्या 62 परिवहन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उनमें से नवीन परिवहन कार्यालय 9, भवन मरम्मत के लिए 3, नयी रोडवेज बस प्रारम्भ करने के लिए 126 तथा अन्य 112 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीया उप मुख्य मंत्री (वित्त) का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जन कल्याणकारी घोषणाएं कर आमजन को राहत प्रदान की है। हमारी सरकार ने विगत 6 माह में परिवहन के क्षेत्र में कई छोटे-बड़े नवाचार करते हुए इससे जुडे वर्गों एवं आमजन को राहत पहुंचाई है।

अध्यक्ष महोदय, परिवहन यानों की फिटनेस सम्बन्धित जिले में ही कराने की बाध्यता समाप्त कर इसकी सुव्यवस्था को सुलभ बनाते हुए परिवहन यानों की फिटनेस राज्य में एनीवेयर कराने का प्रावधान कर दिया गया है, जो एक ही जिले में बांध रखी थी, वह अब कहीं पर भी करवा सकता है।

Ans/rtm 18.20 3n 20.07.2024

इसके साथ ही वाहनों के प्रोटोटाईप अप्रूवल की बाध्यता को समाप्त कर वाहन डीलर्स हेतु वाहनों के विक्रय की प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। आमजन द्वारा पुराने वाहनों को क्रय करने हेतु प्रदेश में संचालित कार बाज़ारों का नियमितिकरण कर डीलर पंजीयन करने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पुराने वाहन आ रहे हैं उनकी छूट खतम कर दी। सैकण्ड हैंड गाड़ियां हैं, उन पर 4-4 लाख रुपये तक का आरटीओ टैक्स बढ़ा रहा है। मैं चाहूंगा आप इसमें इनको थोड़ी सी रियायत दे, नहीं तो कार बाजार बंद हो जाएंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): बिलकुल, आपकी बात पर विचार किया जाएगा।

विगत वर्षों में सर्विस डिलीवरी सिस्टम में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसी क्रम में परिवहन विभाग में आम जन की सुविधा हेतु दिनांक 01-04-2024 से ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन पंजीयन पत्र जारी किये जा रहे हैं। परिवहन कार्यालयों को पूर्णतया कैशलेस करते हुए विभिन्न सेवाओं हेतु निर्धारित फीस/कर का भुगतान डिजीटल पेमेन्ट सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश के समस्त सड़क उपयोगकर्ताओं को निर्बाध एवं सुरक्षित सफर देने के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2023 में प्रदेश में 24694 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 11762 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 23041 व्यक्ति घायल हुए, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। इसी क्रम में परिवर्तित बजट 2024-25 में संभाग स्तर पर दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु में कमी लाने हेतु रोड़ सेफ्टी टॉस्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की गई है।

आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए सड़क दुर्घटनाओं में घटित मृत्यु दर को शून्य करने हेतु आगामी 10 वर्षों की सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य होगा।

परिवर्तित बजट 2024-25 में सड़क दुर्घटना में गम्भीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले भले मददगार को गुडसम रिटर्न के लिए प्रोत्साहन राशि 5,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।

इसी अवधारणा को केन्द्र में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी की केन्द्र प्रवर्तित योजना-PM गति शक्ति के अंतर्गत वाहनों की ओवर स्पीडिंग पर अंकुश लगाने एवं सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा सड़क नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए परिवर्तित बजट 2024-25 में जयपुर-दिल्ली, जयपुर-भरतपुर राजमार्गों एनएच 48 व एनएच 21 एवं 4 स्टेट हाइवे पर आईटीएमएस सिस्टम लागू किये जाने की घोषणा की गयी है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर युवा विधायकों का आह्वान करना चाहूंगा कि वे प्रदेश की युवा शक्ति को सड़क दुर्घटनाओं से दूर रखने की दिशा में अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान में सहयोग कर अभियान को सफल बनाने का काम करे। राज्य में बढ़ता प्रदूषण हम सबके लिए चिंता का विषय है। प्रदेश

के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वातावरण देने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

इसी के क्रम में वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु परिवर्तित बजट 2024-25 में 200 करोड़ रुपये के व्हीकल प्रमोशन फंड, इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन कोष का गठन किये जाने की घोषणा की गयी है।

हमारी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ाने हेतु लोक परिवहन सेवा को दूरस्थ गाँवों से जोडा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न क़स्बों एवं गाँवों में परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाले अन्य श्रेणी मार्गों पर परिवर्तित बजट 2024-25 में 300 किलोमीटर से अधिक प्रतिदिन संचालन करने वाले मंजिली वाहनों के देय कर को 504 रुपये से घटाकर 400 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह किये जाने की घोषणा की गयी है।

ट्रांसपोर्टर्स एवं बस आपरेटर्स के लिए नये पंजीयन व परमिट सरेण्डर करने के उपरांत परमिट प्राप्त करने पर देय स्पार टैक्स में छूट को 15 दिवस से बढ़ाकर 30 दिवस किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

माननीय सदस्यगण, भक्ति, शक्ति, शौर्य एवं पराक्रम की धरा राजस्थान देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी के क्रम में प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने की दृष्टि से संविदा, प्राइवेट सर्विस व्हीकल एवं पर्यटक वाहनों में एकबारीय कर की वर्तमान प्रचलित दर को 10 प्रतिशत कम किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पर्यटको के साथ-साथ प्रदेश के वाहन स्वामियों को भी सुविधा देने हेतु वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण में प्रक्रियात्मक सरलीकरण करते हुए वाहन को भौतिक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है।

हमारी सरकार महिलाओं को सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं महिला सशक्तीकरण के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में राजकीय प्रशिक्षण संस्थान रेलमगरा राजसमंद में महिलाओं को व्यावसायिक वाहन चलाने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2024 को निगम की समस्त साधारण व द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली 6 लाख 4 हजार 338 महिला यात्रियों को निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवायी गयी।

प्रदेशवासियों को सड़क मार्ग का सफर सुरक्षित एवं सुगमता पूर्वक देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। मुझे विश्वास है कि अब खुशहाली, समृद्धि व मजबूती के साथ सड़क दुर्घटना रहित विकसित राजस्थान का संकल्प धरातल पर साकार होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों, श्रेणियों को सस्ती परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्परत है। इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा प्रदेश के 60 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज़ बसों में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को 50 प्रतिशत किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के गठन के बाद विगत छह महीने में हमने 7 करोड़

से अधिक लोगों को रोडवेज़ बसों में रियायती एवं नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई है। जिसमें 6 लाख से अधिक महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई है।

आमजन को सस्ती, सुरक्षित, आरामदायक एवं आधुनिकतम सार्वजनिक यात्री परिवहन सेवाओं का लाभ मिल सके। इसी सोच से हमारी सरकार यात्रियों की सुविधा तथा रोडवेज को सुदृढ़ बनाने हेतु रोडवेज बेड़े में 1300 नई बसें शामिल कर रही है, जिनमें से 300 बसें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसें होंगी।

हमारी घोषणाएं धरातल पर पूर्ण रूप से लागू हों एवं सफल हों, इस हेतु हमने इनकी प्लानिंग पर भी ध्यान दिया है। इसी वजह से रोडवेज में नई बसों को शामिल करने के साथ-साथ रोडवेज की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक हजार 650 कार्मिकों की भर्ती भी की जाएगी।

सरकार केवल बेहतर यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु ही नहीं अपितु इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए भी संकल्परत है, जिसके लिए हमारे द्वारा राज्य के विभिन्न बस स्टैंड, डिपो और वर्कशॉप की रिपेयर, मेंटिनेंस एवं जनसुविधा हेतु भी बजट प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा हेतु 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधा युक्त बस स्टैंड का निर्माण और 14 अन्य जगहों पर बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य करवाएं जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, आज उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं परिवहन विभाग की अनुदान माँगों पर पक्ष और विपक्ष के विद्वान साथियों ने सकारात्मकता के साथ समस्याओं की चर्चा की, कुछ सुझाव दिये। मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी भी दल के सदस्य हो, परन्तु हम सभी की इच्छा है कि हमारा प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बने।

आज चर्चा में जोधपूर शहर के, सूरसागर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की शुरूआत की गई। इनके अलावा मण्डावा, बहरोड़, सूरजगढ, पिलानी, मारवाड़ जक्शन, भीम, भरतपुर, टोडाभीम, सोजत, डीडवाना, बामनवास, विराटनगर, मकराना, महुवा, बयाना, लाडनूं, बानसूर, संगरिया, ब्यावर, रतनगढ़, सलूम्बर, शाहपुरा,

VPS-RTM-20.07.2024-18.30-3o

धरियावद, लालसोट, मुण्डावर, शिव, ओसियां, नोखा, बागीदोरा, जहाजपुरा, चौमूं और मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्यों ने उच्च तकनीकी, परिवहन विभाग की समस्याओं पर चर्चा की है। मैंने उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की समस्याओं के समाधान एवं प्रयास के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने का प्रयास किया फिर भी संक्षेप में यदि दोनों विभागों के बारे में बात करें तो नवीन महाविद्यालय खोलना, नये विषय एवं संकाय खोलना, रिक्त पदों पर नियुक्तियां, भूमि एवं भवन की मुख्य समस्याएं, जिनके लिए हमारी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में नवीन महाविद्यालय खोले गये हैं। 25 महाविद्यालयों में नवीन विषय संकाय खोले

जायेंगे और साथ ही 10 यू.जी. महाविद्यालयों को पी.जी. महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा और साथ ही 10 नये पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जायेंगे।

हम यही नहीं रुकेंगे अपितु पक्ष और प्रतिपक्ष के साथियों ने जो अपेक्षाएं यहां सदन में रखी हैं, उन सब पर माननीय मुख्य मंत्रीजी से विचार-विमर्श कर इन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा की है। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति कर यू.जी.सी. को अवगत करा दिया गया है। अब प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय ब्लेक लिस्टेड नहीं है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसाधनों के अभाव में प्रदेश में लागू करने में आने वाले कठिनाइयों के बारे में अवगत करवाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में आने वाली सभी समस्याओं को आप सभी के सहयोग से दूर किया जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पारित करवा दो।

श्री अध्यक्ष: लास्ट है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): लाख कठिनाई भले हो, मिले चाहे जितने गम, डटकर करेंगे सामना, इच्छा शक्ति न होगी कम। इच्छा शक्ति न होगी कम अर्थात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सम्पूर्ण रूप से लागू करके रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की अनुदान मांगों की अधिकांश मांगें माननीय सदस्यों ने रोड दुर्घटना को रोकने, यातायात के सुगम संचालन हेतु रोडवेज की बसें संचालन करना मुख्य समस्या बतायी है। इन समस्या के समाधान के लिए सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि बजट घोषणा के अतिरिक्त हमें आगामी दो माह में लगभग 510 बसें मिलने के साथ ही आप इस समस्या से निजात पा सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में परम सम्मानीय वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं-

सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,
असफल-सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न माँगते,
पावस बनकर ढलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

जय हिंद। जय भीम। जय भारत। जय राजस्थान। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने बहुत अच्छी बात कही, पूरी बात आपने कही है लेकिन पूरे प्रदेश के जो छात्र संघों की भी डिमांड है, काफी विधायकों ने भी इस बात को रखा है तो उस पर भी दो शब्द कह देते तो थोड़ा ठीक रहता।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में कह दें। समय हो गया। आप एक या दो लाइन में कह दें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्षजी ने ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप एक या दो लाइन में कहना, समय हो गया या आप इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बता देना। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): ओ.के., मैं मिल लूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश का मामला है। डिप्टी सी.एम. साहब ने इतना बड़ा बजट कर दिया, हमारे...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब यह समाप्त हो गया। अब आप पारित करने का प्रस्ताव रखें। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 22- उच्च शिक्षा, मांग संख्या, मांग संख्या 24- तकनीकी शिक्षा तथा मांग संख्या 62- परिवहन को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। हो गया। मैं जवाब दिलवा रहा था, आप लोग एकदम से खड़े हो जाते हो।

मांग संख्या 22- उच्च शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22- उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,41,32,53,000/- (सत्ताईस अरब इकतालीस करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24- तकनीकी शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24- तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,71,16,33,000/- (चार अरब इकहत्तर करोड़ सोलह लाख तैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 62- परिवहन का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 62- परिवहन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,24,39,00,000/- (सोलह अरब चौबीस करोड़ उनतालीस लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.36 बजे सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1
मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा विभाग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-22 मुख्य शीर्षक **उच्च शिक्षा विभाग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)

1. सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, बड़ा खेड़ा महाविद्यालय एवं ब्यावर महिला महाविद्यालय में पर्याप्त स्टॉफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)

2. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नये कॉलेज खोलने पर चर्चा के लिये।

डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)

3. बयाना व रूपवास के कॉलेजों में प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

4. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के महाविद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं. 98)

5. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र पाई पिपलवास ऐरिया में बालिका कॉलेज खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)

6. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के महाविद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं बालिका महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. राजकीय हाड़ीरानी महाविद्यालय, सलूम्बर में स्नातकोत्तर कक्षाओं में इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय के संकाय खोलने पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण, शौचालय बनाने व शुद्ध पेयजल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के हाड़ीरानी महाविद्यालय व सराड़ा महाविद्यालय में "इंडोर स्टेडियम" का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के "गींगला" कस्बे में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)

11. श्रीमती नर्बदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर, राजकीय महाविद्यालय पल्लू व श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय नोहर में विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय नोहर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. श्रीमती नर्बदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर में विभिन्न स्वपोषित संकायों को राजकीय संकायों में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)</u>

14. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रोहित बौहरा (वि.सं. 139)</u>

15. राजाखेड़ा कॉलेज, नरैना व मनियां कॉलेज में स्टॉफ व टीचिंग स्टॉफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)</u>

16. श्री प्रेमसिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय छीपाबड़ौद में कार्यरत निजी कार्मिकों का बकाया भुगतान किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)</u>

18. प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालयों में डिग्री एवं डिप्लोमा के नाम पर विद्यार्थियों से ली जा रही मनमर्जी फीस वसूली की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु चर्चा के लिये।
19. राणा उगमसिंह ईन्दा राजकीय पीजी महाविद्यालय, बालेसर में 'इतिहास' विषय में स्नातकोत्तर (पी.जी.) खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।
20. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नगर पालिका बालेसर सता में राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं गोपालसर में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने हेतु चर्चा के लिये।
21. राणा उगमसिंह ईन्दा राजकीय पीजी महाविद्यालय, बालेसर, वीर शिरोमणी राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय, शेरगढ़ एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय सेखाला में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु चर्चा के लिये।
22. राणा उगमसिंह ईन्दा राजकीय पीजी महाविद्यालय, बालेसर एवं वीर शिरोमणी राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय, शेरगढ़ की चार दिवारी का निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)</u>

23. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने एवं शैक्षणिक स्तर के रिक्त पदों पर प्राचार्य, आचार्य, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं व्याख्याता का पदस्थापन करने बाबत् चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पीपाड़ शहर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित विभिन्न संकायों को राज्य सरकार द्वारा पोषित करने एवं प्राचार्य, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बोरूंदा/बाला/डांगियावास में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)</u>

26. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के धरियावद में राजकीय महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय करने व सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के झेल्लारा में नवीन महाविद्यालय और धरियावद में बालिका महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के राजकीय महाविद्यालय धरियावद व लसा़डिया में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं. 82)</u>

29. प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत व्याकरण विषय में कौमुदी प्रक्रिया के साथ डॉ. पुष्पा दीक्षित की पाणिनीय पौष्पी प्रक्रिया के अध्ययन का विकल्प भी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. राजकीय महाविद्यालय, चौ.हा. बोर्ड, जोधपुर में भवन विस्तार कार्य हेतु विशेष बजट का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. राजकीय महाविद्यालय, चौ.हा. बोर्ड, जोधपुर में व्यवसाय प्रशासन, वनस्पति विज्ञान में पी.जी. और स्नातक स्तर पर संस्कृत, संगीत विषय आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. प्रदेश के विश्वविद्यालयों, उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों में नवीन शिक्षा नीति लागू करने और भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ (आई.के.एस.) आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. राजकीय कन्या महाविद्यालय, गेंवा, जोधपुर में समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिन्दी में पी.जी. और स्नातक स्तर पर संस्कृत, गृह विज्ञान विषय आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)</u>

34. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पांच राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. सिवाना वीर नारायण परमार राजकीय महाविद्यालय के 08 वर्ष से निर्माणाधीन भवन के बन्द पड़े कार्य को पुन: शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. समदड़ी राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन का निर्माण पुरानी सी.हा.सै. स्कूल के बंद पड़े भवन को हटाकर नई बिल्डिंग बनाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
37. सम्पूर्ण निर्मित भवन कन्या महाविद्यालय सिवाना, महाविद्यालय समदड़ी एवं महाविद्यालय सिणधरी का लोकार्पण करके विधिवत शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।
38. राजकीय महाविद्यालय सिवाना गौभक्त रावल गुलाबसिंहजी के नाम से, सिणधरी, समदड़ी महाविद्यालय का नाम वीरवर दुर्गादास राठौड़ एवं समदड़ी कन्या महाविद्यालय माता ललेची के नाम एवं सिवाना कन्या महाविद्यालय का राव बुला राठौड़ के नाम से किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं. 17)</u>

39. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।
40. जिला मुख्यालय भीलवाड़ा में आदर्श वेद महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।
41. माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में आधुनिक सुविधायुक्त कम्प्युटरीकृत लाइब्रेरी एवं भवन निर्माण की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

42. विधान सभा क्षेत्र भीम में संचालित महाविद्यालयों में व्याख्याताओं व अन्य संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।
43. राजकीय बालिका महाविद्यालय भीम पाहिया घोड़ा के भवन को राजकीय महाविद्यालय भीम के परिसर में स्थापित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)</u>

44. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)</u>

45. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय तथा बसावा एवं जाखल में महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)</u>

46. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
47. विधान सभा क्षेत्र आहोर में आहोर उपखण्ड पर क्रमोन्नत राजकीय महाविद्यालय को बजट आवंटित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र आहोर के बागरा, भवरानी, नवीन चांदराई, भाद्राजुन, गुडा-बालोतान में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
49. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भवरानी, बागरा एवं आहोर में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं. 138)</u>

50. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर व अलसीसर को पी.जी. में क्रमोन्नत करने एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय अलसीसर व मलसीसर में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं. 05)</u>

51. सरदारशहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक बजट तुरन्त उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
52. सरदारशहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय, जो कि राजमेस सोसायटी के तहत संचालित है, को नियमित सरकारी महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
53. सरदारशहर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में इतिहास व राजनीति विज्ञान विषय खोलने तथा नया वाणिज्य संकाय चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
54. सरदारशहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में विषय प्राध्यापकों के समस्त रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)</u>

55. प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्तियों के संबंध में चर्चा के लिए।
56. बूंदी कॉलेज में विभिन्न संकायों में डॉक्टरेट तथा उच्च स्तर की शिक्षा हेतु संकायों को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।
57. राजकीय महाविद्यालय तालेड़ा के लिये भवन निर्माण के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
58. बूंदी कॉलेज में स्मार्ट क्लास के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)</u>

59. राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय, बहरोड़ व कन्या महाविद्यालय बहरोड़ में स्नातकोत्तर (पी.जी.) के नये विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
60. राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय, बहरोड़ में रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
61. राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड़ में रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
62. राजकीय धर्मचन्द गांधी जैन महाविद्यालय, बहरोड़ में आचार्यों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड़ में आचार्यों की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं. 95)

64. विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु भूमि व भवन आवंटित कराने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)

65. राजकीय महाविद्यालय रामगढ़, राजकीय मोदी महाविद्यालय, फतेहपुर एवं कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर में स्टॉफ एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)

66. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा शहर स्थित पी.जी. महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा स्थित एम.बी.आर. राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. बालोतरा स्थित एम.बी.आर. राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु खेल-कूद के मैदान विकसित करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के कल्याणपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं. 144)

70. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर, गंगापुर, गाडरमाला, हम्मीरगढ़, करोई एवं सालेटा में महाविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर एवं रायपुर में नवीन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)

72. राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ौदामेव (अलवर) के लिए भूमि आवंटन करवाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के राजकीय महाविद्यालयों, रामगढ़, मुबारिकपुर एवं बडौदामेव (कन्या महाविद्यालय) के भवन निर्माण करवाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगेलाल मीना (वि.सं. 117)

74. राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ में प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राजकीय महाविद्यालय रैणी में प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)

76. बालिका महाविद्यालय कपासन एवं महाविद्यालय राशमी में भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. कपासन एवं मण्डपिया के महाविद्यालयों में प्रिन्सिपल एवं प्राध्यापकों एवं अन्य रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)

78. अजमेर दक्षिण में एक कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. अजमेर स्थित महर्षि दयानन्द महाविद्यालय के रिक्त पदों को अतिआवश्यक रूप से भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये जाने हेतु नियामक आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को सख्ती से तत्काल लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. फर्जी डिग्रियां बांटने वाले निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता को तुरन्त समाप्त कर दोषियों को कठोर सजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)

83. प्रतापसिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. राजकीय महाविद्यालय, बनेड़ा के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

85. राजकीय महाविद्यालय, फूलियाकलां में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. प्रतापसिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा में एक कॉन्फ्रेंस हॉल निर्माण के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)

87. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय महाविद्यालय छोटी खाटू एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय डीडवाना में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय डीडवाना में भूमि व भवन निर्माण की राशि स्वीकृत करवाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय नवसृजित होने पर लैब स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में प्रशासनिक भवन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में पुस्तकालय का पुन: निर्माण कार्य स्वीकृत करवाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)</u>

92. मनोहरथाना महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)</u>

94. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी तहसील में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. झालावाड़ जिले के राजकीय महाविद्यालय खानपुर को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने तथा स्नातक में विज्ञान एवं कॉमर्स संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. झालावाड़ के राजकीय महाविद्यालय झालावाड़, राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय खानपुर में रिक्त पड़े व्याख्याताओं एवं अन्य सभी पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के राजकीय महाविद्यालय खानपुर को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं. 144)</u>

99. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर जिला भीलवाड़ा में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में संस्कृत साहित्य एवं इतिहास विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के राजकीय महाविद्यालय गंगापुर, रायपुर एवं हमीरगढ़ में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं. 96)</u>

101. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर का नाम परिवर्तित कर 'राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर' करने पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में हिन्दी विषय एवं एम.बी. राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में स्नातक में भूगोल विषय प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)

103. किरण माहेश्वरी राजकीय महाविद्यालय कुंवारिया में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमन्द में राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वाणिज्य संकाय में व्यावसायिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन विषयों में अधिस्नातक कक्षायें प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. द्वारकाधीश कन्या महाविद्यालय, कांकरोली में हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास एवं संस्कृत विषयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं. 168)

107. राजकीय महाविद्यालय छोटी सादड़ी में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेडा में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. निम्बाहेड़ा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्नातक स्तर में अंग्रेजी, जियोलोजी एवं स्नातकोत्तर स्तर पर केमेस्ट्री विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. निम्बाहेड़ा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)

111. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मेड़तासिटी में नये विषय हिन्दी, इतिहास, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गोटन में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम इंदावड़ में नवीन राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अतुल भंसाली (वि.सं. 03)</u>

114. एम.बी.एम. विश्वविद्यालय की तर्ज पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं के.एन. महाविद्यालय में भी पूर्व छात्र परिषद का गठन कर क्रियाशील करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं एम.बी.एम. विश्वविद्यालय को आर्थिक सक्षमता हेतु नवीन पाठ्यक्रमों, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग सहित नवाचारों की समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं एम.बी.एम. विश्वविद्यालय में नियुक्त संविदाकर्मियों एवं प्लेसमेन्ट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के नियुक्ति की जांच, वांछित योग्यता के दस्तावेजों की जांच और कार्य प्रभार एवं उपस्थिति का भौतिक सत्यापन के साथ प्रदत्त दायित्वों के निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं एम.बी.एम. विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कार्मिकों के नियमित पेंशन हेतु सरकार द्वारा बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)</u>

119. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम खिवाड़ा में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम कन्टालिया में महाविद्यालय खोले जाने पर महाविद्यालय के भवन का निर्माण भामाशाह द्वारा करके सरकार को सुपुर्द करने विषयक पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)</u>

121. प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रोफेसरों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हंसराज मीना (वि.सं. 188)</u>

122. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पी.जी. महाविद्यालय में स्टॉफ की नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पी.जी. महाविद्यालय में आवश्यक सुविधाएं नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सुरेश मोदी (वि.सं. 183)</u>

124. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना के कॉलेज को पी.जी. में क्रमोन्नत करने व डाबला में नया कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (वि.सं. 50)

125. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील गुढाचन्द्रजी व नादौती के कन्या महाविद्यालय खोले जाने विषयक चर्चा के लिये।

श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)

126. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में राजकीय स्नातक महाविद्यालय चौहटन (यू.जी.) को स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पी.जी.) में क्रमोन्नत कर हिन्दी, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि विषयों में एम.ए. (मास्टर डिग्री) खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में संचालित महाविद्यालयों में प्राचार्य, व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कनिष्ठ सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि के समस्त रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरे जाने हेतु चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)

129. जैसलमेर जिले के उपखण्ड फतेहगढ़ कॉलेज में लेक्चरार के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. जैसलमेर जिले में रामगढ़ कॉलेज में व्याख्याताओं का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

131. जैसलमेर जिले के गांव बडोड़ा, झिझानियाली एवं मोहनगढ़ में कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)

132. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ब्लाक श्री विजयनगर में भामाशाह जमीन एवं उस पर महाविद्यालय बनाकर देने को तैयार है ऐसी स्थिति में उसे राजकीय महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं. 36)

133. विधान सभा क्षेत्र बगरू स्थित राजकीय महाविद्यालय बगरू को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बगरू के प्रतापनगर में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र बगरू के महल रोड़ जगतपुरा में महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र बगरू स्थित राजकीय महाविद्यालय बगरू में पुस्तकालय भवन निर्माण करवाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र बगरू के राजकीय महाविद्यालय बगरू में "विज्ञान संकाय" एवं कला वर्ग में "संस्कृत" विषय की स्वीकृति दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)

138. विधान सभा क्षेत्र शिव में स्थापित राजकीय महाविद्यालय शिव एवं गडरारोड़ में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा के महाविद्यालयों में बेहतर शिक्षा हेतु कॉलेज में ई-लाईब्रेरी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र शिव में बालिकाओं को सुलभ उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यालय शिव पर बालिका महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र शिव में उपखण्ड मुख्यालय शिव पर स्थापित राजकीय महाविद्यालय शिव को स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने एवं उसका नामकरण बाबा गरीबनाथ जी के नाम पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं. 30)

142. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पड़े शैक्षणिक, अशैक्षणिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. प्रदेश के नये खुले महाविद्यालयों में से कई महाविद्यालयों के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

144. राजस्थान विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक, अशैक्षणिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. जयपुर शहर में जे.एल.एन. मार्ग पर निर्मित राजकीय महाविद्यालय भवन में महाविद्यालय शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं. 44)

147. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय, माण्डलगढ़ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित राजकीय विजयसिंह पथिक महाविद्यालय, बिजौलिया के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. माण्डलगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित राजकीय शिवचरण माथुर महाविद्यालय में कक्षा कक्ष बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विनोद कुमार (वि.सं. 153)

151. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कर विज्ञान, कृषि, वाणिज्य संकाय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजकीय कन्या महाविद्यालय में विषय वृद्धि के साथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गोलूवाला में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में बी.एड एवं बी.एस.टी.सी. महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं. 42)

155. रा.म. महाविद्यालय सादुलशहर में स्नातकोत्तर स्तर के लिए 7 कक्षा-कक्ष के निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. रा.म. महाविद्यालय सादुलशहर में गृह विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. रा.म. महाविद्यालय सादुलशहर में 13 रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. सादुलशहर के राजकीय महाविद्यालय हिन्दुमलकोट में रिक्त 21 पदों पर स्थायी नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. सादुलशहर के राजकीय महाविद्यालय हिन्दुमलकोट में पंजाबी विषय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं. 178)

160. भरतपुर संभागीय मुख्यालय पर विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. प्रदेश में विगत तीन वर्षों में खुले नये महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की कार्यप्रणाली एवं भर्तियों में अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

163. प्रदेश में विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये।

164. प्रदेश में कॉलेज शिक्षा में अतिथि संकायों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं. 106)

165. राजकीय महाविद्यालय बसवा का नामकरण महाराणा सांगा राजकीय महाविद्यालय बसवा एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय बांदीकुई का नामकरण सावित्री बाई फुले राजकीय कन्या महाविद्यालय बांदीकुई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. स्व. राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई में नवीन भवन निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित विभिन्न महाविद्यालयों में नये विषय एवं संकाय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं. 200)</u>

169. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के ज्ञान ज्योति कॉलेज, श्रीकरणपुर का सरकारीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं. 200)</u>

170. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के केसरीसिंहपुर में बालिका महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के श्री गुरू गोविन्द सिंह कन्या महाविद्यालय की मान्यता की जांच करवायी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र करणपुर की राजकीय कन्या महाविद्यालय, बुढडा जोहड़, तहसील रायसिंहनगर में पंजाबी विषय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं. 120)</u>

173. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय महाविद्यालय रेवदर व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आबूरोड़ में रिक्त पड़े विभिन्न पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)</u>

174. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सूरतगढ़ एवं बीरमाना महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने, नये पद सृजित करने तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के जैतसर, राजियासर एवं पालीवाला में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सूरतगढ़ एवं बीरमाना के महाविद्यालयों में नये विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सूरतगढ़ में नया कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>स्वामी बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं. 102)</u>

178. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुरा खोर में राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (वि.सं. 60)</u>

180. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैपऊ, बाड़ी, बसई नवाब कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

181. बयाना स्थित राजकीय देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत एक और स्थाई सैक्शन स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजीव कुमार (वि.सं. 171)</u>

182. राजकीय महाविद्यालय भादरा (जिला हनुमानगढ़) में कॉमर्स (वाणिज्य) एवं विज्ञान संकाय स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. राजकीय महाविद्यालय भादरा (जिला हनुमानगढ़) को स्नातकोत्तर (पी.जी.) करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. राजकीय महाविद्यालय भादरा में प्रिंसिपल, आचार्य, सहायक आचार्य सहित अन्य स्टॉफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. राजकीय महाविद्यालय भादरा जिला हनुमानगढ़ के चारदिवारी निर्माण कार्य स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)</u>

186. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कालाडेरा महाविद्यालय में नवीन स्नातक (यू.जी.) विषय गृह विज्ञान, कम्प्यूटर साईंस, भूगोल आदि शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कालाडेरा महाविद्यालय में नवीन पी.जी. विषय हिन्दी साहित्य, जूलॉजी, बॉटनी आदि शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कालाडेरा सहरिया महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं. 144)</u>

189. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के राजकीय महाविद्यालय गंगापुर, रायपुर एवं हमीरगढ़ में अधिकतर शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती शोभा चौहान (वि.सं. 165)</u>

190. विधान सभा क्षेत्र सोजत में स्थित महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने एवं स्नातकोत्तर स्तर शुरू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उमेश मीणा (वि.सं. 23)

191. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के नवीन साबला ब्लॉक में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के दोवडा व आसपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के दोवडा, आसपुर व साबला में राजकीय वीर भील कालीबाई कलासुआ कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)

194. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के बाबा गंगादास राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में स्नातक स्तर पर इतिहास विषय स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिक शास्त्र, संस्कृत, वनस्पति शास्त्र व प्राणी शास्त्र विषय में पी.जी. संचालित करने व रसायन शास्त्र में लैब खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के राडावास राजकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की ग्राम पंचायत खेजरोली में सह-शिक्षा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की ग्राम पंचायत देवन में सह-शिक्षा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (वि.सं. 123)

198. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के जामडोली स्थित जामडोली कॉलेज में शिक्षक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)

199. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के अकलेरा में नया राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के महाविद्यालय के भवन निर्माण कार्य में द्वितीय फेज का रूका हुआ कार्य शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (वि.सं. 123)

201. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में जामडोली स्थित कॉलेज में खेल स्टेडियम बनाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)

202. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ग्राम पंचायत हरमाड़ा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना व राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं बी.एड. कॉलेज की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

203. जिला बारां में राजकीय महाविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के राजकीय महाविद्यालय शाहाबाद में पृथक से खेल संकुल बनाने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित यादव (वि.सं. 143)

205. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में राजकीय महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में महाविद्यालय भवन नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (वि.सं. 47)

209. विधान सभा क्षेत्र धोद की लोसल नगरपालिका स्थित कॉलेज में संसाधन व सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र धोद में सहशिक्षा कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)

211. विधान सभा क्षेत्र कामां के सभी राजकीय कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष मील (वि.सं. 179)

212. बाबा विशम्भर दास कन्या महाविद्यालय होद (खण्डेला) में स्नातकोत्तर (पी.जी.) में राजनीतिक विज्ञान, इतिहास विषय खोलने, होद व खण्डेला में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीम राज भाटी (वि.सं. 107)

213. संभागीय मुख्यालय पाली में विश्वविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)

214. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राजकीय महाविद्यालय में बी.एस.सी. एवं बी.कॉम. विषय (संकाय) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान एवं भूगोल विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं. 155)</u>

216. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के खाजुवाला महाविद्यालय, छतरगढ़ महाविद्यालय एवं पूंगल महाविद्यालय में व्याख्याता एवं अन्य स्टॉफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)</u>

217. विधान सभा क्षेत्र शिव में उपखण्ड मुख्यालय शिव व गडरारोड़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रतन देवासी (वि.सं. 122)</u>

218. माउण्ट आबू (सिरोही) पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय जसवन्तपुरा (जालोर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं. 57)</u>

220. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के उपखण्ड बदनोर में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री कुलदीप (वि.सं. 33)</u>

221. राजकीय महाविद्यालय विराटनगर में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं. 46)</u>

222. जहाजपुर राजकीय महाविद्यालय भवन की चार दीवारी निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय महाविद्यालय में खेल स्टेडियम हेतु भूमि आवंटन के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कोटड़ी (शाहपुरा) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने एवं आवासीय छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय महाविद्यालय में पानी-बिजली की व्यवस्था चार दीवारी निर्माण एवं वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>महन्त बालकनाथ (वि.सं. 114)</u>

227. तिजारा में अलग से महिला महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रामबिलास (वि.सं. 135)</u>

228. विधान सभा क्षेत्र लालसोट की ग्राम पंचायत होदायली के ग्राम समेल में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं. 95)</u>

229. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय महाविद्यालय जालसू में रिक्त पदों पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की शीघ्र स्थायी नियुक्ति कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय आमेर शहर हेतु भूमि आवंटन व शीघ्र भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती गीता बरवड़ (वि.सं. 41)</u>

231. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में महिला महाविद्यालय खुलवाने, आसोप में महाविद्यालय भवन शीघ्र पूर्ण करवाने एवं राजकीय महाविद्यालय बावड़ी में बी.एस.सी. एवं पी.जी. संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं. 22)</u>

232. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के राजकीय कन्या महाविद्यालय को राजसेस (RAJSES) से राजकीय में परिवर्तित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के राजकीय कन्या महाविद्यालय में लाईट-फीटिंग व अन्य विद्युत कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के राजकीय कन्या महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के राजकीय महाविद्यालय करेड़ा में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के राजकीय महाविद्यालय करेड़ा में पेयजल तथा महाविद्यालय परिसर की चारदीवारी निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)</u>

237. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में महिलाओं/बालिकाओं के लिये नये महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. कोटा जिले के राजकीय महाविद्यालय स्थित पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा स्थित राजकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. कोटा जिले के महाविद्यालय में अध्यनरत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. कोटा जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजय कुमार (वि.सं. 169)</u>

242. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के महाविद्यालय के सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अभिमन्यु (वि.सं. 07)</u>

243. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के कन्या महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री समरजीत सिंह (वि.सं. 174)</u>

244. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के भीनमाल शहर में कॉलेज (सरकारी) को पूर्ण रूप से पी.जी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के सरकारी कॉलेज में शैक्षणिक रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं. 87)</u>

246. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं. 01)</u>

248. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्राम किल्चू तहसील बीकानेर में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सभी महाविद्यालयों की चार दिवारी का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सभी महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में देशनोक स्थित राजकीय महाविद्यालय का नाम राजकीय मां करणी महाविद्यालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सीमान्त क्षेत्र गोकुल तहसील बज्जू में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं. 187)</u>

253. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के राजकीय एल.बी.एस. कॉलेज में एक बड़े सभागार का निर्माण करवाने तथा प्रथम वर्ष में संकाय बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (वि.सं. 185)</u>

254. विधान सभा क्षेत्र नोखा में उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)</u>

255. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय में रिक्त कार्मिकों के पद शीघ्र भरने, अशैक्षणिक कर्मचारियों के अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजकीय कन्या महाविद्यालय बबाई को सहशिक्षा में बदलने तथा इसे राजशेष श्रेणी से राजकीय श्रेणी में परिवर्तित करने तथा स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय में एन.सी.सी. शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय में स्व वित्तपोषित योजना के तहत खोले गये एम.ए. अर्थशास्त्र संकाय को राजकीय मद में बदलने तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय बबाई में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में 5 नए कक्षा-कक्ष, 04 प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय भवन (केन्द्रीय) बनाने, सेमीनार भवन और खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित करने तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय बबाई में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 2
मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

1. ब्यावर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

2. बयाना में पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)

3. उदयपुर ग्रामीण एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज टिडी जखर एरिया में खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं.10)

4. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला मुख्यालय सलूम्बर में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

5. विधान सभा क्षेत्र नोहर में राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

6. तकनीकी शिक्षा में सुधार, पॉलीटेक्निकल कॉलेज में प्रवेश एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)

7. तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला में नवीन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

8. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा शहर एवं पीपाड़ शहर में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)

9. पॉलीटेक्निक कॉलेज, जोधपुर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स और माईनिंग विद्या के कोर्सेज प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)

10. प्रदेश के तकनीकी पाठ्यक्रमों में परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम प्रकाशन के अनियमित शेड्यूल के कारण पाठ्यक्रम पूर्णता में तय अवधि से कई अधिक समय

लगने से विद्यार्थियों को होने वाले नुकसान को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

11. सिवाना मुख्यालय पर राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

12. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में स्वीकृत नवीन संकायों हेतु नये भवन के निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में स्वीकृत नवीन संकायों हेतु नये पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
14. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में स्वीकृत नवीन संकायों हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण व आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

15. विधान सभा क्षेत्र भीम की तहसील भीम में नवीन पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

16. पोलीटेक्निक शिक्षण संस्थान, आहोर के सुसंचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
17. विधान सभा क्षेत्र आहोर के तहसील मुख्यालय-भाद्राजुन एवं तहसील-जालोर के सियाणा में तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र आहोर में तकनीकी शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

19. तकनीकी शिक्षा के रिक्त पदों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
20. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा के संबंध में चर्चा के लिए।
21. बून्दी पॉलीटेक्निक कॉलेज में नए विषय (ट्रेड) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

22. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पॉलोटेक्निक कॉलेज खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में महिला पॉलोटेक्निक कॉलेज खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

24.विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में स्वीकृत रिफाईनरी क्षेत्र के पास की जमीन पर स्वीकृत पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

25.प्रदेश के पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के कोर्स को सेमेस्टर प्रणाली से पुनः वार्षिक शिक्षा प्रणाली से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26.प्रदेश के पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को डिप्लोमा के पश्चात् पी.एच.ई.डी., पी.डब्ल्यु.डी. एवं विद्युत विभाग में सहायक अभियन्ता भर्ती में सीटें आरक्षित करने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लादू लाल पितलिया (वि.सं.144)

27.विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के रायपुर एवं गंगापुर में पोलोटेक्निक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)

28.अजमेर में संचालित महिला इंजीनियरिंग कॉलेज को स्व:वित्त पोषित योजना से हटाकर राज्य वित्त पोषित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29.अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज बडल्या में पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30.अजमेर दक्षिण में संचालित महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज में नये कोर्स संचालित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. अजमेर दक्षिण में स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं जीर्ण-शीर्ण चारदीवारी की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32.तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को समयानुसार बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

33.शाहपुरा में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री यूनुस खान (वि.सं.121)

34.नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में राजकीय तकनीकी महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

35.प्रदेश में नवीन राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

36.झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37.इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ में नए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम यथा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स आदि सम्मिलित किए जाने एवं रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)

38.विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर व रायपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

39.पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में उद्योग एवं व्यवसाय के आधार पर परिवर्तन करने एवं स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40.राजसमन्द जिला मुख्यालय पर अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, राजसमन्द में पुस्तकालय के प्राय: बन्द रहने एवं पुस्तकालय में नवीन पुस्तकों और आवश्यक भौतिक सुविधाओं की कमी पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42.राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, राजसमन्द में उपलब्ध विषयों के प्रचार-प्रसार के अभाव में प्रवेश क्षमता 180 में से मात्र 69 विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43.राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, राजसमन्द में खनन विषय प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

44.निम्बाहेड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45.निम्बाहेड़ा में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

46.विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के उपखण्ड मुख्यालय मेड़ता पर राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

47.अटरू में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

48.राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, जोधपुर में सभी विभागों में पार्किंग स्थल के विकास हेतु विशेष बजट प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49.प्रदेश के तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स विषयों, सायबर क्राइम प्रतिरक्षा संबंधी विषयों के समावेश की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50.राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, जोधपुर में समेकित खेल कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम की स्थापना हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, जोधपुर में जोधपुर के स्थानीय परिस्थितियों अनुरूप खनन, हेण्डीक्राफ्ट, पैट्रोलियम संबंधी नवीन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

52.विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पोलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं.50)</u>

53.विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)</u>

54.जैसलमेर जिले के सुल्तान (Sultana) मोहनगढ़ गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर तकनीकी विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

55.विधान सभा क्षेत्र शिव के स्थानीय युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यालय शिव पर पोलीटेक्निक कॉलेज की स्थापना करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

56.प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक, अशैक्षणिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)</u>

57.विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

58.प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59.तकनीकी शिक्षा के संस्थानों में स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60.प्रदेश के पॉलीटेक्निक कॉलेजों में ए.आई. एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)</u>

61. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर व रायपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)

62.प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में हुई संविदा भर्ती में विसंगतियों को दूर करने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

63.विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

64.विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज, ऊनी (केलवाड़ा) में तकनीकी शिक्षक एवं संसाधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65.विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष मील (वि.सं.179)

66.विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में नवीन पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)

67.संभागीय मुख्यालय, पाली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)

68.विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बालिकाओं के लिए पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69.विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

70.विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. कोटा जिले में पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को सक्षम छात्रवृत्ति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72.कोटा जिले में स्थित पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में उद्योगों के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73.कोटा जिले के पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार दिए जाने एवं अन्नपूर्णा रसोई से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)

74.तहसील कोलायत मुख्यालय में तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की तहसील बज्जु में राजकीय तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल (वि.सं.83)

76. खेतड़ी के बबाई क्षेत्र में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. खेतड़ी में महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

78. बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में सेरेमिक्स विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 3
मांग संख्या 62 - परिवहन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-62 मुख्य शीर्षक **परिवहन विभाग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)

1. ब्यावर से बडौदा, हरिद्वार, दिल्ली एवं अन्य जगहों के लिए बसों की संख्या बढाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम (वि.सं. 175)

2. आबू पर्वत से चलने वाली बसों को पुनः चालू करने तथा पिण्डवाडा बस स्टेशन को बस डिपो बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)

3. बयाना एवं रूपवास के मध्य ग्रामीण परिवहन हेतु बस संचालन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. बयाना में बस स्टैण्ड हेतु भूमि आवंटन व निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।
5. बयाना में रोडवेज बसों का परिचालन करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।
6. बयाना से कोट थाना डांग क्षेत्र में ग्रामीण परिवहन हेतु बसों के संचालन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

7. किशनगंज, नाहरगंढ, केलवाडा, कस्बाथाना कस्बों में सरकारी बसों व पथ परिवहन निगम की बसों के स्टोपेज एवं ठहराव के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (98)

8. उदयपुर में जनजाति एरिया से शहरों में आने-जाने हेतु बसों के संचालन की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं.10)

9. जिला परिवहन कार्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. सलूम्बर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सरकारी बसों के संचालन तथा उदयपुर से सराडा, सेमारी, टोकर तक सरकारी बसें चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. प्रदेश में प्रत्येक परिवहन कार्यालय के बाहर यातायात सलाहकारों की औचित्यता के संबंध में चर्चा के लिये।

13. प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा संचालित बसों की R.C. जांच व मॉडल की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं. 05)</u>

14. सरदारशहर में स्वीकृत उप परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण के लिए बजट का आंवटन शीघ्र करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)</u>

15. विधान सभा क्षेत्र नोहर में स्वीकृत रोड़वेज बस डिपो के भवन निर्माण एवं बसों का संचालन करने हेतु चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र नोहर के स्वीकृत परमिट के विभिन्न मार्गों पर निगम की बसों के बंद किये गए संचालन को पुनः संचालित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

17. जयपुर एवं दिल्ली से नोहर के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वॉल्वो व डीलक्स बसों का संचालन किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र नोहर में बिना स्वीकृत परमिट एवं समय सारणी के विभिन्न मार्गों पर संचालित अवैध निजी बसों के संचालन पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

<u>श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)</u>

19. परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार एवं ओवर लोडिंग वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)</u>

20. छबडा उपखण्ड में उप परिवहन कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र छबडा में ग्रामीण परिवहन सेवा के अन्तर्गत बसों के संचालन की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं. 101)</u>

22. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर कस्बे में यात्रियों की सुविधा हेतु नवीन अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बस स्टेण्ड के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में उप परिवहन कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. जोधपुर से शेरगढ मार्ग के बीच संचालित बसों की संख्या में बढोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में लोक परिवहन सेवा बसें शुरू करने हेतु चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)</u>

26. विधान सभा क्षेत्र बिलाडा के 65 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ग्रामीण लोक परिवहन बसों की सेवा से जोडने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बिलाडा में बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर रोडवेज बस स्टेण्ड की मरम्मत कर बस स्टेण्ड पर मूलभूत आवश्यकताओं/सुविधाओं की सेवाएं प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)</u>

28. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में आवश्यक रूट पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करवाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के ब्लॉक लसाडिया से कनेक्टीवीटी सलूम्बर वाया लसा़डिया, बडी सादडी पर राजस्थान पथ परिवहन की बसें संचालित करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के धरियावद वाया लोहागढ वाया भभराना से आसपुर होते हुए अहमदाबाद के लिए बस सेवा के संचालन के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के लिए तीन नई बसें उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं. 82)</u>

32. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में शहरों के निकटवर्ती गांवों से अप-डाउन सुविधा वाली रोडवेज बसों को आरम्भ करने की आवश्यकता की चर्चा के लिये।

33. प्रदेश में निजी परिवहन साधनों के अवैध रूटों पर संचालनों को रोकने के लिए रोडवेज और आर.टी.ओ. का संयुक्त कार्यदल बनाकर अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. प्रदेश में पर्यटन आकर्षण के केन्द्रों वाले शहरों में रोडवेज की ओर से विशेष साइट सीन वाली पैकेज बसों को आरंभ करने और रेलवे की तर्ज पर पर्यटन सर्किट के पैकेज वाली योजनाएं आरंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में नवीन बसी कॉलोनियों में बस स्टेण्ड के लिए आरक्षित भूमि को आवंटित करने के लिए अभियानपूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. रोड़वेज को घाटे से उबार कर आयप्रदत्त एजेंसी के रूप में विकसित करने की समयबद्ध कार्य योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)</u>

37. सिवाना-जालौर-समदडी-कल्याणपुर-जोधपुर के रास्ते पथ परिवहन निगम (रोड़वेज) की बसें शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टेण्ड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. जोधपुर सिवाना के रूट पर चलने वाली निजी बसों को निर्धारित रूट पर चलाने के लिए पाबन्द करने एवं अवैध निजी बसों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. बाड़मेर-बालोतरा-सिवाना-पाली-अजमेर-जयपुर के रास्ते रोडवेज बस चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. ग्रामीण क्षेत्र में लोक परिवहन (निजी) बस सेवा शुरू करने के साथ मुख्य कस्बों तक रोडवेज बस यथा पादरू, समदडी, अजीत, इन्द्राणा, मोऊलसर, खण्डप आदि को रोडवेज बस सेवा से जोडने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं. 17)</u>

42. भीलवाडा जिला मुख्यालय पर रोडवेज डिपो को आधुनिकतम सुविधायुक्त Bus Ports/ Stands का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. भीलवाड़ा रोड़वेज डिपो में तत्काल 100 नई बसें उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

44. भीलवाडा शहर व पैराफेरी क्षेत्र में नई सिटी बसों के संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

45. विधान सभा क्षेत्र भीम के परिवहन कार्यालय को अति. जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र भीम के परिवहन कार्यालय भीम में रिक्त पड़े सभी संवर्ग के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

47. परिवहन कार्यालय भीम के लिए आवंटित भूमि पर नवीन भवन निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)</u>

48. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर से जयपुर तक रोडवेज बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश में लोक परिवहन बसों द्वारा बस किराये में व अन्य मनमर्जी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

50. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में परिवहन कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)</u>

51. जालोर बागरा, डुडसी दी गांव नागणी भेटाला सियाणा काणदर रायपुरिया सवणा सिरोही मार्ग पर पथ परिवहन बसें शुरू करवाने तथा जालोर बिशनगढ बालवाडा रायथल भवरानी, वावडी, नोसरा, अजीतपुरा, काम्बा आहोर, भैरवाडा, गोरन, सांकरण, लेय जालोर हेतु बसों के संचालन की अवाश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र आहोर के पथ परिवहन निगम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें शुरू करवाने तथा आहोर उपखण्ड पर स्थित बस स्टॉप पर बसों के ठहराव की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।
53. विधान सभा क्षेत्र आहोर में सुमेरगढ खेडा, भैंसवाडा, कुआरडा, अजीतपुरा, गुडारामा में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों का ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
54. जालोर एवं बीकानेर, जोधपुर आगार की बसों के नोरवा गांव में ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
55. विधान सभा क्षेत्र आहोर में जालोर आगार से संचालित होने वाली पूर्व की अहमदाबाद की बस पुनः शुरू करवाने तथा जालोर लेटा, कानीवाडा, ऊण, भागली, छीपरवाडा, बुडतरा, चवरहवा, हरजी से मणादर, सिरोही, अहमदाबाद की बस पुनः शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं. 138)</u>

56. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सेवाओं को चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)</u>

57. बून्दी बस स्टैण्ड के विकास हेतु बजट आवंटन तथा नीति निर्धारण के संबंध में चर्चा के लिये।
58. बून्दी आगार के लिए बसों का आवंटन तथा नई बसें खरीदने के संबंध में चर्चा के लिये।
59. प्रदेश में विभाग के रिक्त पदों पर वाहन चालकों व अन्य स्टाफ की भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के आस-पास की तहसील रायथली नैनवा के पाटन/हिण्डौली/तालेडा हेतु बसों के फेरे बढाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.स. 61)</u>

61. भादण तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय कोटपूतली होते हुए जयपुर तक रोडवेज बस चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।
62. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सांतो से भादण होते हुए कोटपूतली तक रोडवेज बस संचालन हेतु चर्चा के लिए।
63. निहालपुरा से बहरोड़-कोटपूतली-जयपुर तक रोड़वेज बस चलाने हेतु चर्चा के लिये।
64. कोटपूतली से वाया कोहराना नारनोल तक रोडवेज बस चलाने हेतु चर्चा के लिये।

65. शाहाजहापुर टोल पर ओवरलोड वाहनों की चैकिंग व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं. 95)

66. विधान सभा क्षेत्र आमेर में कूकस से सांगानेर की बसों का संचालन अचरोल अथवा चन्दवाजी तक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
67. विधान सभा क्षेत्र आमेर में चांदपोल से चौंप तक चलने वाली बस को पुनः आरम्भ कर जाटावाली तक बढाने के संबंध में चर्चा के लिये।
68. विधान सभा क्षेत्र आमेर में ग्राम बगवाडा से चांदपोल की बस को पुनः शुरू करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)

69. फतेहपुर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाने, रामगढ में रोडवेज बसों को रामगढ शहर के अन्दर बस स्टैण्ड तक संचालन तथा रोड़वेज बसों को मोदी राज. महाविद्यालय के पास ठहराव करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)

70. बालोतरा, समदडी, पाली मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस चलाने की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
71. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पटाऊ, सरवडी, चारलाई गांव में राजस्थान रोडवेज बस के स्टोपेज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
72. बालोतरा स्थित बस स्टेण्ड को अत्याधुनिक किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
73. बालोतरा जिला मुख्यालय पर राजस्थान पथ परिवहन निगम का आगार अर्थात डिपों खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
74. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पचपदरा स्थित बस स्टेण्ड का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं. 144)

75. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विभिन्न मार्गो पर बसों का संचालन पुनः प्रारम्भ कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
76. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर एवं रायपुर में नवीन बस स्टैण्ड के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)

77. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में आवश्यकतानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज की बसों का संचालन करने हेतु चर्चा के लिये।
78. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के अलवर-रामगढ़-मुबारिकपुर-खुडियाना-पापडी-चिकानी अलवर रूट पर बसें चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री बहादुर सिंह (वि.सं. 99)</u>

79. जयपुर से वाया कलसाड़ा-खरैरी होते हुए बयाना तक बस का संचालन करने के संबंध में चर्चा के लिये।
80. विधान सभा क्षेत्र वैर में स्थित ग्राम खरैरी-वागरैन से नई दिल्ली तथा आगरा के लिए रोड़वेज बस का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
81. वैर से गोवर्धन के लिए रोडवेज बस का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं. 117)</u>

82. विधान सभा राजगढ-लक्ष्मणगढ में अलवर-मालाखेडा-श्यामगंगा-नवलपुरा-नीलेटा-पाटन-माचाडी-रैणी रूट पर रोड़वेज बसें संचालित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
83. विधान सभा राजगढ-लक्ष्मणगढ में अलवर-राजगढ-माचाडी-बैरेर-कानेटी-पाली-रैणी-भूड़ा-मण्डावर-महुवा रूट पर रोडवेज बस संचालन कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
84. विधान सभा राजगढ-लक्ष्मणगढ में अलवर-राजगढ-माचाडी-रहरडा-रैणी-रामपुरा रूट पर रोडवेज बसों का संचालन कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
85. विधान सभा राजगढ-लक्ष्मणगढ में अलवर जिले के राजगढ़ में रोडवेज बस डिपो स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)</u>

86. विधान सभा क्षेत्र कपासन की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय तक परिवहन की बसों को परमीट देने तथा पुरानी रोड़वेज बसों के स्थान पर नई बसें चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
87. तिजारा आगार की तिजारा से उदयपुर चलने वाली बस को वाया पहुना, राशमी, मातृ कुण्डिया होकर चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)</u>

88. अजमेर शहर में निजी बसों के लिए समुचित स्थान वाले स्टैण्ड निर्धारित नहीं होने से उत्पन्न स्थिती के संबंध में चर्चा के लिये।
89. अजमेर में निजी बसों का संचालन निर्धारित बस स्टैण्ड से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
90. परिवहन विभाग में अनियमितताओं को दूर करने हेतु निरीक्षक एवं उपनिरीक्षकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की एक ठोस कार्ययोजना/नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
91. प्रदेश के विभिन्न शेहरों में स्थित सरकारी बस स्टेण्डों के रख-रखाव एवं नव निर्माण हेतु बजट प्रावधान को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
92. अजमेर दक्षिण के पर्वतपुरा क्षेत्र में निजी बसों के संचालन हेतु एक नया बस स्टेण्ड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)

93. बनेडा में एक राजस्थान पथ परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. भीलवाडा स्थित शाहपुरा में एक हाईटेक मॉडल बस डिपों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेडा की विगत 5 वर्षो में बंद की गई बसों को पुनः चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)

96. डीडवाना आगार में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. डीडवाना आगार में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक, परिचालक, अन्य कार्मिकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. डीडवाना आगार में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यशाला में टिनशेड व सी.सी. सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

100. जिला परिवहन कार्यालय, डीडवाना में जर्जर भवन की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)

101. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में बसों का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)

102. झालावाड जिले की खानपुर एवं बकानी तहसील में आधुनिक बस स्टैण्ड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में ग्रामीण परिवहन सेवा का विस्तार करके प्रत्येक ग्राम पंचायत तक बस सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में चलने वाली बस सेवा रटलाई से झालावाड और बकानी से झालावाड के दो-दो फेरे बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बंद की गई बस सेवाओं यथा बारां से इन्दौर वाया खानपुर, अजमेर से भोपाल वाया रटलाई, झालावाड से खीलचीपुर वाया बकानी, हिंडौन से चांदखेडी (खानपुर) वाया पनवाड़ को फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. झालावाड़ डिपो की नाकारा बसों को हटा कर नई बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.स. 144)

107. विधानसभा क्षेत्र सहाडा से पूर्व संचालित बसों को पुनः शुरू करने तथा लम्बी दूरी की बसों का भी संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. वर्तमान में गंगापुर में सहाडा चौराहा व रायपुर में गंगापुर रोड पर नवीन बस स्टैण्ड निर्माण करवाने हेतु चिन्हित भूमि हेतु बजट स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)

109. कांकरोली से मोही, पीपली आचार्यान, बडलिया, पीपली अहिरान, गोगाथला, कुरज, जुणदा, लापस्या, भीलवाड़ा लोक परिवहन अथवा परिवहन निगम की बस सेवा प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. कांकरोली, पीपली आचार्यान, पीपली अहिरान, गोगाथला, कुरज, रेलमगरा, पछमता, गिलुण्ड, मातृकुण्डिया, चितौडगढ हेतु लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. राजसमन्द में यातायात नगर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. राजसमन्द में निर्मित ट्रैफिक पार्क में गोल्फ कार्ट की अनुपलब्धता, आवश्यक भौतिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण बसों का संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

113. परिवहन निगम के राजसमन्द आगार हेतु नई बसे आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं. 168)

114. निम्बाहेडा में उप परिवहन कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं. 141)

115. विधान सभा क्षेत्र मेडता शहर स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड की चारदीवारी एवं कार्यालय निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं. 131)

116. बांरा से खानपुर वाया अटरू तक बस संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।

117. अटरू से सांगोद वाया कुन्जेड बस संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं. 03)

118. राजस्थान से सटे अन्य प्रदेशों की सीमाओं से लगे तीर्थ क्षेत्रों हेतु विशेष यात्रा पैकेज सेवाओं को आरंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. प्रदेश में रोड़वेज द्वारा पर्यटन आकर्षण केन्द्रों वाले नगरों में साईट सीन पैकेज योजना आरंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. प्रदेश में रोड़वेज द्वारा विभिन्न पर्यटन सर्किट यात्रा पैकेज योजना आरंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रदेश में रोड़वेज को घाटे से उबारने की समयबद्ध कार्य योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. प्रदेश में रोड़वेज तंत्र की सुरक्षा के लिए अवैध रूटों पर निजी परिवहन साधनों के संचालन पर कठोरता से रोक लगाने की समयबद्ध कार्य योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)

123. जोधपुर से सरदार सम्बध मारवाड़ जंक्शन होते हुए उदयपुर के लिये रोड़वेज बसों का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी खुर्द को नाकोड़ा, जालोर, रानी, खुर्द होते हुए उदयपुर के लिए रोड़वेज बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)

125. परिवहन विभाग में निरीक्षकों की अति अनियमितताओं पर रोक तथा ऑवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)

126. कामां से बयाना-हिण्डौन होते हुए करौली कैलादेवी तक बस का संचालन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. ब्रज क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन हेतु स्थानीय बसों का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां से जयपुर के लिए रोड़वेज बसें चलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं. 128)

129. विधान सभा क्षेत्र महवां के मुख्यालय बस स्टेण्ड पर रात्रि के समय लोहागढ़ डिपो की बसों के ठहराव के संबंध में चर्चा के लिए।

130. महवां केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर सुविधाओं के विस्तार एवं बालाहेड़ी मोड़, गाजीपुर मोड़ साथ ही अकरूद, रसीदपुर मोड़ पर बसों का स्टोपेज बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं. 50)

131. टोडाभीम के ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों के संचालन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. टोडाभीम में रोडवेज बस स्टेण्ड की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम से महुवा एवं टोडाभीम से गंगापुर तक बसों के संचालन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं. 187)</u>

134. विधान सभा क्षेत्र कोटपुतली में दांतिल वाया नारेहेड़ा से पावटा तथा बनेटी से खेड़ा निहालपुरा से कोटपुतली तक बस सेवा शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं. 19)</u>

135. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में चौहटन एवं सेड़वा उपखण्ड मुख्यालय पर रोड़वेज बस डिपों खोले जाने हेतु चर्चा के लिए।

136. चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर परिवहन निरीक्षक का पद सृजित कर कार्यालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में ग्रामीण क्षेत्रों बाड़मेर जिला मुख्यालय से चौहटन उपखण्ड मुख्यालय तक चौहटन उपखण्ड मुख्यालय से सेड़वा होते हुए बालासर तक मीठड़ाऊ, धनाऊ ग्राम क्षेत्रों में, चौहटन, धनाऊ, सेड़वा व फागलिया चारों पंचायत समिति मुख्यालय को जोड़ने वाले प्रमुख राजस्व ग्राम में, चौहटन, कापराऊ, बूढ, बावड़ी, गुमाने का तला, मिठड़ाऊ सरूषे का तला, कृष्णा का तला, सोमराड़ा जालीला, दीपला जाटा बेरा, हाथला छोटा-बड़ा बाकासर तक नवीन रोड़वेज बस सेवा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं. 55)</u>

138. जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ सुधारमंडी, PTM होते हुए सुल्ताना मोकला होते वापस जैसलमेर तक रोड़वेज बस सेवा प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

139. जैसलमेर शहर मुख्यालय से सम गांव तक तथा जैसलमेर से लुदवा, रूपसी, पुनमनगर, (खुईमाल) बांधा से 40 RD IGNP SMG नहर तक रोड़वेज बस के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. जैसलमेर से म्यानला गांव तक तथा जैसलमेर से तनोट ग्राम पंचायत मुख्यालय तक रोडवेज बस प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)</u>

141. नगर पालिका बगरू में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.48 पर बस स्टैण्ड निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. नगर पालिका वाटिका में बस स्टैण्ड निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

143. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्थान परिवहन/लोक परिवहन निगम के बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

144. विधान सभा क्षेत्र शिव के गडरारोड़ में बसों के ठहराव हेतु मुख्यालय पर बस स्टैण्ड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

145. जयपुर शहर की बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते यातायात के कारण शहर की चारों दिशाओं में बस स्टैण्ड निर्मित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
146. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में निरन्तर बढ़ रहे घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

147. भीलवाड़ा रोड़वेज बस डिपो में निरन्तर कम हो रही बसों के संचालन से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।
148. भीलवाड़ा बस डिपो को अन्यत्र शिफ्ट कर नया बस स्टैण्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
149. भीलवाड़ा से वाया त्रिवेणी काछोला, अमरगढ़, खजूरी एवं जहाजपुर चलने वाली रोड़वेज बस का संचालन पुनः प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
150. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में परिवहन सुविधा से वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
151. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बन्द की गयी रोड़वेज बसों का संचालन पुनः शुरू कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)

152. पीलीबंगा से वाया पीलीबंगा गांव-दौलतांवाली-बडोपल से सूरतगढ़ तक रोड़वेज बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
153. पीलीबंगा से वाया सरांवावाला-बिलोचावाला-हांसलिया-गोलूवाला होते हुए श्री गंगानगर तक रोड़वेज बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
154. पीलीबंगा से वाया लिखमीसर, खरलिया कैचियां, पदमपुर, श्री गंगानगर तक रोड़वेज बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
155. पीलीबंगा से वाया कालीबंगा-हनुमानगढ़ तक रोड़वेज बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)

156. सादुलशहर से गणेशगढ़ तक वाया मन्नीवाली, सुन्दरपुरा, मम्मड़, पन्नीवाली तक बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
157. सादुलशहर से बीकानेर तक वाया लालगढ़ बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
158. सादुलशहर से पक्का सहारणा तक वाया मन्नीवाली, खाराचक बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
159. सादुलशहर से चिन्तपूर्णी तक बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. सादुलशहर से सालासर बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)

161. भरतपुर सम्भाग मुख्यालय पर शहरी बस परिवहन सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में ग्रामीण बस परिवहन सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21 पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कारगर उपाय किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकडा (वि.सं.106)

164. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में उप परिवहन कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के स्टेट हाईवे के नजदीकी कस्बों में रोड़वेज बसों का ठहराव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

166. विधान सभा क्षेत्र श्रीकरणपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस मार्ग श्रीगंगानगर से केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर से 61 एफ. एवं श्रीगंगानगर से फकीरवाली तथा रिडमलसर से गंगानगर तक बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. गजसिंहपुर में बस स्टैण्ड निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोतीराम (वि.सं. 120)

168. विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय रेवदर डिपो (आगार) को पुनः शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र रेवदर-आबू रोड़ के विभिन्न मार्गों पर राजस्थान रोड़वेज की बसों के नियमित संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र रेवदर-आबू रोड़ के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर अवैध यात्री वाहनों के संचालन पर रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मुख्यालय रेवदर से जयपुर मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की द्रुतगामी सीधी बस सेवा के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)

172. सूरतगढ से छतरगढ़, पूगल, बज्जू के लिए रोड़वेज बसों का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. सूरतगढ़ से अनूपगढ़ चलने वाली बसों का जैतसर (1 GB) कस्बे में ठहराव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर मार्ग पर निजी व सरकारी समस्त बसों के ठहराव हेतु आवश्यक बस स्टैण्ड स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं. 102)

175. जयपुर शहर में संचालित ई-रिक्शा वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने तथा चालकों की पहचान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. जयपुर शहर के परकोटे एवं शहर के धार्मिक स्थलों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. जयपुर शहर में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए पृथक से बस सुविधा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. जयपुर स्थित जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राज. संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के लिए विभिन्न स्थलों हेतु परिवहन सुविधा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. जयपुर शहर में संचालित परिवहन सेवाओं में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु सुरक्षा उपकरण स्थापित करने तथा सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

180. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जोधपुर-तिंवरी-चेराई-चामू-नाथडाऊ-पीलवा-जालौड़ा-लोर्डिया-फलौदी तक नई बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)

181. विधान सभा क्षेत्र बयाना में रोड़वेज बस स्टैण्ड के लिए आवश्यक भूमि एवं बजट राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं. 171)

182. हनुमानगढ़ डिपो में बन्द की गयी अनुबंधित बसों का संचालन पुन: प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र भादरा क्षेत्रों में राजस्थान रोड़वेज की बन्द की गयी बसों के रूट पर बसों का पुन: संचालन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र भादरा के परिवहन सेवा से वंचित अनेक गांवों में बस संचालन की सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र भादरा में हरियाणा के सीमावर्ती अनेक गांवो को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु राजस्थान रोड़वेज अथवा हरियाणा सरकार से वार्ता कर समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिए।

186. हनुमानगढ़ आगार में पर्याप्त बसें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं. 162)

187. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत कालाडेरा में बस स्टैण्ड को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत नांगल गोविन्द से रींगस तक नियमित बसों का संचालन शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. चौमूं से गांव किशन मानपुरा तक नियमित व बेहतर स्थिति वाली बसों का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के गोविन्दगढ़ में बस स्टैण्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र चौमूं पर सुविधा विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं. 144)

192. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर में सहाड़ा चौराहा व रायपुर में गंगापुर रोड़ पर नवीन बस स्टैण्ड निर्माण करवाने हेतु बजट स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उमेश मीणा (वि.सं. 23)

193. डूंगरपुर जिले से निकटतम स्थानों हेतु आवश्यकतानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)

194. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) की सार्वजनिक परिवहन से वंचित ग्राम पंचायत नवलपुरा, मामटोरी कला, नयाबास, रफेरी किशनगढ, पिपलोद नारायण देवीपुरा, बमरसर, देवन, कोट, लेटकाबास, निठारा, निदौंला को परिवहन सेवा से जोडने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. अजमेर रोड़ जयपुर स्थित 200 फिट बाईपास से वाया 14 नम्बर वी.के.आई. दौलतपुरा, शाहपुरा, पावटा, कोटपुतली, बहरोड होते हुए दिल्ली तक नवीन रूट सृजित कर बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. चौमू, उदयपुरिया मोड से ईटावा भेपजी, तिगरिया मोड, निवाणा, नांगलकोजु, खेजरोली, मुण्डरन एंव श्री माधोपुर तक स्टेट हाईवे 37 सी पर परिवहन निगम की बसों के फेरे बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) के शाहपुरा में बस स्टैण्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण) में शाहपुरा आगार को प्रशासनिक एवं वित्तिय शक्तियां देने 20 बसें उपलब्ध कराने तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)

199. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के गांव कोलुखेडी कलां, जावर, कामखेडा, सेमलीहाट, सरडा, भलता, घाटोली में बसों का संचालन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (वि.सं. 123)

200. प्रदेश में प्राईवेट बसों द्वारा अधिक राशि वसूलने पर अकुंश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. प्रदेश में प्राईवेट बसों के लिए पार्किंग स्थल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं. 31)

202. कोरोना काल से बंद पडी बसों का संचालन करने व डग से इन्दौर व डग से झालावाड की बसों का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)

203. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ के किशनगड पुराना बस स्टैण्ड के नवीनीकरण अजमेर से वाया-तिलोनिया-हरमाडा-छोटा नरैना तक बस सेवा, बारोडा से अजमेर वाया अराई, किशनगड नवीन बस सेवा प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं. 142)

204. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बारां जिला मुख्यालय से किशनगंज, रेलावन होते हुए राजस्थान परिवहन निगम की बसें चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बस स्टैण्ड, केलवाडा में बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित यादव (वि.सं. 143)

206. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पंचायत मुख्यालय को यातायात से जोडने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर मुख्यालय पर बस स्टैण्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में शाहजहॉपुर से अलवर, खैरथल से शाहजहांपुर रेवाडी तथा कोटपूतली से सोडावास शाहजहापुर बसों का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (वि.सं. 47)

209. विधान सभा क्षेत्र धोद के विभिन्न गांवों व ग्राम पंचायतों को परिवहन से जोडने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)

210. कामां में सब डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र कामां के पहाडी, जुरहरा और गोपालगढ में बस स्टैण्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुभाष मील (वि.सं.179)

212. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के उदयपुरवाटी से रींगस वाया-बागोरा मुडी की ढाणी, पणिहारवास, रामपुरा प्याऊ, खण्डेला, बरसिंहपुरा, तिवाडी की ढाणी, श्री माधोपुर, रींगस बस संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)

213. विधान सभा क्षेत्र पाली के रोहट-पंचायत समिति में राजस्थान रोडवेज के बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

214. बाडमेर जिला परिवहन कार्यालय का जीर्णोद्धार एवं सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र शिव के हरसानी, भीयाड, गिराब, रामसर व गूँगा में बसों के ठहराव हेतु बस स्टैण्ड की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र शिव के शिव मुख्यालय पर स्थित बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार एवं सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. बाडमेर में स्थित विरदीचन्द जैन बस स्टैण्ड पर सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन देवासी (वि.सं.122)

218. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा (सांचौर) स्थित बस स्टैण्ड का आधुनिकरण व परिवहन बसों के ठहरावों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

219. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के उपखण्ड मुख्यालय जसवंतपुरा (जालोर) व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सुंधामाता (जसवन्तपुरा) में नया आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टेण्ड खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के ग्रामीण इलाकों में परिवहन विभाग की नियमित बसों के संचालन सहित अन्य शहरों के रूट पर बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के माउण्ट आबू (सिरोही) में नया आधुनिक सुविधा व संसाधन युक्त बस स्टैण्ड के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

222. राजस्थान से अहमदाबाद, सूरत, मुम्बई, हैदराबाद, बैगलोंर, पुणे सहित अन्य शहरों में परिवहन की आधुनिक एयर कंडीशनिंग (AC) वोल्वों बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं. 57)

223. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के आसीन्द में कोटा से बदनोर तथा मालासेरी से जयपुर रोडवेज बसों को पुनः शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं. 115)</u>

224. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ के गांवों में रोडवेज बसों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं. 46)</u>

225. जहाजपुर व कोटड़ी में बस स्टेण्ड भवन निर्माण करने एवं सुविधाजनक शौचालयों का निर्माण करने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर पर बस डिपों स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. भीलवाड़ा जिले की बसों को वाया जहाजपुर से पुनः चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रशांत शर्मा (वि.सं. 95)</u>

228. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम बिहारीपुरा, सिरसली, भीलपुरा, अनोपुरा दुर्गा का बास, वाया चौमूं से जयपुर के मध्य यात्री बस का संचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र आमेर के गुढ़ा सुर्जन, जालसू, देवगुढ़ा, दादर बावड़ी, आछांबाई, चतरपुरा खोराबीसल, दादी का फाटक होते हुए जयपुर के बीच चलने वाली बस को पुनः संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती गीता बरवड (वि.सं. 41)</u>

230. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के बावड़ी मुख्यालय पर रोड़वेज बस स्टैण्ड बनाने भोपालगढ़ में रात्रिकालीन बस सेवा शुरू करवाने जोधपुर से डेगाना वाया भोपालगढ़, जोधपुर से सीकर वाया भोपालगढ़, जोधपुर से अजमेर वाया बावड़ी, खेड़ापा, रातड़ी, आसोपा गोटन, अजमेर हेतु बस संचालन शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कुलदीप (वि.सं. 33)</u>

231. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में परिवहन बसों को गांवों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं. 22)</u>

232. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में भीलवाड़ा से वाया माण्डल-हरिपुरा-करेड़ा-देवगढ़ रूट पर संचालित बसों की संख्या में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. राजस्थान मोटर वाहन एक्ट के तहत ऑनलाईन गैस किट व ऑफलाईन गैस किट की दरों में अन्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

234. राजस्थान मोटर वाहन टेक्सन एक्ट के तहत बढ़ाये गये टैक्स से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

235. राजस्थान मोटर वाहन एक्ट के तहत ऑनलाईन टी.पी. को जारी रख ऑफलाईन टी.पी. भी चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. वाहन चालकों को भारी वाहन चालक लाईसेंस बनाने में निर्धारित फीस में शिथिलता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)</u>

237. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्रामीण इलाकों में वंचित गांवों को परिवहन सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

238. कोटा से रामराज्यपुरा होकर ताथेड़ गांव तक नई परिवहन सेवा प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के कैथोल बस स्टैण्ड के जीर्ण-शीर्ण प्रतीक्षालय को आधुनिक बस स्टैण्ड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. कोटा जिले के बालवाहिनी वाहनों की निरंतर जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा।

<u>श्री संजय कुमार (वि.सं. 169)</u>

241. धौलपुर से सैंपऊ जारगा, बसेड़ी, नादनपुर, मासलपुर में रोड़वेज की बसें चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अभिमन्यु (वि.सं. 07)</u>

242. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में बसों का संचालन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समरजीत सिंह (वि.सं. 174)</u>

243. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के बागोड़ा से उदयपुर वाया भीनमाल तथा बागोड़ा से जयपुर वाया जालोर बस (वोल्वो) शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. जालोर से सूरत वाया भीनमाल, रानीवाड़ा वोल्वो बस, बागोड़ा से अहमदाबाद वाया भीनमाल वोल्वो बस तथा भीनमाल से जोधपुर वाया दासपा, सायला बस संचालन शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज पटेल (वि.सं. 187)</u>

245. दिल्ली-जयपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट बसों का कोटपुतली में ठहराव सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र कोटपुतली के परिवहन विहीन सुदूरवर्ती गांवों को परिवहन से जोड़ने तथा कोटपुतली आगार को अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं. 83)</u>

247. खेतड़ी आगार में अतिरिक्त नई बसें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

248. खेतड़ी आगार में आवश्यक वाहन चालकों व परिचालकों का पदस्थापन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

249. खेतड़ी आगार में कार्यशाला में पीने के पानी, शौचालय तथा वाहनों की धुलाई हेतु ट्यूबवैल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. खेतड़ी आगार की कार्यशाला व बस स्टैण्ड प्रांगण के नवीनीकरण तथा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री/विद्युत लाईन रिपेयरिंग और कमरों की मरम्मत कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।